खण्ड–496, अंक–3
शनिवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1937
(05 मार्च, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 496 में 5 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
बी0जे0पी0 युवा मोर्चा के अध्यक्ष के विरुद्ध कठोर कार्यवाही तथा श्री सत्येन्द्र कुमार के हत्यारे को गिरफ्तार किये जाने की मांग ...	7–11
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति 2015–2016 का द्वितीय प्रतिवेदन	11
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति 2015–2016 का तृतीय प्रतिवेदन	11
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति 2015–2016 का चतुर्थ प्रतिवेदन	1 1
हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ के कस्बा पुरदिल नगर से लोहिया गांव अजमतपुर अजगरा तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री लव शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	11
जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ के विकास खण्ड हसायन में ग्राम गढौला से ग्राम रामपुर (नगला बंजारा) तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री सोनपाल सिंह नायक व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	12
जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम कचौरा–अगराना मार्ग से ग्राम सुम्मेंरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री गिरिजा शंकर शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	12
जनपद हाथरस की विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ–एटा मार्ग से ग्राम इकबालपुर होते हुए रतिभानपुर–भैंकुरी मार्ग तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री पुरुषोत्तम शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	12
जनपद हाथरस की विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम मुगलगढ़ी गुरुद्वारे से ग्राम बरई शाहपुर होते हुए नगला ढक तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये	12–13

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जाने विषयक श्री नन्द किशोर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)	13
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	13–24
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	24–44
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (स्वीकृत)	44
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	45–55
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	55–71
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) स्वीकृत)	72
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) स्वीकृत)...	72–81
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) ...	81–96
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)...	96–97
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) ...	97–102
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–69–व्यावसायिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)...	102
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	103
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर	103–114

मतदान, अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत) ... ...
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) 114
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत) 114–125

विषय	पृष्ठ–संख्या
	I
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–74–गृह विभाग (होमगार्ड्स) (स्वीकृत) ...	125–130
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	131
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	131–132
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ...	132–135
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–21–खाद्य एवं रसद विभाग (स्वीकृत) ...	135–143
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	143
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	144
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	144
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	144–166
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	166–167
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	168–170
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	170
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग (स्वीकृत) ...	171–176
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	176–179
सहारनपुर नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री राजीव गुम्बर द्वारा नियम–51 के	179–180

अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...
जनपद गोरखपुर के मलौनी बांध से ग्राम सभा सनहा के पास चौरी होते हुए रायगंज सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य 180–181

विषय **पृष्ठ–संख्या**

उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग के आदेशों की अनदेखी करते हुए मुख्य अभियन्ता अलीगढ़ द्वारा काष्ट डाटा बुक से निर्धारित दर से अधिक पैसा जमा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 181–182
जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम रीगा के मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गेंदा लाल चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ... 182–183
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सीतापुर के अन्तर्गत आने वाले गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 183
जनपद मथुरा के कतिपय ग्राम सभाओं स्थित नेशनल हाई–वे–2 व गोवर्धन रोड के दोनों तरफ बसी आबादी से उत्सर्जित जल की समुचित निकासी हेतु गहरे नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य 184–185
नगर पालिका परिषद् मोदीनगर गाजियाबाद की अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुदेश शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य 185–186
जनपद महोबा में जिला कारागार के नवीन भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कारागार मंत्री का केवल वक्तव्य ... 186–187
जनपद कासगंज के अन्तर्गत सिढ़पुडा में ग्राम पिलखुनी से अखतउमंगदपुर स्थित गंजडुडवारा मार्ग पर कला बम्बा की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक 187–188

निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ... ...

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के अन्तर्गत दोहरीघाट खटिक टोला स्थित देशी शराब की दुकान की बहाली कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 188–191

जनपद हाथरस के अन्तर्गत ग्राम पिछोती से धुवई होते हुए सिकन्दराराऊ हसायन तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य... 191–192

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र कस्ता में पानी की टंकी से निकलने वाली समस्त पाइप लाइनों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार लाला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... 192–193

जनपद मथुरा अन्तर्गत मथुरा एवं वृन्दावन में केन्द्र की तत्कालीन सरकार की जेनर्म एवं यू0डी0आई0 एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत बिछाई गई सीवर लाइन को एस0टी0पी0 से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य 193–194

जनपद मेरठ के अन्तर्गत मवाना शुगर मिल द्वारा हजारों किसानों के गन्ने का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभु दयाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 194–195

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शनिवार, दिनांक 05 मार्च, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य–301

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
15. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
21. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री एटा
23. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
26. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
27. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
29. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
30. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
31. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
33. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
34. 'आनन्द सेन, श्री फैजाबाद
35. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
36. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
37. आलमबदी, श्री आजमगढ़
38. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैंनपुरी
39. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
40. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
41. इकबाल महमूद, श्री संभल
42. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
43. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
44. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
45. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
46. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
47. उदयराज, श्री उन्नाव

' उप चुनाव में निर्वाचित।

48. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
49. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
50. उमाशंकर, श्री बलिया
51. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
52. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
53. ओम कुमार, श्री बिजनौर
54. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
55. 'कपिल देव अग्रवाल, श्रीमुजफ्फरनगर
56. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
57. काली चरन सुमन, श्री आगरा
58. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
59. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
60. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
61. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
62. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
63. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
64. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
65. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
66. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
67. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
68. गोमती यादव, श्री लखनऊ
69. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
70. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
71. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
72. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
73. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
74. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
75. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
76. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
77. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
78. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
79. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
80. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
81. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
82. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
83. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
84. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमतीवाराणसी
85. तसलीम, श्री बिजनौर
86. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
87. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
88. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
89. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
90. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
91. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
92. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
93. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
94. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
95. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
96. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
97. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
98. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
99. धर्मराज, श्री बाराबंकी
100. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
101. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
102. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
103. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
104. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
105. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
106. नवाब जान, श्री मुरादाबाद

' उप चुनाव में निर्वाचित।

107. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
108. नाहिद हसन, श्री शामली
109. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
110. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
111. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
112. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
113. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
114. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
115. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
116. पीतमराम, श्री पीलीभीत
117. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
118. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
119. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
120. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
121. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मैंरठ
122. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
123. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
124. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
125. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
126. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
127. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
128. बदलू खां, श्री उन्नाव
129. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
130. बाबू खां, श्री हरदोई
131. बावन सिंह, श्री गोण्डा
132. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
133. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
134. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैंनपुरी
135. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
136. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
137. बैजनाथ, श्री मऊ
138. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
139. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
140. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
141. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
142. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
143. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
144. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
145. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
146. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
147. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
148. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
149. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
150. महबूब अली, श्री अमरोहा
151. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
152. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
153. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
154. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
155. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
156. माता प्रसाद पाण्डेय, श्रीसिद्धार्थनगर
157. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
158. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
159. 'माविया अली, श्री सहारनपुर
160. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
161. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
162. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ

' उप चुनाव में निर्वाचित।

163. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
164. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
165. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
166. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
167. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
168. मौहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
169. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
170. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
171. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
172. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
173. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
174. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
175. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
176. यासर शाह, श्री बहराइच
177. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
178. योगेन्द्रपाल सिंह, श्रीकानपुर देहात
179. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
180. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
181. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
182. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
183. रणजीत सुमन, श्री एटा
184. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
185. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
186. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्रीललितपुर
187. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
188. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
189. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
190. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
191. रवि शर्मा, श्री झांसी
192. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
193. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
194. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
195. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
196. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
197. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
198. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
199. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
200. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
201. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
202. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
203. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
204. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
205. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
206. राधे श्याम, श्री अमेठी
207. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
208. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
209. राम करन आर्य, श्री बस्ती
210. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्रीसम्भल
211. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
212. राम गोविन्द, श्री बलिया
213. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
214. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
215. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
216. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
217. राम मगन, श्री बाराबंकी
218. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
219. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
220. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
221. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
222. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी

223. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
224. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
225. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
226. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
227. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
228. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
229. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
230. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
231. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
232. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
233. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
234. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
235. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
236. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
237. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
238. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
239. विजय सिंह, श्री रामपुर
240. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
241. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
242. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
243. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
244. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
245. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
246. वीरपाल राठी, श्री बागपत
247. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
248. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
249. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
250. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
251. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
252. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
253. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
254. शाकिर अली, श्री देवरिया
255. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
256. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
257. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
258. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
259. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
260. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
261. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
262. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
263. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
264. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
265. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
266. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
267. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
268. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
269. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
270. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
271. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
272. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
273. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
274. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
275. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
276. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
277. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं

278. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
279. सियाराम सागर, डा0 बरेली
280. सीमा, श्रीमती जौनपुर
281. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
282. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
283. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
284. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
285. सुधाकर, श्री मऊ
286. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
287. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
288. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
289. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
290. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
291. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
292. सुरेश राणा, श्री शामली
293. सुरेश कुमार खन्ना, श्रीशाहजहांपुर
294. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
295. सुल्तान बेग, श्री बरेली
296. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
297. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
298. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
299. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
300. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
301. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन), माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी) तथा खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार) श्री राम सकल गूजर भी सदन में उपस्थित थे।

ख1.00 ,बी0जे0पी0 युवा मोर्चा के अध्यक्ष के विरुद्ध कठोर कार्यवाही तथा श्री सत्येन्द्र कुमार के हत्यारे को गिरफ्तार किये जाने की मांग

'श्री पंकज कुमार मलिक–

मा0 अध्यक्ष जी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं जनपद बदायूं में बी0जे0पी0 के युवा मोर्चा संगठन के अध्यक्ष ने यह बयान दिया है कि जो कन्हैया की जुबान काटकर लायेगा उसको सम्मानित किया जायेगा। यह प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम–56 आयेगा तब आप अपनी बात कहियेगा। अभी आप बैठ जाईये।

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य, श्री गुटियारी लाल दुवेश 'माननीय मुख्य मंत्री जी, सतेन्द्र कुमार के परिवार को 20 लाख का मुआवजा दो' का नारा लिखा हुआ बैनर लेकर अपनी पार्टी के अन्य मा0 सदस्यों के साथ सदन के वेल में आ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य वेल से 'दलित विरोधी' और 'भेदभाव की सरकार' के नारे लगाते रहे)

(इसी मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मा0 सदस्य, श्री पंकज कुमार मलिक तथा श्री अजय कुमार ''लल्लू'' भी अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे, लेकिन व्यवधान के कारण किसी की बात स्पष्ट सुनाई नहीं दी)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर वापस जाइये। बजट पास कराने दीजिये। यह न तो लिखा जायेगा और न ही कार्यवाही का अंग माना जायेगा। ओम कुमार जी, आज आप कहां से आ गये और आये तो पहले वेल में ही आ गये। यहां बैनर दिखाने से क्या होगा, मा0 मुख्य मंत्री जी से कहिये। आप लोग जो वेल से कह रहे हैं वह आप अपने स्थान पर जाकर बोलिये ताकि कुछ समझ में आये। मा0 कालीचरन जी, आप अपनी सीट पर जाकर यह बात कहेंगे तो यहां आ जायेगा और सभी लोग सुन भी लेंगे। आप लोग यहां बोल रहे हैं और कांग्रेस के लोग वहां से बोल रहे हैं। आपको जो भी कहना है वह अपनी–अपनी सीट पर जाकर कहिये।

(बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्यों के द्वारा वेल में आकर नारेबाजी व एक साथ बोलने पर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया। चलो। अपनी सीटों से खड़े होकर बोलो जिससे सब लोग सुनें। आप लोग वहीं खड़े हैं अरे अपनी सीटों पर चलो तभी तो सरकार जवाब देगी।

(नारेबाजी)

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको नियमों में लाओ न। कब हत्या हुयी, कब क्या किया गया। वहां से बोलो न। अपने स्थान से बोलोगे तब न कुछ करेंगे। आप नारे लगा रहे हो। लगाते रहो नारे। कुछ नहीं होगा। उपाध्याय जी, आपको जो कहना हो कहें। मंत्री जी हैं सुनेंगे। वह बतायेंगे। चिल्लाने से क्या होगा।

श्री काली चरन सुमन–

मान्यवर, सरकार का वक्तव्य आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सीट पर चलो। तब तो बोलें। आप लोग सीट पर चलो। मा0 काली चरन जी सीट पर चलो।

(बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गये।)

श्री रामवीर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, 13 तारीख को आगरा में एक दलित कर्मचारी की निर्मम हत्या हो गयी।

श्री अध्यक्ष–

कहां ? कब हुआ है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, आगरा में। उसके मुल्जिमों को भी गिरफतार नहीं किया गया और न उनको मुआवजा मिला। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उनको मुआवजा दिया जाये और मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाये।

'श्री गुटियारी लाल दुवेश–

माननीय अध्यक्ष जी, 13 तारीख को एक ईमानदार लिपिक अपनी ड्यूटी ऑफ करके आ रहा था। उस पर एक माह पूर्व लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि साइड खोल दे। कालेज के माफियाओं द्वारा, जो कालेज का बहुत बड़ा जाल है वहां पर अम्बेडकर विश्वविद्यालय में। उसने मना कर दिया कि मैंने न गलत काम किया है और न करूंगा। उसके घर पर धमकी देने गये। गुण्डों ने कहा कि अगर तुमने साइड नहीं खोली तो हम तुझे गोलियों से उड़ा देंगे। उसने कहा कि हमें मरने की चिंता नहीं है। तुम मार देना पर हम साइड नहीं खोलेंगे। उसके बाद मान्यवर, शाम को जब वह ड्यूटी ऑफ करके आ रहा था। बालीबाल पार्क मैं उन गुण्डों ने पीछे से सटा के उसे गोली मार दी। गोली मारने के बाद वह भाग गये। उसके बाद में आगरा विश्वविद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय बंद रहा। कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। बहुत बड़ा कोकस है

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां पर। वहां पर बहुत बड़ी बेइमानी का जाल बिछा हुआ है। उसको आज तक सरकार के द्वारा कोई घोषणा नहीं की गयी कि उसको पैसा दें। किसी ने नहीं सुनी। हम लोगों ने ही अपने माध्यम से आई0जी, डी0आई0जी0, कलेक्टर को, जैसा हमारी पार्टी है हमने संतुलित तरह से अपना पक्ष रखा। हमने कहा कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए। हमने कहा कि वहां जो कोकस है उनको गिरफ्तार होना चाहिए। कोकस में एक गिरफ्तार हुआ है। यह बहुत बड़ा जाल है। हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति की तीन बेटियां हैं। इस बाबू का रिकार्ड है कि वह घर जाकर महीने की तनखा के पैसे देता था और कहता था कि बेटा मुझे इतने पैसे मिलते हैं। मैं बेइमानी नहीं करता। टीचर के ट्यूशन पढ़ाते थे।

श्री अध्यक्ष–

हम समझ गये। अब हो गया।

श्री गुटियारी लाल दुवेश–

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, उसे गोली से मारा गया है, विश्व हिन्दू परिषद् के लोग होते, तो 15 लाख से कम मुआवजा नहीं मिलता। वह इसलिए दिया गया कि आगरा में माहौल खराब हो रहा था, हमने आगरा को जलने से बचाया है, हमारी विधान सभा का मामला था वह, पहले वहां से मैं विधायक था, बड़ी मुश्किल से आगरा बचाया है, क्या हम लोग यही करें कि आगरा को झोंक दें, वहां पर ताजमहल है, विश्व विख्यात शहर है, मुश्किल से आगरा बचा है, उससे भी पहले बहुत सारे मामले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें। कितना बोलेगे भाई।

श्री गुटियारी लाल दुवेश–

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं हम चाहते हैं कि वह घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलने तो दें।

श्री पंकज मलिक–

मा0 अध्यक्ष जी दोनों का जवाब दिलवा दें, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आप किस नियम में अपनी बात उठा रहे हैं ?

श्री पंकज मलिक–

मा0 अध्यक्ष जी, भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष कहते हैं कि कन्हैया की जुबान काट कर के जो लायेगा, उसे इनकी पार्टी सम्मानित करेगी। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके

माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाय और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जांए। ऐसे बोलते रहोगे, तो कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, जो समस्या रखी है साथी ने हमारे, उसके कई पहलू हैं जैसा आपने कहा है एक तो यूनिवर्सिटी का वहां माफिया ग्रुप और उसमें हमारी कोई खता इसलिए नहीं है कि जो स्टाफ है वहां का चाहे वह टीचिंग स्टाफ हो, क्लरिकल हो, क्लास फोर का हो, वह हमारे जमाने का या हमारा रखा हुआ नहीं है और आज कल किसी को आसानी से आप नौकरी से निकाल नहीं सकते, सस्पेण्ड भी नहीं कर सकते हैं और अब तो हद यह है कि मा0 न्यायालय पोस्टिंग भी खुद ही करता है कहां काम करेंगे, तो यह सब हमारे अख्तियार से बाहर की बातें हैं, लेकिन यह वाकया बहुत जाहिर है दर्दनाक है बहुत अफसोस का है जितनी निन्दा की जाय कम है, मुकाबला मत कीजिए किसको कितना मिला, सरकारें हालात के हिसाब से भी फैसला लेती हैं, अगर इनमे भी दंगा कराने की हैसियत होती तो इनको भी शायद मुआवजा मिल गया होता, अब क्योंकि यह क्लर्क थे और यह आगरा नहीं जलवा सकते थे या कोई शहर नहीं जलवा सकते थे, तो सरकारें यह भी देखती हैं कौन सख्स कितना बड़ा फसादी है और उससे समाज को कितना नुकसान हो सकता है और अगर पैसा देकर वह फसाद रोका जा सकता है, तो पैसा देकर फसाद रोकना मेरे ख्याल से कम नुकसान है, लेकिन मैं नेता सदन से बात करूंगा, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, सारी हमदर्दी भी है सरकार की और मुआवजा देने के सिलसिले में जरूर बात करूंगा।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से यह आ जाता कि कम से कम 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा, मान्यवर, उसकी तीन बेटियां हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं इसी की बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष–

नेता सदन से बात करके करेंगे, आप बैठिये, अब हो गया।

श्री पंकज मलिक–

मान्यवर, जो बातें मैंने सदन के समक्ष रखी हैं, उसका उत्तर भी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी दे दें।

श्री अध्यक्ष–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह कौन सा मामला है ? उन्होंने बयान दे दिया, तो अब आप उसमें हल्ला मचा रहे हैं। आप भी बयान दो। अब बैठो।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, जिस नियम में आपने उठाया था, उसी नियम में आप उठा रहे थे, इन बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कुछ लोगों के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई विकास का एजेण्डा नहीं है, कोई प्यार का एजेण्डा नहीं है, जोड़ने का नहीं है। हां, आपको थोड़ी सी आंखें इसलिए खोलना चाहिए कि बात हमसे शुरू हुई थी और 60 साल में बात कन्हैया तक पहुंच गयी। अब कन्हैया भी खतरे में हैं। अब तक तो अहमद अली ही खतरे में थे। इतनी छूट मिल गयी कि अब कन्हैया भी खतरे में है। हमारी जबान तो गई सो गई, कन्हैया की बचा लीजिए और कंस तलाश कर लीजिए। अगर कंस नहीं ढूंढा, हालांकि कंस न होते तो कन्हैया न होते। तो यह अच्छी बात है। मान्यवर, देखेंगे इसमें कौन सी दफा बनती है। अब तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बहुत कुछ आजादी मिल गयी है। सुप्रीम कोर्ट से वह धारा ही खत्म हो गयी है, जिसमें इस तरह के लोगों को सजा देने का प्राविधान था, फिर भी जो हो सकता है, वह करेंगे। लेकिन जबान बचा कर रखिए, मुंह खोलेंगे तभी तो जबान हाथ आएगी, मुंह ही मत खोलिए।

ख1.16, उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति 2015–2016 का द्वितीय प्रतिवेदन[४]

डा0 धर्म सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं सभापति लोक लेखा समिति, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2015–2016) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति 2015–2016 का तृतीय प्रतिवेदन४

डा0 धर्म सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं सभापति लोक लेखा समिति, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2015–2016) का तृतीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित सिंचाई विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति 2015–2016 का चतुर्थ प्रतिवेदन४

डा0 धर्म सिंह सैनी–

---

४ छापा नहीं गया।

मान्यवर, मैं सभापति लोक लेखा समिति, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2015–2016) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में उल्लिखित आबकारी विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

ख11.17, हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ के कस्बा पुरदिल नगर से लोहिया गांव अजमतपुर अजगरा तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री लव शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४४]

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ के कस्बा पुरदिल नगर से लोहिया गांव अजमतपुर अजगरा तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री लव शर्मा व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ के विकास खण्ड हसायन में ग्राम गढ़ौला से ग्राम रामपुर (नगला बंजारा) तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सोनपाल सिंह आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४४]

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ के विकास खण्ड हसायन में ग्राम गढ़ौला से ग्राम रामपुर (नगला बंजारा) तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री सोनपाल सिंह नायक व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम कचौरा–अगराना मार्ग से ग्राम सुम्मैंरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/ मरम्मत कराये जाने विषयक श्री गिरिजा शंकर शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४४

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम कचौरा–अगराना मार्ग से ग्राम सुम्मेरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री गिरिजा शंकर शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद हाथरस की विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ–एटा मार्ग से ग्राम इकबालपुर होते हुए रतिभानपुर–भैंकुरी मार्ग तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में

---

४४ छापी नहीं गयी।

४४ छापी नहीं गयी।

निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री पुरुषोत्तम शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४४]

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हाथरस की विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ–एटा मार्ग से ग्राम इकबालपुर होते हुए रतिभानपुर–भैंकुरी मार्ग तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री पुरुषोत्तम शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद हाथरस की विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम मुगलगढ़ी गुरूद्वारे से ग्राम बरई शाहपुर होते हुए नगला ढक तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नन्द किशोर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हाथरस की विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम मुगलगढ़ी गुरूद्वारे से ग्राम बरई शाहपुर होते हुए नगला ढक तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नन्द किशोर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6, 7 व 8 में कुछ नहीं अब मद संख्या–9।

ख11.20, उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016[४]

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री यासर शाह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

ख11.21, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

---

४ दिनांक 30 मार्च, 2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

आज दिनांक 05–03–2016 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आप मेरा विषय सुन लीजिए और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दीजिए। मैंने कोई इण्डिविजुअल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं उठाया है। मान्यवर, मैं कई दिनों से सूचना लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, आपका नियम–56 में हमने लिया है। आप अपने विषय पर बोल दीजिए तब तक वह आता रहेगा। हम जानते हैं, आपके विषय को हमने पढ़ा है, आप बोल लीजिए। जो भू–गर्भ जल स्तर नीचे चला जा रहा है, आपका इसी से सम्बन्धित है।

'श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने इस लोकमहत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुमति दी। प्रगति के मार्ग के सामने हमने पिछले दिनों देखा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश सूखे में था। सरकार ने भी इसको गम्भीरता के साथ लेते हुए प्रदेश के लगभग 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए। मान्यवर, इसमें रोज सर्वे आ रहा है और इस बात को बड़े गम्भीरता के साथ संज्ञान, पूरा सिस्टम ही बड़ी गम्भीरता के साथ संज्ञान ले रहा है कि भ–ूगर्भ जल की सतह दिन प्रति दिन नीचे गिरती जा रही है। मान्यवर, पिछले दिनों एक सर्वे के हिसाब से लगभग 2 मीटर यानी 7 फिट भू–गर्भ जल नीचे चला गया है। मान्यवर, जिस समय हैण्डपम्प लगाने की बात होती है तो इस विधान सभा में इस बात को बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं और सारे मा0 सदस्य भी जानते हैं कि जो आम आदमी की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है वह है पीने के पानी की और सबसे कम लागत हैण्डपम्प के ऊपर आती है। मान्यवर, उस कम लागत के कारण अगर पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प मिल जाए। बहुत सारे मानक भारत सरकार ने भी तय किए होंगे और भारत सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार ने भी तय किए होंगे। उसकी दूरी तय की होगी कि 100 मीटर पर लग सकता है, 75 मीटर पर लग सकता है उसकी दूरी कम कर दी गई हो। मान्यवर, लेकिन उस दूरी के कारण हो सकता है कि मानकों में हमने उन किताबों में, फाइलों में इस बात को कह दिया होगा कि पूरा प्रदेश संतृप्त है और पीने के पानी की कहीं कमी नहीं है लेकिन मान्यवर, जो बात मैंने आज आपकी कृपा से उठाई है कि भू–गर्भ जल का स्तर ही नीचे चला गया है। अण्डर ग्राउण्ड वाटर लेवल जिस समय नीचे चला जाएगा तो जितने मर्जी हैण्डपम्प लगे हों मानकों के हिसाब से वह सारे के सारे लगभग ठूंठ सबित हो गए हैं और वहां पर पानी नहीं आ रहा है। ऐसी

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिस्थितियों मैं जब भू–गर्भ जल स्तर के बाद गर्मी भी आ गई है और गर्मी जल्दी आ गई है तो गर्मी में पीने के पानी का बहुत गम्भीर संकट होने वाला है। उस पीने के पानी के लिए हम लोग सरकार से हैण्डपम्प की मांग बहुत वर्षों से कर रहे हैं लेकिन वह नहीं मिला। इस बार उम्मीद है क्योंकि कल जिस प्रकार मा0 मुख्य मंत्री जी ने कृपापूर्वक सहिष्णुता दिखाई है और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी उसको सहमति देते हुए व्यक्त कर रहे थे। मान्यवर, थोड़ा सा मक्खन लगा लें तो हो सकता है कि कुछ हैण्डपम्प वगैरह मिल जाएं।

श्री अध्यक्ष–

अरे, मक्खन खाने के लिए होता है लगाने के लिए नहीं होता है। क्या आप लगाते हैं ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, थोड़ा सा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि भू–गर्भ जल की सतह नीचे होने के कारण हैण्डपम्प ठूंठ हो गए हैं। या तो मिनिमम 200–200 हैण्डपम्प प्रत्येक मा0 सदस्य को नए लगाने के लिए दे दें। नए लगाने के लिए नहीं देते तो 300 की आवाज आ रही है, मैं तो 500 ही कहूंगा तो मान्यवर, या तो नए दे दें अथवा नए देने में अगर कोई कठिनाई आती है तो मेरा यह विनम्र निवेदन जरूर है कि 300–300 हैण्डपम्प रि–बोर के लिए दे दें क्योंकि रि–बोर तो जो लगे हुए हैं उन्हीं को रि–बोर होना है और उसमें तो किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, अगर 300 नए हैण्डपम्प देते हैं तो कृपा होगी नहीं तो 200–200 हैण्डपम्प क्योंकि आप बहुत सारे विकास की बात करते हैं, बहुत सारे धन की उपलब्धता की बात करते हैं, बहुत सारे हाईवेज़ की बात करते हैं लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरत है जिसके ऊपर सबसे कम खर्चा आना है वह हैण्डपम्प है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए और मुझे लगता है कि इस चर्चा में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों बराबर से भागीदारी करेंगे।

(श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, नीरज कुशवाहा जी आपका विषय गिरफ्तारी का था। मैंने मुकदमा अपराध सं0–33 पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैंने जो कहा, उसका उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब मंत्री जी बैठे तो हैं। अब इतना मक्खन लगाने के बाद भी तैयार नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या करूं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, वह उत्तर देंगे, आप उनको बुलाओ तो सही। देखिए, आप बुलाते हैं तो वे जरूर खड़े होते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, वाटर लेविल कम नहीं होने की वजह तो बारिश नहीं होना है और क्योंकि शहरों में बहुत ज्यादा इंटरलॉकिंग है। इंटरलाकिंग का कन्सेप्ट दुनिया के सामने इसलिए आया था कि बारिश होगी तो पानी नीचे जमीन में चला जायेगा लेकिन उन देशों में जहां ये ख्याल हुआ इस पर काम हुआ वहां थोड़ा मिलावट कम होती है, जो रेत डालते हैं वह ऐसी होती है वह नॉन सिल्टेड रेत होती है। हमारे यहां क्योंकि रेत नदी के किनारे से ले आते हैं आधा मिट्टी आधा रेत तो सिल्टेड होने की वजह से उसमें घास निकल आती है और इंटरलाकिंग का मजा जाता रहता है। हमने भी यही प्राविधान किया है अपने विभाग में कि रोड़ा, सीमेंट, रेत मिलाकर पहले उसका बेस बनाया जाए उसके बाद इण्टरलाकिंग की जाए, उस तरह पानी जमीन में नहीं जा पाता तो शहरों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि पक्के मकानात, कॉलोनीज, सी0सी0 रोड्स हैं, इंटरलाकिंग रोड्स हैं तो पानी शहरों में नीचे नहीं जा पाता फिर ये भी सच है अब महाना जी कह रहे हैं अब क्योंकि महाना जी गलत बयानी भी मक्खन लगाकर करते हैं। अब ये किस जगह मक्खन लगाते हैं ये हमें नहीं बताया, कितनी मात्रा में लगाते हैं ये भी नहीं बताया। अलग बताने की बात होगी यह (माननीय सदस्य श्री सतीश महाना जी के खड़े होने के प्रयास में) जब आप बोल रहे थे तो मैं खड़ा हुआ। अब महाना जी की बात को वैसे भी हम मिजाजन भी नहीं टालते हैं लेकिन शहरों में हैण्डपम्प लगाने की जगह ही नहीं है। गांवों के लिए याद हो तो आप सुनते नहीं हैं दरअसल वो देखा है आपने आजकल एक ऐड आ रहा है जिसमें बेटा बाप से कहता है सुनते नहीं हो, कैसा डॉटा है बाप को उसने, मैं तो डांट नहीं सकता क्योंकि आप तो मेरे लिए खुद वालिद की जगह हैं। मान्यवर, क्योंकि नेता सदन ने कहा है कि हम टैंकर्स यूज करेंगे गांव, देहात मैं पानी की कमी किसी तरह से नहीं हो पायेगी। असल मैं तो जब बादशाह गलतबयानी करता है तो सजा प्रजा को मिलती है तो यह सब सजा तो प्रजा को मिल रही है। अच्छा बादशाह होता तो अच्छे हालात होते। अब सूखा तो पड़ ही गया अब खैर यह मनाइये कि ये जो बारिश होनी हैं, ये नहीं हुईं मान्यवर, तो वाकई बहुत ही खतरनाक हालात होंगे, बहुत भयानक होंगे लेकिन उन हालात में भी हम आपसे वायदा करते हैं कि पानी की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। हैण्डपम्प की जहां तक बात है खन्ना साहब आप खुद सक्षम हैं, काहे के लिए आप उन्हें मक्खन सप्लाई कर रहे हैं। आप खुद कहिए।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, जरा यह दिखवा लें। मान्यवर, मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि एक भटकाऊ विभाग का गठन कर दिया जाए। मुख्य मंत्री जी के द्वारा पता चला है कि आज उन्होंने गठन कर दिया है। ये मान्यवर, आप दिखवा लें आपने कार्यालय में कि अगर यह विभाग सृजित हो गया है, तो मेरा प्रस्ताव है मान्यवर, और मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण सदन का यह प्रस्ताव होगा कि इन माननीय मंत्री जी को उसका प्रभारी बना दिया जाए।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मक्खन की बात थोड़ा बता दें। मान्यवर, मैंने तो लगाया था, लगा कहां है, आपको कहां आभास हुआ आप उसको बता दोगे, मेरे को कहीं भी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में, उत्तर आ तो जाने दें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

क्यों बेकार बातों में पड़ रहे हैं आप, बोलते–बोलते आपकी ही जुबान फिसल जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

असल में अगर आपको यह मालूम हो कि मैं रामपुर का हूं तो फिर आप खुद समझ रहे होंगे कि कहां लगा होगा और मैंने कहां समझा होगा। (सदन में हंसी)

श्री अध्यक्ष–

अब आप छोड़िए, इस बहस को।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, खन्ना साहब ने जो बात कही है। अब ये हल्का माहौल रहे मान्यवर, कल से माहौल बहुत टेन्श है। खन्ना जी को असल में कोई काम तो है नहीं, न इन्हें पत्नी के बारे में सोचना है, न बच्चों के बारे में सोचना है, न उनकी खुशहाली के बारे में सोचना है तो यह खुराफात नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे। खाली जेहन शैतान का घर होता है तो सारे लोग मिलकर इन्हें पहले तो अच्छी राय ये दें कि ये जो बचे–खुचे दिन हैं जवानी के ये काम में ले लें (सदन में हंसी) तो मान्यवर, कोई पानी की कमी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री दलजीत सिंह, श्री गयादीन अनुरागी और श्रीमती उमा कान्ती का जनपद जालौन में कालपी हैण्डमेड कागज उद्योग बन्द हो गया है के सम्बन्ध में। इस पर हम ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं। तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का और डा0 राधामोहन दास अग्रवाल का यह बेसिक शिक्षा में जो शासनादेश निकला है, 03–03–16 तथा 24–01–16 में, उस शासनादेश शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में, कोई एक माननीय सदस्य बोल लीजिये।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और तुरन्त का विषय है 03 मार्च 2016 और 26 फरवरी 2016 को यह आदेश निकला है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे ऐक्ट हम सब जानते हैं। 2009 में जब यह प्रवृत्त हुआ था तो इसे मौलिक अधिकारो ऐक्ट में शामिल किया गया और जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है उस ऐक्ट बहुत स्पष्ट प्राविधान है किसी भी क्षेत्र में जो भी निजी असहायतित विद्यालय होंगे उनमें न्यूनतम मैं उस अधिकार की उस ऐक्ट की प्रति अपने पास रखे हूं जो महत्वपूर्ण प्राविधान उस ऐक्ट का है वह इतना ही है कि किसी भी निजी असहायतित विद्यालय में उनकी प्रवेश क्षमता का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश ऐसे बच्चों से लिया जायेगा जो समाज के दुर्बल वर्ग के बच्चे होंगे या समाज के डिसएडवान्टेज ग्रुप, उसकी परिभाषा दी है अनुसूचित जाति, जनजाति जो भी उसके अलग क्राइटेरियास आते हैं, उस ऐक्ट में बहुत स्पष्ट लिखित प्राविधान है कि यह ऐक्ट किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय इस ऐक्ट को बनाने के बाद सरकार ने एक नियमावली बनाई, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं और उस नियमावली मैं उस ऐक्ट को किस प्रकार से लागू किया जायेगा उसकी प्रक्रिया निर्धारित की गयी उस प्रक्रिया को निर्धारित करने के बाद सरकार ने 25 जून, 2011 को एक गाइड लाइन पूरे देश में प्रसारित की। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो ऐक्ट इस बहस में लाना चाहता हूं वह यही गाइड लाइन है, गाइड लाइन यह कहती है कि व्हाइल अण्डरटेकिंग मेंपिंग टू डिटरमाइन द नीड, आवश्यकता को तय करने के लिए जो मैंप एरिया का किया जायेगा एण्ड प्लानिंग फार द स्टेबलिश्मेण्ट आफ द नेबरहुड स्कूल और नेबरहुड विद्यालयों की स्थापना के लिए जो योजना बनाई जायेगी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेण्ट शुड फैक्टर इन द इन्टेक कैपेसिटी जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेण्ट अर्थात राज्य सरकार अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आल द स्कूल्स विदइन द एरिया आफ द लिमिट आफ द नेबर हुड एज प्रिस्क्राइब्ड अण्डर सेक्शन–6, सेक्शन 6 में जितने भी विद्यालय होंगे उनको ध्यान में रखेगी दैट इज द गवर्नमेण्ट आर द लोकल बाडी स्कूल्स अध्यक्ष महोदय सारा खेल यहीं हुआ है, गवर्नमेण्ट आर द लोकल बाडी स्कूल्स जो सरकारी विद्यालय हैं, एडेड स्कूल्स जो सहायतित विद्यालय हैं, स्पेसिफाइड कैटेग्री स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय एण्ड अनएडेड स्कूल्स और असहायतित विद्यालय यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चार कैटेग्री के विद्यालय हैं सरकार ने यह 25 जून 2011 को नियमावली दाखिल की पूरे देश में बटवाई और कहा कि जब आप नेबरहुड की कल्पना को लागू करेंगे तो किसी क्षेत्र ऐक्ट जितने सरकारी, जितने गैर सरकारी सहायतित, जितने स्पेशल कैटेग्री और जितने असहायतित सारे विद्यालयों को संज्ञान में लेंगे और उसके हिसाब से योजना बनायेंगे कि उस क्षेत्र में जो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत 30 इज टू 1, 30

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छात्रो पर एक टीचर का जो मापदण्ड है, वह कितना पूरा हो रहा है और यदि नहीं पूरा होगा तो आप अतिरिक्त विद्यालय की नियुक्ति करेंगे। अध्यक्ष महोदय यह जो ऐक्ट है ऐक्ट में एक स्कूल क्या होता है इसको डिफाइन किया गया है ऐक्ट यह कहता है कि स्कूल मीन्स एनी रिकगनाइज्ड स्कूल इमपार्टिंग एलिमेंन्ट्री एजूकेशन। स्कूल का अर्थ है कोई भी ऐसा स्कूल जो कक्षा 8 तक की शिक्षा देता हो और उसमें 4 कटेगरी हैं ए दि स्कूल स्टेब्लिश बाई दि गवर्नमेन्ट सरकार के स्कूल, बी एडेड स्कूल सहायतित स्कूल, दि स्कूल बिलागिंग टू स्पेशल कटेगरी विशेष युक्ति के एण्ड अन एडेड स्कूल, मैं जो कहना चाहता हूं स्कूल की परिभाषा में सरकार ने जब यह अधिनियम लागू किया तो सिर्फ सरकारी स्कूलों को नहीं जो और सहायतित निजी स्कूल थे उनको भी लागू किया और कहा कि इनकी संख्या को किसी क्षेत्र में ध्यान रखते हुए आप निर्धारित करेंगे तीस इनटू वन का रेशियो। अब अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ी यहीं हो गयी यह गड़बड़ी आज नहीं हुई, यह 2011 की बात है आज उसको बढ़ा दिया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली, 2011 में बनाई इस सरकार के पहले बनाई, इस सरकार को मैं उसके लिए कतई जिम्मेंदार नहीं ठहरा रहा हूं। वास्तव में कोई भी सरकार जिम्मेदार नहीं है यह नियमावलियां हम राजनैतिक लोग नहीं बनाते, यह नियमावलियां अधिकारी बनाते हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी होती है जैसा मैंने कल कहा था ऐक्ट कुछ और पारित हुआ राजस्व का नियमावली कुछ और बनी राजस्व की ठीक वही चीज यहां भी हुई। भारत सरकार की गाइडलाइन्स को न ध्यान मैं रखते हुए एक नियमावली बनाई गयी जिसमें अनावश्यक रूप से वह क्राइटेरिया तय कर दिया गया कि स्कूल की संख्या तय करते समय असहायतित विद्यालयों को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा सिर्फ सरकारी विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय सिर्फ इन दो विद्यालयों को संज्ञान में लिया जायेगा और सरकार ने इस नियमावली के आधार पर एक आदेश पारित कर दिया 20 जून, 2013 को जिसके तहत यह प्राविधान कर दिया गया कि वार्ड को एक इकाई मान लिया जायेगा और किसी भी वार्ड में अगर कोई प्राथमिक विद्यालय होगा तो वहां पर जो स्थित निजी विद्यालय होंगे उनमें किसी प्रकार का प्रवेश नहीं कराया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐक्ट इस बात की गारन्टी देता था कि निजी विद्यालयों में कम से कम 25 परसेन्ट बच्चे प्रवेश किये जायेंगे ऐक्ट की बाध्यता इतनी ही थी ऐक्ट को बाकी चीजों से मतलब नहीं था। ऐक्ट यह सुनिश्चित करना चाहता था कि निजी विद्यालयों में 25 परसेन्ट बच्चे समाज के गरीब और डिसवान्टेज ग्रुप के लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब नियमावली बनाई गयी, अदभुत तरीके से नियमावली बनाई गयी और यह प्राविधान कर दिया गया 2011 में, अध्यक्ष महोदय, कि जिस वार्ड में कोई भी एक प्राथमिक विद्यालय होगा वहां के बच्चे किसी भी निजी विद्यालय में एडमीशन नहीं लिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस आदेश के बाद मुकदमें होते रहे और मुकदमें होने के बाद एक मुकदमा जो अन्तिम हुआ में उसका जिक्र यहां नहीं करना चाहूंगा सिर्फ एक छोटा सा उल्लेख करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो एडीशनल सालीसीटर होते हैं उन्होंने स्वयं इस बात का बयान

दिया द गाइड लाइन्स फार इम्लीमेन्टिंग द आविजन्स आफ द ऐक्ट हैब बीन इश्यूड अण्डर सेक्शन 35 (1) आफ द ऐक्ट वाइ द सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ऑन 25–7–2011 राज्य सरकार के सालीसीटर जनरल ने स्वयं इस बात को कहा कि भारत सरकार ने 25 जुलाई, 2011 को इसके गाइडलाइन्स जारी कर दिये हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके हिसाब से गाइडलाइन्स बनाई है यदि उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन्स में ऐसा कोई हिस्सा है जो भारत सरकार के गाइडलाइन्स के अनुरूप नहीं है तो जो भारत सरकार का गाइडलाइन होगा वही लागू होगा उत्तर प्रदेश का गाइडलाइन नहीं लागू हेागा। आप जानते हैं मेरे पास सारी पत्रावली है यह कोर्ट के अन्दर इस अपनी सरकार के द्वारा दिये गये उनके सालीसीटर एडीशनल एडवोकेट जनरल का यह बयान है। अध्यक्ष महोदय, इसके आधार पर माननीय न्यायाधीश ने कहा कि यह एक सत्य है सरकार ने नियमावली बनाते समय हैज फेल्ड टू कान्सिडर पार्टिकुलर क्वैश्चन आफ नेबरहुड विद्यालय की परिभाषा करते समय सही परिभाषा सरकार नहीं बना पाई है इसलिए नियमावली गलत बन गयी एण्ड द गवर्नमेन्ट इन दिस रिगार्ड टू रेक्टिफाइ द एरर एण्ड डू द नीडफुल टू मेक द गाइडलाइन्स फार इम्पलीमेन्टेशन और सरकार को यह कहा गया कि अपनी गाइडलाइन को ठीक करे और सही प्रकार से नियमावली बनाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या जब सुप्रीम कोर्ट का यह जो आदेश मैंने आपके सामने पढ़ा, इसी आदेश को कोड करते हुए अपील संख्या–333/2012 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए यह जो आदेश पारित हुआ इस सरकार ने दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जिसका मैंने उल्लेख किया, एक नया शासनादेश निकाल दिया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा जा रहा था कि आपने गाइड लाइन गलत बनाई हैं, सही बना लीजिये, आप सारे निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों का प्रवेश करवाइये और सरकार ने उसी न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया और एक नई गाइड लाइन जारी कर दी जिसमें यह कह दिया कि वार्ड का क्राइटेरिया भी खत्म। अब क्राइटेरिया एक किलोमीटर का लागू किया जायेगा और इस एक किलोमीटर के एरिया में कोई भी अगर एक प्राथमिक विद्यालय होगा, वहां किसी निजी विद्यालय में जब कि 30 स्टूडेन्ट का मानक पूरा न हो जाये, प्रवेश नहीं लिया जायेगा और दिनांक 26 फरवरी, 2016 के बाद दिनांक 03 मार्च, 2016 को माननीय उच्च न्यायालय के इसी निर्णय का उल्लेख करते हुए पुनः एक शासनादेश निकाल दिया गया और उसके इसी क्राइटेरियाज को और कड़ाई से लागू करने की बात कही गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेंदार नहीं ठहराता। यह सिस्टम हमारा ऐसा है, आपने देखा कि कितना अच्छा एक निर्णय आया था माननीय उच्च न्यायालय का कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़े और कैसी राजनीतिक बलि लोगों को देनी पड़ी। यही खेल इस शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के माध्यम से इस प्रदेश की नौकरशाही ने जिन महान भावनाओं के साथ यह शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था उसको समाप्त

करने में कर दी और उसका फल क्या हुआ कि गोरखपुर में पिछले साल शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कुल 63 बच्चों का प्रवेश हुआ। कम से कम वहां 500 विद्यालय होंगे और सबकी संख्या 100 के आसपास होती है, आप सोच सकते हैं कि कितने बच्चों का प्रवेश होना चाहिये। 63 ऐसे बच्चे थे जो निजी विद्यालयों में प्रवेश पा पाये। इन विद्यालयों ने एक काकश बनाया है, जो इन काकश के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों को और यह जो शासनादेश जारी करते हैं, उन अधिकारियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज एक निर्णय छपा है माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय चन्द्रचूड़ जी का और उन्होंने सरकार के इस सारे शासनादेश को क्वैश कर दिया है और कहा है कि सरकार ने यह नियमावली गलत बनाई है, सरकार ने यह व्यवस्था गलत की, हर दुर्बल वर्ग के बच्चे का यह अधिकार है कि वह अपने नाइबरहुड में जिस भी निजी विद्यालय में चाहे प्रवेश ले। मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि अगर यह नियमावली बनाई गई है, हम संज्ञान में पा रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा निदेशालय, बेसिक शिक्षा सचिवालय के सारे अधिकारी जिन्होंने इस नियमावली को बनाकर इस प्रकार से अव्यवस्था पैदा की है, इस सरकार को उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये और राइट टू एजूकेशन सही तरीके से लागू करना चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, बहुत विस्तार से रखा है आपने। असल में सुप्रीम कोर्ट का जब यह फैसला आया था तो उससे एक डर बना था और नहीं मालूम क्योंकि मेरे पास इस समय इसकी तफसील नहीं है, बता नहीं सकूंगा। देखिये यह तो नैचुरल जस्टिस के खिलाफ बात है कि जिन विद्यालयों को आप किसी तरह की कोई एड नहीं दे रहे हैं और उन पर पाबन्दी भी आप लगायेंगे, तो यह संभव नहीं होगा। उनके अधिकार के बारे में क्या विभाग ने तय किया है, यह मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपकी बात में इस हद तक तो दम है ही कि जब हम नियमावली बनाते हैं, तो उसको शायद उतनी संजीदगी से नहीं देख पाते। अभी देखिये दो–तीन दिन पहले आई थी फिरोजाबाद की बात, लेकिन आप सब लोग जागरूक हैं इस पर नजर रखते हैं तो कोई सरकार की ऐसी जिद नहीं होनी चाहिये कि जो नियमावली बन गयी, वह कोई आसमानी किताब है, बदली नहीं जा सकती । उसमें जो भी कमियां हैं उस पर विचार भी होना चाहिये और उसमें तब्दीली भी होना चाहिये।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिस बात को उठाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो इस पर आ ही गया है। जो अभी नियम है जिसकी यह चर्चा कर रहे हैं वह यह इसलिये आया कि जो सरकार प्राइवेट स्कूल में एडमीशन करायेगी तो उसको स्टेट गवर्नमेंट फीस देगी और उसकी साढ़े चार सौ फीस एक लड़के पर आ रही है। यह इसलिये ये जी0ओ0 बना कि हर एक किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल है और तीन किमी0 पर जू0 हा0 स्कूल है। सदन में इस बात की बराबर चर्चा होती रही है कि

प्राथमिक स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं, स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो स्कूल में एक तरफ बच्चे कम की चर्चा और दूसरी तरफ हर जगह एक किमी0 पर स्कूल हैं तो हमारे स्कूल ऐक्ट बच्चे पूरे हों और हमारी जब सीट भर जाये तब हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजें क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को उसकी फीस देनी है और हम अपने स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं तो यह दोतरफा नीति एक तरफ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और दूसरी तरफ वही स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल ऐक्ट जिस लड़के का एडमीशन करायेगी उसकी 430 रुपया फीस देगी। तो इसलिये इस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, अभी उसको अधिकारी लोग देखेंगे, बनायेंगे और उसमें भी यह किया गया था कि जो बच्चे निशक्त हों या गरीब हों या बीमार पीड़ित हों उनका नाम प्राइमरी स्कूल में लिखा जायेगा जैसा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है वैसा नियम बन जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, कल माननीय नेता सदन ने जिन शब्दों में बेसिक शिक्षा के बारे में कमेंट किया मान्यवर हम उस बात को दोहराना नहीं चाहते। लेकिन पूरा सदन इस बात से सहमत है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के जो विद्यालय हैं उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उसकी गुणवत्ता क्या है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जब केन्द्र सरकार ने कानून बनाया और 3 नवम्बर, 2011 से उसको लागू किया गया, उत्तर प्रदेश ऐक्ट भी लागू किया गया इसलिये सवाल पैसे का नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर वह लोग जो डिसएडवान्टेज क्लास है, आर्थिक रूप से कमजोर क्लास है और निजी स्कूलों में पढ़ाई कम्परेटिवली बेहतर हो रही है तो उसका लाभ यह न ले पाये इस पैसे को बचाने के चक्कर में। मान्यवर यह कौन सा व्यवहार है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया हमने चुपचाप उसको सुन लिया था कि जहां पर कमी होगी उसको ठीक करेंगे। मान्यवर, यह सरकार बेसिक शिक्षा में सुधार चाहती नहीं है यह सरकार गरीबों के प्रति कतई गंभीर नहीं है और गरीबों को शिक्षा दिलाना नहीं चाहती कि अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ें। इसलिये हम और हमारा दल इसके विरोध में सदन से बहिगर्मन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारा लगाते हुये सदन से बाहर चले गये)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह जो तरीका भाजपा का रहा, इससे फिर एक बार यह साबित हुआ कि यह किसी समस्या का समाधान नहीं चाहते सिर्फ अखबार की खबर चाहते हैं और मैंने तो इनकी थोड़ी सी लाज रख ली थी अब चले गये हैं तो लाज भी नहीं हैं। अब यह किन स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं यह मेरे ख्याल से इशारा मंत्री जी ने कर दिया हैं। हम जैसे लोगों को तो बहुत खुश होना चाहिये मान्यवर, अभी मैं दो मिनट आपके लूंगा। कानपुर एक फंक्शन में गया वहां मुलाकात हुई। एक साहब ने कहा कि यह सी0बी0एस0ई0, के स्कूल चलाते हैं मगर स्कूल में घाटा हो रहा है। मैंने पूछा कि

फीस कितनी है तो बताया कि 10 हजार रुपये पर मंथ तीसरे चौथे क्लास के बच्चों की। तो हमने कहा, क्योंकि हम लेबर मिनिस्टर भी रहे हैं हमें यह मालूम है कि घाटे का मापदंड क्या होता है। आपने यह सोचा कि इस साल हमें दो करोड़ बचना चाहिये था और डेढ़ करोड़ बचा तो 50 लाख रुपये का आपका घाटा हो गया। फिर मैंने पूछा कि अभी 40 बच्चे पूरे देश में साइंस कम्पटीशन में क्वालीफाई किये हैं तो क्या आपका कोई बच्चा उसमें है क्योंकि 10 हजार फीस है आपकी। तो बोले कि नहीं हमारे यहां का कोई नहीं है, इनके यहां का भी नहीं होगा जो चले गये हैं। हम तो उससे बड़े खुश होते लेकिन क्योंकि किसी एक व्यक्ति के फायदे से व्यक्ति का फायदा नहीं हो रहा है जिस मानसिकता को यह फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप 10 हजार फीस लेते हैं और एक बच्चा भी क्वालीफाई नहीं किया। मेरे स्कूल की एक बच्ची इन 40 बच्चों में आई है और मैं मात्र साढे तीन सौ रुपयाफीस लेता हूं तो हमें बड़ा फायदा होता उससे, हम उसके लिए खुश नहीं हैं जो पैसा आपसे मिलता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फायदा होगा, डॉक्टर साहब झांक रहे हैं, आपके निकेतनों को ज्यादा फायदा होगा। तो फायदा पहुंचे किसी को इससे एतराज थोड़े ही है। लेकिन खबर बनाने के लिए जो वाक–आउट हुआ है इसकी निन्दा होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा के मामले पर बजाए इसके कि आप बहस करें, आपने जो बात रखी है उसका जवाब भी लें, उसे भी सुनने की हिम्मत रखें। असल में ये लोग सिर्फ जुबान काटने में यकीन रखते हैं (सत्तापक्ष ने मेंजें थपथपायी) और जुबान काट देंगे, आइन्दा बस ये होने वाला है कान के पर्दे भी फोड देंगे। ये गूंगी और बहरी नेशन बनाना चाहते हैं। मान्यवर, देखिये फासिस्टों का क्या तरीका है, वह धर्म जाति नहीं देखता है, वह विचारधारा देखता है। इसीलिए मैंने कहा कि बात कन्हैया तक आ गयी है, वो विचारधारा देखता है। जो उसकी विचारधारा को नहीं मानेगा, वो उसका दुश्मन है। चाहे पड़ोसी क्यों न हो, चाहे उसका सगा भाई क्यों न हो, चाहे उसकी औलाद क्यों न हो ? वो विचारधारा के विपरीत चलने वाले हर पौधे को काट देगा। यह अच्छा नहीं है, बहस करना चाहिए, डॉक्टर साहब पढ़े–लिखे आदमी हैं उन्हें इस तरह वाक–आउट नहीं करना चाहिए था। सरकार संजीदा है इस पर और जो भी समाज हित में और विशेष वर्ग के हित ऐक्ट होगा वही निर्णय लिया जायेगा।

(श्री दलवीर सिंह व श्री अजय कुमार 'लल्लू' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप तो डिप्लोमा इन्जीनियर्स के हड़ताल पर सूचना दिये हैं, उससे आपको क्या परेशानी है ?

चौथी सूचना श्री नीरज कुशवाहा मौर्य जी की जनपद फर्रुखाबाद के थाना राजापुर ऐक्ट दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–33/2016 में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया है।

पांचवी सूचना श्री सिनोद कुमार शाक्य जी की है, वह उपस्थित नहीं हैं।

छठी सूचना डा0 मो0 अयूब की जनपद संतकबीरनगर के सेमरियांवा ब्लाक में सरकारी आई0टी0आई0 कॉलेज की स्थापना न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, इस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया है।

सातवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र श्रमिक कालोनी बाबूपुरवा में राजकीय चिकित्सालय की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, इस पर भी मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया है।

इसके अलावा श्री संतराम कुशवाहा व उमा शंकर सिंह की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया है।

(श्री दलवीर सिंह व श्री अजय कुमार 'लल्लू' के खड़े रहने पर)

अब आप डिप्लोमा इन्जीनियर्स पर कल सूचना दीजियेगा। हम आपकी सूचना पढ़ लिये हैं।

'श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2015–2016 का अन्तिम महीना है। पूरे प्रदेश के जूनियर इन्जीनियर हड़ताल पर हैं। हमारी विधायक निधि से लेकर पी0डब्ल्यू0डी0 या अन्य विभागों में सारे काम ठप्प हैं। यह वित्तीय वर्ष 2015–2016 का अन्तिम महीना है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई न कोई सरकार निर्णय ले जिससे कि विकास कार्य पूरे प्रदेश के रूके हुए हैं उन पर काम किया जा सके। इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दो शब्द कह दें, सरकार का पक्ष आ जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपने सदन में बोल दिया, हो गयी बात आपकी। उन्नाव के मा0 सदस्य पंकज गुप्ता जी अब लकड़बग्घा परेशान किये है तो यह नियम–56 में उठाओगे ?

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज–

मान्यवर, एक बहुत गम्भीर मामला है इसको सुन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

अब आज का काम खत्म, अभी कल सदन रहेगा, कल दीजिएगा।

(श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज अपनी सूचना हाथ में लेकर सदन की वेल में आ गये।)

गम्भीर मामला है तो वेल में कूदने की क्या जरूरत है ? आप जबरदस्ती कराओगे।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज (सदन की वेल से)–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर मामला है। दो लड़कियों की अपहरण करके हत्या कर दी गयी, उनमें से एक दलित समाज की थी, दूसरी अल्पसंख्यक समाज की। कानून–व्यवस्था का मामला है।

(ब0स0पा0 के कई सदस्यों द्वारा श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज को सुने जाने का आग्रह करने पर।)

श्री अध्यक्ष–

क्यों वकालत करते हो, कितना सुना जाए। अभी आगे भी सदन है, आज बजट लेने दो, कल सूचना दे देना।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज (सदन की वेल से)–

मान्यवर, इस पर सरकार का जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष–

आप पहले अपनी सीट पर चलिये, आप एम0 पी0 भी रहे हो और सीनियर मेम्बर हो। चलिये जो कहना है अपनी सीट से कहिये।

(श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज वेल से वापस अपनी सीट पर आ गये)

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज (सदन की वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी, एक अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है, हमारे महोबा जनपद का मामला है, कानून–व्यवस्था से जुड़ा हुआ बड़ा गम्भीर मामला है एक दलित समाज की और एक अल्पसंख्यक समाज की लड़की दोनों छात्राओं का अपहरण करके हत्या कर दी गई। यह घटना 3 तारीख की है। कुमारी सुनीता पुत्री...

श्री अध्यक्ष–

मुकदमा तो दर्ज है।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज–

जी मुकदमा कायम नहीं किया, कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री अध्यक्ष–

कायम किया। अच्छा बैठिये। संसदीय कार्य मंत्री जी इस घटना को दिखवा लीजियेगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, वैसे यह संभव नहीं है कि ऐसी घटना हुई हो। नहीं, घटना हुई है यह तो संभव है लेकिन ऐसी घटना होने के बाद एफ0आई0आर0 लाज न हुई हो, पुलिस ने कोई कार्यवाही न की हो बात समझ में नहीं आती। लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य ने कहा है इसको अभी तुरन्त दिखवायेंगे। जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है,

सख्त ही कार्यवाही होगी। ऐसा अपराध हो और कार्यवाही न हो यह संभव नहीं है। इस सरकार में संभव नहीं है।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आज का टाइम खत्म। अब अभी रखिये, कल भी है, कई दिन है। आगे की मद ले रहा हूं। अब आप लोग बैठें। कल दीजियेगा।

ख11.56, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष मैं अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,31,12,95,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आपको एक ही बजट रखना है या दूसरा भी रखना है।

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

उस पर विवाद नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा दूसरे वाले पर विवाद नहीं है। तो आप इस पर कुछ बता दें तो यह कट मोशन रख दें। आप बोल लीजये दो मिनट।

'श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास का पांचवीं बार बजट रखने का मौका मिला है, मैं आपका भी और नेता सदन का भी आभारी हूं। ग्राम विकास सीधे गांव से जुड़ा गरीब से जुड़ा एक विभाग है जिसकी योजनाएं, जिसके कार्यक्रम सीधे गांव की गरीब जनता को प्रभावित करते हैं। हम लोग अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि देश के सबसे बड़े किसान नेता, गरीब नेता, मजदूरों के नेता हमारे राष्ट्रीय नेता जी से हमने यही सीखा है कि अगर किसी गरीब किसान के चेहरे पर मुस्कान ला सको, उसके आंसू पोंछ सको तो काम करने का मतलब होता है। हम आज के दिन नेता सदन अपने मुख्य मंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी सरकार बनने के बाद जब पहली बैठक हुई हम लोग भी छात्र जीवन से बहुत जगह गांव जाते थे, देखते थे कि गरीब को छत देने की बात तो सब करते थे लेकिन कहीं 40 हजार रुपया तो कहीं 45 हजार

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपया में उसको छत मिलती थी। आज नेता सदन के हम आभारी हैं पूरे प्रदेश की तरफ से कि पहली बैठक में उन्होंने फैसला लिया कि अगर गरीब को छत दो तो गरीब को महसूस हो कि उसकी मदद की गई है।

आज लोहिया आवास जिसकी कीमत 3 लाख 5 हजार रुपये है। उसमें सोलर लाइट भी है, पंखा भी है और पिछले बजट में सदस्यों ने कहा था कि यह योजना गांवों में उत्सव का माहौल कायम करती है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई योजना उत्सव के माहौल में तब्दील हो जाय तो उसके लिये किसी दूसरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम लोग जब गांव में जाते हैं तो इतना बढ़िया मकान देखने को मिलता है। उसकी बढ़िया छत है। गरीब के पसीने की बात तो सबने की लेकिन गरीब का पसीना सूखेगा कैसे इसकी बात सिर्फ हमारे नेता अखिलेश यादव ने की है। (मेंजे थपथपाई गईं) हमें याद है कि नेता जी ने कई मौकों पर कहा कि गरीब की दुआ भी लगती है और गरीब की बद्दुआ भी लगती है। तो काम वह करो जो गरीब की दुआ लगे। मैं आज इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश मैं एक ऐसी गरीबों की योजना लोहिया आवास जो हर गरीब के मन से यह दुआ निकल रही है कि यह सरकार आगे भी काम करे और 2017 में फिर बहुमत की सरकार अखिलेश जी की बने। माननीय अध्यक्ष जी तमाम ऐसी योजनाएं हैं। हम ग्रामीण पेयजल पर भी काम कर रहे हैं हम सामने के सदस्यों से यह अनुरोध भी करेंगे कि पानी की समस्या जो है, उसमें जो हमें बजट मिलता है उसमें करीब पूरी–पूरी कटौती कर दी गई है। लेकिन हम नेता सदन के आभारी है। कल ही नेता सदन ने कहा कि आठ सौ करोड़ की व्यवस्था कर स्टेट सेक्टर से करके राज्य के लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। बुन्देलखण्ड में जहां टैंकर से पानी दे रहे हैं वहां हम नदियों पर भी काम कर रहे हैं हम तालाबों पर भी काम कर रहे हैं मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है कि तालाबों का सुन्दरीकरण का काम कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री सड़क योजना पर भी काम कर रहे हैं एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। मैं एक घटना का जिक्र और भी करना चाहूंगा 403 सदस्य यहां और बैठे हैं जब कोई गांव में मरीज बीमार होता था असाध्य रोगी होता था तो उसकी मदद का सिर्फ एक रास्ता था मुख्य मंत्री फण्ड की व्यवस्था होती थी लेकिन आज मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि हमारे विधायकों के लिए वह व्यवस्था की, जिससे विधायकों का भी सम्मान बढ़ा और हर वित्तीय वर्ष में 25 लाख की अपने क्षेत्र में असाध्य रोगियों की मदद करने का काम मुख्य मंत्री जी की ओर से हो रहा है।

तमाम ऐसी योजनायें हैं जो ग्राम्य विकास से संबंधित हैं मैं इतना ही कहना चाहूंगा अपने माननीय सदस्यों से, हम लोग गांव को सुधारने के लिए, गांव में काम करने के लिए, यह जो योजनायें हैं वह गांव में जो छोटे मोटे काम हैं उसमें मदद करने का काम करेंगी। अक्सर चर्चा चलती है इण्डिया मार्का टू हैण्डपम्प की, हम माननीय सदस्य खन्ना साहब से कहना चाहेंगे कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं यह लिखा–पढ़ी है कोई भाषण नहीं है जो हमें पैसा मिलता था उससे 70 परसेन्ट लगभग कटौती भारत सरकार कर रही है सरकार के मंत्री यहां बैठे हैं और कोई ऐसा विभाग नहीं है कि भारत

सरकार की मदद मिलती हो सबमें कटौती हो रही है। हम आश्वस्त करना चाहते हैं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार मजबूत इरादे के साथ प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं गांव की खुशहाली के लिए, गांव की तरक्की के लिए, और गांव को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम करना होगा हम करेंगे।

(मेंजें थपथपाई गईं)

'श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ग्राम्य विकास के अन्तर्गत आने वाली सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ग्रामीण परिवेश से आते हैं छात्र जीवन से इन्होंने संघर्ष किया है लेकिन आज अपने विभाग का बजट रखते वक्त इन्होंने जो गांव की खुशहाली की बात करी, जो गांव के गरीब की बात करी, किसान की बात करी, पार्टी की बात करी, अपने नेता की बात करी, तो यह सुनकर ऐसा लगा कि गांव का आदमी बिल्कुल छत के नीचे पहुंच गया है, सारे ग्रामीणों को छतें मिल गई हैं, सबको पेयजल की व्यवस्था सुचारु रूप से मिल गई है। मलिन बस्तियां साफ कर दी गई हैं, शौचालयों की व्यवस्था कर दी गई है, मजदूर पलायन नहीं कर रहा है अन्य प्रान्तों में मजदूर नहीं जा रहा है ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था इन्होंने इतनी अच्छी कर दी है कि किसी को पेयजल के बारे में इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प के बारे में मुख्य मंत्री जी से नहीं कहना पड़ा है दलीय नेताओं ने अनुरोध नहीं किया इतना पेयजल इन्होंने उपलब्ध कराया है इतना विकास इन्होंने गांव का कराया है कि परिलक्षित हो रहा है।

पता नहीं मंत्री जी ग्राम ग्रामीण से जुड़े हैं इतनी पीड़ा है उनके अन्दर, लेकिन आज ऐसी बातें कर रहें हैं ठीक है करनी भी चाहिए क्योंकि आपको चुनाव में जाना है चुनावी वर्ष है बजट भी चुनाव को देखकर बनाया गया है। साढ़े तीन लाख करोड़ का भारी–भरकम बजट, अध्यक्ष जी उसमें जो ग्राम्य विकास का बजट आया है, ग्रामों के लिए जो बजट आया है हम गणित के बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे हैं लेकिन जो बताया है उसमें हम परसेन्ट निकालते हैं तो हमें चार परसेन्ट से ऊपर गांव के लिए नजर नहीं आता है और उसमें देने वाली नौकरियों के लिए भी है और अन्य मदों के लिए भी खर्चा है और कितना खर्चा गांव के लिए किया जाएगा अध्यक्ष जी, इस पर एक सवालिया निशान लग गया है। गरीबों की छत दिलाने की बात करते हैं लोहिया आवास दे रहे हैं आप, लेकिन किनको दे रहे हैं इस पर प्रश्नचिन्ह लगा है। इसी सदन में लोहिया गांव के चयन में इसी जगह पर नेता सदन द्वारा घोषणा की गई थी कि विधायकों की अनुशंसा

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर उनका चयन किया जाएगा लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि घोषणा कुछ होती है और क्रियान्वयन उसका कुछ होता है। लोहिया ग्रामों का चयन करें किसी भी ग्राम का चयन करें उस ग्राम में आवास दिलायें लेकिन उस ग्राम के अन्दर लोहिया आवास देने का काम आपने किसको किया, जो गरीब हैं उनको देने का काम आपने नहीं किया बल्कि जो आपकी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं उनको लोहिया आवास देने का काम आपने किया है।

(शोर)

आज बता रहे हैं गांव में उत्सव का माहौल है ग्राम में गरीब बहुत प्रसन्न है।

उसको छत मिल गई उसको शौचालय मिल गया उसको पीने का पानी मिल गया मनरेगा के तहत उसको रोजगार मिल गया और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उसकी सड़क हो गई। आप तो मुझे बम्बई में मिले थे मैं भी इत्तेफाक से बम्बई मैं था वहां पूर्वांचल के लोगों ने आपको बुलाया था बम्बई गए आप पूना गए आप उन लोगों से मिले जाकर जो उत्तर प्रदेश से पलायित होकर काम की तलाश में जाते हैं। वहां से वह पैसा भेजते हैं तब उनका घर बनता है। आप बात करते हैं पेयजल की आज आप देख रहे हैं कि पानी की हालत क्या है हमारे पास पड़ोस के जनपदों में फ्लोराइड और आर्सेनिक युक्त पानी मिल रहा है। गले का कैंसर, घेंघा न जाने कितनी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। रिपोर्ट आई कि 300 फीट बोरिंग का पानी दिया जाए। व्यवस्था की गई लेकिन वह 300 फीट वाली बोरिंग चन्द जगहों पर लगकर रह गईं। फिर यह हुआ कि ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे ओवरहेड टैंक बनाकर पानी की व्यवस्था की जाएगी लेकिन आज अफशोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पेयजल की व्यवस्था कतई ग्रामों में अच्छी नहीं है।

इसीलिए हमारे सदस्य कहते हैं कि हमें पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत अच्छी सड़क बनी है लेकिन उसकी रिपेयरिंग का काम नहीं है। अन्य सड़कें जो बनी हैं उनमें प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क अच्छी और मजबूत बनी है यह टिकाऊ भी है हम लोग जब निकलते हैं लेकिन अगर वह टूट गई हैं तो उनकी रिपेयरिंग का काम नहीं हो पा रहा है। हम और आप जब ट्रेन से चलते हैं तो भारत का असली गांव दिखाई देता है रेलवे लाइन के किनारे भारत का विकास और शौचालय की व्यवस्था सब दिखाई देते हैं। किस तरह से हमारे गरीब घर के लोग चाहे वह बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों वृद्ध हों अधिकांश लोग रेलवे लाइन के किनारे खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। महात्मा गांधी की बात, गांव की सफाई की बात गरीब की बात लोहिया जी का सपना शौचालय देने की बात आज किसी भी क्षेत्र में आप नहीं कर पाए हैं। शौचालय आप उपलब्ध नहीं करा पाए हैं आवास आप उपलब्ध नहीं करा पाए हैं मलिन बस्तियों को आप साफ नहीं कर पाए हैं आप बात करते हैं। मनरेगा की हालत यह है कि जाब कार्ड में पक्षपात, रोजगार नहीं फण्ड आता है लेकिन वह ट्रांसफर हो जाता है। आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम कहां है धरातल पर वह नहीं दिखाई देते अध्यक्ष जी

एक बहुत बड़ी बात जो विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की बात आती है उसमें भी सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक है यहीं पर हमारे माननीय सदस्य लोग बात कर रहे थे वह लोग जब द्वार बनाने के लिए लिखकर देते थे तो नहीं बनाया गया वहां पर बताया गया कि महापुरुषों के नाम पर द्वार नहीं बना सकते। मंत्री जी आपके अन्तर्गत आने वाला विभाग है डी0आर0डी0ए0 विभाग डी0आर0डी0ए0 विभाग पूरी तौर पर घूसखोरी के लिए जाना जाता है रिश्वतखोरी के लिए जाना जाता है। वहां पर वगैर रिश्वत दिए काम नहीं होता।

श्री अध्यक्ष–

कुछ नीतिगत बात भी बताइए।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

अध्यक्ष जी गांव की बात कर रहे हैं तो गांव की बात कर लेने दीजिए। आप ग्राम विकास की बात कर रहे हैं ग्राम का विकास कैसे होगा जब ग्राम विकास अधिकारी ही नहीं है एक–एक ग्राम विकास अधिकारी के पास पांच–पांच छह–छह गांवों का चार्ज है भला होता मंत्री जी कि आप बजट रखते वक्त यह कहते कि हमने समस्त गांवों को जो उत्तर प्रदेश के गांव हैं उन गांवों में ग्राम विकास अधिकारी देने का काम किया। ए0डी0ओ0 की स्थिति यह है चाहे ए0डी0ओ0 पंचायत हो, ए0डी0ओ0 स्टेटिक्स हो, ए0डी0ओ0 एग्रीकल्चर हो उनकी वहां पर तैनाती नहीं है। गांव गरीबों के लिए अगर सड़क बनाने की बात आती है तो इंजीनियरिंग विभाग के लोग भी नहीं हैं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में भी बहुत कमी है बेहतर होता कि भाषण देते वक्त आप यह कहते कि हमने गांव गरीबों और किसानों का ध्यान दिया है। दो परसेंट के बजट पर आज ध्यान दे देंगे। डेढ़–दो परसेंट से आप विकास कर देंगे। सिर्फ खोखली और बेमतलब की बातें हैं जो आप ध्यान आकृष्ट करके गांव और गरीब को भटकाना चाहते हैं अगर गांव की असलियत देखनी है तो भ्रमण करिए। मुख्य मंत्री जी द्वारा यहां से निर्देश दिया गया कि गांव में अधिकारी विश्राम करेंगे विश्राम करने के लिए गांव में जहां जाते हैं उनके जाने से पहले वहां पर टेंट शामियाना उनके वी0आई0पी0 पण्डाल लग जाते हैं वहां पर राजस्व अधिकारी तैनात हो जाते हैं कि गांव, गरीब की सच्चाई बताने के लिये उनके पास जाने नहीं दिया जाता है। इसलिये यह सरकार जो गांव और विकास की बात कर रही है, यह बिल्कुल निराधार है। एक–डेढ़ परसेन्ट के बजट पर गांव और किसान का विकास नहीं हो सकता है। जब तक ग्रामीणों को शौचालय न उपलब्ध हों, मलिन बस्तियों में सफाई व्यवस्था न हो, उनके यहां नाली और खड़ंजा न हो, गांव में आवास अच्छे तरीके से न दिये जायें, प्रकाश की समुचित व्यवस्था न हो, तब तक ग्राम विकास का सपना जो लोहिया जी ने और गांधी जी ने देखा था, वह पूरा नहीं हो सकता है। इसलिये मा0 अध्यक्ष जी, में आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि गांव और ग्रामीण की दशा और दुर्दशा को देखिये। मैं चन्द लाइने कहकर अपनी बात समाप्त

करूंगा। 'खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने के सिवा और कुछ दिखाई न दे, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, तू इतनी भी ज्यादा सफाई न दे'। धन्यवाद।

श्री अब्दुल मशहूद खां–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मा0 मंत्री जी ने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि जो पब्लिक का पैसा है वह पब्लिक तक पहुंचाया जाये, गांव के विकास पर खर्च किया जाये, लेकिन हमारे मा0 सदस्य अभी जो कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे उनको यह नहीं मालूम है कि इस देश को आजाद हुये कितने साल हो गये हैं। इस देश को आजाद हुये लगभग 70 साल होने जा रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस दौरान जितनी सरकारें आईं हैं, इस सरकार को छोड़कर इन चार सालों में मा0 मंत्री जी ने ईमानदारी से जितना प्रयास किया है किसी अन्य ने किया हो तो बता दें। (सत्तापक्ष की ओर से मेंजों की थपथपाहट) लच्छेदार भाषण देने से कुछ नहीं होता है। आप गांवों में जाकर हकीकत देखिये कि समाजवादी सरकार ने जो लोहिया आवास दिये हैं, वह कितने महत्वपूर्ण हैं। आप जाकर देखिये कि गांव, गरीब और आखिरी इंसान तक विकास की किरण पहुंचाने की कोशिश पूरी ईमानदारी के साथ की गयी है। इससे महत्वपूर्ण बजट हो ही नहीं सकता। बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री राम चन्द्र यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे ग्राम विकास विभाग के इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। प्रदेश सरकार की जो ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं हैं, खासतौर से जो ग्रामीण अंचल में पीने के पानी की गंभीर समस्या है, उस समस्या से जहां एक तरफ गांव की असेवित बस्तियों में पीने के पानी का बड़ा गंभीर संकट है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पशुओं के लिये पीने के पानी की बड़ी गंभीर समस्या है। मनरेगा जैसी योजना में बहुत सारे तालाब जो दो वर्ष पहले बनाये गये, उन तालाबों में आज पानी नहीं है। आगे भी तालाब बनाने की एक बड़ी योजना है। जिन तालाबों को बनाकर हम गांवों के किनारे छोड़ देते हैं, यदि कभी कहीं आग लगती है तो आग बुझाने के लिये पानी भी उस तालाब से नहीं मिल पा रहा है। पीने के पानी की गंभीर समस्या के समाधान के लिये कहीं न कहीं इस बजट में सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। बहुत सारे गांवों में बनाये गये तालाब जो आज सूखे पड़े हैं उनमें पानी की व्यवस्था कैसे होगी ? आज बहुत सारे गांवों में असेवित बस्तियों में दो साल पहले जो हैण्डपंप लगाये गये थे आज वह खराब पड़े हैं और पानी नहीं दे रहे हैं। यह कहा गया है कि हर क्षेत्र में हर वर्ष 100 हैण्डपम्प मरम्मत के नाम पर दिये जायेंगे, मैं समझता हूं कि जनपद फैजाबाद में मेरी विधान सभा की जो स्थिति है, वहां करीब 500 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प ऐसे खराब पड़े हैं जिसमें पानी दूर–दूर तक नहीं

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आता है। पिछली बार हम लोगों ने मा0 ग्राम विकास मंत्री जी को खासतौर से मवई विकास खण्ड की बहुत सारी ग्राम पंचायतें चाहे वह नौगवांडीह हो, चाहे हंसराजपुर हो, चाहे देवइत हो, चाहे रामपुरजनक हो, चाहे उमापुर हो, चाहे भटमउनाराणपुर हो, चाहे सणवां हो, चाहे न्यौरा हो, इन सारी गांव पंचायतों में जो गोमती नदी के किनारे गांव पंचायतें हैं, इनमें पीने के पानी की समस्या है और पानी खारा है। आज तक उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही इस बजट में उन गांवों के लिए अलग से बजट देने की व्यवस्था की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, लोहिया आवास की बात कही जाती है, इन्दिरा आवास की बात कही जाती है। इन्दिरा आवास में, लोहिया आवास में जिस तरीके की उनके चयन की कार्यवाही है, उसमें जिस तरीके से हम लोगों को डी0आर0डी0ए0 की बैठकों में बगैर नाम के चयन कर सूची पकड़ा दी जाती है कि इन गांवों में आपको चयन करना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक नाम लेकर बताना चाहता हूं, एक रतनपुर ग्राम पंचायत है, मवई विकास खण्ड की, वहां का हरि ओम नाम का एक विकलांग जो इन्दिरा आवास का पात्र है, फैजाबाद के जिलाधिकारी से ले करके, मुख्य विकास अधिकारी से ले करके, बी0डी0ओ0 तक वह अपनी दरख्वाश्त लेकर दौड़ता रहा, वह गांव इस वर्ष समग्र ग्राम में चयन है लेकिन उसे आज तक आवास नहीं दिया गया, लेकिन उसी ग्राम पंचायत में जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिनके घर पक्के हैं, उनको लोहिया आवास आवंटित कर दिए गए हैं। हमने लिखा–पढ़ी में शिकायत की, लेकिन आज तक कोड़रा ग्राम पंचायत के पात्रों का जो चयन किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जवाब आया है कि हमने उस बी0डी0ओ0 के खिलाफ ग्राम विकास विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया है, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। माननीय अध्यक्ष जी, जब अधिकारी बैठ करके सरकारी योजनाओं में लूट–घसोट करेंगे, उसे बेचने का काम करेंगे और सत्यापित होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है, गांव, गरीब की मदद करने की, गांव के गरीबों की मदद करने की, उस मंशा पर पानी फिरता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज लोहिया आवास योजना में, इन्दिरा आवास योजना में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है और जिस तरीके से सरकार ने जांच कराने के बाद कार्यवाई नहीं की, उससे प्रश्न उठता है कि आखिर कौन लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र का सबसे प्रमुख मार्ग है, भेलसर–उमापुर रूदौली, अध्यक्ष जी, हमारे पास मा0 मंत्री जी का जवाब है, यह प्रथम सोमवार को अतारांकित प्रश्न सं0–21 है, जिस मार्ग के बारे में हमने प्रश्न किया था कि इस मार्ग का निर्माण क्यों बन्द कर दिया गया ? जवाब है, मा0 मंत्री जी का कि निर्माण कार्य बन्द नहीं किया गया है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–2 के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किए जाने के फलस्वरूप दि0 31–07–2015 से प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है, अतएव प्रश्नगत मार्ग को निर्मित न कराये जाने

के कारणों की जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि आज रूदौली के लोग सड़कों पर हैं, 08 तारीख को उस सड़क को जाम करने का वहां के नागरिकों ने, व्यापारियों ने एलान किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरीके का जवाब, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मा0 मंत्री जी का जवाब है कि कार्य नहीं बन्द किया गया है और दूसरी तरफ मौके पर काम बन्द कर दिया गया है। मान्यवर, आखिर उस सड़क के लिए कौन लोग बाधा पैदा कर रहे हैं ? मान्यवर, मंत्री जी का बयान है कि काम चल रहा है, अफसर बयान देता है कि धन नहीं है, सरकार ने रोक लगायी है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए, मैंने संग्राम यादव को बुला लिया है।

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, यह ग्राम्य विकास विभाग का महत्वपूर्ण बजट है। अध्यक्ष जी, यह चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, चीफ सेक्रेटरी के आदेश के बावजूद ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता अगर उस मार्ग पर रोक लगाते हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी के उस बयान के खिलाफ बयान देने वाले, मंत्री जी के उस आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गयी और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी है तो निश्चित रूप से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता को बचाने का काम किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए, चाहे जितना बोलें, अब आपका नहीं लिखा जायेगा।

(मा0 सदस्य, श्री राम चन्द्र यादव बोलने का प्रयास करते रहे, लेकिन माइक ऑफ कर देने के कारण कुछ सुनायी नहीं दिया और डा0 संग्राम यादव ने बोलना प्रारम्भ कर दिया।)

'डा0 संग्राम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए ग्राम्य विकास विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, हम आपका बहुत–बहुत आभार करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बजट प्रस्तुत करते हुए हमारे माननीय मंत्री जी ने शुरुआत में ही कहा कि हम ऐसे नेतृत्व के साथ काम करते हैं। जिनके मन में गांव है, गरीब है, किसान है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, कमजोर हैं, अल्पसंख्यक हैं। आजादी के बाद जिन्हें इस देश में तरक्की करने का अवसर नहीं मिल पाया। हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने और मा0 नेता सदन श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसे लोगों के

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए योजनायें बनायी हैं। मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ कहा कि हम ऐसी जगह पर पहुंचने का काम किये हैं जो वास्तव ऐक्ट विकास से कोसों पीछे रह गये। चौधरी साहब भी कहते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। हमारे नेता आदरणीय नेता जी ने कहा कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और नेता सदन ने भी कहा कि हमारा जो बजट है वह खेती को मजबूत करेगा, किसान को मजबूत करेगा, नौजवान को मजबूत करेगा। हम जानना चाहते हैं कि अभी जो कटौती प्रस्ताव ला रहे थे वह हमारे मा0 मंत्री जी के बारे में कहे कि वह छात्र राजनीति से निकले हैं। हमारे यहां छात्र राजनीति की एक बहुत लम्बी कतार है।

सामाजिक आन्दोलनों से जुड़े हुए लोगों की। यही कारण है कि जब हम नीतियां बनाते हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी कुछ ही वर्ष पहले आपकी सरकार थी। क्या पचास हजार में आवास बन जाते हैं। 70 हजार में आवास बन जाते हैं। हम मा0 मंत्री जी का आभार करते हैं कि जब इस तरह से नीतियां, कार्यक्रम बन रहे थे। हमें खुशी है कि हमने नीतियां और कार्यक्रम बनाते हुए ऐसे गरीब को जब आवास देने की बात आयी तो हमारे नेता मा0 अखिलेश यादव जी ने कहा कि तीन लाख पांच हजार में ऐसे आवास बनाओ ताकि गरीब के मन में विश्वास पैदा हो कि यह सरकार उनके लिए काम कर रही है। आप देखना चाहते हो तो हम केवल जिस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे हैं आइये कभी विधान सभा क्षेत्र के बूढ़नपुर तहसील में, जाइये सिखौना गांव ऐक्ट। जो गरीब रहता है, बुनकर रहता है जो सिलाई करके अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं। ऐसे 42 परिवार जो झोपड़ियों में रहते हैं जिनके लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने धन्यवाद प्रस्ताव में भी कहा था कि एक ऐसे परिवार के दरवाजे पर मैं जब गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आंखें भरकर कहा कि विधायक जी मैंने सोचा नहीं था कि इस जन्म में वतन मिल जायेगा। जो झोपड़ियों में रहते हैं वह पक्की ईंट देखकर उनके मन में वतन के प्रति विश्वास पैदा होता है। आप दलित के बहुत बड़े शुभचिंतक थे। आप दलितों पिछड़ों की बात करते थे। क्या एक भी योजना आप बता सकते हैं जिसमें सीधे तीन लाख पांच हजार किसी गांव के गरीब को देने की कोई योजना थी। मा0 अध्यक्ष जी, जब हम लोग गांव में जाते थे तो हमारे सामने कैंसर से पीड़ित व्यक्ति खड़ा हो जाता था। लीवर सिरोसिस से बीमार खड़ा हो जाता था। शेरू भईया आप जानना चाहते हो तो जाओ हमारी बूढ़नपुर तहसील के बड़ा गांव में, और दलित से पूछो कि अखिलेश यादव जी की नीतियां कैसी हैं तो आपको बतायेगा। ऐसे दर्जनों दलितों का नाम मैं दे सकता हूं जिनको विधायक निधि से सीधे उनके इलाज के लिए दो लाख, तीन लाख जितने भी पैसे के इस्टीमेट की आवश्यकता हुयी उसको देने का काम किया गया है। आज हम मा0 मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। हम विधायक निधि में ऐसे मैं मदद नहीं कर पाते थे आज हमारे नेता सदन और मा0 मंत्री जी ने ऐसी योजना लाये हैं और योजना ही नहीं लाये उस योजना का पूरा क्रियान्वयन जब जहां जैसे चाहें आप उसको दे सकते हैं।

मान्यवर, आज पानी की गंभीर समस्या है। आज जब बजट प्रस्तुत हो रहा है तो उस समय भी कहा गया, मा0 नेता सदन ने ईमानदारी से कहा कि आज पानी के कारण बीमारियां हैं और उन बीमारियों के लिए हमारी सरकार योजना बना रही है। हम पाइप लाइन योजना के अंतर्गत गांव के अंदर पानी की टंकी बनाकर शुद्ध पानी देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार लगातार गांव और किसान की खुशहाली का काम कर रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि कटौती प्रस्ताव रखते वक्त आप उन नीतियों को देख लिये होते और आप अपनों को भी झांक लिये होते कि आप ऐसी कौन सी योजना लाये। हम आपके नेता के मुंह से तो कभी सुनते नहीं कि जो गरीब है उसके इलाज की क्या व्यवस्था होगी। जो कैंसर से पीड़ित है उसके इलाज की क्या व्यवस्था होगी। आपके एजेण्डे में ही नहीं है। आप नहीं चाहते हो। तो मा0 अध्यक्ष जी, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो बजट लाया है उसमें गांव के गरीब के इलाज की भी व्यवस्था है, गांव के गरीब को पक्की सड़क से जोड़ने की व्यवस्था है। गांव के गरीब को पक्की सड़क से भी जोड़ने की व्यवस्था है, लोहिया आवास दे करके उनके मन में लोकतंत्र और देश और प्रदेश के प्रति सम्मान की भी व्यवस्था है, मा0 अध्यक्ष जी यह बजट आजादी के बाद हमारे नेता की जो सोच है, मा0 नेता सदन की जो सोच है, वह मा0 मंत्री जी के बजट में पूरी तरह से दिखाई देता है, इन्हीं भावनाओं के साथ हम मा0 मंत्री जी के लाये हुए बजट का हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका बहुत–बहुत आभार भी प्रकट करते हैं कि आपका बजट सीधे तौर पर गांव के अन्दर सही कह रहे थे, खुशहाली है मान्यवर अगर इनको नहीं दिखाई देता, तो हमसे ले लें और यह क्या कहना भ्रष्टाचार–भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार तो आप अपने किस्सों में कर बैठे हैं, उसको सुधार कराइये, जब आपके नेता का चयन ही इस आधार पर हो रहा है कि काली कमाई का सबसे ज्यादा पैसा कौन देगा, वही आपकी पार्टी का टिकट पायेगा, तो आपको भ्रष्टाचार पर बहस करने का कहीं से कोई अधिकार नहीं है। मान्यवर, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री पंकज कुमार मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी इस बुकलेट की भूमिका में लिखा है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, प्रदेश की अधिकांश आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की सुनियोजित, आर्थिक अवस्थापना संसाधनो का निर्माण तथा रोजगार, इसकी योजनाओं के बारे में लिखा गया है और यह भी स्वीकार किया गया है कि इस देश का इस प्रदेश का विकास गांव से होकर के निकलता है। गांव अगर विकसित है, गांव में रहने वाला वह किसान विकसित है, तो इस हिन्दुस्तान का भला होगा, उत्तर प्रदेश का भला होगा, चौधरी साहब की बात को अभी संग्राम भाई ने बताया। मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग जब सदन में आये तो आप लोगों को देखा, बहुत अच्छे–अच्छे लोग यहां मिलते हैं, पहली बार सीखने का मौका मिला, योजनाएं अच्छी बनी हैं, मैं तारीफ करता हूं, लेकिन योजनाओं को सही ढंग से उन पर काम नहीं किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार यहां बैठे सदस्यों मैं नहीं है, इनकी सोच में नहीं है, लेकिन जो मेरे सामने यहां बैठे हैं, इनकी नीतियों में, इनके काम करने के तरीके में भ्रष्टाचार है, इसको दिखवाया जाना चाहिए, इनका और आपका, जब से हम लोगों ने होश सम्भाला है, हमें तो बजट बनाने का मौका मिला नहीं, आपका और इनका तर्क–वितर्क चलता रहे, तो अच्छा है, हमारी तो आप सुझाव के रूप में बातें लीजिएगा।

मान्यवर, लोहिया ग्राम विकास की बात है, गांव में भवन बनता है, लेकिन वास्तव में मैं जाता हूं अपने क्षेत्र में अभी एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने जिला प्रशासन को कहा था, बहुत खामियां हैं, भवन तिरछा बना हुआ है, सही ढंग से काम नहीं होता, वहां ग्राम प्रधान या जो भी इकाई के द्वारा काम किया जाता है, प्रस्ताव दिये जाते हैं, प्रस्ताव चला जाता है, लेकिन उस पर सही ढंग से काम नहीं होता है, बहुत सारी शिकायतें हैं मंत्री जी यहां कहना ठीक नहीं है, मैं आपको लिख करके दूंगा। दूसरी बात, पहले मेरी आपसे बात हुई थी पीने के पानी की टंकियां, आपने कहा कि बहुत पैसा आयेगा तो टंकियां बनेंगी, एक टंकी का निर्माण नहीं हुआ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी पीने के पानी की टंकियां बनी हैं, कोई भी सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही है, मेरे क्षेत्र में बलुआ है, बुड़ाना है, बबीसा है कहीं जा करके आप देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप ताज्जुब करेंगे, गांव के विकास की बात यहां हो रही है, वहां के प्रधान, पंचायत करते हैं कि इस टंकी को न चलाया जाय, क्यों, क्योंकि टंकी टूटी हुई है और बहुत सारे गांव ऐसे हैं परसों मैं दौरे पर गया, जब यहां आया उससे पहले, तो जहां टंकी की नालियां जो हैं वह फूटी हुई हैं और पाइप में दूषित पानी मिलता है, आप सर्वे करा लो, औपचारिकता नहीं मैं सुझाव के रूप में बात कह रहा हूं, गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हैं लोग, मैं गांव का नाम बता देता हूं, लिलौन है, सिम्भालका है, सिक्का है, शामली जनपद के आस–पास के जो गांव हैं, पूर्ण रूप से पानी की वजह से बीमार हैं। तो ऐक्ट उम्मीद करूंगा कि मा0 मंत्री जी इस पर कोई पुख्ता काम जरूर करेंगे। आप कह रहे थे शौचालय की बात, वास्तव में जब ट्रेन से नहीं, हम तो जब गांव में घुसते हैं मान लीजिए 04 बजे सुबह जाना पड़ गया, जब गांव में लाइट पड़ती है, तो बहुत सारी माताएं, बहनें उठ करके साइड में हो जाया करती हैं, आज भी इसमें पूर्ण रूप से काम नहीं हो पाया है, आज भी आवश्यकता है, पुख्ता काम करने की आवश्यकता है और काम होना चाहिए।

मा0 अध्यक्ष जी, शौचालय का बुरा हाल है, हम हिन्दुस्तान में रहते हैं और विश्वास करते हैं गांव में, गांव के विकास में विश्वास करते हैं बार–बार बात करते हैं, लेकिन हमारी आत्माएं रोती हैं उस समय जब हम अपनी माता–बहनों को जंगल में जाते देखते हैं, वास्तव में आज बहुत बुरी स्थिति है। आपने जो सड़कें बनाई हैं लोहिया विकास योजना में, उनको सड़कों के, भवनों के देख–रेख के लिए भी पैसा होना चाहिए अगर ऐसा कोई पैसा है तो मुझे उसकी जानकारी है नहीं और न ही उस पर काम किया जाता है। मैंने शिकायत की, मेरे यहां जनेश्वर मिश्र मैं लोहिया में सी0ई0सी0 उनकी खराब हो गयी। अच्छा काम होता है, अच्छा पैसा दिया जाता है। उनके खिलाफ

कार्यवाही होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए मैं आपको लिख करके दूंगा। अध्यक्ष जी, गांव से गांव की सड़क से जोड़ने की बात हुई, मेरे क्षेत्र में बलवां गांव से निलोन को जोड़ने वाला जो गांव से गांव को रास्ता जोड़ता है, ग्राम निलोन से बलवां, वह 2 किमी0 का कच्चा रास्ता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो दिक्कत होती है। जब ग्राम विकास का बजट आयेगा और उस पर गांव के लोगों की बात नहीं होगी तो दुख होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बार–बार आप मुझे देख रहे हैं। बात बहुत है, कर नहीं पा रहा हूं। चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार इसी में जो हमने सुझाव दिए हैं, इस साल आप ऐसा कर देंगे कि सबको एक तरफ से बराबर विकास करेंगे, हर गांव का विकास होगा तो हम यहां आपकी तारीफ करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं भाई शेरू द्वारा प्रस्तावित कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

'श्री अभय नारायण सिंह पटेल–

माननीय अध्यक्ष, हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि ग्राम विकास जैसी योजना पर मुझे बोलने का आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। ग्राम विकास ऐसी योजना है और माननीय मंत्री जी ने रखा है, यह गांव पंचायतों से आती है, जिसमें गांव का विकास होता है। हम अब तक जानते हैं और हमने देखा भी है कि गरीब की आंख से आंसू आते हुए भी देखा है। गरीब की बरसात में क्या स्थिति होती है, उसको देखा है। हम जानते हैं कि बाढ़ के समय उनकी क्या विभीषिकाएं होती हैं। उनके आवास न होने के नाते वह अपना सामान कहीं नहीं रख पाते हैं। मैं अपने माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस बजट मैं, 3 लाख 5 हजार रुपये दे करके, उस गांव में जहां बिजली जा ही नहीं सकती थी, वहां बिजली और पंखे की व्यवस्था की है। बटन उसको नहीं दबाना है। ऐसी व्यवस्था उन्होंने लोहिया गांव के विकास के लिए की है। उसमें भरपूर आवास हैं, जबकि अभी भाई साहब कह रहे थे, इस धनराशि में उसका शौचालय भी बन जायेगा। हमारी मां–बहन–बेटियां बाहर नहीं जायेंगी। इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे मुख्य मंत्री जी ने की है। इस परिस्थिति मैं इसके पहले जितनी भी सरकारें आयी हैं, उन सरकारों में दम भी नहीं था। उनके सोचने की शक्ति नहीं थी कि उसके बारे में यह सोचें कि गरीब का जीवन–यापन कैसे होता है। 70 हजार 50 हजार रुपये देते हैं, 5 या 6 हजार रुपये की 1 हजार ईंट आती है। आप भी जानते हैं कि ईंट की कीमत नहीं होती थी, वह आवास कैसे बनाये। आखिर में लांछन लगाते थे कि ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी जिसको दण्ड देता है, स्थितियां यह थीं कि पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं है तो बनेगा कैसे ? अच्छे लोग अच्छी सोंच रखते हैं, गांव से जो आए हैं, गरीब के घर से आए हैं, उनके बारे में यह जानकारी है कि गरीब को आवास कैसे मिलना चाहिए। हमारे गांव हैं, हरिया ब्लॉक में आराजी ग्वाला करखिया, जिसका पॉपुलेशन 12 हजार है, यहां 168 मकान बने हैं और मैं

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक गांव होगा जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या में लोहिया गांव बना है।

मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं कि इसमें आपने ग्राम पंचायतों में गरीबों के लिए इण्डिया मार्का हैण्डपम्प जो दिया है। हर गांव में 100 की संख्या पर हमारे ग्राम विकास मंत्री ने 100 घर को 1 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प दिया है। यह रि–बोर करने की जो सूचनाएं हैं, जब हमें सूचना मिलती है, भाई साहब को चयन प्रक्रिया के बारे में, इंदिरा आवास के बारे में पता ही नहीं था वह कह रहे थे कि आवास तिरछा बन गया है। उस गरीब के पास जो आवास बनना चाहिए किस मीटर में बन रहे हैं। जब जमीन नहीं है, तो मजबूरी में उसको तिरछा बनाना पड़ेगा। यह स्थितियां हैं। जमीन कौन देता है, गरीब को कौन देता है। जमीन तो अमीर लेता है, गरीब पाता ही नहीं है। सरकार पिछले साल भी थी, अभी भाई साहब ने कटौती का प्रश्न रखा है, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। यह गरीब से आए थे, अमीर से नहीं आए थे। गरीबों की ओर से आए थे, गरीब की बात रखने के लिए उत्तर प्रदेश में आए थे, लेकिन उन्होंने अमीर की बात रखी, गरीब की नहीं रखी, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय मंत्री जी के बजट पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द, धन्यवाद।

'श्री राजेश त्रिपाठी–

मा0 अध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर हमारे दल के शेरू भाई द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं कुछ विषयों पर मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि आपने बजट दिया है, आप कार्य करना चाहते हैं, आपने संकल्प दोहराया है। जनपद गोरखपुर की एक सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क है उरूवा बाजार–धुरियापार। मा0 मंत्री जी, इसका 2011 में इसका शिलान्यास हुआ था और 2011 से लेकर आज तक यह सड़क कछुए को भी मात दे रही है, विभाग इस तरह से काम कर रहा है। अगर दौड़ कराई जाए तो कछुआ आगे आ जाएगा और विभाग पीछे हो जाएगा। हालात ये हैं कि कई बार मेंने अधिकारियों से कहा कि अगर वह ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो कम से कम उसे ब्लैकलिस्टेड कर दीजिए। वह सड़क पूरी 8 कि0मी0 उखाड़ दी गई है, उस पर बड़ी–बड़ी गिट्टी पड़ी है और अब तक 4 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, हाउस में कई बार दिया जा चुका है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि आपका यह संकल्प कैसे पूरा होगा, अगर विभाग अपने स्तर से सड़क ऐसे ही बनाएगा तो मा0 मंत्री जी, आप चाहे जितना बड़ा बजट लेकर आ जाएं, आपके अधिकारी आपको फेल कर देंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप जो शौचालय बनवा रहे हैं, आपको धन्यवाद कि आपने शौचालय का बजट इस बार भी दिया है तो आप बेहतर बनाएं और अच्छा बनाएं लेकिन मा0 मंत्री जी, आप यह भी देखें कि जो शौचालय गांव में बने हुए हैं उनमें खर–पतवार, लकड़ी–गोइठा रखा जा रहा है तो

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपका विभाग जागरूकता भी फैलाए ताकि वे लोग शौचालय का उपयोग करें। आप 12 हजार रुपये देकर बनवाए तो दे रहे हैं मगर ग्रामीण उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। विभाग को ऐसी कोई योजना बनानी होगी कि अगर शौचालय बनें तो ग्रामीण उसका उपयोग करें, उसको स्टोर रूम न बनाएं, जो गांवों में हम लोग जाते समय देखते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आपसे लोहिया ग्राम की बात करना चाहूंगा और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप जो लोहिया ग्राम की स्कीम लेकर आए हैं, जो आप बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, अच्छा लगा लेकिन उसके साथ भी वही स्थिति कछुए वाली है, मैं फिर वही आपकी कछुए चाल की बात कर रहा हूं। हमारे वहां एक गांव है मटिहानी, ब्लॉक–गोला, तहसील–गोला, जनपद–गोरखपुर। आपने 2013–14 में यह गांव चयनित किया था। आप बताइए कि जो 2013–14 का चयनित गांव है और अगर उसमें एक काम भी अब तक शुरू नहीं हुआ, न सोलर लाइट लगी, न पिच बना, न कुछ हुआ तो बताइए कि इस साल जो आप चयनित गांव लाएंगे उन्हें आप अक्टूबर–नवम्बर तक कैसे पूरा करेंगे। ये है आपके विभाग की काम करने की गति। मेरा सिर्फ यह कहना है कि बजट कम लाइए, विभाग को तेज दौड़ाइए तो शायद बेहतर होगा। आप 10 गुना ज्यादा बड़ा बजट ला दीजिए और काम नहीं होगा तो कैसे चलेगा।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करिए।

श्री राजेश त्रिपाठी–

अध्यक्ष जी, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आप बहुत अच्छा बजट लाए हैं, धन्यवाद। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं और जो आप कहते हैं कि हम पोखरा खोदवाएंगे, मनरेगा से पोखरा खोदवाएंगे। मान्यवर, हमारे वहां एक पोखरा सूखा हुआ है। हमारे वहां उड़नपुरा ग्राम सभा में एक आदर्श पोखरा के नाम से, मनरेगा से पोखरा खोदा गया था। वह नदी के किनारे से कुछ ही दूरी पर है मगर वह पानी से विहीन है तो सरकार उसका सुन्दरीकरण कराए। उस पोखरा में पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो। यह सरकार हैण्डपम्प देने की बात कर रही है लेकिन वह पिछले बार की तरह केवल वादा न रह जाए और इस बार गांवों को वह हैण्डपम्प मिलें। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं।

'श्री नागेन्द्र सिंह 'मुन्ना यादव'–

मा0 अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। मा0 अध्यक्ष जी, कटौती के प्रस्ताव को रखने वाले भाई शेरू साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बातों को कटौती के माध्यम से रखा। मैं बताना चाहता हूं कि पार्टियां चलती हैं नीतियों से, कार्यक्रमों से और जिस पार्टी के

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास नीति होती है, कार्यक्रम होता है, वही पार्टी सरकार बनाती है तो उन्हीं कार्यक्रमों और नीतियों के आधार पर काम किए जाते हैं। आपको भी जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया था। डॉ0 अम्बेडकर के नाम को लेकर आप लोगों ने जिन दलितों के साथ छलावा करने का काम किया है, उनके विकास की बात करते थे आप, उनके हित में कितना बड़ा काम आपकी सरकार में हुआ है वह जनता से छिपा हुआ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आजाद भारत के अंदर आज आजादी के लिए लड़ाई हो रही है, बहुत से हमारे गरीब किसान, मजदूर हमारे ऐसी बसावटों में रहते थे, जिनको रास्ते से मिलने का आज तक मौका नहीं मिला था, उन बसावटों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने ऐसे गरीब लोगों के बारे में सोचने का काम किया है। महात्मा गांधी, डॉ0 लोहिया, डॉ0 अम्बेडकर के सपनों का भारत, जो सपना था उनका सपना था उनका उस रास्ते पर उत्तर प्रदेश अब बढ़ने का काम कर रहा है। यह साम्प्रदायिक ताकतें, ये भ्रष्टाचार, फांसीवाद की बात करने वाले लोग इनको बुरा लगता है। अनुसूचित जाति की बस्तियों पर इंदिरा आवास के नाम पर पीले ईंटों की मकान बनाये जाते थे और दूर से वह बस्तियां परिलक्षित होती थी और दिखाई पड़ती थी कि इसमें दलित समाज के लोग रहते हैं।

मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने 2–3 लाख रुपये से मकान को दो कमरे का मकान बनाया है और शौचालय और लाइट के लिए धन की व्यवस्था करने का काम किया है, जिनको एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का मौका मिला है। मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि दलितों के नाम पर भवानीपुर गांव हैं, हमारी सदर विधान सभा क्षेत्र मैं जहां तनुषाद जाति के लोग रहते थे, जिनके पास आवास की एक भी व्यवस्था नहीं थी। 141 आवास बनाने का काम हमारी सरकार में हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है और महात्मा गांधी, डॉ0 लोहिया और अम्बेडकर जी के सपनों के रास्ते पर चलकर काम कर रही है इसीलिए जब 1989 मैं माननीय नेताजी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो सबसे पहले शौचालय बनाने का काम हमारे आदरणीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। माननीय अध्यक्ष जी, एक ओर आज प्रदेश में तमाम दलों को सरकारें बनाने का मौका मिला लेकिन उन गरीबों, कमजोरों के हित में जिस सरकार ने काम किया है, उसको जनता जानती है और समय आने पर इसका जवाब देने का काम करेगी। आपने मुझे इस ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश में जिलों में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग ग्राम्य विकास विभाग है। प्रदेश की 70 प्रतिशत

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनसंख्या ग्रामों में बसती है लेकिन आज जो गांवों की स्थिति है वह बहुत ही सोचनीय है। हम बड़ी–बड़ी बातें हाउस में कहते हैं, रखते हैं। अभी हमारे एक माननीय साथी कह रहे थे कि उस गांव में जाकर देखिएगा 160 बन गए, वहां 150 बन गए लेकिन मान्यवर, जहां के गांवों में एक भी नहीं बना क्या वह इस प्रदेश के नागरिक नहीं है, क्या इस प्रदेश के निवासी नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, टी0टी0एस0पी0 पेयजल योजना है। उसकी इतनी गंभीर स्थिति है। माननीय मंत्री जी का प्रश्नों में जवाब भी आया है कि 60 परसेन्ट सब बंद पड़ी हैं, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि 90 परसेन्ट टी0टी0एस0पी0 बन्द है। चाहे जनपद मथुरा हो या और कोई हो, प्रश्न में माननीय मंत्री का जवाब में भी यह आया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात आप कहते हैं कि हम शौचालय बना रहे हैं। आबादी के हिसाब से शौचालय बना रहे हैं, लेकिन जब पानी ही नहीं है तो शौचालय में क्या करेगा आदमी, उसको स्टोर तो अपनेआप बनाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामों की स्थिति ऐसी है और इस समय भी चाहे हम इस सरकार के बारे में कहें, चाहे किसी भी सरकार के समय में कहें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हमारा एक ही उद्देश्य आपके माध्यम से सरकार को यह बताना है, यह कहना है कि अगर वास्तव में विकास चाहते हैं तो सबको बराबर से देखिएगा, बराबर से चलिएगा। हमारे जनपद मथुरा में मान्यवर, गांव की सड़कें हैं बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं फर्रे ओल मार्ग पूरा जर्जर पड़ा है, जबकि वह दूसरे राज्यों से जुड़ा है, भरतपुर राजस्थान का रास्ता जाता है। इसी तरह से राया से सादाबाद मार्ग पूरा जर्जर पड़ा है। इसी तरह से फर्रे ओल मार्ग अकेला मार्ग है जो राजस्थान को जोड़ता है, पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे चाहेंगे कि आप सरकार से कहें। माननीय अध्यक्ष जी, जब हैण्डपम्प की स्थापना होती है। 100 दे दो 200 दे दो, मान्यवर हैण्डपम्प स्थापित होते हैं तो बड़े–बड़े हर जिलों में ठेकेदार बने हुए हैं, 5000 रुपये लेंगे और जहां मर्जी हैण्डपम्प लगवा लीजियेगा हम लोग रिकमेंण्ड करके भेजते हैं पर कोई भी फायदा नहीं होता है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने की अनुमति मांगने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पूरन प्रकाश जी अब आप समाप्त करें।

श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी ग्राम विकास के बजट को आपको पहुंचाना है, आप पहुंचाइये। आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

'श्री गजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट पर कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां सरकार के पक्ष के माननीय सदस्य बड़े–बड़े

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास की, गांव को आगे बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं वहां गांव का विकास पूरे प्रदेश में कहां हो रहा है। शायद इनके बचाने से हम लोगों को ज्ञात नहीं पड़ रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश का हिस्सा जनपद बुलन्दशहर अनूप विधान सभा क्षेत्र भी हैं वही उसके गांव भी हैं जब पहले जो मेरी पुरानी विधान सभा है जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं तो मेरे यहां की जो पुरानी विधान सभा क्षेत्र के जितने गांव थे जो अम्बेडकर योजना थी सारे के सारे गांव उसमें संतृप्त हो गये थे और जो मेरी नई विधान सभा क्षेत्र जो नई परसीमन 2012 का विधान सभा चुनाव लड़ा वहां पर एक अगौता विधान सभा लगती थी वहां परमानेन्ट समाजवादी पार्टी की खाते की सीट रहती थी पांच बार वहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीती और जो हिस्सा वहां का मेरे हिस्से में आया है पांच बार वह सपा के हिस्से में सरकार वाला जो गांव मेरे हिस्से में है, अगौता ब्लाक के लखातपुर ब्लाक के गांव, बुलन्दशहर ब्लाक के गांव उन गांव की दशा यह है कि उन गांव में सी0सी0 रोड, काली रोड आप छोड़ दो गांव के अन्दर खड़न्जा तक भी टूटे हुए हैं, नाली है नहीं विकास के नाम पर जो बड़े–बड़े वादे आज समाजवादी सरकार कर रही है माननीय मंत्री जी बड़े बजट की मांग कर रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि पीछे 3 बार सरकार पहले बनी है और आज भी सरकार बनी है यदि गांव का विकास हुआ तो फिर उन गांव का नम्बर कैसे इस बजट में नहीं आया।

ऐक्ट आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगौता ब्लाक के खेड़ी, बौन्दरा, बीहरा, तौमडी, पिपाला, सैगली, महेशपुर, पसौली, अलावा, नसीरावाद दौलतावाद हो, रामगढ़ हो, लखावटी हो, मूढ़ी बकापुर हो, गंगाहरी हो, भंडौरिया हो, ख्वाजपुर अशरफपुर हो, नगला जीत उर्फ जिताका हो, खनोदा हो, पवसरा हो, बिसुन्दरा हो, लौहरका हो, पाली बेगपुर हो, भावसी हो, औरंगाबाद हो और इसी के साथ चरौरा मुस्तफावाद हो, नगला करन, मैंथना जगतपुर, जहरा, सैमली, जीवत, सराय छबीला, ईस्माइला, सैदपुरा, भीकनपुर, पोथ, जनौरा, नौबतपुर, बालका, सुरजावली, औरंगपुर मोहसन, बकौरा, मीरपुर, अकबरावाद कूडा, जमनाठेर, जौठ, आलमगीरपुर नैनसुख, मिर्जापुर अगरपुर उसके साथ साथ अड़ौली, बंगला पूठरी, मानकपुर, उटरावली, मिल्क मौहसनगढ़, हजरतपुर समसपुर, कलौली, दोहली, पौण्डरी, जुलेपुरा, कुछेजा, मुरसाना, किशनपुर, शिवाली, आलमगीरपुर, धनौरा, फरहादपुर, सीकरी, शाहपुर, रशीदपुर, सदरपुर, सन्नौट, सलैमगढ़, बुढ़ाना, रसूलपुर, तेलिया उर्फ मैंथाना, आजनी, खनपुरा, जुगसा खुर्द, जुगसाना कलां, नवीनगर, डबकौरा, मानकरौरा, रौडात्र बदरखा, शेखपुर रोरा, जटवाई, गहना गोवर्धनपुर, खिरजाबाद, गुंचावली यह वह जगह हैं जहां समाजवादी पांच बार चुनाव जीती इन गांव में विकास नहीं हुआ है और यदि गांव के विकास का कहीं जिक्र है।

मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी गांवों की चिन्ता करते हैं तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इन गांवों का भी विकास करा दे तब तो हम लोग मानेंगे कि सरकार सही गांवों की चिन्ता करती है। इन गांवों में पानी पीने की कोई योजना नहीं है, इन गांवों में शौचालय की कोई योजना नहीं है, इन गांवों में कोई

विकास नहीं है। माननीय मंत्री जी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार विकास की बात करती है तो फिर मेरे यहां विकास दिखाई देना चाहिए। मान्यवर, मेरे यहां भी सड़क बननी चाहिए। किसान की फसल बरबाद हो गयी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसानों को कहीं भी फसल का मुआवजा नहीं मिला किसान अपना मकान बना नहीं पा रहा है उसको मुआवजा दिया जाय। आपको बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया।

'श्री सुभाष पासी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सदन मैं जो बजट आज यह ग्राम्य विकास का पेश हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि मैं बम्बई से बिलांग करता हूं, बम्बई मैं मैंने देखा है झुग्गी झोपड़ियों में जो हमारे उत्तर भारतीय लोग रहते हैं उनके लिए वहां की सरकारें 225 फिट या 269 फिट का मकान बनाकर देती हैं। लेकिन उस योजना के बराबर में माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस शहर को जो पूरे दुनिया में 17वें नम्बर पर विकास के मामले में बम्बई शहर आता है उसके मुकाबले जो लोहिया ग्राम की सुविधा माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है मैं उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह तीन लाख पांच हजार प्रति मकान को माननीय मुख्य मंत्री जी ने लोहिया आवास के लिए दिया है जिसमें वहां के रहने वालों के लिए अच्छे सुसज्जित मकान, अच्छे ट्वायलेट, बाथरूम उस गांव की सड़के सोलर लाइट से लगी हुई इस तरह से लोहिया आवास का विकास हो रहा है यह हमारे लिए बहुत ही उपलब्धि की बात है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग लिखकर दे दीजिए मैं सब लिखवा दूंगा।

श्री सुभाष पासी–

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक महिषा गांव मुसहरों की बस्ती है साढ़े चार सौ घर की वह बस्ती है। साढे चार सौ घर के अन्दर 383 लोगों को मकान मिल रहा है यह बहुत बड़ी बात है। तीन लाख पांच हजार के हिसाब से उन घरो का विकास हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस–जिस गांव में लोहिया की योजना लागू हुई है वहां की सड़के, वहां के रोड, वहां की लाइट सोलर लाइट जो हर मकान पर लगायी जा रही है यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कहना चाहूंगा कि शहरों मैं भी यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है जो यहां पर हो रही है। रही सरकार के विभागों की बात जिस तरह से सरकार ने अपने बजट को पेश किया है जिस तरह से यहां पर एम्बुलेंस सेवा से लेकर के, सड़कों से लेकर के, पुलों से ले करके जो काम हो रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है। मैं

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बताना चाहूंगा 2002 से हमारे विधान सभा में एक गंगा का पुल बन रहा था वह गंगा का पुल हमारी लोहिया बस्ती जहां से लोहिया गांव की योजना लागू की है, वहां आज वह पुल पूरा बनकर तैयार हो चुका है। उन गरीबों के लिए जो मुसहर बस्ती है जो हरिजन है आज सरकार हमारी उनके लिए काम कर रही है यह बहुत बड़ी बात है।

(बहुजन समाज पार्टी के अनेक माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर ख ग ग ग , शब्द हटाये जाने की मांग करते रहे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा)

अध्यक्ष जी, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं आप लोगो ने बहुत कहा है हमें कहने दीजिए। आज ख ग ग ग , बस्ती की बात आप करते हैं मैं भी उसी ख ग ग ग , से बिलांग करता हूं मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं अनुसूचित जाति जनजाति का आप इस तरह की बात मत कीजिए और मैं मेरे समाज की बात कर रहा हूं हमारे समाज के लोगों की जितनी मदद यह सरकार कर रही है उतनी किसी सरकार ने नहीं किया है। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत कुछ दिया है और जितना हितैषी इस समाज की हमारी समाजवादी सरकार है उतना और कोई सरकार नहीं रही है न ही उनके लिए किसी ने इतना काम किया है।

श्री अध्यक्ष–

पासी जी, आप बैठ जायें।

श्री सुभाष पासी–

यह लोग यहां पर बहुत बोलते हैं और हमने कभी नहीं बोला है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं, तो इन्हें सुनना चाहिये। आप अनुसूचित जाति के सबसे बड़े हितैषी बनते हैं। हम भी उसी जाति से विलांग करते हैं, आप अनुसूचित जाति के ठेकेदार तो नहीं हो ? हम भी उसी समाज से हैं, दूसरे समाज से हम नहीं आते हैं। आप केवल अपने आपको उनके हितैषी दिखाना चाहते हो। हमारी बात तो आप सुनिये, हम सरकार की उपलब्धियों के विषय में बात कर रहे हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार अपनी बात कहते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुभाष पासी जी, अब आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हो गया है। माननीय सदस्यगण, आप लोग भी बैठ जाइये और आपमें से कोई एक माननीय सदस्य बोले, जब सब लोग बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आयेगा।

श्री उमाशंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए उचित शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जबकि वह बताते हैं कि वह इसी

नोट :– ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

समाज से हैं। यह एक आपत्तिजनक शब्द है जिसे कार्यवाही में नहीं रखना चाहिये, उन्होंने ¸ग ग ग¸ शब्द का प्रयोग किया है। इसे कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इस शब्द को कार्यवाही में नहीं रखा जायेगा।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा कटौती पर बोलने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप सब लोग बैठ जाइये। शेरू भैय्या आप बोलिये और बब्बन सिंह आप लिख कर दे दीजिये, हम उसे जुड़वा देंगे। आगे बहुत सारे विभागों के बजट निर्धारित हैं, आप लोग उस पर बोल लीजियेगा, अब आप लोग बैठिये।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर श्री अब्दुल मसहूद खां, श्री राम चन्द्र यादव जी, श्री संग्राम यादव जी, श्री पंकज मलिक जी, श्री अजय नारायण सिंह पटेल जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री गजेन्द्र सिंह जी, श्री सुभाष पासी जी द्वारा अपने विचार रखे गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब, कमजोर, बेसहारा जिनके सिर पर छत नहीं है उनको आवास दिलायें, शौचालय की व्यवस्था करायें, जिन लोगों के पास शौचालय नहीं है उनको शौचालय मिलना चाहिये। खराब पड़े हैण्डपम्प, यहां प्रश्नों के प्रहर में कई बार यह सूचना आई है कि लाखों की तादाद में हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, उनको सही करने की जरूरत है। पानी की टंकियां जिसमें सप्लाई नहीं शुरू हो पाई है या जिसमें गुणवत्तापरक पाइप लाइनें नहीं हैं, पेयजल की व्यवस्था कराई जाये। ग्रामीण मार्गों को जोड़ा जाये, प्रधानमंत्री सड़क योजना में, जो सड़कों को क्षति हुई है उनको बनाया जाये। इन सब चीजों को जब तक मंत्री जी सुधार नहीं लेते, हमारी समझ से गांव और गरीब के कल्याण की कोई बात नहीं है। जबकि प्रदेश और देश का दिल गांव में बसता है, गांव की दशा और दुर्दशा आज अत्यन्त खराब स्थिति में है। चंद लोगों को आवास देने से, कुछ लोगों के लिए नल देने से या गांव में दस या पांच परसेण्ट लोगों को सड़क, नाली और खड़न्जा देने से और प्रकाश की व्यवस्था कर देने से पूरे प्रदेश और पूरे गांव के विकास का जो ढिंढोरा पीटा गया है कि गांव का विकास कर दिया, गरीब का विकास कर दिया, किसान का विकास कर दिया, मजदूर का विकास कर दिया, महिलाओं का विकास कर दिया, वृद्ध और बच्चों का विकास कर दिया, यह सब सिर्फ कपोल कल्पित और स्व–बखान करने वाली बातें है। ग्राम्य विकास विभाग में जो पद रिक्त पड़े हैं, चाहे वह गांव से लेकर ब्लाक से लेकर जिले स्तर पर काम करने वाले लोगों के हों, उनको अविलम्ब भरा जाये और गांव को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाये। जब तक गांव के लोगों को छत नहीं मिलेगी प्रत्येक गरीब को घर और आवास नहीं मिलेगा,

---

नोट :– ¸ग ग ग¸ यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रत्येक गरीब व्यक्ति को गांव में शौचालय नहीं मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, तब तक गांव आगे नहीं बढ़ सकता और जब गांव आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम समझते हैं कि हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

माननीय अध्यक्ष जी, शैरू भाई जब कटौती पेश कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अक्सर बोलते हैं, कोई बढ़िया बात कहेंगे लेकिन दुर्भाग्य इनके दल का कि बम्बई में रहकर ग्राम्य विकास के बारे में सोच रहे थे। मैंने सोचा कि कोई बजट की बात कहेंगे, कोई गरीब की बात करेंगे, कोई किसान की बात करेंगे लेकिन इन्होंने कोई शेर पढ़ दिया। इधर कई दिनों से शेर शायरी ज्यादा पढ़ रहे हैं हम लोग तो पढ़ते नहीं हैं, हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, काम में भरोसा रखते हैं। इनको एक चीज जरूर सिखाना चाहते हैं कि 'जो होता है यह होने दो यह पौरुष ही कथन है जो हम चाहेंगे वह होगा' इन शब्दों को जीवन में इनको उतारना चाहिये। इन्होंने बजट की बात कही। 17 प्रतिशत इस बार हमने विभाग का बजट ज्यादा रखा है और जो आवास की बात कर रहे थे अबकी 78 प्रतिशत बजट लोहिया आवास के लिये ज्यादा रखा गया है यह इतिहास है इससे पूरे देश और दुनिया का विकास हो सकता है। इन्होंने छत की बात कही, यह सही है कि हमने छत दिया और आपने गरीब को पत्थर देने का काम किया जो आप वहां बैठे हो। हमने पहले कहा कि गरीब की दुआ और बददुआ दोनों लगती है जो पूरे प्रदेश में पत्थर का काम किये तो यह वही बददुआ है जो वहां चले गये हो और जो छत दे रहे हैं वही दुआ है जो माननीय मुख्य मंत्री प्रदेश ऐक्ट दुबारा भारी बहुमत से मुख्य मंत्री बनने जा रहे हैं।

एक बात और आई, मनरेगा की बात आई तो आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की तुलना में 87.15 प्रतिशत मानव दिवस हमने ज्यादा किया है। जहां तक हैन्डपंप की बात है 41 हजार हैन्डपंप हमने रि–बोर किया। 2015–2016 में हर विकास खण्ड में 50 हजार हैंडपंप रि–बोर कराये गये थे। आर्सेनिक की बात आई उसमें हम लोग काम कर रहे हैं फ्लोराइड की बात आई, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। मनरेगा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 300 करोड़ रुपये दिया, पहली बार ऐसा काम हो रहा है। यह वह योजनायें हैं जिसके बारे में आपने कटौती के समय कहा कई सदस्यों ने अपने भाषण में कहा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री सड़क की बात आई हमने अपने बजट में पहले ही कहा था कि भारत सरकार किस सोच के तहत और किन साजिश के तहत उत्तर प्रदेश को जो मदद दी है, वह काट रहे हैं यह वही बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी नेता सदन ने कहा और हमने भी कहा कि हम कभी धन का रोना नहीं रोते हैं हम अपने प्रयासों से उस काम को कर रहे हैं और तेजी से कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले साथी रामचन्द्र जी ने कहा, यह पुराने साथी हमारे हैं और इसी पार्टी से सीखकर वहां गये हैं, संघर्ष करते हैं। इनकी बातों को हम गंभीरता से दिखवा रहे हैं जो उचित होगा उस पर हम जरूर काम करेंगे। हम

समाजवादियों का यह चरित्र है कि जो कहते हैं वह करते हैं, हम मुंह छिपाकर काम नहीं करते हैं। अभी साथी पंकज जी कह रहे थे और अध्यक्ष जी नई जानकारी आज मिली कि कांग्रेस के सदस्य सुबह 4 बजे काम करने के लिये निकलते हैं। हम लोग सोचते थे कि हम लोग ही ज्यादा मेहनत करते हैं। कभी–कभी बारह, दो और तीन बज जाता है जब शादी ब्याह चलता है लेकिन यह जो 4 बजे निकलने वाली बात है यह नई चीज है अध्यक्ष जी। पंकज भाई चले गये दुर्भाग्य की बात है कि वह साथी गरीब किसान नौजवान की बात करते हैं जिनका पूरा नेतृत्व, पूरी लीडरशिप कभी बाहर तक नहीं निकले, वह किसान की बात करते हैं।

हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह जी किसान की बात करते हैं, नेता सदन भी किसान की बात करते हैं। यह जो तमाम चीजें और तमाम सुझाव आये हमने सबको देखा। पंकज जी ने अधिकारियों की बात कही। अधिकारियों से काम लेना सीखिये और अधिकारियों का सम्मान करना भी सीखिये। यह बात हमने माननीय मुलायम सिंह और माननीय मुख्य मंत्री जी से सीखी है। चार साल हो गये पांचवां बजट पेश कर रहा हूं यह बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने अधिकारी मेरे साथ काम किये हैं वह बेदाग और मजबूत अधिकारी है और उनकी एक साख उत्तर प्रदेश में है। तमाम बहू–बेटी हमारे साथ काम करती है हम अधिकारियों से काम लेना जानते हैं। जहां तक ग्राम्य विकास की बात रही, हमारी कोशिश है कि हर गरीब की मदद की जाय, हर किसान, नौजवान की मदद की जाय। अभी आपने तालाबों की बात की। कितनी बड़ी संख्या में हमने तालाबों का काम किया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ग्रामीण पेयजल पर काम किया और नई योजना शुद्व पेयजल सेवा योजना के अन्तर्गत हमने काम किया। बुन्देलखंड क्षेत्र में हमने कम से कम 200 करोड़ रुपये देने का काम किया। हमने यह नहीं कहा कि बुन्देलखंड में दिक्कत नहीं है अगर बुन्देलखंड में दिक्कत है तो सरकार उसका समाधान करे उसमें काम भी करे। हम यह कह सकते हैं कि हमारी सोच गरीब है। हमारी सोच गरीब, किसान, नौजवान है। हम लोग गरीबों के बीच और किसानों के बीच में काम करते हैं। हर समाजवादी यह सोचता है कि जब तक गरीब, किसान, नौजवान मजबूत नहीं होगा, उत्तर प्रदेश और देश मजबूत नहीं होगा। केवल लच्छेदार भाषण देने से प्रदेश और देश का विकास नहीं हो रहा है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन डेढ़ साल से ज्यादा हो गये दिल्ली की सरकार को, 73 सांसद उत्तर प्रदेश से गये हैं, हमारी मद्द होनी चाहिए लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि चाहिए सब आपको, लेकिन आप अपने नेताओं पर इतना दबाव बनाओ कि जहां से 73 सांसद गये हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी विधान सभा है। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश आज दुनिया का छठां, सातवां मुल्क होता। उस प्रदेश को कितनी मजबूती के साथ और कितनी ईमानदारी के साथ और बड़ी इच्छाशक्ति के साथ हमारे नौजवान और ऊर्जावान मुख्य मंत्री चला रहे हैं इसलिए मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहते हैं।

मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं करूंगा मैं शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया से यही कहना चाहूंगा कि वह हमारे साथी हैं, यह गरीब और किसान का बजट है इसलिए अपना

कटौती का प्रस्ताव वापस करिये और बजट को पास कराइये। हर चीज में कटौती ठीक बात नहीं है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, कुछ मजबूरियां हैं सच को सच कहना सीखो। हमने सीखा अपने नेता से, अगर विपक्षी भी कोई अच्छा काम करता है तो उस काम की तारीफ होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद तमाम सरकारें बनीं लेकिन जब–जब समाजवादी की सरकार बनी, नेताजी मुख्य मंत्री बने तो काम हुआ। 2012 के बाद जो प्रचण्ड बहुमत की सरकार बनी है प्रदेश को सबसे नौजवान व ऊर्जावान नेतृत्व जो अखिलेश यादव जी के रूप में मिला है जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में विकास के काम हुए हैं आजादी के बाद से यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। यही ग्राम्य विकास और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट हम लोग गरीब, किसान, नौजवान के बीच में लेकर जायेंगे और 2017 में बहुमत की सरकार बनायेंगे अखिलेश जी को दुबारा मुख्य मंत्री बनायेंगे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

(श्री पंकज मलिक, श्री सुरेश राणा एवं श्री प्रदीप चौधरी के अपने आसन पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

पंकज जी जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो आप चले गये थे। अब सवाल पूछने आये हो। बैठिये, अब कुछ नहीं, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 1,32,12,95,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख01.03, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–12 (2) में विवाद नहीं होना है उसको भी प्रस्तुत करिये।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह 'गोप')–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिष से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 6,16,55,04,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

लघु सिंचाई, पशुधन तथा पंचायती राज मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिष से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष मैं अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 12,42,26,95,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारी जब से सरकार बनी है यह पांचवां बजट है। यह पशुधन डिपार्टमेंट है, इसके पहले अध्यक्ष जी हमें भी इसी सदन में लगभग 15 साल हो गये। इस सदन में पशुधन डिपार्टमेंट पर केवल सवाल और जवाब होते थे कभी कोई काम पशुधन डिपार्टमेंट में हम जानते हैं किसानों के पक्ष में नहीं होता था लेकिन जब से हमारी सरकार आई है इसमें काम हो रहा है। हमारी सरकार इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप में मना रही है। पशुधन डिपार्टमेंट, जब से मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद सबसे पहले कामधेनु डेयरी योजना उत्तर प्रदेश में लागू हुई। आपने देखा होगा कि अध्यक्ष जी, पशुओं की जो वैरायटी थी अच्छी, जो नस्ल थी अच्छी वह विलुप्त हो रही थी और दूध के बारे में इसी सदन में तमाम तरीके से सवाल उठते थे कि मिलावटी दूध मिल रहा है, दूध कम हो रहा है, तमाम कटान के बारे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय साथी आरोप लगाया करते थे लेकिन जब से यह सरकार आई है उत्तर प्रदेश में कटान में बड़े पैमाने पर रोक लगी है और लगभग कामधेनु योजना के तहत 65 हजार ऐसे नस्ल के पशु जो 12 लीटर से ऊपर 25 लीटर 30 लीटर तक दूध देते हैं उत्तर प्रदेश में बाहर से आये। इस तरह से अच्छी नस्ल के पशुओं की तादात बढ़ी और नस्ल भी बढ़ी। इसके साथ–साथ अध्यक्ष जी, कामधेनु डेयरी के माध्यम से अब तक लगभग 2800 कामधेनु डेयरी स्वीकृत हुईं और जिसमें 1800 क्रियाशील हुई। इसके माध्यम से 65 हजार जानवर बढ़े और 11 हजार लोगों को रोजगार मिला। 1365 करोड़ का निवेश हुआ उत्तर प्रदेश में।

अध्यक्ष जी, कामर्शियल एयर जो पक्षियों का हमारे प्रदेश में एक करोड़ अंडे डेली बाहर के दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आते थे लेकिन उसमें लगातार काम हुआ और 30 हजार पक्षी लेयर कामर्शियल का जो हमने पहले दिया था प्रोजेक्ट उसमें बहुत ज्यादा ऐसे पूंजीपति उत्तर प्रदेश में नहीं थे जो इसको कर सकें लेकिन उसके बावजूद भी 332 उद्यमी इसमें आये और उन लोगों ने इस पर काम किया। आज 27 हजार से ऊपर पर

डे अंडा पैदा करने में सेल्फ डिपेन्ड उत्तर प्रदेश हो रहा है। इसमें लगभग 100 इकाइयां क्रियाशीाल हो गई हैं और लगभग 27 लाख अंडे पैदा हो रहे हैं। 11 हजार लोगों को रोजगार मिला और 225 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। यही नहीं अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी को जब लगा कि छोटे–छोटे उद्यमी उत्तर प्रदेश में भी अंडे की एक योजना कामर्शियल लेयर की करना चाहते हैं तो उन्होंने 10 हजार पक्षी लेयर की एक छोटी योजना उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने पशुधन डिपार्टमेंट को दिया। आज तमाम ऐसे लोग इस योजना को करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि अभी दो महीने पहले यह योजना आई है और जिस पर 81 ऋण अब तक स्वीकृत हो चुके हैं 81 उद्यमियों को आने वाले समय में देखियेगा कि आने वाला समय जो 2018 का जो लक्ष्य हमारा है, 2018 तक एक करोड़ से ऊपर अंडा उत्तर प्रदेश पैदा करेगा और उत्तर प्रदेश आत्म निर्भर होगा और लोगों के स्वास्थ्य के लिये, लोगों के रोजगार के लिये पशुधन डिपार्टमेंट बड़े पैमाने पर काम करेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, टीकाकरण के क्षेत्र में हिन्दुस्तान में पहली सरकार है माननीय अखिलेश यादव जी की, जो पशुधन डिपार्टमेंट में जो टीकाकरण के रूप में 4 करोड़ 56 लाख 6 महीने के अंदर टीकाकरण करा करके पूरे देश में रिकार्ड बनाने का काम किया है। इससे ज्यादा आज तक किसानों के लिये हम जानते हैं किसी सरकार ने काम करने का काम नहीं किया था। माननीय अध्यक्ष जी, अभी 387 विकास खण्डों के लिये इसी बजट में हमारे साथी देखेंगे क्योंकि किताब पढ़ते होंगे इसी बजट में हमने 387 विकास खण्डों का चयन किया है। 387 विकास खण्डों में मोबाइल क्लीनिक वैन देने का काम जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदमियों के लिये, जिस तरीके से पूरे प्रदेश की जनता के लिये देने का काम किया है कि अगर कोई मरीज होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करेंगे उसी तरह से पशुधन डिपार्टमेंट के लिये, जो अनबोलता हमारा पशु है, जो हमारी बात को समझता नहीं है, ऐसे पशुओं के लिये मुख्य मंत्री जी ने जो काम किया है मोबाइल क्लीनिक वैन दे करके कि अगर कहीं कोई पशु किसी गांव में बीमार पड़ता है तो आप एक नम्बर पर फोन करें तो मोबाइल वैन जायेगी और उस पशु का इलाज करेगी। उस पशु का इलाज अगर समझ में नहीं आता तो हर मंडलों में जिस तरीके से पी0जी0आई0 का आपका हॉस्पिटल है उसी तरीके से हर मंडलों में इसी बजट में आप पढ़िये हमने हर मंडलों पर पॉलीक्लीनिक देने का काम किया है और वह समझिये पशुओं का पी0जी0आई0 है। अगर उसके रोग का कोई डाक्टर पता नहीं लगा पाता तो वहां से सीरिंज से उसका खून ले करके आयेगा और जांच करायेगा। जांच कराने के बाद उसका अच्छे से इलाज हो सकेगा। ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जितने उत्तर प्रदेश के जनपद हैं सारे जनपदों पर हमने लैब की स्थापना किया है इसी बजट में आप पढ़िए जैसे हास्पिटल होता है उसी तरह से पशुओं के हास्पिटल की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों में करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी लगभग 246 ऐसे पशु चिकित्सालय है उत्तर प्रदेश के जो जीर्ण–शीर्ण हो गए हैं या जो अभी बने नहीं हैं तो 246 अस्पतालों का जीर्णोद्धार और

नया हास्पिटल बनाने का लक्ष्य हमने इसी वर्ष 2016–17 में प्राविधान कराने का काम किया है। रहमानखेड़ा बाबूगढ़ में सीमैंन सेन्टर जो उच्च कोटि का होगा जहां पर 25–25 लाख सीमैंन गुणवत्ता वाला सीमैंन पैदा किया जाएगा। जो आम किसानों का जो पशुपालक हैं उनका हाई ब्रीड जो अच्छे नस्ल के ब्रीड हैं उस ब्रीड्स को उनके पशुओं को दिया जाएगा और एक लाख पशु का उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हम लोगों ने चयन किया है कि एक लाख पशुओं का हम लोग इस वर्ष बीमाकरण कराने का काम करेंगे तो अगर किसी पशुपालक का पशु मरता है कहीं कोई दैवी आपदा आती है तो कम से कम उसका बीमा रहेगा उस पशुपालक की पूंजी खत्म नहीं होगी वह पशुपालक दुबारा आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होगा और बीमा की राशि से वह दुबारा रोजी–रोटी जमाने का काम करेगा। मान्यवर, इसलिए अध्यक्ष जी आज अगर पशुधन विभाग के लिए किसी मुख्य मंत्री जी ने काम करने का काम किया है तो वह अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए हम सारे सम्मानित सदन से और जो कटौती का प्रस्ताव रखेंगे उनको कटौती का प्रस्ताव रखना नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह की योजना आज तक किसी भी मुख्य मंत्री ने अपने बजट में करने का काम नहीं किया है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत आने वाली सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह पशुधन का दुबारा बजट पेश कर रहे हैं। यहीं पर पूर्व पशुधन मंत्री जब बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने यह कहकर सदन का ध्यान आकृष्ट किया था कि हम बेजुबानों का बजट पेश कर रहे हैं। बेजुबानों का बजट पेश कर रहे हैं वह अपनी बात नहीं कह सकते हैं इसलिए इसको पास करा दिया जाए। हमारे काबिल मंत्री जी ने यह बात नहीं कही लेकिन एक बहुत पुरानी चौपाई है कि गोधन, गजधन बाजधन और रतन धन खान, गोधन को आदि काल में धन के रूप में माना जाता था क्योंकि जब यहां व्यापार के अन्य साधन नहीं थे तो वही गाय से मिलनें वाला पशुओं से मिलने वाला दूध, पशुओं से मिलने वाला घी, पशुओं से मिलने वाला खोया हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता था बल्कि हम व्यापार करके उससे पैसे कमाने का काम करते थे। माननीय मंत्री जी को भी याद होगा, हमारे बचपने में गाय अगर बच्चा देती थी तो अगर बछड़ा होता था तो उससे जुताई करने का काम किया जाता था और अगर बछिया होती थी तो उससे दूध लेने का काम किया जाता था आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस सदन में कि इन बेजुबानों के साथ क्या किया जा रहा है मैं कतई अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल न देता अगर इन पशुओं, लाचार बेबस पशुओं की तस्करी न की जाती।

इन लाचार पशुओं को पानी के टैंकर में भरकर के उनको बेचा न जाता, उनकी तस्करी न की जाती, स्कार्पियो मारुति वैन में भी माननीय मंत्री जी देखते होंगे कि एक छोटी सी मारुति में पीछे की सीट हटा करके उनमें पांच–पांच, छः–छः पशुओं को भरने के बाद और किसी भी पार्टी का झंडा लगाने के बाद उन गाड़ियों को तस्करी के रूप में लिया जा रहा है आज क्या हालत हो गई है। हमारा प्रदेश दूध के मामले में आत्मनिर्भर था जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा थी ढाई करोड़ के लगभग यहां किसान हैं लेकिन इन बेजुबान पशुओं की तस्करी होती है अक्सर यहां पर बात आती है उधर से बात उठती है कि कौन बीफ मास्टर है उधर से बात उठती है कि केन्द्र सरकार अगर इनका निर्यात बन्द कर दे तो इनका कटान बन्द हो जाएगा। आज किस तरह से पशुओं को ट्रकों पर लदाकर चोरी से भेजा जाता है। दरवाजे पर ट्रकों को लगाकर, पिकअप को लगाकर चोरी करके भेजा जाता है। मैं यह बात सदन में पूरी जिम्मेंदारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि अगर पुलिस और प्रशासन के लोग नहीं मिले हों तो यह तस्करी नहीं की जा सकती है। बजट ठीक है, मुख्य मंत्री जी की सोच बहुत अच्छी है दूध ऐक्ट हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, खोए में हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, घी में हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए मिलावट इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि अगर हम बाजार से दूध, घी और खोया खरीदते हैं तो पानी मिला दें वहां तक गनीमत है लेकिन सिंथेटिक मिलाकर, कैमिकल मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है और हमारी महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

आज पशु चिकित्सालयों की कितनी कमी है चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं बिल्डिगें नहीं हैं मंत्री जी आज हम कटौती प्रस्ताव पर बल नहीं देते अगर आप कहते कि प्रत्येक पशु चिकित्सालय में हमने पशु चिकित्सक की तैनाती कर दी है पशु चिकित्सालयों की बिल्डिगों को हमने बना दिया है। पशु चिकित्सक बनाने के लिए हमने यूनीवर्सिटी खोल दी है जहां से हजारों हजार की तादात में पशु चिकित्सक जाएंगे। आज आप अंडे की बात कर रहे हैं अंडे में हमसे छोटे प्रांत चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो वहां से हमें निर्यात करना पड़ रहा है। ढाई करोड़ पशु एक लाख पशुओं का बीमा करके आप बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं। अपनी पीठ ठोंक रहे हैं आप सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं ढाई करोड़ कृषक हैं अगर एक कृषक के पास एक दुधारू पशु है तो ढाई करोड़ पशु से कम हमारे उत्तर प्रदेश में दुधारू पशु नहीं हैं। इनमें मात्र एक लाख पशुओं का बीमा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से हम आते हैं अध्यक्ष जी आप भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आते हैं बाढ़ आकर जब चली जाती है तो कई बीमारियां गंभीर रूप लेती हैं जिसमें हम लोगों को चपेट में आना पड़ता है। लेकिन इसके साथ–साथ पशुओं को भी गम्भीर बीमारी धर लेती हैं। गरीब का पशु मरता है। आज एक जोड़ी भैंसे की कीमत एक लाख रुपए से कम नहीं है आज उसका बीमा नहीं है वह पशु जब मर जाता है हम कृषि ऋण लेते हैं कृषकों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं। लेकिन पशुओं का बीमा नहीं कराया जाता है अगर आप सभी दुधारू पशु और भैंसे और बैल जिनसे हम जुताई का काम

करते हैं ग्रामीण गरीब लोग करते हैं अगर आप अनिवार्य रूप से पशु बीमा कर दें तो मैं कतई अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल नहीं दूंगा चारा और चारागाह का विकास चारागाहों की जमीन को नाम चेंज करके उनको पट्टे पर दिए जाने का काम किया जा रहा है आज कुक्कुट विकास योजना है, भेड़ तथा ऊन विकास योजना है सूकर विकास और बकरी विकास की आप बात कर रहे हैं लेकिन इनमें कहीं पर भी धरातल पर कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं स्लाटर हाउस बने हैं ठीक है उनको अनुमति केन्द्र सरकार ने दी है लेकिन अगर उनको 25 पशुओं के कटान का परमिट प्राप्त है तो ढाई सौ पशुओं को काटा जा रहा है और स्थानीय डाक्टर जब तक यह सर्टीफिकेट न दें कि पशु स्वस्थ है तब तक उनको काटने की अनुमति नहीं मिलती है लेकिन फर्जी तरीके से या डाक्टर लालच में उनको अनुमति दे देते हैं या स्लाटर हाउस के लोग इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि वह डाक्टर की अनुमति के वगैर ही पशुओं का कटान करते हैं। ढाई सौ पशु चिकित्सालय हैं जो सेवा कर रहे हैं पशुपालकों की किसानों की लेकिन इन अस्पतालों में कितने डाक्टर हैं यह माननीय मंत्री जी जब बताएं तो हमें जानकारी दे दें कई जगहों पर डाक्टर छोड़ दीजिए कम्पाउंडर तक नहीं हैं। ताला लगा हुआ है गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है बात कर रहे हैं कि राजस्थान और हरियाणा से अच्छे नस्ल के पशु ला रहे हैं अगर आप वाकई में पशु ला रहे हैं तो यह बात स्वागत योग्य है लेकिन यहां गजरिया में बहुत बड़ा पशु फार्म था जिसमें दसों हजार की तादात में पशु रहते थे दुधारू और अच्छी नस्ल के पशु रहते थे आपने उस जमीन को किसी अन्य उपयोग में लिया लेकिन अच्छा होता कि उससे बड़ा पशु का फार्म खोला जाता। हमारे यहां लखीमपुर में भी पशु का फार्म है जहां दुधारू पशु मिलते हैं। लेकिन वहां पर उनकी देख–रेख के लिये जितने बजट की आवश्यकता है उतना पैसा आपके पास नहीं है, जितना पैसा उनको देना चाहिये उतना पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, इसलिये मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके पशुधन विभाग का 12,42,26,95,000 रुपये का इतना बड़ा बजट है। प्रत्येक व्यक्ति को दूध की आवश्यकता होती है, सुबह उठकर करीब–करीब हर व्यक्ति चाय पीता है, बच्चों को पौष्टिकता के लिये दूध की आवश्यकता होती है, हमारे खिलाड़ियों को भी दूध की आवश्यकता है।

हमारी महिलाएं जो एनीमिक हैं उनको भी दूध की आवश्यकता है। आप कामधेनु डेयरी योजना लाए हैं जो स्वागतयोग्य है। आपने 2800 कामधेनु डेरियां शुरू की हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि उनमें जो ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत होता है, उसमें बैंक कितना परेशान करते हैं ? आपने इस संबंध ऐक्ट प्रभावी कार्यवाही करने की कोई कोशिश की है ? बेहतर होता कि आप उस संबंध में बात करते। मा0 मुख्य मंत्री जी यहां पर जब भी बजट रखते हैं तो अमूल की बात आती है कि अमूल का प्लांट लाए हैं, अमूल का प्लांट चल रहा है, दूध हम इकट्ठा करेंगे, उसका चिलिंग प्लांट लगायेंगे, प्रदेश में दूध की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन मैं अपनी

पूरी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं चाहे वह हरियाणा हो, चाहे उत्तरांचल हो, चाहे राजस्थान हो, उनसे दूध की आपूर्ति होती है। आप सुनिश्चित करें कि जानवरों का कटान न हो, दुधारू नस्ल के जानवर यहां पर आयें, दूध की उपलब्धता हो। पहले कहा जाता था कि 'दूधो नहाओ पूतो फलो', उस दूध से नहाओ जो अब सिंथेटिक है, यूरिया से बना हुआ है। आज चर्चा यह होती कि आप देशी घी खाइये, गाय के दूध का घी खाइये, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, आप तो डायबिटिक होने के नाते जानते ही होंगे कि उसमें गाय का घी खाने के लिये कहते हैं, लेकिन गाय का घी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस तादात में गायें उपलब्ध ही नहीं हैं, भैंस उपलब्ध ही नहीं हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा हूं। इसके बहुत ही गम्भीर परिणाम होंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, आगे अभी बहुत बजट बाकी है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मा0 अध्यक्ष जी, पशु और पशुधन समाप्त होने की कगार पर पहुंच गये हैं। इसलिये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों पर ध्यान देना चाहिये। छोटी डेयरियां खोलनी चाहिये, चार–चार, आठ–आठ, दस–दस पशुओं की डेरियां हों, उनके लिये भी योजना बनाएं। नियमित रूप से पशुओं का बीमाकरण कराया जाये। पशु चारागाह के वास्ते जो जमीन होती थी उन जमीनों को एक अभियान चलाकर खाली कराया जाए। यहां पर गोला विधान सभा क्षेत्र से हमारे विधायक जी बैठे हैं, इनके क्षेत्र बने अस्पताल में चार साल से डाक्टर नहीं है। हम समझते हैं कि जब तक दूध की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, पशुओं के कटान को नहीं रोका जायेगा तब तक हम इन बेजुबानों के साथ न्याय नहीं कर सकते, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी आप इसका उत्तर दे दें तो हम इसे पास करा दें। अभी आगे और बजट बाकी है।

(मा0 सदस्य, डा0 मो0 अयूब के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

मा0 डाक्टर साहब, आप दो मिनट में अपनी बात कह लीजिये।

'डा0 मो0 अयूब–

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे समझ ऐक्ट नहीं आता है कि स्लॉटर हाउस का नाम सुनते ही लोगों का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है ? मैं बिल्कुल प्रोफेशनल बात कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि दुधारू पशुओं के दूध के माध्यम से ग्रामीणों को, कृषकों को, पशुपालकों को फायदा होता है, धनार्जन होता है, मगर जब वह दूध नहीं देते हैं। आप भाई ने अवैध पशु कटान के बारे में कहा, जब तक

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिस्टमेंटाईज्ड नहीं होगा तो अवैध होगा और जब सिस्टमेंटाइज्ड हो जायेगा, जब उसका एक मानक बन जायेगा तो वह अवैध नहीं होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि 50 परसेन्ट अगर बैल होंगे, भैंसे होंगे तो ग्रामीण उसका क्या करे, पशुपालक क्या करे ? क्या उसको ऐसे ही छोड़ दे ? उसको टहलने के लिये छोड़ दे ? उसका समुचित उपयोग होना चाहिये और उसका लाभ कृषक को, पशुपालक को मिलना चाहिये और उसके लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है। अध्यक्ष जी, अगर मैं कोई अनीतिगत बात कर रहा हूं तो बता दें। मैं नीतिगत बात कह रहा हूं। जब पूरी दुनिया में इसकी व्यवस्था है और सभी लोग, मैं बार–बार कहता हूं कि जब पूरी दुनिया में इसकी व्यवस्था है, हमारे बहुत सारे राज्यों में इसकी व्यवस्था है तो या तो सरकार जो हमारे पशु चाहे वह प्रतिबन्धित हों, चाहे गोवंश हों या गो–वंश न हों तो जो पशु दूध नहीं देते हैं, फिर उनका कृषक या पशुपालक क्या करे ? सरकार के पास उसकी कोई व्यवस्था है ? तो मैं समझता हूं कि दूध की अनुपलब्धता और धीरे–धीरे पशुओं का कम होना, इसका मुख्य कारण है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए।

डा0 मो0 अयूब–

अध्यक्ष जी, मैं तो वैसे भी बहुत कम बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए।

श्री रविन्द्र जायसवाल–

अध्यक्ष जी, अयूब खां का कहना है कि ऐसे पशुओं को कटवा देना चाहिए, उन्हें गोली मार देना चाहिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 मो0 अयूब–

अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात रखने के लिए सक्षम हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए, अब हो गया। मंत्री जी को बोलने दीजिए। बैठ जाइये और मंत्री जी का जवाब सुनिए।

लघु सिंचाई, पशुधन तथा पंचायती राज्य मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)–

अध्यक्ष जी, पहले तो शेरू भाई को मैं जवाब दे दूं, हमको लगता है कि या तो यह बजट पढ़े नहीं, इस किताब को देखे नहीं, यह केवल हवा–हवाई बात कर रहे थे, इनको पता ही नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूं, किस विषय में बोल रहा हूं, किस विभाग पर बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, इनको बजट की जानकारी नहीं थी लेकिन कटौती का प्रस्ताव

इन्होंने रखने का काम किया, फिर भी इनको मैं धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, आज इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मिलावटी दूध मिलता है, शहर में महिलाओं को, नौजवानों को किसी को दूध नहीं मिल रहा है। शेरू भाई, आपकी सरकार थी, पांच साल और तब भी यह गाय–भैंसे भी थी और तब भी उत्तर प्रदेश में आदमी थे, मानव थे, तमाम लोगों को दूध की आवश्यकता थी, लेकिन एक बूंद भी दूध बढ़ाने की व्यवस्था के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी गाय बढ़ाने का काम नहीं किया। तब भी उत्तर प्रदेश में कटान होता था, जो स्लाटर हाउस हैं, वहां कटान होती है और गो–वंश के जितने पशु हैं, उनके कटान का कहीं काम नहीं होता और अभी जो आपने कहा कि बैलों को कटवा दें, इनको कटवा दें, आप बता दे, हिन्दुस्तान में केवल बजट के माध्यम से सरकारें नहीं चलती हैं, परम्पराओं के आधार पर भी सरकारें चलती हैं। तमाम ऐसी मान्यताएं हमारी हैं, उन मान्यताओं को भी ध्यान में रखकर सरकार को चलाया जाता है। कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता, जिससे देश के अन्दर गदर हो जाए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, गो–वंश पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध है, चाहे वह गाय हो, चाहे बैल हो, उसका कटान हम नहीं करा सकते। गोवंश के पशु जो भी हैं, इस देश का निर्माण आज नहीं हुआ है, हम लोग जानते नहीं, कब इस देश का निर्माण हुआ। इसलिए जो परम्पराएं हैं, उन परम्पराओं के खिलाफ इस तरीके की कोई योजना हमारी नहीं है। भारत की सरकार है, केन्द्र में, अध्यक्ष जी, जो भी कानून वह चाहें, बना दें, क्योंकि यदि हम कानून बनायेंगे, तब भी वह कानून लागू नहीं हो सकता। स्लाटर हाउस से जो निर्यात होता है उसका लाइसेंस केन्द्रीय गवर्नमेण्ट देती है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नहीं देती है। इसलिए जो सवाल आपने सदन में किया है, वह सवाल आपका आपत्तिजनक है।

(डा0 मो0 अयूब के खड़े होकर पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए, मंत्री जी की बात सुनिए। मंत्री जी, आप जवाब दीजिए, हम बजट पास करायें।

(डा0 मो0 अयूब तथा कुछ अन्य सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश राणा–

अध्यक्ष जी, कुछ लोग गदर ही कराना चाहते हैं, एक गदर वाले उस कुर्सी पर बैठते हैं, एक गदर वाले ये हैं, दो ही तो हैं, हाउस में।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(मा0 श्री जाहिद बेग जी अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे, लेकिन उनका माइक आफ था।)

श्री अध्यक्ष–

अरे, यह क्या है। अरे बैठो न।

(इस बीच मा0 सदस्य श्री सुरेश राणा, श्री जाहिल बेग, श्री वसीम अहमद जी एक साथ बोलते रहे जिससे सदन में शोर उत्पन्न हो गया। शोर–शराबे के मध्य।)

श्री वसीम अहमद–

जो आपने कराया है। मुजफ्फरनगर में जो करवाया है, जो स्टिंग आपरेशन करवाया, आज दूध का दूध पानी का पानी साफ हो गया है। आज आप पकड़े गये हैं। आपने जो दिल्ली में करवाया था वही आपने मुजफ्फरनगर में भी करवाया था। आपने दिल्ली में वही काम करवाया और आज नंगे हो गये आप, दिल्ली की सरकार नंगी हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, बैठिये, आपने विरोध दर्ज कराया। राणा जी आप बैठें।

श्री राज किशोर सिंह–

आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी शेरू भाई तस्करी के बारे में कह रहे थे। आप यह जानते हैं कि जितने भी स्लाटर हाउस हैं। तस्करी अगर कहीं होती भी है, कहीं ऐसी सूचना मिलती है तो पुलिस उसमें कार्रवाई करती है, पकड़ती है, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 होती है। तमाम तरीके से उनको दण्ड मिलता है लेकिन जब से उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार आयी है तब से इसमें भारी कमी हुयी है और आपने अभी पशुओं के बीमा पर कहा। तो आज तक किसी सरकार ने एक पशु का बीमा कराने का काम नहीं किया था। आज पहली बार पशुओं के बीमा का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार चलाने जा रही है जिसमें एक लाख पशुओं का बीमा कराने जा रही है। यह अपने आपमें देश का रिकार्ड है। इसमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि डाक्टरों की तैनाती नहीं है। आज शत–प्रतिशत अस्पतालों में डाक्टरों की तैनाती है। जहां पर कोई डाक्टर नहीं है किसी न किसी के चार्ज में है। चयन आयोग को गया है और बहुत जल्द ही दो–ढाई सौ डाक्टर हमारे आ रहे हैं। जैसे ही डाक्टर हमें मिलेंगे वैसे ही तैनाती भी वहां हो जाएगी और मा0 अध्यक्ष जी, अभी कामधेनु का जिक्र किया गया। आप यह जानते हैं कि पहले की सरकार में लगातार दूध के संबंध में बवाल चलता था। सिंथेटिक दूध आदि के बारे में बवाल चलता था। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने कामधेनु डेरी योजना दिया है। आपने एन0सी0आर0 के इलाके में कहा, दिल्ली के अगल–बगल दूध नहीं मिल रहा। तमाम साथी यहां बैठे हैं। आप पूछिये सबसे ज्यादा डेरी कहां खुल रही हैं। आज सबसे ज्यादा अगर डेरी खुली है तो दिल्ली के एन0सी0आर0 के इलाके में खुली हैं। अध्यक्ष जी, आज इतना दूध उत्तर प्रदेश में पैदा होने लगा कि किसानों को दूध का उचित रेट नहीं मिल पा रहा है। सरकार इस पर चिंतित है। सरकार इसकी चिंता कर रही है कि कैसे हम पशुपालकों का दूध लें और उनको अच्छा रेट मिल सके और यह कह रहे हैं कि आज दूध ही नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आपके जनपद में नयी डेरी लगी है। आप अपने जनपद में पता करिये और इन्होंने कहा कि किसानों के लिए दो–चार

डेरी लाना चाहिए। अध्यक्ष जी, बड़ी डेरियां इसलिए लायी गयी हैं कि इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर अच्छी नस्ल के पशु आ रहे हैं और यह अच्छी नस्ल के पशु उत्तर प्रदेश में डेरियों के माध्यम से आयेंगे तो एक चेन सिस्टम बनेगा। दूध की बढ़ोत्तरी तो होगी ही और आने वाली हमारी पशुओं की नस्ल सुधरेगी और उत्तर प्रदेश के पशुपालक और किसान बड़े पैमाने पर दूध पैदा करेंगे और रोजगार पाने का काम करेंगे। इसलिए व्यवस्था कर रहे हैं। हो सकता है कि यह तो दूध पीते नहीं हैं। यह तो मांस, मछली खाने वाले लोग हैं।

इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अण्डे की भी व्यवस्था की है। अण्डे और मुर्गे की व्यवस्था इसलिए किया है कि अगर इनको दूध नहीं चाहिए तो अण्डा और मुर्गा खायें। इसलिए शेरू भाई आपने कोई सलाह दिया नहीं। केवल आप कहते रहे कि यह नहीं हुआ वह नहीं हुआ। मा0 अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो हमारा पशु है जो अपने दर्द को बता नहीं सकता। किसान हो सकता है कि उसकी पीड़ा दर्द को समझ जाये। अगर उसकी भावना को समझने का काम किया है तो आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने समझने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर आदमियों को पी0जी0आई0 की जरूरत है तो हो सकता है कि पशुओं को भी पी0जी0आई0 की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि अगर आपका पशु बीमार है। डाक्टर के पास कोई ऐसा यंत्र तो है नहीं जिससे यह पता लगे कि इस पशु के अंदर क्या बीमारी है। वह केवल मुंहपका और खुरपका दो चीज जानते थे और जानने के बाद दवा की गोली और इंजेक्शन ठोंक देते थे। पशु मरे या जिंदा रहे। मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब बजट पर चर्चा होने लगी तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आदमियों के लिए पी0जी0आई0 है उसी तरीके से पशुओं के लिए पी0जी0आई0 होना चाहिए। जिस तरीके से लैब में हमारे खून की जांच होती है, उसी तरह से पशुओं के खून की जांच होनी चाहिए और सही इलाज पशुओं को मिलना चाहिए, हर जनपद में लैब होना चाहिए, मा0 अध्यक्ष जी हर जनपद में लैब और पी0जी0आई0 और उन्होंने कहा इसके साथ–साथ ए0आई0 हमारे पशुपालक की अगर 30–30, 40–40 गाय तमाम ऐसे गांव में पशुपालक हैं छोटे–छोटे जो 30–30 गाय 40–40 गाय तमाम इलाकों में रखते हैं और ए0आई0 के लिए वह हास्पिटल तक अपने पशु को नहीं ले जा पाते, मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा इस पर सबसे बड़ा ध्यान होना चाहिए और उन्होंने मोबाइल क्लिनिक वैन दिया कि अगर पशुपालक वहां से टेलीफोन करता है, उसकी गाय गरम है तो वहां पर तुरन्त ए0आई0 करने के लिए वैन पहुंचे और वहां पर ए0आई0 करें और अगर वह बीमार है, तो वहीं से इन्जेक्शन से खून ले और ला करके लैब में चेक करा कर उचित दवा उस पशुपालक के पास पहुंचाये, तब उत्तर प्रदेश की तरक्की होगी, तब देश की तरक्की होगी, तब उत्तर प्रदेश का किसान जो किसान दिवस इस साल मनाया जा रहा है, तब उत्तर प्रदेश का किसान, किसान दिवस मनाने का काम करेगा, तब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने का काम करेगा और आपने जो कहा दूधो नहाओ, पूतो फलो, यही कामधेनु योजना उत्तर प्रदेश में करेगी, इसलिए एक बार फिर मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आपसे कहता हूं, इस पर कोई कटौती न रखें,

यह उत्तर प्रदेश का बहुत जनहित का बजट है, बहुत अच्छा बजट है, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

हां कुशवाहा जी आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री सन्तराम कुशवाहा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पशुधन पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

बोलने का समय अब खत्म हो गया है, आपको अगर कोई स्पष्टीकरण पूछना हो तो पूछ लीजिए।

'श्री सन्तराम कुशवाहा–

मा0 अध्यक्ष जी, हम मा0 मंत्री जी की बात से पूर्ण सहमत हैं, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पूरे प्रदेश ऐक्ट अच्छी नस्ल के लाखों कामधेनु डेयरी योजना के प्राजेक्ट लगाये, एक प्रोजेक्ट में 100 अच्छी नस्ल की गायें खरीदी जाती हैं। मा0 अध्यक्ष जी, 100 अच्छी नस्ल की गायें दूध देंगी और उनसे बछिया पैदी होंगी, बछड़े पैदा होंगे, अच्छी नस्ल की अगर बछिया पैदा होगी तब तो डेयरी मालिक अपने पास रखेगा, लेकिन 100 गायों में अगर 50 बछड़े पैदा हो गये, सदन बहुत विद्वान है, हमारी भी पीड़ा है, हर किसान की पीड़ा है, किसी किसान के पास अगर 10 गायें हैं और उसके 10 बछड़े पैदा हो जाते हैं जो अच्छी नस्ल की गाय कहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छी नस्ल की गायों के जो बछड़े हैं किसी किसान के, किसी दुकानदार के, किसी व्यापार के काम में नहीं आते हैं और एक गाय जो दूध देने वाली है, उसका भोजन 200 रुपये रोज का खर्चा है, जो गैर दूध देने वाली नश्ल है उसका कम से कम 100 रुपये रोज का खर्चा आता है, अगर एक किसान के पास 05 बछड़े घर पर रहेंगे तो उसका 500 रुपये रोज खर्च होगा, तो ऐसी स्थिति में न तो गरीब किसान, न तो रहीस किसान और न ये डेयरी मालिक 50 बछड़े अपनी डेयरी में नहीं रख पायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सन्तराम कुशवाहा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं मा0 मंत्री जी ने कहा है कि बिल्कुल हम कटान नहीं करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने जो बजट दिया है, उसमें बछड़े की व्यवस्था के लिए कोई इन्तजाम नहीं किया है और न ही उनके लिए कोई बजट दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि गरीब किसान जो

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पशुपालन करेगा और उसके पास जो फालतू बछड़े रहेंगे तो वह उनके भोजन की व्यवस्था कैसे करेगा, इसलिए उसे बजट मिलना चाहिए।

श्री राज किशोर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, इसके पहले आप देखिये हम लोग जब छोटे थे तो गांवों में बैल चलते थे कि नहीं चलते थे, हर समय का सिस्टम, हर समय की अपनी अलग–अलग परम्परा, अलग–अलग कार्यशैली होती है। आज की डेट में आपने जो कहा बछड़े पैदा होंगे, आप यह बताइये क्या बछिया नहीं पैदा होंगी। ए0आई0 जो आज हमारी मोबाइल वैन, मैं वैन की व्यवस्था कर रहा हूं, मोबाइल वैन जाकर वहां ए0आई0 करायेगी। आज वही बछड़े जो 40–40 किसानों के पास गए हैं, जो वैरायटी चेंज हो रही है, वही बछड़े किसानों के पास रहेंगे। इससे भी आदमी रोजगार प्राप्त करेगा। अगर दो बछड़ा जिला लिया, कम से कम चार गायों की ए0आई0 करायेगा तो उसके पेट का जीविकोपार्जन होगा।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिए।

(श्री सन्तराम कुशवाहा तथा डा0 मो0 अयूब सहित कुछ माननीय सदस्यों के अपने–अपने स्थान से लगातार बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह क्या पूछ रहे है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं सुन लीजिए। अब आप बैठिए। जवाब दे रहे हैं सुन लीजिए। बैठिए। डा0 साहब वह जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। यह किसी की नहीं सुनने वाले हैं, यह अपनी ही सुनायेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं आपने सांड़ों के बारे मैं कहा, बछड़ों के बारे मैं कहा। आज आरगेनिक खेती के लिए आज गोबर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दूसरी चीज अगर यह बछड़े होंगे और उस इंटीरियल के गांव में जहां हमारी वैन नहीं पहुंच सकती, जहां हमारे डाक्टर नहीं पहुंच सकते, वहां पर यह बछड़े सांड़ के रूप में काम करेंगे।

(कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे यह क्या बहस कह रहे हैं। आप बैठिए हम बजट पास करा रहे हैं। बैठ जाइए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12 अरब, 42 करोड़, 26 लाख, 95 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

'कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष मैं अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 42,61,32,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं हमारे नेता धरतीपुत्र माननीय नेता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके आशीर्वाद से वर्ष 2016–17 का कृषि बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय प्रदेश के युवा एवं किसान माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा किसान हित में किए जा रहे कार्यों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें एक आदर्श मुख्य मंत्री के रूप में निरूपित कर रहा है। आज हमारे किसान वैज्ञानिक एवं विभागीय अधिकारियों की मेंहनत और सहयोग से उत्तर प्रदेश अनाज के मामले में सरप्लस राज्य बन गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने 21 करोड़ की आबादी वाले विशाल प्रदेश की जनता को भोजन उपलब्ध कराना, शिक्षा का प्रबन्ध करना, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करने के लिए एक कड़ी चुनौती है। प्रदेश में लगभग दो–तिहाई जनसंख्या परोक्ष–अपरोक्ष रूप से कृषि से जुड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को डी0वी0डी के माध्यम से सीधे जो किसानों के अनुदान, पहले जो सीधे किसानों को दिया जाता था। उसऐक्ट तमाम गड़बड़ियां होती थीं तो उसको ठीक किया गया है ताकि डी0बी0टी0 के माध्यम से, निष्पक्षता से किसानों को अनुदान का पैसा मिले जिसकी सराहना पूरे देश में की गई है और पूरा उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान लागू हुआ है उसकी सराहना पूरे देश में की जा रही है। भारत की सरकार ने, मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसको सम्मानित करने का काम किया है।

(इस समय 1 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री शारदा प्रताप शुक्ला पीठासीन हुए)

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज एग्रीजक्शन के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक हजार दुकानें खोलने का काम है जो बी0एस0सी0 (ए0जी0) और एम0एस0सी0 (ए0जी0) लड़के होंगे उनको वन्स ऑफ वन स्टॉप शॉप के माध्यम से चयनित कर कृषि स्नातकों को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है जिसमें बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रो न्यूट्रिएण्ट, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक, लघु कृषि यंत्रों की किराए पर उपलब्धता एवं प्रसार सेवाओं के साथ–साथ कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन की सुविधा उपलब्ध होगी। उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 60 हजार का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। चयनित पात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा बैंक ऋण दिलाने की कार्यवाही चल रही है। महिलाओं की खेती की सहभागिता बढ़ाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक के कार्यक्रम के अन्तर्गत 23 महिला समूहों को चयनित किया गया है। चयनित महिला कृषकों को ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यन्त्र बांटे गए। मा0 मुख्य मंत्री जी के कर–कमलों से ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपी गई। फसलों की उत्पादकता प्राप्त करने वाले कृषकों को वर्तमान में 20 हजार, 15 हजार एवं 10 हजार रुपये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाता था। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस धनराशि को बढ़ाकर अगले वर्ष के लिए 01 लाख, 75 हजार एवं 50 हजार किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में पहली बार प्रगतिशील महिला कृषक को प्रोत्साहित करने के लिए पृथक रूप से 01 लाख, 75 हजार और 50 हजार के तीन पुरस्कार प्रारम्भ किए जा रहे हैं। कई वर्षों से बुन्देलखण्ड में सूखे और वर्षा की स्थिति को देखते हुए तिल की खेती को प्रोत्साहित करने तथा किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तिल उत्पादन की योजना प्रारम्भ की गई जिसमें पूर्व में दिए गए अनुदान 20 रुपये प्रति किलोग्राम को बढ़ाकर चालू वित्तीय वर्ष ऐक्ट 100 रुपये प्रति किलोग्राम अनुमन्य कराया गया है जिसके परिणामस्वरूप बुन्देलखण्ड में गत वर्ष के आच्छादन 2.41 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 3.49 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश के सूखाग्रस्त 50 जनपदों में रबी हेतु गेहूं, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन के बीजों के लिए अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया गया है। गेहूं के प्रमाणित बीजों पर 1000 रुपये प्रति कुण्टल, मोटे अनाज के बीजों पर 400 रुपये प्रति कुण्टल, दलहनी फसलों के बीजों पर 2500 रुपये प्रति कुण्टल और तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों पर 1200 रुपये प्रति कुण्टल का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया गया है। मृदा परीक्षण के लिए व्यवस्था कराई गई है। आज मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 2016–17 को किसान एवं युवा वर्ष घोषित किया गया है। इस वर्ष में किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में इस वर्ष भी डी0बी0टी0 कार्यक्रम के माध्यम से इसके अन्तर्गत बीजों पर दी जा रही सब्सिडी किसान भाइयों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। जो इससे अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 में यथावत् चलाया जाएगा। विभाग द्वारा संचालित किसान पारदर्शी योजना के माध्यम से किसानों का पंजीकरण कार्यक्रम अगले वित्तीय वर्ष में भी इस वर्ष की भांति चलाया जाएगा। बुन्देलखण्ड मैं इस वर्ष चलाई गई तिल उत्पादन योजना के उत्साहवर्धक परिणाम एवं किसान भाइयों मैं इसकी लोकप्रियता को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में भी चलाया जाएगा। वर्ष 2015–16 मैं कुल 48.43 लाख

कुण्टल बीजों का वितरण किया गया और वर्ष 2016–17 हेतु 55.50 लाख कुण्टल बीजों का वितरण लक्ष्य है जिसऐक्ट खरीफ मैं 11 लाख कुण्टल तथा रबी में 44.50 लाख कुण्टल का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2015–16 में कुल लगभग 88 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष लगभग 100 लाख मैट्रिक टन की उपलब्धता रही है। वर्ष 2015–16 में लगभग 97 लाख मैट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2015–16 में कुल 84021.9 करोड़ का फसली ऋण वितरण का लक्ष्य है जिसमें खरीफ में 227071.9 का फसली ऋण वितरण किया गया। रबी में 11863.74 करोड़ एवं कुल 34634.81 करोड़ फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टीसाइज, बायोएडजेन्ट के वितरण में 75 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है तथा साथ ही मृदा सूक्ष्म तत्वों की कमी दूर करने एवं भूमि सुधार उद्देश्य से जिप्सम का वितरण भी 75 प्रतिशत अनुदान पर किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, ठीक है, कटमोशन आने दीजिए। माननीय मंत्री जी संक्षेप में कहिए।

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी बहुत लंबा है। 116 योजनाएं प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में माननीय सदस्य जो कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं इनको अगर जानकारी हो जाए तो ये शायद अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। इस नाते यह बताना बहुत जरूरी है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मान्यवर, फोटो कॉपी दिला दें, हम पढ़ लेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, बोलिये।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अधिष्ठाता जी, मंत्री जी सम्भवतः कृषि विभाग का बजट पहली बार रख रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इनका पूरा भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए, उसको कार्यवाही का अंग कर दें और हमको एक फोटो कॉपी दीजिएगा हम वह पढ़ लेंगे, बहरहाल मेरे कुछ सुझाव हैं, कुछ बातें हैं चूंकि मैं गांव का किसान हूं इसलिए कुछ बातें यहां पर कहना चाहता हूं, कटौती पर। चूंकि भारत देश का

सबसे बड़ा प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश है और इसका मूल आधार कृषि है। हम लोग कृषि पर आधारित हैं, जब भी बात आती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ये चीज कही जाती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अपने उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 167 लाख हेक्टेअर है और लगभग ढ़ाई करोड़ से कुछ कम किसान हैं। इसी पुस्तिका में माननीय मंत्री जी के द्वारा दिये गए आंकड़ों में कितना विरोधाभाष है हमारे मंत्री जी अगर देखेंगे तो यहां से जाने के बाद अधिकारियों को एक डांट लगाएंगे। इन्होंने इसमें लिखा है कि 2015–16 में 626.64 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य है और उसी के आगे लिखते हैं कि 464.27 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। मान्यवर, कितना बड़ा विरोधाभाष है कि उत्पादन हो नहीं रहा है और लक्ष्य आपने निर्धारित कर दिया। वर्ष 2017 में इन्होंने कृषि विभाग की जो वार्षिक वृद्धि दर बताई है वह 5.1 परसेन्ट है और हमारे पास आंकड़ा है जिसमें भारत की जो कृषि दर है वह 7.6 प्रतिशत है। कहां भारत जा रहा है और कहां हम जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ा प्रदेश है, सबसे कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है। सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें तो हमारे राज्य का जी0एस0डी0पी0 8.24 परसेन्ट है, जबकि महाराष्ट्र का 14 परसेन्ट है।

(सत्ता पक्ष से आवाज आई कि पढ़ा हुआ मान लिया जाए)

पढ़ा हुआ इसे क्या मान लेंगे, यह आंकड़ा है। आंकड़े बताने पड़ेंगे। हमारे सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र हमसे छोटा है। वह आगे जा रहा है, बजट की बात करें साढ़े तीन लाख करोड़ का बजट है और अधिष्ठाता महोदय साढ़े तीन लाख करोड़ में बयालिस हजार करोड़ का बजट रखा गया है जो एक प्रतिशत है। भारत कृषि प्रधान देश है, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। कृषि पर आधारित गांव, गरीब, किसान, उनको धरतीपुत्र की उपाधि हासिल है। किसानों की बात की जाती है लेकिन बजट एक प्रतिशत, डेढ़ प्रतिशत है, ग्राम विकास का अगर जोड़ लें तो तीन–चार प्रतिशत से ज्यादा बजट नहीं है। पिछले साल उन्तालिस हजार करोड़ था इस साल दस प्रतिशत बढ़ा दिया टोटल बजट पन्द्रह बीस प्रतिशत बढ़ा और कृषि पर बजट कम होता जा रहा है इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो कृषि पर बजट आया है, कृषि पर चाहे जो भी इन्होंने लक्ष्य रखे हों 2014–15 मैं इन्होंने चौरासी हजार करोड़ फसली ऋण का लक्ष्य रखा कि चौरासी हजार करोड़ रुपये हमें बांटने हैं लेकिन उसके सापेक्ष चौंतिस हजार छः सौ चौंसठ करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित हुआ जो अगर मंत्री जी परसेन्टेज निकाल लेंगे, खुद पता चल जायेगा बत्तीस लाख कास्तकारों को कृषि क्रेडिट कार्ड देने की बात की और जब दिया तो चौरासी हजार से चौंतिस हजार घट कर रह जाते हैं।

यह कैसा लक्ष्य है, यह कैसा इनका सपना है, गांव गरीब का सपना अधिष्ठाता महोदय क्या ऐसे पूरा होगा ? हम एक किसान हैं, कृषि प्रधान देश है, आज जैन्यून किसान हमारे सबसे ज्यादा छोटे किसान हैं। छोटे किसानों की तादात ज्यादा है जिस तरह शहरों का विस्तारीकरण हो रहा है क्या कृषि मंत्री जी के पास योजना है कि इन

छोटे किसान जो समाप्त होते जा रहे हैं जिनके जमीनों को आवासीय लोग भू उपयोग परिवर्तित कराकर आते हैं। अधिष्ठाता महोदय रह रहे हैं गांव और शहर दोनों से वाकिफ हैं, कई योजनायें आपके क्षेत्र से निकल रही हैं, किस तरह से छोटे कास्तकारों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, उनका वजूद समाप्त होता जा रहा है। कोई उन्हें रोकने की योजना नहीं है। कोई इनको कृषि कार्य कराने की योजना नहीं है। फल, सब्जी कुछ भी उत्पादित करने की उनकी कोई योजना नहीं है। आज जमीन का हिस्सा कम होता जा रहा है। जमीन नहीं बढ़ेगी और अधिष्ठाता महोदय हम लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। हमें खाद्यान्न की आवश्यकता है, खाद्यान्न का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जितना आप लक्ष्य रखते हैं पूरा नहीं हो पा रहा है। किसान उत्पादन करता है, किसान को खाद समय से मिल जाती है तो बीज समय से नहीं मिलता बीज समय से मिल जाता है तो डीजल के रेट मंहगे। क्या आपने कभी यह अनुमान लगाया कि मंहगा श्रम है, खाद मंहगी जा रही है, यही सदन में यह बात आयी कि यूरिया पड़ोसी राज्यों से 60–70 रुपये कम है मंत्री जी ने कहा कि 50–60 रुपये कम है। अगर 300–350 में 60 रुपये कम हो जाये हमारी गणित बहुत कमजोर है लेकिन 20 प्रतिशत तब भी आ जाता है। 20 प्रतिशत यूरिया हमको पड़ोसी राज्यों से मंहगी मिल रही है। इस पर चिन्ता अगर इस बजट में की होती तो बात समझ में आती। हमें पड़ोसी राज्यों में ट्रैक्टरों पर एक लाख सवा लाख रुपये का अनुदान इनको मिल रहा है।

यहां पर ट्रैक्टरों की बात आती है तो यू0पी0 स्टेट एग्रो पूरे प्रदेश में अधिकारी बैठे हैं आप आंकड़ा निकाल कर देख लें कि ढाई करोड़ कृषकों के सापेक्ष क्या हजार लोगों को ट्रैक्टरों पर अनुदान दिया है जो अनुदान देना है कृषि उपकरणों पर, कृषि उपकरणों पर आपने अनुदान दिया है, डीजल पर तो आप फैक्ट्री वालों को अनुदान दे रहे हैं और किसानों के लिए अगर डी0बी0टी0 की बात कर रहे हैं, डी0बी0टी0 की योजना अच्छी है, लागू कर दें किसानों को, मैं भी किसान हूं मैंने भी अपना नम्बर फीड कराया है लेकिन आज तक हमें डी0बी0टी0 में कोई बेनिफिट नहीं मिला है। मान्यवर सिंचाई की जब बात आती है किसानों की सिंचाई का काम तो यह कहा जाता है कि नहरों के अन्तिम छोर तक हमने दे दिया, पानी की बात आती है नलकूप की बात आती है, नलकूप भले ही हम मान लें कि 100 प्रतिशत इनके चल रहे हैं जबकि 95 प्रतिशत चल नहीं रहे हैं लेकिन मात्र 18 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो सिंचाई नहर से या नलकूप से करते हैं। 82 प्रतिशत लोग आज सिंचाई अपने संशाधनों से करते हैं, बिजली की व्यवस्था है वहां पर, जहां पर बिजली की व्यवस्था है, किसान भाई हमारे सारे विधायक पहली बात यही कहेंगे कि ऐक्ट गांव से चुनकर आता हूं, पेशे से किसान हूं आप अगर सदन का ऐवरेज निकालेंगे तो 80 प्रतिशत लोग जिन्होंने दो साल में खेती जरूर 90 प्रतिशत लोगों ने की होगी लेकिन आज उनको बिजली कनेक्शन लेना हो तो कितना मंहगा होता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मण्डियों में जब आपने अपनी फसल उत्पादित कर दी धान के क्रय केन्द्र खुले, गन्ने के पेमेंन्ट बाकी है, हमारे भाई बैठे हैं में यूपी स्टेट में दीपक पटेल जी के साथ कई बार गया माननीय मंत्री जी मैं आपके संज्ञान

में लाना चाहता हूं इलाहाबाद की वह घटना है कि तीन चार साल पहले जो उन्होंने धान का क्रय किया था उनको अभी तक पैसा नहीं मिला। गन्ने के पैसे की तो बात आई लेकिन धान का पैसा न मिले, पिछले साल का पैसा बकाया है, गेहूं का पैसा न मिले, पिछले साल का बकाया है। आप देखें धान और गेहूं के खरीद केन्द्रों पर क्या बिचौलियों के माध्यम से खरीद की गयी है। उनको पैसा नहीं मिला धान खरीद का पैसा नहीं मिला।

आज जो हमारी परम्परागत खेती थी जो मोटे अनाज थे आज वह गायब होते जा रहे हैं। आप भी पूर्वान्चल से आते हैं काला नमक धान जानते होंगे। काला नमक धान बरकरार रहे उसकी खुशबू बरकरार रहे पूर्वान्चल के काला नमक धान का वजूद उस तरह से न खत्म हो जाय जैसे मोटे अनाजों का वजूद खत्म हो गया है। कहां गया सावां, कोदो, काकुन, सोरों इस तरह के मोटे अनाज। आज योजना में दिया होगा 10–5 करोड़ मंत्री जी आपने लेकिन अगर बाजार में जायें, गोण्डा के किसी बाजार में जायें सावां, कोदो, काकुन, सोरो यह बाजार से कतई गायब है। आज डाक्टर लोग बताते हैं कि यह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे हैं। हम किसान हैं कृषि पर बात कर रहे हैं, कृषि विभाग का बजट है और यह मोटे अनाज दिन प्रतिदिन गायब होते जा रहे हैं। बड़ी चिन्ता इस सदन में हुई गन्ने के भुगतान पर, गन्ने की पीड़ा बड़ी आई, ठीक है, आप चीनी मिल मालिकों को अगर बोनस दे रहे हैं आप कतई दें 50 रुपये कुन्तल इस साल आपकी देने की योजना है आप कतइ दें। भले ही आपको अधिकारियों ने न बताया हो कि गन्ने का परता खुद जो रिपोर्ट आ रही है डेढ़ किलो प्रति कुन्तल पर उनको अतिरिक्त चीनी मिल रही है और 2400 के भाव पर जो चीनी थी वह 3200–3400 रुपये में हो रही है फिर भी उनको अनुदान की जरूरत है। आज दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में आज गरीब को कुछ नहीं है, आज दाल हमारी जितना उत्पादन होना चाहिए थी वह नहीं हुई, दाल का उत्पादन नहीं कर पाये। दाल की यहां पर बात आई कि इक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं और दाल बाहर से लाई जा रही है लेकिन दाल पर अगर 50–60 रुपया किलो खरीद के लिए दिया जाता तो गांव, गरीब और किसानों को मिलता। किसान पैदा कर रहा है इतना अनाज आज उसको रखने के लिए उसके पास पर्याप्त जगह नहीं है।

आज हम 300 कुन्तल, ढाई सौ कुन्तल गेहूं और चावल धान पैदा करते हैं जब हम लोगों के पास रखने के लिए जगह नहीं है और न सरकार के पास कोई योजना है। योजनायें हैं, बड़े वेयरहाउस बन रहे हैं, बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त है, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त है लेकिन क्या विकास खण्ड स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर इन गोदामों को नहीं रखना चाहिए। खाद्यान्न जैसे हम पैदा करते हैं बिचौलिये आने लगते हैं और हमें औने–पौने उनको बेचना पड़ता है। खरीद केन्द्र की बात रही, सच हमें भी मालूम है कि धान की खरीद केन्द्र पर कतई खरीद नहीं हुई और अभी भी आप जाग जायें कि इस वर्ष धान और गेहूं की खरीद सही करा दें। पड़ोसी राज्य हरियाणा लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, अध्यक्ष जी, किसानों की बात आ जाने

दीजिए यही एक मंच हैं जहां से किसानों की बात कही जा सकती है और किसानों के हमदर्दी की बात अगर उनको कुछ थोड़ा सा मरहम लग जाय तो अच्छा होगा।

आज हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में आप देखें 400 रुपये कुन्तल, 500 रुपये कुन्तल उनको बोनस दिया जा रहा है। पंजाब में देखें आप अगर धान, गेहूं सरकारी क्रय केन्द्र पर जाते हैं तो 500 रुपये कुन्तल, 400 रुपये कुन्तल आपको बोनस दिया जाता है। और हम उत्तर प्रदेश में 400 रुपये कुन्तल, 500 रुपये कुन्तल सस्ती दरों पर बिचौलियों के माध्यम से बेचते हैं सिर्फ हमारे पास भंडारण की क्षमता नहीं है। बेहतर होता मंत्री जी प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर भंडारण की व्यवस्था करते। अगर भंडारण की व्यवस्था पर छूट दे किसानों को तो भंडारण हो और वह गोडाउन का अपने निर्माण करें। जिससे वह अपने अनाज का भंडारण कर सके। प्रारम्भिक सोसाइटी है बात बहुत होती है कि प्रारम्भिक सोसाइटी लेकिन उन सोसाइटियों का क्या वजूद है भवनों की उनकी क्या स्थिति है, कर्मचारियों की उनकी क्या स्थिति है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पड़ोसी राज्यों में अभी अभी एक रैली हुई एक नेता जी आये उन्होंने कहा कि खेती को 3 हिस्सों में बाटिये, हमें लगा पढ़े लिखे होंगे, मुख्य मंत्री रहे हैं, अब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं बोले 3 हिस्सों में खेती को बाटिये। एक मैं परम्परागत खेती करिये दूसरे में पौध लगाइये एक पेड़ 30–35 लाख का बिकेगा तीसरे में मधुमक्खी पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन करिये। कौन सा ऐसा पैड़ है अधिष्ठाता महोदय, जो 30–35 लाख का बिक जाता है। उनको यह चीज जाननी चाहिए सही चीज यह है कि अगर पापुलर, यूकेलिप्टस हम लोग अपनी मेढ़ों पर लगाते हैं तो काटने में हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं। कानून बदला जा सकता है हरियाणा की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह, उत्तरांचल की तरह कि जो हम लोग पौध लगाये चाहे वह पापुलर का हो, चाहे यूकेलिप्टस का हो उस पौध को कृषि उपज बनायें। जब हम अपनी खेती में प्लान्टेशन करके पैदा करते हैं तो कृषि उपज होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा पैसा मिलता है सरकार को, वन विभाग की रसीद काटने के लिए उसके लालच में कृषि में यह बदलाव नहीं आ पा रहा है कि जो हम अपनी पैदावार करें उसको हम कृषि उपज कह सकें। आज बुन्देलखण्ड की बात करी हमारे कृषि मंत्री जी ने भी बुन्देलखण्ड के लिए किया मैंने भी पढ़ा है साहित्य। 15 करोड़ रुपये जो दिया गया है वह तिल से तेल बनायेंगे उसके प्लान्ट के लिए है वह किसानों को 20 रुपया कुन्तल मिलेगा तिल कितना पैदा होता है, हम आप सब जानते हैं पैदा करते हैं तिल हमें आपको मालूम है लेकिन 15 करोड़ रुपये का बजट सीधे से प्राविधान है उनके लोगों के लिए। बुन्देलखण्ड की बात करते समय आपको याद आना चाहिये था कि किसान जब सूखा राहत की चेकें मांगने के लिए गये थे, तो उनके साथ कितनी बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की गई थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था। आज प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी उपज का उसे मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वाटर लेवल तेजी से नीचे गिर रहा है। अभी परसों ही हमने टी0वी0 पर देखा था कि

बुन्देलखण्ड में एक किसान ने प्राइवेट लोगों से ढ़ाई लाख रुपये का लोन लिया था कि जिससे कि वो बोरिंग लगा दे, उसने बोरिंग लगाई। वह सात एकड़, आठ एकड़ का कास्तकार था, उसने बोरिंग से मटर की सिंचाई का काम किया, लेकिन वाटर लेवेल नीचे चला गया जिससे उसकी बोरिंग फेल हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। आज आपको सोचना चाहिये कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये कि किसान की आत्महत्यायें रोकी जाये। आगे कृषक दुर्घटना बीमा योजना की बात है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप हमारी बात आ जाने दीजिये, यह छोटी–छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम कोई पढ़ नहीं रहे हैं, मंत्री जी पढ़कर बता देंगे। अधिकारी लिखकर दे देंगे और मंत्री जी पढ़ देंगे, जवाब आ ही जायेगा। अधिष्ठाता महोदय, कृषक दुर्घटना बीमा योजना की बात है। खेती में हमारे बुजुर्ग का नाम है, 80 साल का वृद्ध खेती करने नहीं जा सकता है, उसके चार लड़के हैं, जमीन उसके नाम नहीं आई है और वह लड़के खेत में जाते हैं, उनको कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ न दीजिये, लेकिन अगर कृषि का कार्य करते हुए वह अपने पिता की खेती में जाते हैं, तो पारिवारिक लाभ योजना में उनको भी सम्मिलित कर लिया जाये। जो कृषक है, उसके परिवार के लोग जो कृषि करने जाये, उनको सम्मिलित कर लिया जाये। अधिष्ठाता महोदय, आप बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिग्री कालेज की, प्रदेश में 75 जिले हैं और 36 जिलों में कुल 36 महाविद्यालय हैं, कृषि की बात हो और किसी जिले में कृषि महाविद्यालय न हो। कैसे पूरा हो सकता है। प्रत्येक जिले में कृषि महाविद्यालय होने चाहिये और हमारे जो लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय खोला गया है, हमने इस बजट में पढ़ा कि उसमें पैसा देने का काम इन्होंने नहीं किया। भूमि सेना को मजबूत करने की बात आई, भूमि सेना बनेगी, भूमि सेना के लिए बजट दिया गया, लेकिन भूमि सेना ने क्या अपना काम सुचारु रूप से किया ? आज बात आती है कि ब्याज माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया, तो क्या आपने किसानों का सारा कर्जा माफ कर दिया। प्राइमरी सोसाइटियों में जो आपका पैसा डूबा पड़ा था या भूमि विकास बैंक का जो पैसा वसूल नहीं हो सकता था, उसको माफ करने का काम किया है। आज बीज गोदाम हों, चाहे कृषि रक्षा इकाई हो, चाहे साधन सहकारी समिति हो, 820 साधन सहकारी समिति, 8135 विभागीय बीज गोदाम, 820 कृषि रक्षा इकाई, इस प्रकार लगभग 9000–10000 की कुल संख्या है। कृषि रक्षा इकाई में भवनों की स्थिति क्या है। आपके प्रारम्भिक समितियों में भवनों की क्या स्थिति है, यह देखने योग्य बात है। आप कहते हैं कि हम योजनायें बनाते हैं। हम कृषि सुविधाओं को तकनीकी देने के लिए काम कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, आप कृषि कार्ड देते हैं, कृषि कार्ड चलता है तीन लाख रूपये तक का जो बनता है, उस पर तीन लाख रुपये है, तीन लाख से जैसे ही बढ़ता है तो

उस पर साढ़े तेरह परसेण्ट और चौदह परसेण्ट हो जाता है। तो इसमें कमी करने की जरूरत है। ट्रैक्टर पर हम लोन लेते हैं, तो उस ट्रैक्टर का लोन हमें चौदह परसेण्ट देना पड़ता है, जबकि प्राइवेट फाइनेंस में कार और स्कूटर लेने जाते हैं, तो वह 11 परसेण्ट और 12 परसेण्ट पर मिल जाता है। कैसा किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है। इस लोन को कम होना चाहिये। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। गन्ना सोसाइटियों में जब हम लोन लेने जाते हैं, तो ऋण सीमा पचास हजार रुपये है। अब आप दस एकड़ के जोतकार हैं और गन्ना समिति में जब आप जाते हैं तो पचास हजार रुपये की ऋण सीमा है, उसके ऊपर वह दे नहीं सकते। इस गन्ना सोसाइटी की ऋण सीमा को बढ़ाया जाना चाहिये। उसको बढ़ाने की जरूरत है। कृषि ऋण लेने जाते हैं, तो बैंक वाले कहते हैं कि पहले बारह साला लेकर आओ, जब हम उन्हें बारह साला देते हैं कि हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं है, तो उसके बाद नो ड्यूज लेने के लिए वह हमें भेजते हैं और प्रत्येक बैंक के नो ड्यूज पर 250 रुपये सरकारी फीस बैंक लेती है। आपके माध्यम से सदन का संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि जो वो कृषक जब लोन लेने जाते हैं तो बारह साला की जरूरत नहीं है और उससे लोन की जो फीस ली जाती है, उसको कम कराया जाये। आगे सोलर पम्प की बात है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी बात आ जाने दीजिये, यह इनकी योजना में हैं, हम सब जाने तो क्या स्थिति है इस योजना की। अधिष्ठाता जी, आप जो सोलर पम्प दे रहे हैं, पिछले साल आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह था दो हजार सोलर पम्प तीन हार्स पावर का। इनमें 75 प्रतिशत अनुदान है। सोलर पम्प का वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है और इस साल कृषि विभाग का जो बजट आया है जो आपने यह पुस्तिका दी है इसमें एक सोलर पम्प 3 हार्स पावर का देने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है इससे लगता है कि सरकार इसे देना नहीं चाहती।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें। समय का ध्यान रखिये। आपको 15 मिनट हो गया। धर्मपाल जी अपनी बात प्रारम्भ करें।

'श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय सदस्य शेरू भाई के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात प्रारम्भ करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में किसानों की सर्वाधिक संख्या है। उत्तर प्रदेश में जब किसान प्रभावित होता है तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। किसान खेती करे तो कैसे करे और फिर खेती न करे तो

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या करे। माननीय अधिष्ठाता जी, किसान जो उत्पादित करता है वह सस्ता बिकता है और जो खरीदकर लाता है वह महंगा लाता है। आज उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। किसान बहुत मजबूर हो चुका है बेमौसम बरसात के कारण से, ओलावृष्टि से और ऐसी हवायें चली जिससे उसकी फसल नष्ट हो गयी। सरकार का भी किसान विरोधी रवैया है इससे उसका बड़ा नुकसान हुआ, मुआवजा उसे मिला नहीं वह उसे मिलना चाहिये। मुआवजा आज भी तहसीलों में पड़ा हुआ है, किसान को वितरित नहीं किया गया और किसान आत्महत्या कर रहा है इसलिये कर रहा है क्योंकि खेती का लाभकारी मूल्य उसको नहीं मिल रहा है उसको मुआवजा नहीं मिला और गन्ने के बकाये का भुगतान नहीं हुआ, गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं मिला और बुवाई के समय खाद, बीज, कीटनाशक दवाई इत्यादि नहीं मिली। जो धान का समर्थन मूल्य 1450 रूपये प्रति क्विंटल था। धान के तौल केन्द्र सरकार के रिकार्ड में तो चले होंगे लेकिन वास्तव ऐक्ट किसान का धान समर्थन मूल्य पर खरीदा नहीं गया। माननीय अधिष्ठाता जी, सबका पेट भरने वाला किसान आज भूखे पेट सो रहा है आज वह आत्महत्या करने को बाध्य हो रहा है अपनी बेटी के हाथ कैसे पीले करे, बच्चों को शिक्षा कैसे दिलाये, साहूकार का जो कर्जा ले लिया है उसको कैसे चुकता करे। इन सब बांतों को ध्यान में रखकर किसान आत्महत्या करने को बाध्य हुआ और सरकार कहती है कि किसानों ने आत्महत्या नहीं की। मान्यवर, इस समय आज भी तहसीलों में मुआवजे की राशि पड़ी है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं।

रेशम एवं वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री महबूब अली) (बैठे हुये)–

सब बंट गया है।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी, सब जगह नहीं बंट गया है यदि आप दिल पर हाथ रखकर बोलोगे तो मैंने प्रश्न किया था उससे पता चला कि अभी भी मुआवजे की राशि तहसीलों में बकाया पड़ी है। आप सरकार के किसान हितैषी हो तो उसको बंटवाने का काम करें। मान्यवर, यह मुआवजा बंटने की बात करते हैं। लेखपाल और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से, जिस किसान का नुकसान हुआ, उसको मुआवजा नहीं मिला और जिसका नुकसान नहीं हुआ है, उन्होंने पैसा देकर उस धनराशि को ले लिया है तो इस तरीके से पैसा बंटा है।

माननीय अधिष्ठाता जी, आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने यहां प्रश्न भी लगाया था और कुछ कठिन भी नहीं है कि एक कृषि आयोग बनना चाहिये। अभी तक कृषि आयोग नहीं बना है यदि कृषि आयोग का गठन कर देंगे तो जो उन्नतिशील बीज है, दालें आप बाहर से मंगाते हैं दालें पैदा नहीं होतीं, बीज आपके पास उन्नतिशील है नहीं। यदि इन चीजों पर आप ध्यान दे लेंगे तो मैं समझता हूं तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। आपने 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित किये हैं, बाकी जिलों का क्या दोष था उन जिलों को सूखाग्रस्त क्यों घोषित नहीं किया गया वहां भी कठिनाई हुयी और वहां भी

इसी तरीके का माहौल बना है तो इस तरह की जो स्थिति बनी है आज उत्तर प्रदेश की, वह नहीं होती और प्रदेश में जो पक्षपातपूर्ण वातावरण बना है किसानों के साथ वह नहीं बनता। माननीय मंत्री जी ने एक संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की बात कही है। मान्यवर, वास्तव में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। किसान की फसल खेत में खड़ी है, बर्बाद हो जाती है और कटकर उसके घर पर भी आ जाती है तो उसका नुकसान गेहूं की फसल पर डेढ़ प्रतिशत, खरीफ की फसल पर 2 प्रतिशत और बागवानी की फसल पर 5 प्रतिशत का नुकसान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इस तरीके से जो परिस्थितियां बनी आज उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर) ओलावृष्टि का जो पैसा दिया है वह अभी भी पैसा पड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको वितरित नहीं किया और किसानों को जो उन्नतिशील बीज इत्यादि देते हैं 75 प्रतिशत का अनुदान है। पेस्टीसाइड्स पर, डाई, सल्फेट, यूरिया पर भारत सरकार का 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 प्रतिशत कम कर दिया, 50 प्रतिशत भारत सरकार का ही अनुदान शेष बचा है, ये हैं किसानों के हितैषी। माननीय अधिष्ठाता जी, निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति खराब है और मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना लागू करके किसानों के आंसू पोछने का काम किया है। आज देश का किसान खुश है। मैं आपसे विशेष आग्रह और अनुरोध के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो सबका पेट भरने वाला किसान है, जो भूखे पेट सो रहा है, कृषि आयोग का गठन करवाकर, जिन किसानों को अभी मुआवजा नहीं मिला है उसको मुआवजे की राशि वितरित करवायी जाए और किसान को अभी जो गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित होगा। समर्थन मूल्य पर कम से कम 100 रुपया प्रति क्विंटल के बोनस देने की घोषणा माननीय मंत्री जी करें। यह परम्परा रही है। भारत सरकार जब कोई भी समर्थन मूल्य घोषित करती है तो हर प्रदेश सरकार कम से कम 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का काम करती है। इस परम्परा को निभाकर किसानों के आंसू पोछने का काम करें। इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री नीरज कुशवाहा मौर्य व श्री रविन्द्र भड़ाना के खड़े होने पर)

श्री रविन्द्र भड़ाना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मा0 सदस्य शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका आभारी हूं। मान्यवर, कृषि और किसान इससे संबंधित बहुत सारे अन्य विभाग भी इसमें जुड़ते हैं उसका कारण है कि किसान और किसान की समस्यायें, कृषि और कृषि से संबंधित विषय ये थोड़ा व्यापक है। जब कृषि का विषय आता है तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से आता हूं। मान्यवर, गन्ने की फसल होती है, गन्ने का मूल्य जब तय करने बैठते हैं तो हम कहते हैं कि लाभकारी मूल्य दिया जाये लेकिन लाभकारी मूल्य के बजाय

उसे और कम कर देने की बात होती है। गन्ना मूल्य के भुगतान की बात आती है तो गन्ना मूल्य के भुगतान में सरकारें हाथ पीछे खींचती हैं, मिल मालिकों के साथ में खड़ी होती हैं और गन्ना मूल्य का भुगतान आज तक शेष पड़ा है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर) अरे सुन तो लीजिए, कुछ अच्छे सुझाव दे रहा हूं, आप सुनने का काम करें। मान्यवर, किसान को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए लेकिन प्रोत्साहन के बजाए कहीं न कहीं किसान को दबाने का प्रयत्न होता है। आज चीनी के भाव जो है लेकिन पिछले दिनों चीनी आयात होने के कारण गन्ना किसान बहुत ज्यादा पिस रहा था। उसका मूल्य नहीं बढ़ पाया उसके गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया। आज बोवाई में गन्ना कम हो गया है। गन्ना बोवाई कम होने के कारण जो अगले वर्ष आयेंगें उनमें उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। चीनी उत्पादन पर भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई की बात होती है, नहरों में पानी नहीं है मान्यवर। हम कहते हैं कि किसानों को मुफ्त पानी दे रहे हैं लेकिन नहरों में पानी नहीं है। हम कहते हैं कि डार्क जोन हो गया, पानी नीचे चला गया है रसातल में। मान्यवर, जो सीपेज की व्यवस्था थी नहरों के अंदर। जो नहरी विभाग से संबंधित है, नहरों को साइडों से पक्का करके, नालों को पक्का करके नालियों को, बम्बों को, पक्का करके उसकी सीपेज की व्यवस्था खत्म कर दी गई है और आज पानी का जलस्तर नीचे चला गया है। मान्यवर, बागपत जिला मेरठ जिला ऐसे जोन बन गये हैं जहां पर बिजली के कनेक्शन भी नहीं दिये जा रहे हैं। मान्यवर, डार्क जोन के कारण जब किसान को उत्पादन करने के लिये नलकूप का कनेक्शन नहीं मिलेगा तो मान्यवर, वह अपनी फसलों को कहां से पैदा कर पायेगा। उसकी व्यवस्था कौन करेगा ? अगर यह भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता तो बहुत अच्छा होता। मान्यवर, विद्युत की हालत बहुत खराब है, आप जानते हैं, सरकार उसमें सुधार करे।

श्री अधिष्ठाता–

विद्युत पर तो बहुत चर्चा हुई है। नीरज जी अब आप कहें।

श्री रविन्द्र भड़ाना–

मान्यवर, दो मिनट का विषय है। अभी तो मुझे एक मिनट पूरा नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं बहुत कम समय में रख रहा हूं। मान्यवर, रास्तों की यह स्थिति है कि किसान जब अपना गन्ना, अपना आलू ले करके चलता है। मान्यवर, मेरे यहां हापुड़ रोड एक से नरहैड़ा जुररानपुर मार्ग है मात्र 4 किलोमीटर का। चार साल से लगातार प्रश्न लगाता आ रहा हूं वहां सड़क नहीं है, सड़क में खड्डे हो गये हैं। मान्यवर, वह नहीं बन पाई है। मान्यवर, चंदसारा से गगोल मान्यवर, सड़कों पर खड्डे हो गये लगातार प्रश्न लगाता आ रहा हूं, मंडी समिति से कहा, गन्ना विकास से भी कहा लेकिन नहीं बन पा रही है। उपलहरा से महरौली मार्ग कच्चा मार्ग पड़ा है, गन्ना लेकर किसान नहीं जा सकता है। मान्यवर, चंदसारा से खेडा मार्ग कच्चा पड़ा है। फफूंडा से पिपलीखेड़ा मार्ग जो वाया 69 नम्बर ट्यूबवेल से जाता है, कच्चा पड़ा है किसान के गन्ने का रास्ता वही है लेकिन उससे होकर जाने वाला मार्ग कच्चा पड़ा है मान्यवर आज तक नहीं पक्का

किया गया। यह सब रास्तों के मामले हैं। मान्यवर, कृषक के परिवार को शिक्षा चाहिए। आज शिक्षा का आधार यह है मेरे गांव फफूड़ा के अन्दर जूनियर हाई स्कूल है मैंने बार बार सरकार से कहा कि इसको उच्चीकृत करके हाई स्कूल बना दें। मान्यवर, इन्टर कालेज होना चाहिए। लेकिन मान्यवर, इस मामले में भी भेद भाव किया जा रहा है। कृषकों के बच्चे कहां पढ़ेंगे मान्यवर। हालात यह है कि पढ़ने के लिये विद्यालय चाहिए।

मान्यवर, दबंगों के द्वारा चक रोडों पर कब्जे हो रहे हैं। तालाबों पर कब्जे हो रहे हैं। उनको खोदा जाना चाहिए है, उसमें पानी कहां से आयेगा। जब पटे पड़े हैं उनकी खुदाई बरसात का पानी इक्कट्ठा हो सकेगा।

मान्यवर, इस तरह के जो हालात पैदा हो गये हैं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यूक्लिप्टस के पेड़। मान्यवर, यह यूक्लिप्टस का पेड़ अमरीका से आया था। नहरों के किनारे लगाया जाता था, तराई के जंगलों में लगाया जाता था। मान्यवर पूरे उत्तर प्रदेश को सूखा और डार्क करने का काम इस पेड़ ने किया है। उस पर भी कृषि विभाग विचार कर ले तो इस पर बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है।

'श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज कृषि विभाग के बजट पर कटौती का जो प्रस्ताव हमारी पार्टी के भाई शेर बहादुर जी ने रखा है, उससे मैं अपने आप को सम्बद्ध करते हुए मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम लोग जिस प्रदेश में रहते हैं यहां किसानों के दम पर ही राजधानी में खुशहाली आती है। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो लखनऊ की सड़कों पर भी खुशहाली नहीं आती। ऐसे में सरकार किसान वर्ष मना रही है और माननीय मंत्री जी को अभी यह विभाग मिला है, एक साल का समय है, कुछ क्रांतिकारी कदम उठायें जिससे किसानों को लगे कि उनकी भलाई के लिये काम हो रहा है। मेरे कुछ सुझाव हैं जैसे कि आज सिंचाई की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिये किसानों को इस किसान वर्ष में यह घोषित किया जाय कि हम उनको मुफ्त में सिंचाई देंगें और उनके खेत तक बिजली पहुंचाकर उनको सिंचाई के साधन उपलब्ध करायेंगे क्योंकि आज यह चर्चा हो रही है कि वाटर लेविल नीचे जा रहा है और वक्त की मार के कारण बरसात नहीं हो रही है फसलें बरवाद हो रही हैं। यह व्यवस्था सरकार कराये जिससे किसानों को कुछ राहत मिले। दूसरा मान्यवर, प्रदेश के अन्दर कृषि योग्य भूमि सत्तर प्रतिशत है जिस पर खेती होती है लेकिन कोई योजना न होने के कारण लगभग चालीस फीसदी भूमि ऐसी है जहां पर खेती किसान नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि चाइना के अन्दर मात्र 15 प्रतिशत खेती करने लायक जमीन बची है और हमारे यहां 65–70 प्रतिशत, लेकिन चाइना का किसान हमारे यहां से बहुत समृद्धशाली है जो एवरेज वन की इनकम है वह एक लाख रुपये महीने की है और हमारे यहां दस हजार रुपये महीना भी किसान नहीं कमा पा रहा

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है इस पर चिन्तन करना चाहिए माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए कैसे हम यहां पर नई तकनीक, नई टेक्निक लाएं कि हमारा किसान आगे बढ़ सके। आज जब सब्सिडी की चर्चा होती है तो तमाम विभागों में कृषि को लेकर कहा जाता है कि सब्सिडी हम दे रहे हैं। जो आंकड़े हैं उसको देखें आज उद्योग धन्धों को कृषि से ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। चाहे वह भारत सरकार दे रही हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार दे रही हो। उद्योग धन्धों को सब्सिडी आप ज्यादा दे रहे हैं और किसान जो हमारा अन्नदाता है उसको आप सब्सिडी कम दे रहे हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में जो यूरिया की खाद दूसरे प्रान्तों से मंहगी बिक रही है उसमें यहीं पर सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि अगर हम दूसरे प्रान्तों जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब आदि है अगर हम दूसरे प्रान्तों के बराबर रेट करेंगे तो लगभग आठ सौ करोड़ का सालाना बोझ सरकार के ऊपर आएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतने बड़े प्रदेश में जहां पर करोड़ों की तादाद में किसान रहता है उनके लिए आठ सौ करोड़ का भार सरकार सह लेती है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी यह किसान वर्ष मनाया जा रहा है किसानों की भलाई के लिए आठ सौ करोड़ का भार सरकार वहन करे और जो दूसरे प्रान्तों में यूरिया का रेट है उसी रेट पर यूरिया किसानों को उपलब्ध कराई जाए। ताकि किसानों का भला हो।

मान्यवर, अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो सब जानते हैं कि हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है लेकिन उसके बावजूद. भी आज सबसे ज्यादा परेशान किसान ही क्यों है। आज सबसे ज्यादा दुःख तकलीफ में किसान ही क्यों रहता है इस पर चिन्तन होना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ साथी धर्मपाल सिंह जी ने कहा कि एक कृषि आयोग का गठन होना चाहिए इस पर भी मैं बल देता हूं कि ऐसे आयोग बनाकर और उन पर जो किसानों की समस्यायें हैं उनकी सुनवाई हो। अभी पंजाब में एक नया एक्सपेरीमेंट हुआ है कि जैसा मौसम है उसी के अनुसार फसलें बोने की व्यवस्था कराई जाए।वहां पर कुछ लोगों ने सर्दी के मौसम में स्ट्राबेरी की फसल उगाई और उस फसल से उनको इतना लाभ हुआ कि वहां सरकार ने किसानों के लिए एक नया विभाग बनाया है कि जहां पर जैसा मौसम है वह उस मौसम के अनुसार फसल उगाते हैं तो उनको सलाह भी देंगे और बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा और जो किसानों का उत्पादन होगा उसको लेने का भी सरकार काम करेगी ऐसी व्यवस्था भी सरकार को सोचना चाहिए। माननीय मंत्री जी जब बोलेंगे इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

'श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस कृषि के बजट पर कटौती प्रस्ताव रखने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं दो–तीन छोटे–छोटे सुझाव दूंगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की पूरी आत्मा किसानों में बसती है और किसानों के लिए यह सरकार इतनी गम्भीर होनी चाहिए, चाहे वह देश की सरकार हो या प्रदेश की,

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दोनों गम्भीर नहीं हैं यह मैं इसलिए कह सकता हूं कि आप देख सकते हैं ओलावृष्टि और सूखे की मार किसान झेल रहा है और अभी हमारे आदरणीय धर्मपाल सिंह जी इस बात को रख रहे थे और इधर के सारे सदस्य इस बात को कह रहे थे कि जनपद की तहसीलों में सारे किसानों को ओलावृष्टि और सूखे का चेक प्रदान कर दिया गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जहां तक ओलावृष्टि के मुआवजे का मामला है। अब तक तमाम उन गांवों का पैसा नहीं जा पाया है किसानों के खाते में किसान अभी भी लगातार तहसील से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक चक्कर लगा रहे हैं। पहले एक पैमाना दिया गया था एक एकड़ पर 1500 रुपए लेकिन बाद में आज स्थिति यह है चाहे वह एक एकड़ फसल का नुकसान हो या 10 एकड़ फसल का नुकसान हो किसानों को मात्र 1500 रुपए की धनराशि दी जा रही है। यह दो तरफा व्यवस्था है पेपर टी0वी पर देखें तो दोनों सरकारें किसानों की मसीहा कही जाती थीं केन्द्र सरकार ने कहा कि हमने पांच हजार करोड़ रुपया दे दिया इन्होंने कहा कि हमने 3200 करोड़ रुपया दे दिया लेकिन किसानों को कहीं एक रुपया नहीं मिला और पूरे प्रदेश का किसान अपने को छला और ठगा महसूस कर रहा है। मान्यवर, धान क्रय केन्द्र और गेहूं क्रय केन्द्र की स्थिति क्या है स्थिति यह है कि केवल नाम के क्रय केन्द्र हैं और कहीं किसानों का न धान खरीदा जा रहा है न गेहूं खरीदा जा रहा है केवल माफियाओं का धान और गेहूं खरीदा जा रहा है। आम किसान अगर धान क्रय केन्द्रों पर लेकर जाता है या गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसी भी किसान का धान और गेहूं नहीं खरीदा जाता। बुन्देलखण्ड के किसानों की क्या स्थिति है आप जानते हैं लगातार सदन में चर्चा हो रही है बुन्देलखण्ड का किसान किस निराशा भरे जीवन को जी रहा है। आत्महत्या कर रहा है लोग बदहाली की स्थिति में हैं। किसान चिन्तित है भयावह है बुन्देलखण्ड छोड़कर पलायन की स्थिति में है। उनके परिवार के बच्चे और बूढ़े ऐसी दशा में जीने को मजबूर हैं सरकार ने अब तक ऐसे कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात की घोषणा जरूर की अब हमें देखना है कि उसे जमीन पर उतारने का कितना प्रयास करते हैं। जब यू0पी0ए0 की सरकार थी उस समय श्री राहुल गांधी के प्रयास से 3100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया लेकिन वह पैसा बुन्देलखण्ड की व्यवस्था को सुधारने के लिए था किसानों के लिए गरीबों के लिए मजलूमों के लिए लेकिन उस पैसे का सदुपयोग न हो पाने के कारण कहीं न कहीं धन का बंदरबांट हो गया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अब आप अपनी बात रखें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अधिष्ठाता महोदय मैं लास्ट बात कहकर समाप्त करूंगा जिस तरह यू0पी0ए0 की सरकार ने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाते हुए किसानों का कर्जा माफ किया था मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आज पूरे प्रदेश का किसान चिन्तत और घबराहट की स्थिति में है किसान दुर्दशा के दंश को झेल रहा है आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा

कि आप क्या ऐसी कोई नीति बनाएंगे किसानों के कर्जा माफी पर विचार करने का काम करेंगे। आपने केवल एक छोटी सी बैंक का कर्जा माफ किया था सहकारी बैंकों का लेकिन जो किसान तमाम बैंकों से ऋण लिया उसको कर्जा माफ करने का काम आपने नहीं किया। मण्डी समिति की सड़कों की क्या दशा है।

श्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय शेरू भाई जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने कटौती प्रस्ताव पेश किया है। इन्होंने कहा कि बी0बी0डी0 के माध्यम से जो अनुदान बीज का अनुदान हमने लिया है और अभी खाते में पैसा नहीं गया है अगर आपका खाता नम्बर हो और आपने लिया है तो वह नम्बर हमको दे दीजिए अगर पैसा नहीं गया होगा तो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। दूसरी चीज यह जिस पार्टी में हैं जब इनकी सरकार थी तब किसान जब खाद लेने जाता था तब लाठी पाता था यह सरकार 2012 में बनी है इस सरकार में खाद भरी पड़ी है कोई कमी नहीं है आपकी सरकार बहुत किसान हितैषी थी। किसानों के लिए कोई काम आपने नहीं किया सोलर पम्प के बारे में आपने कहा इतनी बढ़िया योजना है आपने सोलर पर लगवाया है कि नहीं यह बताइए। नहीं लगवाया। आप इसमें एक मांग करिये कि विधायक निधि से जो कृषक अंश है उसको हम देंगे बाकी 75 प्रतिशत छूट सरकार देगी और उसमें आप सोलर पंप लगवाकर देखिये कि कितनी बढ़िया योजना है। आप बुन्देलखण्ड की बात करते हैं। बुन्देलखण्ड सूखा से पीड़ित है। उसमें सरकार ने किसान के लिये तालाब बनाने की योजना बनाई है, उसके अंतर्गत जो भी किसान अपने खेत में सिंचाई के लिये तालाब बनाना चाहता है उसके लिये 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था मा0 मुख्य मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड के लिये की है जिससे वहां सूखे से निपटा जा सके। जहां तक भाई धर्मपाल जी का सवाल है, आफत यही हैं। किसान जब खेती करता है तो वह समझता नहीं है कि प्रकृति साथ देगी कि नहीं देगी और जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र अथवा राज्य में बनती है तो सूखा, आंधी–पानी, भूडोल सब आ जाता है। इसलिये सबसे बड़ी आफत तो यह खुद हैं। यह भगवान राम के दुश्मन हैं, हमेशा उनके नाम पर यह ठगने का काम करते हैं इसीलिये भगवान राम का श्राप है कि इस प्रदेश और इस देश में जब–जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयेगी तो सूखा, ओलावृष्टि, प्रकृति साथ नहीं देगी। इस नाते इनके कारण किसान का जो लक्ष्य है वह पूरा नहीं हो सकता है। हम भगवान राम के वंशज हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, भगवान राम के परिवार के हैं, हम लोग राम को जानते हैं, आप तो राम के नाम पर लूटने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो बक्से से निकालकर राम को बेचने का काम करते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है तो बक्सों में बंद कर देते हैं। इसी नाते यह आपका पाप है कि आज सूखा, ओलावृष्टि, मौसम, प्रकृति कुछ साथ नहीं दे रहा है। आज प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना लागू की गयी है, जिसमें कहा गया है कि 50 प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार देगी। एक हजार करोड़ का बोझ राज्य सरकार पर पड़ेगा। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा जा रहा

है। केंद्र सरकार एक पैसा नहीं दे रही है। बीच में यह किसान हितैषी बैठे हैं और एक आप बैठे हैं। अभी शेरू भाई ने कहा कि लखीमपुर खीरी महाविद्यालय के लिये पैसा नहीं दिया गया है। इस वर्ष उसके लिये 13 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। आपकी जब सरकार थी तो आपने कितने महाविद्यालय बनवाये थे और कहां बनवायें थे, एक भी नाम बताईये ? आपने एक भी महाविद्यालय कृषि के लिये बनवाया ? आपको कृषि की बड़ी चिन्ता है, एक नाम भी बता दीजिये ? पत्थर लगवाया, मूर्ति लगवायीं, कांच की, फिर चांदी की, फिर सोने की, फिर पीतल की और कोई हाथ काट ले जा रहा है और कोई कुछ ले जा रहा है। आप बताईये कि आपने किसानों के हित में क्या किया ? हमारे मा0 विधायक जी चले गये, इनको गन्ने की बहुत चिंता थी। यदि गन्ने की चिंता है तो केंद्र की सरकार ऐक्ट आपके 73 एम0पी0 हैं। सबसे पहले विदेशों से चीनी मंगाना बंद करें। चीनी का दाम जब बढ़ेगा तभी गन्ना किसानों की हालत सुधरेगी। जब तक आप चीनी मंगाते रहेंगे गन्ना किसानों की हालत सुधर नहीं सकती है। यह तो मा0 मुख्य मंत्री जी हैं जो इतनी बहादुरी से इतना पैसा देकर किसी तरह किसानों को बचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग बोलने लायक नहीं हैं। मौर्या जी कह रहे हैं कि विदेशों के जैसी खेती करो।

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

आपको पता नहीं है कि हमारे देश का किसान बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। विदेशों में अगर टेम्परेचर देखना होता है तो करोड़ों रूपये की मशीन लगाकर देखते हैं। हमारे देश का किसान अंगूठा दाबता है और बता देता है कि बोया जाये कि न बोया जाये, हमारे देश का किसान इतना बड़ा वैज्ञानिक है। आपको ज्ञान कम है, आप विदेशों का दौरा ज्यादा करते हैं। कहते हैं सब्जी पैदा करो, कैसे पैदा होगी ? आप मौर्या समाज के हैं जहां आपके समाज में सब्जी की खेती सबसे ज्यादा होती है, लेकिन शायद अब आप करते नहीं होंगे। इस नाते जानकारी करिये। यह किसान का देश है, किसान का प्रदेश है। किसानों के लिये यह सरकार काम करना चाहती है। मा0 मुख्य मंत्री जी किसान वर्ष मना भी रहे हैं, अगला किसान वर्ष घोषित है। आप लोग इसमें अच्छे सुझाव दीजिये जिससे किसानों का भला हो और शेरू भाई, आप हमारे मित्र हैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लीजिये और किसान बनिये। आप खेती कराते हैं, मैं जानता हूं। आप 300 कुन्तल अनाज बटाई पर पैदा करते हैं, राजा–महाराजा हैं, मुझे भी पता है। इस नाते खेतों के किनारे आप कभी नहीं गये होंगे। खेती कराने के लिये बटाई पर देते हैं, हजार कुन्तल अनाज पैदा करते हैं। इस नाते कटौती का प्रस्ताव वापस लीजिये।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

अधिष्ठाता महोदय, राजा–महाराज सही कृषि मंत्री थे, आपके जनपद के थे, उन्हें हटा दिए हैं ये, तो इनको हर जगह वही दिख रहा है। अधिष्ठाता महोदय, शायद विभाग के अधिकारियों ने यह नहीं बताया है, जो वर्ष 2016–17 में आय–व्ययक है, इतनी बड़ी पुस्तिका जो तीन सौ, चार सौ पन्नों की है, इस किताब में इन्होंने लिखा है कि 217 लाख जोतों का मृदा परीक्षण हमारी सरकार ने 2008 में कराया था। अधिष्ठाता महोदय,

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इसी किताब में यह जो उल्लेख कर रहे हैं कि 2008 में दो लाख सत्रह हजार कृषकों का मृदा परीक्षण कराया तो शायद मंत्री जी यह भूल गए कि 2008 में हमारी नेता बहन कु0 मायावती जी की सरकार थी, रह गयी बात इस सरकार की, राहत आयुक्त का पद कितने दिन खाली पड़ा रहा? राहत का जो कार्य है, चाहे सूखा राहत हो, बाढ़ राहत हो, अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, राहत आयुक्त के पद पर यदि समय से तैनाती कर दिए होते तो हम मानते कि यह किसान के हितैषी हैं। 70 किसानों की मृत्यु हुई है, अध्यक्ष जी, 70 किसान मरे, सूखा झेले, ओलावृष्टि झेले, अतिवृष्टि झेले, बाढ़ की विभीषिका हुई, खाद्यान्न का उत्पादन दिन–प्रतिदिन कम हो रहा है, यह पुस्तिका बता रही है कि खाद्यान्न के उत्पादन में निरन्तर गिरावट आयी है। रह गयी किसान की आय की बात, आज छोटे किसान की प्रति महीना आय 1650 रूपये है, आंकड़ों में आप देखें तो एक किसान की 1650 रूपये उसकी महीने में आय है। आज शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र, आशा कार्यकत्रियां, आंगनबाड़ी कार्यकत्री जो हैं, वह प्रति महीने 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार कमाते हैं, लेकिन हमारा गरीब किसान जो 2 करोड़ से ऊपर गरीब किसान है, उनकी आय आज अध्यक्ष जी, 1650 रुपये प्रतिमाह है, इसलिए इसको बढ़ाने की जरूरत है। सूखा राहत में, अतिवृष्टि में, ओलावृष्टि में जो मुआवजा बांटा गया, उस मुआवजे में अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा पक्षपात किया गया, वह मुआवजे की धनराशि वहीं बांटी गयी, जहां अधिकारियों ने बताया। आप जैविक खेती को बढ़ावा दें, किसान के लिए फसल बीमा योजना अनिवार्य रूप से लागू करें, जिस दिन यह सब काम करेंगे, मंत्री जी, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा, बजाय इसके लिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर और बल देता हूं और साथ–साथ मा0 धर्मपाल सिंह जी, रविन्द्र भड़ाना जी, नीरज मौर्या जी और अजय कुमार लल्लू जी ने जो हमारे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोले हैं, उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले भी सदन में यह बात रखी है कि दूसरे प्रान्तों से हमारे यहां यूरिया के दाम ज्यादा हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कितनी बहस हो चुकी है, आपके नेता, मौर्या जी ने इस पर कितनी बहस की है ? उस पर सरकार का जवाब आ गया और यह तय है कि जो बात आ चुकी है, जिस प्रश्न पर एक बार चर्चा हो चुकी है, अब आप समाप्त करिए।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें अनुमति देंगे, अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को हम अंगूठा टेक बनाये रखेंगे, हम बाहर की टेक्नॉलोजी यहां नहीं लायेंगे। तो चलो, अंगूठा टेक बनाने का काम करो लेकिन कम से कम यूरिया के दाम घटाने का काम जरूर करें।

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

अध्यक्ष जी, मैंने यह नहीं कहा। आपने यह कहा कि विदेश का किसान बहुत अनुभवी है, उसे बहुत जानकारी है, तब हमने कहा कि हमारे यहां के किसान उनसे ज्यादा अनुभवी हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 42,61,32,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

रू2.50, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

रेशम एवं वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री महबूब अली)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,67,64,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप दोनों विभाग का एक साथ रख दें।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

रेशम एवं वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री महबूब अली)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,46,56,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

शेरू भाई, मेरे विचार से इसमें चर्चा की जरूरत नहीं है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मान्यवर, यह गरीब बुनकरों से जुड़ा हुआ विभाग है। इसलिए दो–दो मिनट बोल लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बोल लीजिए। अब आप एक साथ कटौती रख दें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपयाकर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। माननीय अध्यक्ष जी, यह समाज के बहुत गरीब वर्ग के लोगों का हथकरघा और रेशम विभाग दोनों पर बोलने के लिए कटौती प्रस्ताव रखा हूं। चूंकि हम सब लोग खादी पहनते हैं। बुनकरों की आज क्या स्थिति है। हमेशा चर्चा होती है और इस पुस्तिका में भी चर्चा हुयी तो इस सरकार को सिर्फ आजमगढ़ का मुबारकपुर दिखायी दिया। अच्छा है हम उसके विरोधी नहीं हैं। आप वहां पर जितना पैसा देना चाहें दें लेकिन उसके अतिरिक्त आपको अन्य जगहों का प्रदेश के बुनकरों का चाहे संतकबीरनगर रहा हो। चाहे आपका सिद्धार्थनगर रहा हो। चाहे आपका सीतापुर हो। और अन्य जनपद ऐसे हैं कि वहां पर बुनकरों की हालत और बुनकरों की अनुमन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह कह रहा हूं कि हथकरघा बुनकरों की सिर्फ इसमें बातें की गयी हैं। बातें ज्यादा हैं उनके लिए काम कम हैं। उनका कार्य करते समय अगर किसी की मृत्यु होती है अपंग होता है तो 60 हजार, एक लाख इतने रूपये। कितना कम है। मा0 अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा पेशा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित किये हुये है। कई पैतृक चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहां से विलुप्त हो चुकी हैं। अब बात करें तो विषय से अलग हट जाता है। हमारी जो पारम्परिक विधायें थीं। हमारे जो पारम्परिक पेशेगत कार्य थे वह सब धीरे–धीरे खत्म होते जा रहे हैं और इसमें पावरलूम, हथकरघा, चरखा चलाते हुए तो गांधी जी ने पूरा अपना जीवन व्यतीत किया, क्योंकि उससे उनको जो अंग्रेजों के जमाने में जो कपड़े आते थे, जो वस्त्र आते थे, उससे मुक्ति मिलती थी और एक गरीब को काम मिलता था, काम मिलकर वह अपनी जीविका चलाता था, आज उनको पावरलूम के लिए बिजली देने का काम नहीं है, उनके लिए कोई योजना नहीं है, उनका माल अगर वह बनाकर तैयार करें तो उसकी मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, पिछली बार भी

वस्त्र उद्योग मंत्री ने यहां पर कटमोशन रखा था गंगवार जी ने, तो उन्होंने एक वायदा किया था कि सीतापुर में हम उसकी बिक्री के लिए मार्केटिंग का इन्तजाम करेंगे, आज नहीं है। बनारस का सिल्क उद्योग, बनारस का रेशम उद्योग पूरी दुनिया में जाना जाता था, आज रेशम की बात जहां आती है तो दक्षिण भारत में चाहे वह श्रृंगेरी हो, चाहे कांचीपुरम हो, अन्य जगहों के रेशम के कपड़े आप भी पहनते हैं और हम लोगों के घर में जरूरत पड़ती है आज उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, हम बात कर रहे थे यहां पर जूट पर, कृषि विभाग में बात आई कि हमारा लखीमपुर, सीतापुर जनपद जूट उत्पादन में बहुत अग्रणी जाना जाता था, उससे रस्सियां बनती थीं, आज जब पॉलीथीन पर प्रदेश सरकार ने पूरा पाबंदी लगाई है, अगर हम जूट पैदा करते तो जूट से झोले बनते, जूट से रस्सियां बनती, जूट तमाम चीजों ऐक्ट सहायक सिद्ध है, इसलिए अध्यक्ष जी, कहने को तो इन्होंने 2016–17 में समाजवादी हथकरघा बुनकर पेन्शन योजना, जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग विकास योजना न मालूम कितनी योजनाओं का इन्होंने जिक्र किया, 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम का भी इसमें जिक्र किया गया है। प्रदेश सरकार हो चाहे केन्द्र सरकार हो उन्होंने बुनकरों के लिए हथकरघा चालकों के लिए, पावरलूम के लिए सब्सीडी उपलब्ध कराने के लिए राशि दी है 05 करोड़, क्या होता है अध्यक्ष जी इसमें, 05 करोड़ की राशि बहुत ही कम है, जबकि 12780 बुनकर परिवारों को लाभान्वित कराने के लिए कहा है 07 परिक्षेत्रों में, सेक्टर अगर बनाया जाय इनका तो सीतापुर और लखीमपुर यहां पर इनके कोई अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं। आज 2015–16 में पावरलूम बहेलि कस्बों में स्वतंत्र विद्युत फीडर लगाये जाने की बात की है और बजट दिया है 15 करोड़, किसानों को अलग से विद्युत फीडर देने की बात थी, लेकिन इनको बिजली तो तब देंगे जब अध्यक्ष जी बिजली उपलब्ध होगी, अव्वल तो बिजली उपलब्ध नहीं है और बिजली अगर उपलब्ध है तो अलग फीडर की बात कर रहे हैं, बजट इतना कम है अध्यक्ष जी कि जिसमें उन बुनकरों का कोई भला होने वाला नहीं है। साधारण मृत्यु की दशा में कामगारों के लिए 60 हजार रूपये का, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर डेढ़ लाख, दुर्घटना के कारण अपंगता डेढ़ लाख, दुर्घटना के कारण आंशिक अपंगता पर 75 हजार रूपये, यह बहुत ही कम है अध्यक्ष जी, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हमने किसानों को 05 लाख देने का काम किया है तो कम से कम बुनकर परिवार वही हैं जिनके पास खेती का कोई साधन नहीं है, व्यापार का उनके पास कोई साधन नहीं है, परम्परागत रूप से वह अपना पेशा, अपना कार्य करते हैं और उसऐक्ट भी इन्होंने महात्मा गांधी बुनकर योजना, बड़ी योजनाएं हैं, जनेश्वर मिश्र पावरलूम, आधुनिक पावरलूम, समाजवादी हथकरघा, राष्ट्रीय हथकरघा विकास ये सारी योजनाएं हैं और अध्यक्ष जी जो बजट का इसमें प्राविधान किया है, वह बजट अत्यंत कम है, इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, क्षेत्रीय आधार पर पिछड़े हैं, इनकी भलाई के लिए प्रदेश में बुनकरों की भलाई के लिए ठोस योजनाएं बनें, दुर्घटना

होने की दशा में उनको उचित मुआवजा मिले और उनके द्वारा तैयार कराये गये माल की बिक्री के लिए उचित बाजार व्यवस्था की जाय, धन्यवाद।

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का अवसर दिया। बुनकर, कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला मजदूरों को एक साधन है, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सौ साल चले अढ़ाई कोस, हमारे यहां कहावत है ये, उसी तरीके से सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जैसे हमारे शेरू भाई ने कहा है, उन सारी योजनाओं का लाभ बुनकर को नहीं मिला और चूंकि मैं स्वयं एक बुनकर परिवार का सदस्य हूं और गोरखपुर का रहने वाला हूं, जहां बुनकर सबसे ज्यादा काम कर रहे थे। चाहे वह आजमगढ़ हो, बनारस हो, अम्बेडकरनगर हो, संतकबीरनगर हो, गोरखपुर हो, लखीमपुर हो, सीतापुर हो। यह सारे बुनकर बहुल्य इलाके हैं और जो खलीलाबाद संतकबीरनगर का है, वह हथकरघा उद्योग का, इस देश की सबसे बड़ी मण्डी रही है। पूरे देश के लोग यहां तक कि वहां से विदेशों में भी सप्लाई हुआ करती थी। मगर सरकार की जो बुनकर विरोधी नीतियां हैं, सरकार की जो मुसलमानों के विरुद्ध नीतियां हैं, क्योंकि बुनकर में ज्यादा मुसलमान हैं और बहुसंख्यक समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है, वह उसमें है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही बुनकर हैं, 60 प्रतिशत हमारे बहुसंख्यक समाज के हिन्दु भाई बुनकर हैं और 40 प्रतिशत सिर्फ मुसलमान हैं। तो यह गलतफहमी नहीं है। मैं उन सभी लोगों की बात कर रहा हूं, जो बुनाई से लगे हुए हैं। चाहे वह किसी भी धर्म या जाति के हों। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज सारे बुनकरों की जितनी भी व्यवस्थाएं थीं, वह सारी ध्वस्त हैं और सारे बुनकर मजदूर होते चले जा रहे हैं। खलीलाबाद का जो व्यवसाय था, जो सबसे बड़ा जीवनयापन का साधन था, वह आज पूरे तरीके से बर्बाद हुआ है। सरकार ने उस पर न तो गंभीरता से विचार किया है और न कोई नीति दी है। आपके माध्यम से मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आखिर सरकार यह कब जांच करायेगी कि बुनाई जो पूरे क्षेत्र की जीविका का साधन था, वह क्यों खत्म होता चला जा रहा है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप भी हमारे क्षेत्र के हैं, आप भी जानते हैं कि 70 प्रतिशत मुसलमान नौजवान चाहे वह आप के जिले का हो, सिद्धार्थनगर का हो, चाहे संतकबीरनगर जिले का हो, यह सब मजबूर हो करके, अपने क्षेत्र से जा करके जो बुनाई करते थे, वह बड़े–बड़े महानगरों में जा करके मजदूरी का काम कर रहे हैं। मान्यवर, उसमें से एक प्रतिशत सेठ हो सकते हैं, मगर 70 प्रतिशत नौजवान ? तो आखिर सरकार की मंशा क्या है, सरकार की नीति क्या है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है। मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं, कि जो भी उपाय या जो भी सरकार की नीति बुनकरों की समस्याओं के हल के लिए बनी है, वह आज नाकाफी है और उन गलत नीतियों की वजह से आज बुनकर जीवनयापन के लिए, भुखमरी के लिए कगार पर खड़ा हुआ है। इसके लिए यह सरकार का दायित्व है कि उनका समाधान करें। मैं अब अपना सुझाव देना चाहता हूं। जनता सरकार में जनता

साड़ी बुनी जाती थी, को–आपरेटिव बुनकरों के लिए था। बुनकरों के लिए सस्ते दाम पर सूद, उनको रंग और जो भी सामान बुनाई के लिए होता था, वह उपलब्ध होता था। इस सरकार ने वह पूरा खत्म कर दिया है। को–आपरेटिव से खरीदने की व्यवस्था थी। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार को जो भी वस्तु की आवश्यकता हो। चाहे अभी तो साड़ी बेचने की बात कर रहे हैं कि हम गरीब जनता को साड़ी देंगे, तो बुनकरों से साड़ी क्यों नहीं खरीदते। सारे कार्यालयों में सबको ड्रेस की जरूरत पड़ती है, तो बुनकरों से वह खरीदिये। उसका इस्तेमाल करिए। दो चीजे होती हैं कि उनको बढ़ावा भी हो जायेगा और रोजगार भी होगा। को–आपरेटिव से सरकार खरीदने की व्यवस्था करे। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि उनके पास बुनाई के अलावा जीवनयापन के लिए कोई और व्यवस्था नहीं है। उनके बच्चों के लिए तालीम की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से दुर्घटना बीमा में जो सुविधाएं किसान भाईयों को दी गयी हैं। मैं आपके माध्यम से और कुछ नहीं कहना चाहता। जो सुविधायें किसान भाईयों को दी गयी हैं या जिस तरीके से उन पर विचार किया जा रहा है और जो बजट उनके लिए दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिए।

डा0 मो0 अयूब–

अध्यक्ष जी, अभी मैं केवल मिनट बोला हूं और एक मिनट और दे दीजिए। अध्यक्ष जी, ये पूरे देश, प्रदेश के बुनकरों का सवाल है। ये पूरे प्रदेश के बुनकरों की रोजी–रोटी का सवाल है। जब तक सरकार को सही मायने में सच्चाई का संज्ञान नहीं होगा, सरकार नीति बना ही नहीं सकती, सरकार की नीति कैसे बन सकती है। अध्यक्ष जी, बुनकरों के लिए बीमा कराया जाए जिस तरीके से किसानों के लिए 5 लाख रुपये का बीमा कराया गया है, वैसे ही बुनकरों का भी 5 लाख रुपये का बीमा कराया जाए। जैसे किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, वैसे ही बुनकरों को क्रेडिट कार्ड दिया जाए। जिस तरीके से 4 परसेण्ट पर किसान को लोन दिया जाता है उसी तरीके से हथकरघा खरीदने के लिए बुनकर को 4 परसेण्ट पर लोन दिया जाए। जिस तरीके से 80 परसेण्ट, 75 परसेण्ट तक सब्सिडी दी जाती है पशु खरीदने के लिए उसी तरीके से उनको सब्सिडी दी जाए। जो व्यवस्था किसानों के गेहूं और अनाज को खरीदने के लिए होती है उसी तरीके से को–ऑपरेटिव के माध्यम से उनके सामान को खरीदने की व्यवस्था की जाए। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो मैं समझता हूं कि बुनकरों की समस्याओं का निदान हो जाएगा। साथ ही एक जो बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश सरकार के सामने उसका समाधान हो जाएगा। इसके अलावा बिजली की समस्या है। किसान को तो कभी–कभी सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है मगर बुनकर हमेशा बिजली पर निर्भर है इसलिए बिजली की व्यवस्था बुनकरों के लिए अलग से की जाए। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका, आपका धन्यवाद।

'श्री अहमद हसन–

मा0 अध्यक्ष जी, आज सदन मैं मा0 सदस्य डा0 अयूब साहब की बात सुनकर तकलीफ भी हुई और हैरत भी हुई। इतनी गलत बयानी एक इंसान कर सकता है ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा नहीं था। मान्यवर, सबसे पहले बुनकरों की यहां आबादी बहुत अच्छी है, टाण्डा की है, जलालपुर की है, जहां से में खुद आता हूं। साथ ही मऊ, बनारस, मैंरठ, मुबारकपुर ये सारे इलाके हमारी जान–पहचान के हैं और सबसे पहले इन बुनकरों के लिए मा0 मुलायम सिंह साहब के जमाने में किसान की तरह जो किसानों को ट्यूबवेल पर बिजली फ्री मिलती थी, उस वक्त फ्री नहीं मिलती थी 120 रुपये लगता था। उसी तरीके से पावर लूम पर, 65 रुपये से एक पावर लूम पर बिजली दी गई। आज टाण्डा और सारी जगह पर जो पावर लूम इण्डस्ट्री है वह 95 परसेण्ट है और एक्सपोर्ट भी कर रही है। आज महाराष्ट्र में एक पावरलूम पर बुनकर को सिर्फ हर महीने बिजली के लिए 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार रुपये दिए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 65 रुपये देना चाहते हैं और दिन भर चौबीस घण्टे बिजली मिलती है। इतनी बड़ी सुविधा देश के अन्दर बुनकरों को कभी नहीं दी गई है। मा0 मुलायम सिंह साहब के जमाने में दी गई है और उसके बाद आज कोई भी बुनकर न भुखमरी के कगार पर है और पहले वह भिवण्डी जाता था लेकिन अब सारे लोग वापस आ रहे हैं। आप देख लें कि इतनी बड़ी खुशहाली जो आज मेरठ में है कि वे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टाण्डा का एक्सपोर्ट हो रहा है, मऊ का एक्सपोर्ट हो रहा है, बनारस का एक्सपोर्ट हो रहा है। इतनी बड़ी सुविधा जो मा0 मुलायम सिंह साहब ने दी थी और आज बुनकरों के लिए मार्केटिंग की जितनी बड़ी सुविधा श्री अखिलेश जी, मुख्य मंत्री जी ने दी है उतनी बड़ी सुविधा देश के अन्दर किसी प्रदेश में बुनकरों को नहीं दी गई है। अब मार्केट खोली जा रही है। करोड़ों रुपये बजट में दिये गए हैं मुबारकपुर में और उनके परचेजिंग के लिए बनारस में बाकायदा मार्केट किया जा रहा है और यह सब जानकर मुझे अफसोस है माननीय सदस्य ऐसा कह रहे हैं, बजट में भी लिखा है और इतनी बड़ी सुविधा आज जिस तरह से खुशहाली किसानों पर आ रही है उसी तरह से आज बुनकरों में पूरी तौर से खुशहाली आ रही है और उनके विकास के काम हो रहे हैं इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह जाकर देखें अभी शुरू किया था कहां से शुरू किया था सफर, चार सीट तो हथनी की थी। अध्यक्ष जी, अबकी इलेक्शन में इनके कन्डीडेट को 2200 वोट मिले हैं और कहां से जो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है जहां से हमारा कन्डीडेट 65 हजार वोट पाकर जीता है। इसलिए यह है कि राजनीति तो मैं नहीं जानता लेकिन आदमी को हकीकत का भी सामना करना चाहिए और आज मैं दिल से कह रहा हूं कि हम सब की खुशकिस्मती हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जहां नौजवान हैं, ईमानदार हैं, वहां बहुत दर्दमंद दिल रखते हैं। हर वर्ग के लिए जो उन्होंने किया वह हिन्दुस्तान के किसी दूसरे प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया होगा या तो श्री मुलायम सिंह साहब ने किया या अखिलेश जी ने किया और दूसरी कोई मिसाल नहीं

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जब भी सवाल उठाया जाए तो देखा जाए कि आज बुनकरों मैं हर तरीके से विकास हुआ है पढ़ाई में आगे बढ़ने पर गौर किया जा रहा है। अभी उनके लिए बीमें की योजना है। वह जो एक बहुत बड़ा एरिया बचा है हथकरघा का, क्योंकि यह मेहनत करता है, उसको भी माननीय अखिलेश जी ने बीमा योजना का लाभ उसी तरह से कर दिया है, जिस तरह से किसानों को कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी का यह भी ऐलान जो होने वाला है जो में अभी यहां नहीं कह सकता। सारे बुनकरों के लिए वही सुविधायें होंगी जो किसानों के लिए होंगी किसी तरह के भेदभाव का सवाल नहीं है। न किसी तरीके का विकास के क्षेत्र में, आगे बढ़ाने के सिलसिले में, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बुनकर हो, चाहे कोई वर्ग हो अगड़ा–पिछड़ा सब के लिए समाजवादी सरकार बराबरी का काम कर रही है। विकास और बराबरी का हिस्सा दे रही है।

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि हमारा नाम आया है।

(माननीय सदस्य डा0 मो0 अयूब वेल में आ गए)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बोल चुके हैं, अब क्या है ? अब हम आपको निकाल कर बहार कर देंगे बता दे रहे हैं। आप बहुत अति कर डाले हैं, अकेले एक मेम्बर हैं और दिन–भर खुराफात।

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नाम आया है।

श्री अध्यक्ष–

क्या नाम आया है, हम सुन रहे थे, जो उन्होंने कहा। उन्होंने यही कहा कि आपने असत्य बात बताई तो इसमें नाम आ गया तो क्या हो गया ? आप सीट पर चलकर अपनी बात कहें। सीट पर चलकर कहें अन्यथा लिखा नहीं जायेगा।

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ माननीय मंत्री जी ने कहा है कि किसानों की तरीके से उनको सभी सुविधायें मिल रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

मिल रही है नहीं कहा, मिलेगी कहा है।

डा0 मो0 अयूब–

हां तो वही बात कहीं है कि किसानों की तरह सुविधायें उनको मिलने वाली है। मुख्य मंत्री जी देने वाले हैं तो दोनों बात इन्होंने की हैं, क्या बीमा 5 लाख मिल रहा है ? क्या किसानों को डायरेक्ट 24 घंटे बिजली मिल रही है। एक भी क्षेत्र ऐसा हो तो बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पूरा भाषण तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब बहस न करें, बैठें आपकी बात आ गई है। अब दूसरे को बोलने दें। आप जब बोल रहे थे तो कोई टोक नहीं रहा था। दूसरे को क्यो छेड़ रहे हो।

श्री रविन्द्र जायसवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे भारत में, जब भारत के लोगों यहां बेटी होती है तो कल्पना होती है कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी उसकी शादी करूंगा तो उसे बनारसी साड़ी पहनाऊंगा। पूरे भारत में कल्पना होती है, जब उसको बेटा होता है तो कल्पना करता है कि मेरे बेटे की जब शादी होगी, तो उसकी शादी में साड़ी हम बनारस की ले आएंगे। यह कल्पना थी, एक प्रयास था लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, धीरे–धीरे बनारस में साड़ियों का काम कम होता जा रहा है। कई कारण हैं, सरकार ने अच्छा काम किया है बधाई देता हूं उनको भी, लेकिन एक चुनौती है, यह सच है बनारस के अंदर साड़ी बुनने वाले लोग आजकल पेण्टिंग कर रहे हैं, डेलीवेजेज मजदूरों का काम कर रहे हैं। चुनौती है कि हमें क्या करना चाहिए, चिन्तनीय विषय है कि हमें क्या करना चाहिए ? भारत सरकार ने बुनकर सुविधा केन्द्र खोलने के लिए एक ही जगह पर उनका रॉ मेटेरियल हो, वीबिंग हो, ट्रेडिंग हो और एक्सपोर्ट हो। यहां पर 280 करोड़ रुपये देकर लालपुर में बुनकर सुविधा केन्द्र खोला। उसके लिए प्रदेश सरकार से जमीन मांगा गया था। एक साल जमीन नहीं दी गयी बाद में सी0पी0डब्लू0डी0 में उसको लालपुर में बनाया गया। एक साल से उसको रोका रहा कि लैण्डयूज और नक्शा पास करने के नाम पर अगर यह काम पहले हो जाता तो आज बुनकरों की हालत बेहतर होती, उसके बाद आठो ब्लाकों में ब्ब् के लिए भारत सरकार ने पैसा दिया 55 लाख रुपये प्रति ब्ब्, माननीय राज्यपाल जी गये थे, उसका उद्घाटन करके आये किराये के लैण्ड पर मात्र 300 स्क्वायर मीटर लैण्ड चाहिए था, जिला प्रशासन ने जमीन दे दिया, गवर्नर साहब ने उद्घाटन कर दिया बाद में वहां के डी0एम0 ने उस लैण्ड को कैन्सिल कर दिया और कहा कि भारत सरकार 300 मीटर का पैसा दे जो जमीन नजूल की है जो वीवर्स के लिए है, भारत सरकार ने पैसा दिया और राज्यपाल उद्घाटन करके आये थे उसके बाद डी0एम0 ने कैन्सिल कर दिया। मेरा सुझाव है कि इसको बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार की योजना थी उस्ताद योजना इसमें जो परम्परागत पिता–बाबा जो बुनाई करते थे, बच्चे भी करे वहां केवल सीखे न बल्कि पढ़े प्रदेश सरकार का उसमैं अंश है उसमैं सहयोग नहीं कर रही है, वह सहायोग करे, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं यह मेरा सुझाव है कि प्रदेश सरकार अपने जितने विभागों में ड्रेस बनाती है, उसमें उत्तर प्रदेश के खादी के बनारसी साड़ी अनिवार्य किये जायें और जितने लोग शर्ट पहनते हैं आज कल पावर लूम पर खादी के सब कपड़े बनते हैं उनको अनिवार्य कर दिया जाये, उससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अन्त में कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली के अन्दर, बाम्बे के अन्दर, कल्कत्ता के अन्दर जो यू0पी0 गेस्ट हाउस है उसमें वहां पर शो–रूम बना दिये जायें। बाम्बे के अन्दर यू0पी0 गेस्ट हाउस बहुत सुन्दर बनाया गया है, बहुत अच्छा

बनाया गया है उसके नीचे हाल खाली है उसमें अगर खादी का शोरूम बना दे तो उसको बढ़ावा मिलेगा। बहुत–बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में सरकार आई है ज़री का एक्सपोर्ट बन्द हो गया, ज़रदोज़ी का बन्द हो गया, पैचवर्क का बन्द हो गया, बनारसी साड़ियों का बन्द हो गया। देखिये डिमान्ड और सप्लाई दो का रिश्ता एक साथ चलता है। डिमान्ड होगी तब सप्लाई होगी। आपने विदेश को जाने वाला सामान रोक दिया, डिमान्ड कट हो गयी। डिमान्ड बन्द हो गयी। जब डिमान्ड ही नहीं है तो सप्लाई के लिए माल कौन बनायेगा। आप पहले एक्सपोर्ट तो खुलवाईये, अडानी ही करें कोई परेशानी नहीं है, दाऊद करलें पाकिस्तान से दोनों का मिलाकर करा दीजिये लेकिन एक्सपोर्ट खुलवाइये। आप पढ़े–लिखे सदस्य हैं, और अच्छे हैं कभी आपने कोई हल्की बात या लड़ाने वाली बात नहीं की। में लड़ाने वाली बात नहीं कर रहा हूं अगर एक्सपोर्ट नहीं खुलेगा, मुरादाबाद से लेकर रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर ये चार–पांच जिलों में लाखों घरों के चूल्हें बन्द हो गये, इसलिए कि एक्सपोर्ट बन्द हो गया। आप कैसी बात कर रहे हैं, में आपसे कह रहा हूं न कि इन सारी चीजों का ज़री, ज़रदोज़ी, पैचवर्क और जितना भी साड़ी वर्क है, जो हैण्डवर्क है उस सब का एक्सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने बन्द कर दिया है।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, भारत की कारीगरी दुनिया में प्रसिद्ध है और दुनिया के लोग भारत की कारीगरी को पसन्द करते हैं, कहीं कोई बन्द नहीं है।

श्री मुख्तार अंसारी–

माननीय अध्यक्ष जी हम संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार बुनकरों के प्रति गम्भीर है और चाहती है कि बुनकरों की भलाई हो तो एक बहुत ही अच्छा सुझाव है कि बुनकरों द्वारा तैयार किया गया जो कपड़ा है, जो सामान है उसे सरकार खुद खरीदे और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर उसको बेचे इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जायेगा और माल की खपत भी हो जायेगी। यही मेरा सुझाव है।

'श्री महबूब अली–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो हमारे शेरू भाई के और अयूब साहब के बहुत सारी बातों का जवाब अहमद हसन साहब ने दे दिया है लेकिन यह बात सही है कि हथकरघा से संबंधित जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार अगर कहीं मिलता है तो हथकरघा से मिलता है। अब यह पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण, बहुत से लोग अगर न जानते हों तो करीब ढाई लाख मजदूर आज की तारीख में रह गया है हथकरघा का जो पहले करीब साढ़े 6 लाख हुआ करता था, कहीं न कहीं पहली सरकारों की गलत

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नीतियों के कारण उसमें कमीं आई है। आज पावरलूम का यानि कि आज देश तरक्की कर रहा है, प्रदेश तरक्की कर रहा है और पावरलूम की तरफ बहुत से कारीगर जा रहे हैं। आज साढ़े चार लाख जो पावरलूम पर निर्भर रहने वाले, काम करने वाले, उससे जिन कारीगरों को रोजगार मिल रहा है उसके लिए सरकार क्या करेगी, सरकार का जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है। मैं कहूंगा कि अभी भाजपा के माननीय सदस्य कह रहे थे आप बड़ी लम्बी चौड़ी मांगे करने के लिए खड़े हो जाते हैं लेकिन शायद आपने यह महसूस नहीं किया कि अभी आपके सामने एक बार भी पंचवर्षीय योजना से राष्ट्रीय हथकरघा विकास योजना डिलिन्क, आप लोगों ने कर दिया। जिसका साढ़े चौरासी करोड़ रूपये से इन मजदूरों को लाभ मिलता था, में कहना चाहता हूं कि शायद आपको इसका अधिकार भी नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा था हमारे शेरू भाई ने कि हमारे आजमगढ़, मुबारकपुर में, मुबारकपुर में तो हमने साढ़े 1200 करोड़ रुपये का विपणन केन्द्र बनाया है जिसमें आपके मुख्तार अंसारी जी का जवाब भी इसी में आ जाता है कि माल इकट्ठा करके उसके मार्केट रेट के हिसाब से सरकार उसको खरीदेगी और देगी। जहां तक है बहुत सी ऐसी चीजे हैं हम अभी इस पर, जो इस पर नहीं है यूनिट को छोड़कर हम व्याज में भी कटौती करने जा रहे हैं जैसे अभी कहा है कि बिजली पर कटौती हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं बिजली पर जो सब्सिडी गवर्नमेन्ट दे रही है डेढ़ सौ करोड़ रुपये हम बुनकरों को दे रहे हैं। बुनकरों के साथ साथ बहुत से लोग न जानते होंगे पहली बार हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस चीज को बहुत गम्भीरता से लेकर धुनकरों को भी उसमें जोड़ा है और अब बिजली सब्सिडी धुनकरों को भी उसी भांति दी जायेगी। मैं कहना चाहूंगा जहां तक आज रेशम की बात है यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ी और बनारसी साड़ी और हथकरघा से संबंधित बहुत से ऐसे हाथ के बने सामान हैं जिससे बहुत बड़ा धन विदेशी भी देश को मिलता था उसके लिए हमारी सरकार ने जहां तक है आपने जिक्र किया था बहराइच का, श्रावस्ती का, बलरामपुर का उस पर हम गम्भीर है, सीतापुर लखीमपुर पर भी विचार कर लेंगे और उसको देखते हैं जो सम्भव हो सकता है, अगर जरूरी है तो उस पर काम होगा। हमने सारा जवाब दिया है। यह विपणन केन्द्र हम और भी प्रदेश में जिस तरह से मुबारकपुर है इस तरह से प्रदेश में और दूसरी जगह भी खोलने का प्रयास कर रहे हैं। आज जहां तक है हमने इसमें बहुत बढ़ाया है अगर रेशम के धागे की बात की जाय तो 112 टन पिछले हफ्ते में 130 प्रतिशत हमने इसको बढ़ाया है। आज मेरा अनुरोध है शेरू भाई से, मेरे ख्याल से तो इसमें ज्यादा कुछ कहने की नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि आज का ठेका कटौती का आपने ही ले रखा है। मैं चाहूंगा कि आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अध्यक्ष जी, कटौती के प्रस्ताव पर अभी जो लोग बोले डा0 अय्यूब साहब, माननीय मंत्री जी श्री अहमद हसन साहब, श्री रवीन्द्र जायसवाल जी, मुख्तार भाई हम सबका धन्यवाद देते हैं और इसके साथ–साथ एक बात आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी काफी वरिष्ठ मंत्री हैं और जिम्मेदारी मंत्री हैं। इस

पुस्तिका में पृष्ठ संख्या–8 पर जो लिखा हुआ है पावरलूम कामगारों के लिए समूह बीमा योजना उसमें कहीं किसानों के बराबर का जिक्र नहीं है, अगर कहीं कोई बात इनके मुंह से निकल गई हो, तो उसको संशोधित कर लें और एक स्पष्टीकरण हमारे माननीय सदस्य और पूछना चाहेंगे।

श्री मो0 जासमीर अंसारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने यहां की एक महत्वपूर्ण समस्या रखना चाहता हूं। मेरे यहां जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में कताई मिल बीस साल पहले से लगा हुआ है और अब तक चालू नहीं हो पा रहा है। मेरा अनुरोध है कि इसको चालू करा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों का चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 02 अरब, 67 करोड़, 64 लाख, 19 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों का चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 03 अरब, 46 करोड़, 56 लाख, 48 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन से एक अनुमति चाहूंगा। एजेण्डा में मद संख्या–25 है। माननीय कारागार मंत्री जी की पत्नी का दिल्ली में आपरेशन होना है और वह जल्दी जाना चाहते हैं, इसलिये मैं आप लोगों से चाहता हूं कि उनका बजट रखवाकर चर्चा करा दें।

ख03ण्27, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12,56,88,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री मान्यवर जी, मैंने 24 प्वाइंट चुने हैं, जो मैं दस–दस सेकेण्ड में कह देना चाहता हूं। मैं अपने विभाग के बारे में 24 बातों पर आपसे आर्शीवाद और आपकी आज्ञा मांगता हूं। नम्बर–1 मुलाकातें–मुलाकातों का मसला, दूसरा रिहाई का मसला, तीसरा कारागारों में चिकित्सा सेवायें, चौथा मसला भोजन गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ फूड, पांचवा मसला पेयजल की समस्या जो बीमारियां पैदा करता है, छठां मसला कि क्षमता से अधिक कैदी, 52000 की लगभग क्षमता है और 89000 बंदी हैं, पैरोल ऐक्ट बेज्जती खज्जलख्वारी, न्यायालय में पेशी का मामला, कारागारों की सुरक्षा, 60 से 70 वर्ष, 70 से 80 वर्ष और 80 से 90 वर्ष के ऊपर के बंदी बहुत जेलों में हैं, उनका क्या करना है उनकी किस्मत का फैसला, महिला बन्दियों की समस्यायें, 3490 बन्दी हैं 488 बच्चे हैं उनका मामला, मुलाकात करने वालों की तकलीफें, जो मुलाकात करने आते हैं महिलायें आती हैं उनकी तकलीफें, 14वां मसला आर्थिक दण्ड प्राप्त बन्दी जो पैसा नहीं पे कर सकते, दो–दो साल से अंदर हैं उनका मसला विचाराधीन बन्दियों को अगर जितनी सजा होनी है जैसे 307 में सात साल होनी है, साढ़े तीन साल से वह विचाराधीन है तो उनका क्या करना है यह मसला। कौशल विकास, बन्दियों में गुणवत्ता पैदा करना जिससे वह बाहर जाकर धन कमा सकें। संवदेनशील कारागार, माफिया जिसको कहते हैं बाहुबली, उन कारागारों का उनके लिये भी मेरे पास कुछ विचार हैं। सी0सी0टी0वी0 कैमरे और मोबाइल, जैमर, यह मसला। 3500 बंदी रक्षक कम हैं। टोटल 7 हजार बंदी रक्षक चाहिये और 3500 रक्षक ही नहीं है यह एक मसला भर्ती प्रक्रिया। बहुत से लोग ऐसे है जो अधिवक्ता की फीस नहीं दे सकते इसलिये जेल में फंसे हुये हैं, उनकी मदद का मसला। मैं एक कमेंटी गठन करना चाहता हूं जो एथेक्स कमेंटी हो जो हर 20 दिन बाद रिहाइयों का फैसला करे यह मैं आपसे मदद चाहता हूं। एक मैं चाहता हूं कि डी0एम0 और एस0एस0पी0 काले नाग की तरह पेरोल और रिहाई के मुद्दे पर चौकड़ी मारकर बैठ जाते हैं, तीन–तीन महीने रिपोर्ट नहीं आती और रिपोर्ट कौन भेजता है सिपाही। सिपाही जाता है घर में, छिपकर 5 हजार लेता है। इन मुद्दों पर मैं आपका ध्यान चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह आप बजट रख रहे हैं या कटमोशन रख रहे हैं। वैसे आप सीधे हैं और सही बात कर रहे हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

मैंने इन मुद्दों को रख दिया, अब आप इन पर बोलिये, मैं इनका हल करने की कोशिश करूंगा।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कारागार विभाग अभी शीघ्र ही माननीय मंत्री जी को मिला है और मुझे यह कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय मंत्री जी ने विभाग की कमियों को समझा और उसको आज सदन के बीच में रखने का काम भी किया। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही सच्चाई के साथ यह बयां किया कि आज तमाम ऐसे कैदी, जिनको पैरोकारी करने के लिये वकील नहीं मिल पाते हैं जिनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है वह बेचारे आज भी जेलों में सड़ रहे हैं और इस देश में जो पहुंच वाले लोग हैं जैसे अभी देखा कि महाराष्ट्र में संजय दत्त जब चाहे पैरोल पर चले आयें जब चाहे चले जायें। तो माननीय मंत्री जी ने जो सच्चाई को स्वीकारा है, इसके लिये मैं इनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको सुधारने का काम भी करेंगे। माननीय मंत्री जी बड़े सीनियर हैं और केन्द्र सरकार में भी रहे हैं और जो बात मैं आज रखना चाह रहा था उसे माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकारा है कि जो कैदी है उनको कौशल विकास मैं लगाया जाय क्योंकि जो जेल है उसका दूसरा रूप है सुधार गृह। तो वहां पर सुधार करने के लिये लोग जाते हैं उनको हम व्यवसायिक प्रशिक्षण का काम दें तो यह एक अच्छा कदम होगा। एक कैदियों की बड़ी समस्या है, मैं जेल विजिट पर गया था तो वहां पर जो स्टाफ हैं, डाक्टर हैं, कैदियों को दमा का रोग हो रहा है और इसका जो कारण है वह वहां इस्तेमाल होने वाला कम्बल है। यह मांग आई है और माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको नोट करे कि जो वहां कम्बल है वह प्योर वूल का कम्बल है उसका लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वह अलग रखा रहता है। इसलिये अगर उसको बदलने का काम कर दिया जाय तो बहुत अच्छा कार्य होगा। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि जेलों की जो क्षमता है उससे बहुत अधिक कैदी हैं, चूंकि हमारे यहां अधिकतर जेलें अंग्रेजों के जमाने की हैं। पहले शहर छोटे होते थे, आज शहरों का विस्तार हो गया है तो जहां–जहां पर जेलें शहर के बीचोबीच में आ गयी हैं उनको शहर से बाहर करने का काम भी किया जाए। मान्यवर, जो खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग है उसको अगर कैदियों से जोड़ा जाए तो इसका काम कैदी वहां पर कर सकते हैं, यह व्यवस्था करायी जाए। एक बड़ी समस्या है जो महिला कैदी हैं, महिला कैदियों के साथ जो 06 वर्ष तक के बच्चे उनके साथ रहते हैं, उसके

बाद जब वह अलग हो जाते हैं तो उनके शिक्षा की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी मां जेल के अंदर है, अगर मां ने कोई सजा काटी है तो उस बच्चे को सजा न मिले इसलिए ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी विशेष व्यवस्था कराने की जिम्मेंदारी सरकार तय करे। मान्यवर, तमाम पद खाली हैं मा0 मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मनोचिकित्सक की भी आवश्यकता जेल में है उसकी भी व्यवस्था हम समझते हैं माननीय मंत्री जी करायेंगे। सी0सी0टी0वी0 कैमरे की बात आपने कह दी। मान्यवर, अनुरक्षण का भी बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। जेलों के कर्मचारी वहां रहते हैं उनके आवास बहुत जीर्ण–शीर्ण हैं। सोलर लाइट सिस्टम को अगर जेल में लगा दिया जाए तो बिजली भी बचेगी और उनको जो बिजली की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी होती रहेगी। मान्यवर, अभी सुबह मैंने व्यक्तिगत रूप से मा0 मंत्री जी से भेंट भी की थी, हमारे जनपद के एक कैदी हैं उनको एक केस में 07 साल की सजा हुई थी, 04 साल वह काट चुके हैं और इस समय वर्तमान में उनकी समस्या यह है कि वह दोनों आंखों के अंधे हो गये हैं। दोनों आंखों से उन्हें दिखायी नहीं पड़ता है, जेल में वह पड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें जरूर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करते हुए जो एक ब्लाइंड कैदी है मैं समझता हूं कि उसकी सजा माफ होनी चाहिए। मान्यवर, कुछ कर्मचारियों की भी बातें हैं जैसे हमारे बंदी रक्षक हैं जिस तरह से पुलिस विभाग के लोग काम करते हैं ठीक उसी तरह से जेल के भी बंदी रक्षक काम करते हैं तो उनको भी जैसे पुलिस के लोगों को भत्ते दिये जाते हैं वह भत्ते उनको भी देने का काम करें। जैसे पुलिस विभाग के लोगों को फल भत्ता दिया जाता है, यह फल भत्ता उनको भी देने का काम कराया जाए जिससे उनके मन में यह बात न आये कि हम इनसे कहीं अलग हैं। मान्यवर, अंत में चूंकि मा0 मंत्री जी अभी नये–नये आये हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह जेलों को सुधारने का काम करेंगे। जेल में जो मौतें हो रही हैं बड़ी गम्भीर समस्या है। जेल में मौत न होने पाये इसके लिए जो वहां पर अस्पताल बने हैं या समय–समय पर वहां पर स्वास्थ्य कैम्प लगाकर अगर कोई कैदी वाकई गम्भीर रूप से बीमार है तो उसकी सजा माफ कर उसको छोड़ दिया जाए या उसका सही इलाज कराया जाए। अंत में मैं यही कहते हुए कि जो 70 साल उम्र से ऊपर के कैदी हैं और उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो उनको छोड़ने के लिए सरकार जरूर विचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

(श्री उमेश पाण्डेय के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

उमेश पाण्डेय जी, जेल पर क्या बोलोगे ?

श्री उमेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यक्तिगत है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं व्यक्तिगत रूप से मिल करके भी मैंने अपनी पीड़ा कही है। 16–10–2005 को मेरे भाई की हत्या हुई थी, हमारे भाई के हत्यारों को, जेल मैनुअल के हिसाब से सजायाफ्ता कैदियों को सेण्ट्रल

जेल में होना चाहिए परन्तु जब से सरकार बदली है तब से हमारे भाई के हत्यारे मऊ जिला जेल में निरुद्ध हैं और वहां पर मौज मस्ती कर रहे हैं, जेल नाम की कोई चीज नहीं है। साथ ही आज उनको पेरोल पर छोड़ने की कार्यवाही हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं सदन के माध्यम से कि क्या उनको न छोड़ने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप लिख करके दे दीजिए।

श्री उमेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी से आश्वासन दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आप लिख करके देना।

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर, कई बार लिख करके दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष–

पाण्डेय जी, बैठिये आपकी बात आ गयी, माननीय मंत्री जी सुन लिये, जब वह जवाब देंगे, तब बोलेंगे।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से 2/3 बातें रखना चाहता हूं। मान्यवर, अलीगढ़ जेल की क्षमता 500 कैदियों/हवालातियों की है।

श्री अध्यक्ष–

वह तो बताया, आप क्यों उसको दोहरा रहे हैं। वह सब स्वीकार कर लिया है उन्होंने।

ठाकुर दलवीर सिंह–

और समस्याएं हैं। पूरे जनपद हाथरस के कैदी अलीगढ़ जनपद की जेल में है। 2800 से 3000 कैदी हमारे यहां अलीगढ़ की जेल में हैं। इतनी बीमारी, इतनी समस्या बनी हुई है अलीगढ़ जेल की। हाथरस जेल के लिये अभी तक जमीन नियत नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी से जल्दी हाथरस जनपद की जेल अलीगढ़ की जेल से अलग बनाई जाय। मुलाकात करने के लिये....

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिये। मंत्री जी अभी खुद ही बतायेंगे। अंसारी जी आप एक मिनट में कहें। आप इतना लिखकर लाते हैं सुझाव पता नहीं कितना माना जाता है कितना नहीं।

श्री मुख्तार अंसारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय कारागार मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार कारागार विभाग के लिये 12,56,88,29,000 रूपये का बजट पास किया है उसके सुधारों के लिये। माननीय मंत्री जी अनुभवी हैं और बुजुर्ग आदमी हैं और सबसे बड़ी बात है कि सरदार हैं इसलिये हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि वो बंदियों की समस्याओं के बारे में गम्भीरता से सोचेंगे और आज फैसला लेंगे। क्योंकि इसके पहले जो बजट पेश हुआ था उसमें सम माननीय मंत्री श्री बलराम यादव जी थे उन्होंने कुछ वायदे किये थे लेकिन वह सब अधूरे रह गये इसलिये आज हम पुनः चूंकि 32 साल से भी अधिक समय मैंने जेल के अंदर गुजारा। आते जाते रहे हैं, और मुझे कटु अनुभव है इसलिये मैं अपने अनुभव को माननीय मंत्री जी से बांटना चाहता हूं और अपना अनुभव उन्हें बताना चाहता हूं जिन चीजों से बहुत कुछ सुधार हो जायेगा। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब देश गुलाम था उस वक्त से आज तक यह लागू है कि 14 साल की सजा पूरी कर लेने के बाद सजायाफ्ता बंदी को राज्य सरकार चाहे तो दया याचिका पर उसे छोड़ सकती है और उत्तर प्रदेश में भी यह जी0ओ0 लागू है लेकिन यह बहुत धीमी स्पीड से चल रहा है। जिस वजह से आज कल कोर्टों में सजा का ग्राफ तो 56–57 परसेन्ट तक चला गया है। पहले 2–3 परसेन्ट था, आज 56–57 परसेन्ट है जिससे जेलों में कैदी बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उनको जिस तेजी से छोड़ना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इसलिये हमारी आपसे मांग है कि 14 साल की सजा जो बंदी काट चुका है जेल में, उन बंदियों को एक–एक करके, दया याचिका उनकी मंगा करके, फार्म ऐ भरवा करके जो नियम एक आपने बना रखे हैं और फार्म यह भरे जाते हैं लेकिन आपने कहा है एक–एक दो–दो महीना, लेकिन दो–दो चार–चार साल और दस–दस साल यह फार्म पेंडिंग हैं यहां शासन में आकर, और उस पर कोई निर्णय नहीं होता है। आगरा की सेन्ट्रल जेल में मैं हूं और वहां 30 से 35 साल तक की सजा के पुराने बूढ़े 90 साल तक के बुड्ढे लोग सजायाफ्ता बंदी बंद हैं जो लैटरीन भी बिस्तर पर करते हैं इसलिये ऐसे लोगों को सबसे पहले, सूची मंगा करके, पूरे प्रदेश की मैंने सूची मंगाई है और लगभग 700 ऐसे बंदी हैं 90 हजार कैदियों में जिनको दया याचिका पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को जैसे हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों में छोड़ा जाता है अगर छोड़ा जाय तो माननीय मुख्य मंत्री जी और इस सरकार का बहुत ज्यादा नाम होगा और लोग समझेंगे कि कमजोर, गरीब औरे बेसहारा की सुनने वाली भी यह सरकार है। इसी के साथ साथ जो बंदी 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल के बूढ़े हो गये हैं जो लोग पांच साल, छः साल, सात साल की सजा काट चुके हों, और जो 80–90 साल का बूढ़ा बन्दी है वह कोई अपराध बाहर निकल कर नहीं सकता है। वहां भी वह बोझ बना हुआ है हास्पिटल में ढाई सौ, तीन सौ बन्दी जो रहते हैं उसमें दो सौ के करीब बूढ़े बिल्कुल बीमार बन्दी हैं ऐसे बन्दियों को जिनकी 14 साल की सजा नहीं भी हुई है उन पर भी आप विचार कीजिए कि उन पर आप दया याचिका हो तो छोड़िये। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह यह अधिकार दे दिया है राज्य सरकारों को अभी सुप्रीम कोर्ट ने, राजीव गांधी जी के हत्यारों के बारे में जब लोग सुप्रीम

कोर्ट में गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह अधिकार दिया है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो किसी भी बन्दी को दया याचिका पर छोड़ सकती है। इसके बाद माननीय मंत्री जी मैं एक बात आपसे और चाहूंगा कि आप बंदियों से श्रम लेते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में हर जेलों में बन्दी काम करता है खेती करता है, मजदूरी करता है, झाड़ू देता है, पोंछा लगाता है आठ घंटा, और उसको आप तनख्वाह देते हैं हिन्दुस्तान में सबसे कम, 40 रुपया, और अर्द्धकुशल को 30 रुपया और अकुशल को 25 रुपया, हिन्दुस्तान में यह सबसे कम है मैं चाहता हूं कि कम से कम जो सबसे गरीब प्रदेश हमारा माना जाता है बिहार, वहां है 121 रुपया और 100 रुपया और 80 रुपया, तो कम से कम बिहार जितनी श्रम करने वाले मजदूरों को जो दिन भर खेती कर रहे हैं सुबह से शाम तक, खेत में हल चला रहे हैं उनको इतनी तनख्वाह मिले उससे वह, हमने अपनी आंख से देखा है वह बन्दी अपना पैसा इकट्ठा करता है जो 600 रुपये होता है, 600 रुपया इकट्ठा करके अपने घर भेजता है अपने बच्चों को भेजता है पढ़ने के लिए अपना परिवार चलाने के लिए, इसलिए यह मदद होनी चाहिए कि जब वह श्रम कर रहे हैं उन से काम लिया जाता है तो उनकी मजदूरी बढ़नी चाहिए और 120 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिए।

श्री मुख्तार अंसारी–

माननीय अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि टेलीफोन बूथ की सुविधा हिन्दुस्तान की बहुत सी जेलों में है टेलीफोन बूथ अगर लगा देते हैं तो यह जो जैमर लगाने का पैसा बरवाद कर रहे हैं यह बरवाद नहीं करना पड़ेगा जाइए एक रुपया डालिए और बात करिए। सारे फोन रिकार्ड होंगे जैसे तिहाड़ जेल ऐक्ट है अगर अफगानिस्तान में भी उसको बात करनी होती है तो कोई अफगानिस्तान भी बात करता है पैसा डाला और बात कर लिया वह रिकार्डिंग हुई अगर वह लीगल है तो आगे जाने देते हैं नहीं तो उसे डिलीट कर देते हैं तो ऐसी व्यवस्था अगर यहां कर देंगे तो आप पचासों करोड़ रुपया जैमर में जो बरवाद करेंगे टेलीफोन बूथ की सुविधा आप देने के लिए माननीय मंत्री बलराम यादव जी ने आदेश भी कर दिया था लेकिन पता नहीं क्यों अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमें तो जो जानकारी है इस पर बजट भी एलाट हो चुका था लेकिन आज तक टेलीफोन बूथ नहीं लगा है तो इसे लगवाया जाए।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री मुख्तार अंसारी–

मान्यवर मेरी पन्द्रह बीस मांगें हैं इनको सुन लीजिए। टेलीफोन बूथ जो लगवाए जाएं वह किसी ऐरी गैरी कमीशनखोर कम्पनी से नहीं बल्कि बी0एस0एन0एल0 कम्पनी जो बड़ी कम्पनी है उससे टेलीफोन बूथ लगवाया जाए ताकि वायरिंग अच्छी हो। पांचवीं

मांग हमारी है कि जेलों में नब्बे हजार बन्दी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जेल में सब मिलाकर पचास नाई होंगे तो कम से कम दो चार सौ नाई रख लें जिससे सरकार को गरीब लोगों को रोटी देने का भी फायदा मिलेगा। अब तीन हजार बन्दी लखनऊ में हैं अब अगर हम लोगों को दाढ़ी बनवानी होती है तो इंतजार करना पड़ता है तीन हजार बन्दी पर एक नाई है किस दिन किसका नम्बर आएगा इसलिए हर जेलों में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि हर जेल में आठ दस नाई रख दिए जाएं जिससे बाल और दाढ़ी की सफाई हो सके और उनके जुंआ न पड़ पाए। साथ ही साथ हम एक मांग और करते हैं पैरोल की, हिन्दुस्तान के बहुत से सूबों में यह लागू है सभी बन्दी जो कैदी होते हैं जो विचाराधीन हैं वह नहीं। जिनको सजा हो गई है और जिनकी सब जगहों से खारिज हो चुकी है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सब जगह से ऐसे कैदियों को 60 दिन का पैरोल दिया जाता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेती के लिए मकान के लिए जिस चीज के लिए भी हर जगह यह लागू है। हमारे प्रदेश में जिसका सोर्स है उसका हो जाता है गरीब बंदियों पर यह लागू नहीं हो पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह हर बंदियों पर लागू होना चाहिए। जो भी बंदी दरखास्त देकर अपने घर जाना चाहता हो अपने परिवार से मिलना चाहता हो उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करके साल में 60 दिन के लिए पैरोल देना चाहिए जिससे वह अपनी खेती, अपना घर बना सकता है। सातवीं मांग है कि

श्री अध्यक्ष–

जो महत्वपूर्ण मांग हो उसे कह दें। आप हर साल यह पढ़ते हैं।

श्री मुख्तार अंसारी–

सफाई के बारे में हम कहना चाहते हैं कि अक्सर अधिकारी यह करते हैं कि जो बड़े लोग आते हैं उनको झाड़ू पर लगा देते हैं उनको पहले झाड़ू दिलवाते हैं फिर पैसा वसूली करते हैं कि आपसे काम नहीं कराया जाएगा इसके लिए एक लाख दे दो पचास हजार दे दो अगर दस बारह स्वीपर हर जेलों में रख लिए जाएं तो सरकार को गरीब लोगों को नौकरी देने के लिए मौका मिलेगा और इससे जिन बन्दियों के बारे में यह सिद्ध नहीं है कि वह दोषी हैं उनको झाड़ू और नाली भी साफ नहीं करनी पड़ेगी। मानवता के नाते यह काम जरूरी है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त कर दें। बहुत हो गया। आपका कोई नया नहीं है हर साल यह पढ़ते हैं।

श्री मुख्तार अंसारी–

अध्यक्ष जी सुन लीजिए। यहां अस्पतालों में 90 प्रतिशत एक्सरे मशीन खराब हैं 10 प्रतिशत बस ठीक हैं पूरे प्रदेश ऐक्ट आप रिपेयर के नाम पर हर साल बजट में 50–50 लाख तक भेजते हैं लेकिन यह अधिकारीगण पैसा सिर्फ खा जाते हैं रिपेयर नहीं कराते हैं। अभी माननीय मंत्री राजा भैया ने ठंडे पानी की मशीन दी है सारी मशीनें एक

बार चलीं बाद में कोई गंदी हो गई किसी का वासर बदलना है किसी की टोंटी बदलनी है वह वैसे ही फेंक दी गईं इसलिए इसमें हमारे प्रदेश का पैसा लगा है बजट बरबाद हो रहा है हम चाहते हैं कि जो पैसा दिया जाय उसऐक्ट यह आदेश किया जाय कि उन मशीनों को बनाकर पुनः लगाया जाय पांच साल की उसकी गारण्टी है और दो साल में फेंक दी गई है। अस्पतालों में एक्स–रे मशीनों के साथ साथ खून को टेस्ट करने के लिए एक बड़ी समस्या प्रदेश में हिन्दुस्तान में है कि लोगों को सुगर हो जाती है और दो दो महीने लग जाते हैं बाहर से गार्ड आने में और बन्दी को बाहर जाने में उसमें दो खतरा रहता है कि बन्दी भाग जाएगा इसलिए वह गार्ड नहीं देते हैं अगर शुगर चेक करने के लिए लैब बना दी जाए मात्र एक लाख दो लाख में बन जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में जो इस बार इतना बड़ा बजट है इतना बड़ा बजट कभी नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में तो अगर यह व्यवस्था कर ली जाए कि बलगम चेक हो सके खून चेक हो सके छोटी–छोटी चीजें अस्पतालों में चेक हो सकें ऐसी मशीनें लगवा दी जाएं। साथ ही साथ अभी साथी ने कहा कि बहुत सी जेलें अंग्रेजों के जमाने की हैं 70–80 प्रतिशत जेलें अंग्रेजों की बनाई हुई हैं इन जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं तो हर जेलों में कम से कम चार–चार, पॉच पांच बैरकें बना दी जाएं एक बैरिक में डेढ़ सौ सवा सौ बन्दी रहता है एक बाथरूम है सवा सौ आदमियों को इस एक बाथरूम में पर डे जाना है उसमें माननीय मंत्री राजा भैया ने आदेश किया था तो फ्लश लग गया था तो जो बन्दी जाता था वह फ्लश कर देता था बाथरूम साफ रहता था अब वह रिपेयर के नाम पर 90 प्रतिशत खराब हो चुका है यह प्लास्टिक का होता है आप भी घर में देखते होंगे कि वह खराब हो जाता है मिस्त्री आया उसे बना दिया छोटा सा काम होता है मगर अधिकारी नहीं करते हैं रिपोर्ट तो भेज देते हैं बजट मंगा लेते हैं काम नहीं कराते हैं इसलिए उनका रिपेयर होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि गंदे बाथरूम में जब बंदी जाता है तो उस गंदगी की वजह से उसको बीमारी होती है और 50 तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिये मैं मा0 मंत्री जी से खासतौर से चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सभी जेलों के बाथरूमों मैं फ्लश लगवाये जायें। हमने मांग की थी तो मा0 मंत्री जी ने आगरा जेल के 200 बाथरूम में फ्लस लगवाये थे, लेकिन यह फार्मूला उत्तर प्रदेश की सभी जेलों पर लागू होना चाहिये। जब एक बाथरूम में 100 आदमी बाथरूम जा रहे हैं तो लोटा लेकर पानी डालने से वह जाम हो जायेगा। आप इसको सोचेंगे तो समझ जायेंगे कि यह परेशानी कितनी बड़ी है। मा0 अध्यक्ष जी, अब मेरा 15वॉ सवाल है कि मा0 मंत्री जी ने, राजा भईया ने भी और श्री बलराम भाई ने भी ज्यादातर जेलों ऐक्ट मुलाकात की जाली कटवा दी है, लेकिन अभी कुछ जेलों में वह जाली बची है जहां पर अधिकारियों ने शरारत के तौर पर जाली नहीं कटवाई है। उस जाली के माध्यम से बहुत कमाई की जाती है। जो गरीब बंदी है वह पैसा नहीं दे पाता है तो उसकी जाली में मुलाकात कराई जाती है और जो अमीर बंदी है वह 2000 और 5000 रुपये देता है तो उसकी मुलाकात जाली के बाहर कराई जाती है। इसलिये मैं मा0 मंत्री से मांग करता हूं कि एक तरह का फार्मूला सभी पर लागू होना चाहिये और पूरे उत्तर

प्रदेश की जेलों मैं जाली कटवा देनी चाहिये और यह काम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जेल से शुरू करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

अभी आपकी कितनी मांगे हैं ? अब समाप्त करें। आपकी जो दो–तीन मांगें बची हैं उसे लिखकर दे दीजिये।

श्री मुख्तार अंसारी–

मान्यवर, अभी 15वें पर हैं। (सदन में हंसी) आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि जेलों के लिये बजट भी गया था और आर0ओ0 मशीन भी खरीदी गयी थीं, लेकिन सिर्फ दो महीनों में ही उत्तर प्रदेश की सभी जेलों की आर0ओ0 मशीनें खराब हो गयीं। यह बहुत बड़ी समस्या है। अभी मेरी जानकारी के हिसाब से 25 लाख रुपये लखनऊ के लिये दिये गये हैं, उसमें से सिर्फ एक लाख रुपये ही खर्च होगा बाकी 24 लाख रुपया खा लिया जायेगा। इसलिये यह सख्ती से कह दिया जाये कि जिन जेलों में आर0ओ0 मशीन नहीं हैं वहां आर0ओ0 मशीन लगाई जायें और बंदियों को साफ–सुथरा पानी दिया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक मांग कारागार प्रशासन विभाग के लोगों के लिये करना चाहता हूं जो कि कारागार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पौष्टिक आहार भत्ता दिये जाने से संबंधित है। जिस तरह पुलिस को, पी0ए0सी0 को और आपके विधान सभा के कर्मचारियों को भी पौष्टिक आहार भत्ता दिया जाता है, उसी तरह हमारे कारागार के सिपाहियों, कर्मचारियों को भी पौष्टिक आहार भत्ता दिया जाना चाहिये। साथ ही साथ में यह भी मांग करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों के सुप्रिन्टेन्डेंट और वरिष्ठ अधीक्षकों को उनकी सुरक्षा के लिये ए0के0 47 से लैस सुरक्षा गनर भी उपलब्ध कराया जाना चाहिये ताकि वह जेल मैंनुअल का सही ढंग से पालन कर सकें और निर्भीक होकर कानून का पालन करा सकें। मेरे बहुत से सुझाव हैं, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, आप हमें जल्दी समाप्त करने के लिये कह रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि मा0 मंत्री जी हमारी इस मांग को गंभीरता से लेंगे और कुछ इस तरह का निर्णय लेंगे जिससे हम सभी लोग संतुष्ट हो सकें।

(मा0 सदस्य, श्री पूरन प्रकाश के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

जेल से संबंधित सभी बातें आ गयी हैं, आप बैठ जाईये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, मुख्तार साहब ने बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथी हैं और काफी अरसे से जेल में भी हैं और जाहिर है उनके तजुर्बों की बुनियाद पर हैं, उन पर ध्यान होना चाहिये। मैं आपसे एक जानकारी चाहूँगा और सदन को भी जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया कि शहरों के बीच जेलें आ गयी हैं उससे दो खराबियां हैं, मान्यवर, जेलें शहरी आबादी से दूर रखी जाती थीं ताकि कोई सामाजिक बुराई पैदा न हो सके। लेकिन अब जेलें शहरों के अन्दर आ गयी हैं,

बहुत कीमती जायदाद भी हैं, वह। यह अच्छी बात है कि अंग्रेजों के जमाने की हैं तो मिलावट थोड़ी कम थी, कैदी तोड़ कर भाग नहीं पाते हैं और यह अच्छी बात है कि आधे रक्षक होने के बावजूद भी यह हमारे कैदियों का सीधापन है और शराफत है कि आपके कन्ट्रोल में हैं, भागेंगे नहीं। लेकिन एक बड़ी समस्या यह आ रही है कि जहां जेलें बन रही हैं, वहां किसी न किसी कारण से लोग स्टे ले आते हैं, कोर्ट से और उससे दोहरा नुकसान हो रहा है। सरकार का भी पैसा लग जाता है और जिसको आप काम करने के लिए देते हैं, उस ठेकेदार का पैसा भी रुक जाता है। इस तरह कई सौ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो अदालतों के स्थगनादेश की बुनियाद पर बर्बाद हो रहा है और जेलें बन नहीं पा रही हैं। आधे मन से अधिकारी रह रहे हैं, आधी जेल बन गयी, 60 परसेंट बन गयी, 70 परसेंट बन गयी और हाईकोर्ट से वह स्टे वैकेट नहीं करा पा रहे हैं। बहुत जरूरी हो गया है, मान्यवर, या तो कुछ ऐसा करिए कि आपकी मुलाकात चीफ जस्टिम साहब से हो। सरकार बहुत परेशान है, इसको लेकर और बहुत से ऐसे मामलात हैं, जिसमें हम यह उम्मीद नहीं करते हैं कि स्टे दिया जायेगा लेकिन उन चीजों में स्टे हो रहे हैं। अदालतों की नाराजगियां अगर सरकारों से होने लगेंगी तो यह लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक होगा। एक तरफ तो हम लोग कितनी आसानी से प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करते हैं, यह लोकतंत्र की खूबी है, जो देश का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन अगर हम कोई सही बात भी अदालत के बारे में कहें तो यकीनन कन्टेंम्ट होता है। अगर लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की तानाशाही नहीं चल सकती तो फिर किसी की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। इससे भी मुल्क कमजोर होगा और अगर जुडिशियल हैरासमेंट होगा तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। मेरे ख्याल से कोई ऐसा मौका जरूर निकालिए, आप कि हम जितने नेता हैं, सभी राजनैतिक दलों के, आपकी अध्यक्षता हो और एक चीफ जस्टिम महोदय से मुलाकात होनी चाहिए ताकि सरकार अपना पक्ष उनके सामने रखे, सरकार की कोई गलती है तो हम सरकार की ओर से माफी मांगे लेते हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हो रही हैं, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के विकास पर काफी असर पड़ रहा है, इस मामले में भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी के प्रमुख और हमारे माननीय नेता जी बहुत दफा लोगों के हितों के लिए जेल गए। उन्होंने मुझे बुलाकर कुछ बातें कहीं और श्री लोहिया जी जो बहुत बड़े सिद्धान्तवादी थे, जिनके सिद्धान्तों को समावादी पार्टी निर्वहन करती है, वह भी नैनी जेल और अन्य जेलों में रहे। मेरा सम्बन्ध जेल विभाग से है, मुझे खुशी है कि आज की मीटिंग में, सदन के इस इजलॉस में हमारे वरिष्ठ नेता, वह भी यहां हाजिर हैं, श्री शिवपाल सिंह जी, श्री आजम खॉ साहब, हसन साहब, सभी हैं। मैं कुछ बातें लिखकर लाया हूं। जब मैंने पहले बोला था तो मेरा जो तजुर्बा है, लोकसभा में जवाब देने का, राज्यसभा में जवाब देने का कि विरोधी दल से जितने शस्त्र छीन सको, छीन लो। (हंसी) तो मैंने जब पढ़ा कि जेलों में बन्दी बहुत हैं,

कैदी बहुत हैं, चिकित्सा है तो मैं आपसे शस्त्र ही छीन रहा था, आपको पता नहीं चला, मैंने छीन लिया। अब मैं आपको शस्त्रविहीन कर रहा हूं। देखना, अभी देखना, अभी आप, नम्बर–1–शस्त्रविहीन होंगे। श्री अध्यक्ष जी, पहली बात, मैं लिखकर लाया हूं, अभी नहीं लिखा है, पूरी तैयारी से आया हूं कि मैंने आज माननीय अखिलेश जी, जो हमारे मुख्य मंत्री जी हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक घोषणाएं करनी हैं। बहुत बढ़िया हैं, हमारे मुख्य मंत्री। 'खूबसूरत औरत वह होती है, जिसकी सौतन भी तारीफ करे।'

(हंसी गूंजी)

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह आपको कहीं आपके पड़ोसी ने तो नहीं बता दिया।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

हमारे मुख्य मंत्री जी की कुछ तो इमीजियेट सौतने हैं कुछ देश में हैं। प्रकाश सिंह बादल से लेकर नीतीश कुमार से लेकर ऊपर तक 29 के 29 अन्य मुख्यमंत्री और यहां बैठे सभी सज्जन सौतन तो नहीं, लेकिन तारीफ करते हैं। ऐक्टंने आपको सौतन नहीं कहा। लेकिन कभी–कभी भाषण में गर्मी खाकर आगर आपा खो जाते हैं। पहली घोषणा में आप ही के माध्यम से करता हूं। हे वाहे गुरू भगवान, हे हजरत मोहम्मद साहब, हे गुरू गोविन्द सिंह जी, हे कृष्ण महाराज मेरी यह बात जो में कह रहा हूं कि मेरे मुख्य मंत्री जी को तो ताकत दो और मेरी इस बात पर जो में छोटी–छोटी 15 घोषणायें करूंगा इन 15 घोषणाओं के लिए विपक्ष को आशीर्वाद दो। भगवन, सीधे न देना आपके माध्यम से, अदरवाइज काम बिगड़ जाएगा। लेकिन मुख्य मंत्री जी को सीधे। क्योंकि उनको आशीर्वाद ताकत मांगी है। पहली बात मैं शिवपाल जी, आजम खां साहब, हसन साहब और आप जो मालिक हैं हाउस के। मैं आपके माध्यम से पहली बात कहता हूं कि तीस मार्च के बाद मेरे मुख्य मंत्री जी की हिदायत के मुताबिक एक भी जेल में जाली नहीं रहेगी। (मेंजे थपथपायी गयीं।) मुझे बोल लेने दो मौर्या जी। मैं कबाड़खाने वालों को, कबाड़ियों को कहता हूं आइये मेरी जेलों की जाली ले जाइये। बेचकर किसी दुखियारे को मदद कर दें। हमारी जाली ले जाओ बेच दो। हम पैसे नहीं लेंगे। नम्बर–2, रुकिये। दूसरी घोषणा, 1895 का 121 वर्ष पुराना अंग्रेजों की लानत अंग्रेजों का मेंनुअल तीस सितम्बर तक बदल दिया जायेगा। तीसरा, माननीय अखिलेश जी की आज्ञा से प्रिय मुख्य मंत्री जी की आज्ञा से में घोषणा करता हूं कि 1895 से रोजाना मुलाकात दो घण्टे थी और हफ्ते में दो दिन। मैं एलान करता हूं कि 30 मार्च के बाद पहली अप्रैल से मुलाकात दो घण्टे की बजाय चार घण्टे होगी और पहले समय 11 से 01 था अब 11 से 03 होगा।

श्री मुख्तार अंसारी–

मुलाकात का समय आपने चार घण्टे कर दिया लेकिन मुलाकात 04 दिन भी तो कर दीजिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप चेयर को सम्बोधन करें। मेरी आपसे विनती है कि चार घण्टे मुलाकात होगी और चार दिन नहीं बल्कि दो दिन की बजाये तीन दिन होगी। दो दिन की बजाये एक दिन बढ़ा रहा हूं। चार कर देंगे, जब भर्ती कर लेंगे, मैं उस पर भी आता हूं। एक भी नाखून काटने योग्य शस्त्र आपके पास नहीं छोड़ा जायेगा, सब बातें कह लूंगा, अगली बात चार घण्टे मुलाकात होगी, जो मुलाकात करने आते हैं, वह दूर से आते हैं तीन–तीन सौ किमी0 से और उसमें हमारी माननीय महिलायें भी आती हैं। ये एक चिट्ठी मान्यवर मेरे पास है, यह कई पेज की है बहुत बड़ी चिट्ठी है, 22 वर्ष की एक बेटी ने लिखी है, मैं हाउस में खड़े होकर कहता हूं, मैं तो यह पढ़ नहीं सकता, तीन दफा रूमाल निकाल कर रोया था, 22 वर्ष की बेटी एक चिट्ठी लिखे, प्लीज हंसो मत, यह बच्ची की बेइज्जती है, 22 वर्ष की बेटी मान्यवर मैं आपके माध्यम से साथियों को बताता हूं, उसने क्या मेंहनत की है और मैं बताता हूं यह सब क्या करना चाहिए मैं बहुत कुछ इस चिट्ठी से सीख कर बोल रहा हूं, सिर्फ 22 वर्ष की बेटी है, मैंने लिख दिया उसको चिट्ठी के जवाब मैं बेटा पूजा, उसने इसी पर लिखा है कि शुक्र है एक शासन अखिलेश जी का भी आया जो दुःखी बंदियों की बेटियों को बेटा कह कर सम्बोधन करते हैं, इसका भी जिक्र किया है। मेरे मुख्य मंत्री जी, मेरे नेता मुलायम जी सहर्ष ही, जिसको कट्सी कहते हैं इंग्लिस मैं उसको कैरीऑन करते हैं, अपहोल्ड करते हैं। अब मैं क्या लिख रहा हूं, इस बेटी का भी मैंने जिक्र कर दिया, अब देखना क्या है, मुलाकात इतनी होगी, जाली खत्म होगी और 2149 मौर्या जी आपने कहा कि अन्धा आदमी है, में होमवर्क कर के आया हूं थैंक्यू आपने भी कहा, 1273 साठ वर्ष से सत्तर वर्ष के कैदी हैं, सत्तर से अस्सी वर्ष के 667 हैं, अस्सी से ऊपर 186 हैं, कुल 2149 हैं, मैं आपके माध्यम से यकींन दिलाता हूं कि 30 जुलाई तक यह सभी बाहर चले जायेंगे, यह लागू होंगे, मैंने वह सुप्रीम कोर्ट वाला भी निकाल लिया है, 161 वाला भी निकाल लिया है, ए–फार्म भी स्टडी कर लिया है, मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, एक कमीशन में पांच साल में जज रहा हूं, मुझे पता है, मेरे नेता कैसे हैं, मेरे नेता मेरी कलम पकड़ते ही नहीं, लिखते जाओ, रोकते नहीं, मुझे गर्व है मेरे नेता पर। आगे देखिये ये निकल जायेंगे, मुलाकातें ई–नेटवर्क से इकसित हजार मुलाकात हो चुकी है, यदि नेट पर आप मुलाकात का टाईम फिक्स करते हैं तो मुलाकात हो जाती है, इसको भी बढ़ावा दिया जायेगा। अब रहा पी0सी0ओ0, इसके लिए जो आपने बात कही बी0एस0एन0एल0 आपके माध्यम से इन्होंने कहा मुझे बी0एस0एन0एल0 को ही देंगे, इसका कारण है कि 40 लाख रुपये में एक कम्पनी काम देती है कि 40 लाख में काम ले लो, मेंने कहा हम नहीं लेंगे, क्योंकि 40 लाख में काम करते हो, आप छल्ली भून कर देने की बात तो कह रहे हो, लेकिन आपके पास तो कोयला ही नहीं है, भूनोगे कैसे। जो कम्पनी मुझसे कह रही है 40 लाख में काम ले लो, मैंने कहा अपने घर रखो, मैं गवर्नमेण्ट को दूंगा, बी0एस0एन0एल0 चूंकि तारो का सिलसिला और सिलसिला सारा उनके पास है, छोटी कम्पनी के पास नहीं, मेरी तो जेल एक लखनऊ में 25 किमी0 दूर है, वहां हम सिवाय बी0एस0एन0एल0 के कैसे करेंगे। तो पी0सी0ओ0 लग जाएंगे और

लागवी तौर पर अक्टूबर तक ए टू जेड लग जाएंगे। दो–दो फोन होंगे एक दिन में पांच मिनट, दूसरे दिन पांच मिनट तक बंदी घर बात कर सकेगा लेकिन हम आपके सामने तस्लीम करते हैं कि हम रिकार्डिंग करेंगे ताकि कोई ऐसी बात न हो जाये। जो महाबली कहलाते हैं उनकी भी बात रिकार्ड हो। मैंने कहा आपको, आप तो हॅस पड़े, मैंने तो खुद आपको हथियार दिया था, चूंकि मेरे पास हथियार छीनने का मंत्र था। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज 52,572 बंदी रखने की क्षमता मेरे पास है। लेकिन 79,843 बंदी हैं, तो यह तो नर्क है। मुझे खुशी तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने रामूवालिया को वह विभाग दिया जो श्री कृष्ण महाराज की जन्मस्थली है, उनका जन्म तो यहां ही हुआ। उसके बाद ही अर्जुन और युधिष्ठिर या जो कुछ भी हुआ। मैं विनती कर रहा था कि अब देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं तैयारी करके आया हूं, खाली हाथ नहीं क्योंकि आपके सामने मेरी पेशी है। इसलिए आया हूं 12,980 बंदियों के लिए 9 जेलें और इसी साल मुकम्मल हो जाएंगी। 12,980 बंदियों की जगह और बन जायेगी। 4,500 बंदी रखने की जगह और ललितपुर में मिल जायेगी। बीजेपी वाले सज्जनों खुश हो, जब अयोध्या की बात हुई थी तो आडवाणी जी ललितपुर में ही भाग्यशाली थे। वहां बंद थे। मैंने ललितपुर को चुना है।

(सदन में हंसी)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

अब थोड़ी सी ताली बजा दें। माननीय अध्यक्ष जी, असल में मेरे सज्जन लांछन लगाने के शौकीन हैं आजम खां जी कहते रहते हैं। बीजेपी वाले लांछन लगा देते हैं वैसे जैसे आंवले के बगैर अनाज हजम नहीं होता। इन भाईयों को कभी–कभी ऐसा है, हमेशा नहीं कभी–कभी लेकिन इसलिए जब यह चाहे प्रश्नकाल के बाद आधा घण्टा लांछन काल का रख लिया करें।

(सदन में हंसी)

श्री अध्यक्ष–

शांत रह कर सुनिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनती कर रहा था कि 52,572 की मेरी क्षमता है एक, 12,980 क्षमता नौ जेल से बन जाएंगी। 4,500 ललितपुर वाली जेल में और आ जाएंगे, और 30 जून तक आखिर 30 जुलाई, 2,149, 70 साल वाले अंधे, बीमार, लंग्स खराब वाले सबको मिलाकर और यह छोड़ देंगे तो मेरे पास 52,572 से बढ़कर 70 हजार 52, अब देख लीजिए कितना फर्क पड़ गया। इसका श्रेय श्री अखिलेश जी को जाना चाहिए, मेरी समाजवादी पार्टी को जाना चाहिए। अगली बात मैं 14 बरस सुप्रीमकोर्ट कहती है कि 'मिनिमम टेनयोर द बंदी मस्ट हेव सर्वड विदहिन द जेल' का कर लिया है। पूरी हिन्दी मुझे नहीं आती। जो 14 से ऊपर माफी की मियाद है, वह मियाद डालकर अगर 14 मिनिमम है, ऊपर ज्यादा है, तो ऐसा प्रावधान, मैं कल दिल्ली जाऊंगा क्योंकि मेरी पत्नी

का आपरेशन है, तो उसके बाद मैं जाकर बड़े–बड़े लीगल एडवाइजर्स से सलाह लूंगा। हमारे इस हाउस में भी मैं इशारा नहीं करना चाहता, एक बहुत बड़े लीगल ज्यूडिशियरी से आए सज्जन बैठे हैं, तो वह अधिकारी है इसलिए मैं कहता हूं, सभी से मशवरा लेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन यह छोड़ेंगे नहीं। जब 14 साल की बात आपने कह दी या तो न्यायालय अपनी बात से मुकर जाए।.....

मैंने लफ्ज सख्त कह दिया है कि या तो पीछे हट जाएं वरना हम छोड़ेंगे। एक नई बात कर रहा हूं, यह पैरोल की बात मैं बिल्कुल कन्फेस करता हूं, अभी मुख्य मंत्री जी को कहा नहीं है। एस0एस0पी0, डी0एस0पी0, दरोगा, सी0ओ0 फलां–फलां आखिरी एक सिपाही, एक सिपाही जाता है, जाकर कहता है कि रुपया 40 हजार लगेगा। एक तो 40 हजार मिल गया तो पैरोल दे दो इसके आने से द्रौपदी का यज्ञ हो जाएगा। अगर नहीं तो कहता अगर आ गया तो महाभारत हो जाएगी इसलिए मैंने इसका रास्ता निकाला कि रैण्डम चेकअप होगा, वह भी डी0जी0 ऑफिस से, नीच तो कर नहीं सकता। आई ऐम गोइंग टू मीट माई ऑनरेबिल होम मिनिस्टर ऐण्ड हमारे मुख्य मंत्री जी। गृह सचिव, प्रमुख सचिव गृह, डी0जी0 उनको तो बुलाऊंगा, इनको मिलूंगा। अगर 15 रिपोर्ट आईं, 15 ही अगेन्स्ट इनमें से 3 देख ली जाएं रैण्डमली, अगर सिपाही की एस0एस0पी0 गलती निकाले तो उसकी ए0सी0आर0 में रिकार्ड कर दिया जाए कि बगैर देखे, आंख मूंदकर इसने दस्तखत किए फिर पता चलेगा कि प्रमोशन कैसे रुकता है। मैं विनती कर रहा हूं ये भी मेरे दिमाग में है। मैंने फिर कहा भगवन, मान्यवर, अध्यक्ष जी की कृपा से आपको आशीर्वाद मिले। मेरी ये बात परवान कर दे, मैं कर दूँगा। आगे देखिए ये देखिए मैंने ऑर्डर किए हैं। मैं ये भी लेकर आया हूं। हर महीने पहली बात तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अंसारी जी को कहता हूं कि जितने आदमी बन्दी हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, एक जादू सिंह, क्या नाम है यादव हैं वह, वह 105 बरस के हैं जेल ऐक्ट हैं। एक 1966 से जेल में है, माफ करना आपको तो पता नहीं है, मैं ही आपको बता रहा हूं ताकि आप अटैक करें लेकिन मैं बात करता हूं, सुनिये, 1966 से जेल में है, ये सब जाऍंगे हुजूर 30 जुलाई तक। अब जो मैं आपको बात कह रहा हूं कि ये मैं ले आया हूं ऑर्डर। आज तक ये ऑर्डर नहीं हुआ। एक सदस्य द्वारा उस दिन मेरे कान में, मुंह में एक बात पाने की कोशिश की गई कि मैंने आपके पूर्वज जेल मंत्रियों को कहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से हाथ खड़े करके कहता हूं कि मेरे पूर्वज जेल मंत्री बहुत बुद्धिमान, प्रबुद्ध और ज्ञानवान लोग थे उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं उनके पैरों पर चल रहा हूं इसलिए मैं विनती कर रहा हूं कि ये जो मेरे पास आया है ये देखिए, मैं वक्त नहीं लूंगा। मैंने इसमें साफ कर दिया है और बुरा न मानना, कल का ऑर्डर है 4 मार्च का, आप पढ़ भी लेना। 4 मार्च का मैंने कल ऑर्डर जारी किया है। क्या जारी किया है कि हर महीने सेकेण्ड सैटर डे को पहली बात तो यह कि जितने ये 80 बरस के, 70 बरस के, 60 बरस के हैं ये अपने जनपद की जेलों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अपने जिलों में चले जाएंगे, जहां के ये रहने वाले हैं। पहली बार देखना कि मेरे मुख्य मंत्री जी ने मुझे क्या हिदायतें दी हैं। ये अपनी जेलों में जाएंगे और

वहां का डी0एम0 और एस0एस0पी0 बाई ऑर्डर, बाहुकुम सेकेण्ड सैटर डे वे जाएंगे, जेल में जाकर आंखों से देखेंगे कि ये बंदी 60 साल का है, ये महिला 60 साल की है, ये 70 और ये 80। नम्बर टू, पहली मीटिंग में मैंने हुकुम दे दिया है मा0 मुख्य मंत्री जी की जो ताकत मुझे बख्शी गई है कि 26 मार्च को हर डी0एम0, हर एस0एस0पी0 जेल जाएगा और 26 मार्च तक ये सभी बंदी अपने घरों की जेलों को जाएंगे। पहली कार्यवाही वाहे गुरू, भगवान का नाम लेकर ये शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अंसारी जी से कहता हूं कि आपने तो 20 किलोग्राम मांगा था इधर कुण्टल आ रहा है। आगे देखिए हां मांगा जरूर आपने। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि आर्थिक दण्ड में 399 लोगों को छोड़ा गया हैं यह मैंने ही शुरू किया है। इसी साल छोड़े गए हैं, अभी इस 4–5 महीने में छोड़े गए है। वह कैसे छोड़े हैं वह पैसे नहीं देने की वजह से, फोन चुरा लिया या टिकट नहीं दिया, छोटी–छोटी बातों में उनको सजा हुई दो महीने और जुर्माना हो गया 25 हजार का, 30 हजार का।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहने की जुर्रत करता हूं कि एक बेचारी नेपाल की महिला साढ़े तीन वर्ष जेल इस बात में काट गई थी, क्योंकि उसको 55 हजार या शायद एक लाख का जुर्माना हुआ था और जुर्माना की रकम उसके पास नहीं थी, मैंने हिन्दू भाइयों को विशेषकर मुसलमान भाइयों को, सिखों को तो चलो मैंने जोर से भी कह दिया और सिन्धियों को कहकर पैसे लिये क्योंकि सरकार अपराधी की पेमेंण्ट नहीं कर सकती ''नो गर्वनमेण्ट पे फॉर एक क्रिमिनल'' इसलिए मैंने रास्ता निकाला पैसे निकालकर आप शाबासी देंगे कि ऐसे 400 व्यक्ति निकल गए हैं और इस साल अंत तक मेरे दिमाग में गुरू गोविन्द सिंह जी का साढ़े तीन सौवां जन्मोत्सव आ रहा है। इसी दो–चार महीने के आखिर तक 4000 से ज्यादा ऐसे जो लोग हैं ये भी छोड़ दिये जाएंगे और यह भी बंदियों की गिनती हो जायगी। आगे अभी पेयजल की बात की गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अंसारी जी से पूछता हूं कि अंसारी जी अगर कोई ठोस बात आपके सामने हैं, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है तो लिखकर दे जाना। आप अपने 19 प्वाइंट भी दे जाना। ये यहां रखे जाना क्योंकि कई दफा दोस्तों की बुरी बातें बाद में थोड़ा–सा शहद जैसी लगती हैं, हमेशा तो नहीं, इसलिए मैं विनती कर रहा हूं कि हो जायेगा। नया जेल मैन्युअल आ जायेगा। एक और बात मैंने कह दिया है कि हम समय निर्धारित करेंगे कि इतने दिन में एस0एस0पी0, डी0एम0 साहब या तो पैरोल की रिपोर्ट भेजें अगर आप सांप की तरह ऊपर बैठे रहेंगे शेषनाग की तरह कागजों के ऊपर फिर 31 दिन के बाद मैं सोच रहा हूं कि फिर हम कहेंगे कि आप कागजों का रखो ''वी विल कन्सीडर इट एज डीम्ड एन0ओ0सी0'' इसका मतलब है कि तुम्हें कोई ऐतराज ही नहीं है। अगर आप भेजते ही नहीं है तो ऐतराज भी कोई नहीं है। इसलिए यह भी हम करने वाले हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी के आर्शीवाद से जरूर करेंगे, बेखौफ होकर करेंगे। अगर फिर भी लड़ाई हो जायेगी डी0एम0, एस0एस0पी0 जिम्मेदार हो जाएंगे कि आपने क्यों नहीं रिपोर्ट भेजी, अगर गलत भेजी वह भी दोषी और अगर नहीं भेजी फिर भी श्रीमान्, नहीं रहेंगे। आगे की बात मैं

कहता हूं, चिकित्सा की बात। किसी ने भी इसके बारे में नहीं कहा, मुझे उम्मीद थी अन्सारी जी बहुत मेहनत करके आये हैं। आप भी यह बात कहना भूल गए परन्तु मैं कहता हूं कि चिकित्सकों की कमी है, 3500 बंदी रक्षकों की कमी है। आजम खां जी ने बहुत जोर से मेरा प्रोत्साहन किया। मैं जब कैबिनेट मीटिंग से निकला अभी आठ दिन हुए। मैं निकल रहा था, मैंने ऐसे ही मुख्य मंत्री से कह दिया नमस्कार जी, मैं थोड़े से बंदीरक्षक भर्ती कर लूं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कहा मैं थोड़े से बंदी भर्ती कर लूं। बंदी रक्षक भर्ती कर लूं, मैंने कहा ना हिन्दी पर अभी रियाज नहीं है तो वे बोले कितने कम हैं। मैंने कहा जी रिक्शेवाला यदि एक रुपया मांगे और देने वाला पचास पैसे दे तो वह सवारी को वह एलाउ नहीं करता, अपने घर रख दे कहता है। मेरी हालत यह है कि 7000 बंदी रक्षक चाहिए और मेरे पास 3500 हैं। वाहे गुरू की कसम एकदम से खड़े हो गए ये क्या, अभी भर्ती करो। मैंने कहा जी एक नई फंसा दी है बीच मैं, साइकिल के तारों में डण्डा फंसा दिया है। नई प्रणाली तो मान्यवर, ने हुक्म दिया मेरे मुख्यमंत्री ने कि पिछली प्रणाली से कर लो, तो अब हो रहा है। अब मैं करूंगा और आप देखेंगे कि वह भर्ती भी कैसे होती है। बस आखिर में मैं खत्म करता हूं। भर्ती हो जायेगी अब चिकित्सकों का अकाल पड़ा हुआ है देश में भी है और जेल में भी है। मेरी जेल में चिकित्सक नहीं है उसके लिए तो मैं परमिशन मांग रहा हूं कैबिनेट से पूछना पड़ेगा कि रिटायर हुए कुछ व्यक्ति 70 साल तक ले लिये जायें। मैं खुद एम0सी0आई0 जाकर आया हूं, मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया से चेयर पर्सन से पूछ कर आया हूं कि क्या हम 70 साल की उम्र तक चिकित्सक को रख सकते हैं उन्होंने कहा, मैंने तो 67 साल तक कहा था उन्होंने कहा आप चाहे 70 तक रख सकते हैं लेकिन जो वेतनमान है उसमैं थोड़ी कमी करनी होगी। मीनव्हाइल मैंने एक इलाज निकाला है, मैंने प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, हैल्थ प्रिन्सिपल सेक्रेट्री साहब से बिनती की, मिनिस्टर साहब तो माननीय मुख्य मंत्री जी हैं मैंने कहा ऐसा करो एक इलाज है 67 जेल हैं जनपद 75 हैं आप जनपद से सिर्फ 2 डाक्टर एक हफ्ते ऐक्ट मेरी एक जेल में भेज दिया करो तो चार हफ्ते मैं 8 डाक्टर आ गये तो महीने में में 08 डाक्टरों की सेवा जेलों में लेने का एक साधन बनाया है, वह भी मैं कर रहा हूं। आखिर ऐक्ट नाई की बात कही है, ऐक्ट तो सिख हूं नाई की बात ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि हम तो करते नहीं लेकिन सरकारी जिम्मेदारी ऐक्ट नाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, सरकारी जिम्मेदारी है। मैं तो केन्द्र में फूड मिनिस्टर था मुझे एक अजीब सी बात कही गयी चलो अकेले में बतायेंगे। जो भर्ती करेंगे कोशिश करेंगे नाई उसमैं हो जाये। हम सिक्खों में नाई नहीं कहते बहुत अपमान शब्द है इसको कहते हैं राजा सिक्ख तो राजा सिक्ख भी भर्ती कर लेंगे सिक्ख मैं लफ्ज काटता हूं राजा भी भर्ती कर लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

राजा भैय्या से भी पूछ लिया है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया–

वो समाज के राजा है यह तो देश के राजा हैं, मैं आखिर में विनती करता हूं आखिर ऐक्ट मेरी बात यह है कि 4306 पिछले तीन महीने में जब से मैं आया हूं नई ट्वायलेट्स बनाई गयी हैं। अब आखिर में एक वर्ल्ड में रोको कैन्सर इन्स्टीट्यूशन है, बहुत बड़ी है इंग्लैण्ड ऐक्ट। एन0आर0आई0 पंजाबी बहुत हैं, सिक्ख बहुत हैं श्री अध्यक्ष जी वहां इन्सीडेन्टली रोको कैन्सर वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रान्च लन्दन में शुरू होती है उसके अध्यक्ष एक सरदार जी हैं सरदार कुलवन्त सिंह धारीवाल। मैंने उनसे बात की मैंने कहां कि यार सड्डे जेला विच कैन्सर दी प्राब्लम है, जे तू मदद कर देंगे तो मेरी बात अच्छी हो जायेगी वह मान गया कि रोको कैन्सर के जरिये उसने एक नारा दिया है, नारा थोड़ा सा मुश्किल भरा है, वह कह रहा है कि दुनिया भर के सिक्खों को समझाना चाहता हूं कि रोटी का लंगर लाओ, दाल का लंगर लाओ लेकिन केले जलेबियां और चीजों का लंगर मत लाओ, दवाई का लंगर लाओ। ही इज ए फलैग बिअरर। मुझे उसने कहा है कि मैं पांच जेलों मैं 31 दिसम्बर तक फ्री रोको कैन्सर लाऊंगा और दवाई भी फ्री दूंगा। मैंने इतने स्टेप उठायें बहुत धन्यवाद आपने मेरी निजी मुसीबत को गौर करके मेरा बजट पहले ला दिया उसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री नीरज कुशवाहा मौर्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी अच्छी अच्छी घोषणाएं की हैं मैं आशा करता हूं कि यह पूरी भी होंगी लेकिन कुछ बिन्दुओं पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया एक कम्बल की बात मैंने रखी थी और महिला बन्दियों के बारे में आपने कुछ नहीं दिया इस पर भी विचार करेंगे। कम्बल के बारे में जरूर विचार कर लें यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं उम्मीद करता हूं माननीय मंत्री जी जो बाते छूटी हैं उन पर गौर करके आगे इसका ध्यान रखेंगे।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

मान्यवर, हम महिला बन्दियों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं 428 बच्चे हैं जेलों में उनकी पढ़ाई का बन्दोबस्त कर रहे हैं, यह छूट गया था। दूसरा जो हैं उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहता मान्यवर, से पूछकर।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25–गृह अनुभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12,56,88,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख्अ०36, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम एवं सेवा योजन मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,11,73,70,000 रुपये से रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम एवं सेवा योजन मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग(सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 83,28,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कटमोशन रख दे तो इसको पास करा दें।

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अधिष्ठाता महोदय, सरकार की जितनी भी नीतियां श्रमिकों के लिए बनी हैं वह ज्यादातर संगठित मजदूरों और श्रमिकों के लिए हैं। असंगठित श्रमिकों के लिए सरकार के पास कोई कारगर उपाय या कारगर नीति नहीं बनी है। संगठित मजदूरों से कई गुना ज्यादा असंगठित मजदूरों की संख्या है। संगठित मजदूरों के हित की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुए हैं। मण्डल स्तर पर और जिला स्तर पर उनके अधीन बहुत सारे अधिकारी भी नियुक्त हैं। सरकार के पास 50 से 60 की संख्या में बहुत सारी योजनायें भी उनके हित के लिए प्रस्तावित हैं और लागू हैं । मगर आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी योजनायें हैं इससे श्रमिक समाज को न तो कोई फायदा मिला है और न ही श्रमिक समाज से जुड़े परिवार को और उनके बच्चों को ही कोई फायदा मिल पाया है। श्रमिक समाज को आज तक दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य, उनके बच्चों के लिए परवरिश,

उनके बच्चों के लिए तालीम, उनके बच्चों के लिए रोजगार इसका कोई उपाय नहीं किया गया है। असंगठित मजदूर को तो भगवान के ही भरोसे छोड़ दिया है, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है। सरकार के पास उनके लिए कोई कारगर नीति नहीं है। असंगठित मजदूर के अन्तर्गत ज्यादातर बुनकर हैं, धुनकर हैं और दस्तकार, बीड़ी मजदूर, जरी बनाने वाले, कालीन बनाने वाले, तांबे के बर्तन बनाने वाले मजदूर हैं, मगर अभी तक उनकी जीविका के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कोई उपाय नहीं सुझाये हैं। अगर हम सिर्फ मुरादाबाद का जिक्र करें तो पचास हजार से ज्यादा जो कारीगर हैं तांबे के बर्तन बनाने वाले वो पहले कारीगर थे, जिनको सरकारी सहायता लोन की शक्ल में दी गई थी, मगर सरकार की नीतियों की वजह से उनका काम लाभप्रद न होने की वजह से वह लोन चुकता नहीं कर पाये और उन सभी के खिलाफ वसूली के मुकदमें चल रहे हैं, वसूली हो रही है, उनके घर को नीलाम किया जा रहा है, ऐसे में वह सब अपने घरों को छोड़ करके भागे–भागे फिर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरीके से और सारे विभागों मैं किसान भाईयों के कर्जे माफ हुये हैं, उसी तरीके से इन सभी दस्तकारों को जो तांबे के बर्तन बनाने में लगे हुये हैं, मुरादाबाद हुआ, चाहे प्रदेश के अन्य जिलों में हुआ है, उनका जो कर्ज है वह माफ किया जाये। चूंकि यह सारे के सारे काम धन्धे बिजली से आधारित हैं इसलिये उनको किसानों के तरीके से ही सस्ती दर पर बिजली दी जाये ताकि उनका रोजगार लाभप्रद हो और उनकी जीविका चले। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से समाज का जो अति पिछड़ा वर्ग है और जो अति दलित वर्ग है, वह भी बहुत कमजोर वर्ग है, जो छोटे–छोटे उद्योग धन्धे करते हैं, जो बिल्कुल मजदूर की तरह से रहते हैं, चाहे वह मछली मारने वाला मछुआ समाज हो, चाहे वह कुम्हार समाज हो जो अपनी मजदूरी करता है, चाहे भूजा भूजने वाला गौड समाज हो, इसी तरीके से जो बहुसंख्यक समाज का अति पिछड़ा हिन्दू वर्ग है, वो भी मजदूरों की शक्ल में रहता है, बुनाई करने वाले जो बुनकर हैं, बुनाई से उनका पूरा परिवार पचास से सत्तर हजार रुपया ही कमा पाता है। सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि उसके काम का लाभप्रद मूल्य मिल सके और जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, जो अपना काम करते हैं उनके लिए कोई नीति नहीं है कि जिससे उनको लाभप्रद मूल्य मिल सके। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज का जो कमजोर वर्ग है, शिक्षा में, सामाजिक हैसियत में और माली हालत में जो भी समाज का कमजोर वर्ग है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको तरक्की देने के लिए संविधान में व्यवस्था दी है गई, आरक्षण दिया गया है। मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देता हूं कि जो मजदूर है, जो असंगठित मजदूर है जो संगठित मजदूर है इन दोनों प्रकार के मजदूरों के बच्चों के विकास के लिये बढ़िया अच्छे स्कूलों में आरक्षण की व्यवस्था की जाय और जितनी भी नौकरियां प्रदेश सरकार की हैं उनमें आरक्षण की व्यवस्था की जाय क्योंकि इनके पास न तो संसाधन है और न ही अपने बच्चों को पढ़ाने का कोई संसाधन है। जो सेवायोजन कार्यालय उत्तर प्रदेश में हर जिले में हैं इसमें युवाओं का नौकरी के लिये रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार को

यह सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि यह सबसे कमजोर समाज है यह मजदूर है इसलिये सेवायोजन में पिछड़े वर्ग के लिये, मुसलमानों के लिये और अति पिछड़े दलित वर्ग के लिये, जो बुनकर समाज है इनके लिये सेवायोजन में आरक्षण की व्यवस्था हो। क्योंकि जो बड़ा आदमी होगा वह संगठित या असंगठित मजदूर नहीं बनेगा, इसलिये हर जगह तो फर्जीवाड़ा हो सकता है लेकिन इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। तो आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि देश का आजीविका का, सबसे कमजोरों का सबसे बड़ा वर्ग है और सेवायोजन विभाग जो उनको रोजगार देता है, जो इस समाज का काम है इसलिये इस समाज के लिये कम से कम 50 प्रतिशत का आरक्षण सेवायोजन में हो ताकि इन गरीबों के बच्चे जो आश्रित हैं, इनको सहायता हो सके और उनको भी आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद।

श्री शाहिद मंजूर–

माननीय अधिष्ठाता जी, डा0 साहब ने कटमोशन रखा और कटमोशन के नाम पर कुछ सुझाव दिये हैं। ऐक्ट इन सुझावों पर ही बात करना चाहता हूं। डा0 साहब को बहुत चिन्ता है गरीबों की, पिछडों की, दलितों की और अल्पसंख्यकों की। शायद डा0 साहब को यह मालूम नहीं, कि जिस पृष्ठभूमि से मैं आया हूं बचपन से लेकर अब तक गरीबों के लिये, पिछड़ों के लिये, दलितों के लिये और समाज के उन उपेक्षित वर्गों के लिये ही सोचा है और काम किया है, जिनकी ओर डा0 साहब इशारा कर रहे थे। पढ़ाई के समय में हिन्दी में एक कविता पढ़ी थी जिसकी लाइन है 'श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक–बिदुर जाड़े की रात बिताते हैं। स्त्री की लज्जा बस वस्त्र बेंच कर ब्याज चुकाये जाते हैं मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। मैं इन्हीं पंक्तियों के आधार पर पालिटिक्स करता हूं, राजनीति करता हूं और सौभाग्यशाली हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय नेताजी ने अगर किसी विभाग की जिम्मेदारी दी है तो वह श्रम विभाग है और मेरी मर्जी का विभाग है जिस विभाग में कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूं और पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है कि जब से विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, श्रम विभाग ने हजारों–हजारों की तादाद में और लाखों–लाखों की तादाद में मजदूरों को सहायता देने का काम किया है चाहे उनको साइकिल दी हो, चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की हो। एक बात और डा0 साहब के संज्ञान में लाना चाहता हूं इसलिये डा0 साहब ने जो इशारा किया, उन्हीं को इंगित करके यह बात कह रहा हूं कि पैदा होने से लेकर और मरने तक उन गरीब मजदूरों के लिये अगर कोई योजना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चला रहा है तो वह श्रम विभाग चला रहा है। अगर डा0 साहब को इसकी जानकारी नहीं है तो श्रम विभाग से जानकारी ले लें और जिनके लिये वह चिन्तित हैं उनका वह रजिस्ट्रेशन करायें और एक से लेकर आखिर तक किसी भी तरीके की न पैसे की कमी है और न योजनाओं की कमी है। पैदा होने से लेकर मरने तक गरीबों के हितों की श्रम विभाग रक्षा

कर रहा है। डॉक्टर साहब ने एक सुझाव दिया बच्चों की पढ़ाई के लिए, मैं उनके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में अपने संसाधनों से 24 स्कूल जिसमें 100–100 बच्चे निःशुल्क डे–स्कॉलर की तर्ज पर रह रहे हैं और उनके खाने,पीने, कपड़े व दवाई का कम्पलीट खर्चा श्रम विभाग अपने संसाधनों से उठा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकों तथा जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उन सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करायें। जो 40 कैटेगरी के मजदूर हैं उनका जो भी रजिस्ट्रेशन करायेगा तो उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर आखिर तक की जिम्मैंदारी श्रम विभाग, बी0ओ0सी0 बोर्ड उसको उठाने की कोशिश कर रहा है और उसको उठा रहा है।

मैं आपके संज्ञान में श्रम विभाग की एक और बात लाना चाहता हूं कि जबसे हमने काम संभाला है 02 लाख रजिस्ट्रेशन थे। यह नियम और कानून पुराना नहीं है। आज की तारीख में तकरीबन 25 लाख बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग करा चुका है। हम श्रमिकों के लिए एक नहीं अनेकों लाभकारी योजनायें चला रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करायें, अगर अपने इलाके में इन योजनाओं का लाभ देने के लिए जब तवज्जो नहीं देंगे, जब तवज्जो नहीं दी जायेगी तब फिर ऐसी अज्ञानता की बात होगी। मैं तो नहीं कहता कि डॉक्टर साहब जैसे काबिल आदमी उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं। मैं इस सदन को और डॉक्टर साहब को यकीन दिलाता हूं कि श्रम विभाग उन तमाम मजदूरों के बारे में, उन तमाम उपेक्षित लोगों के बारे में, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था श्रम विभाग उन सबके विषय में कुछ न कुछ योजना चला रहा है और लाखों–लाख की तादाद में उन लोगों को फायदा पहुॅचाने की बात कर रहा है। डॉक्टर साहब से मैं आग्रह करूंगा कि जब काम अच्छा हो तो हर किसी बात पर विरोध नहीं करना चाहिए। अगर विभाग ठीक काम कर रहा है माननीय अध्यक्ष जी, तकरीबन 5 लाख साइकिल हम लोग पिछले वर्षों में बांट चुके हैं। समस्या यह थी कि गरीब के पास न साइकिल थी, मजदूरी पर जाने के लिए कहीं किराये पर लेनी पड़ती थी या कोई और व्यवस्था करनी पड़ती थी लेकिन इस विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद में उन्हें साइकिल दी गयी और वो साइकिल जो क्वालिटी में सबसे बेहतर साइकिल है चाहे एटलस हो या हरक्युलिस या दूसरी साइकिलें हों, मजदूरों को वह साइकिल हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। जहां तक स्वास्थ्य का मसला है, डा0 साहब खुद डाक्टर हैं यहां पर जितने डॉक्टर हैं कोई समाजसेवी नहीं है चाहे हमारे मित्र अग्रवाल साहब आगे बैठे हों, पैसे लेकर ही इलाज करते हैं लेकिन श्रम विभाग अपने मजदूरों के बच्चों और मजदूरों के लिए कैशलेश इलाज की व्यवस्था की है जो पहले ई0एस0आई0 में था उसी सिस्टम को हम लागू कर रहे हैं उसी के हिसाब से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान मैं लाना चाहता हूं कि जिन मजदूरों की उम्र 60 साल हो गयी है और उनका पंजीयन 03 वर्ष का है उनको श्रम विभाग 1000 रुपये महीने की पेंशन, इसी महीने से देने जा रहे हैं उसकी हमारी तैयारी पूरी हो गयी है। मैं अपने तमाम साथियों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि

अपने इलाके में रहने वाले तमाम मजदूरों का पंजीयन करायें जो उस कैटेगरी में आते हों और उन तमाम योजनाओं का लाभ उठायें। आखिर में मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि वह अपने कटमोशन को वापस ले लें और अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसमें हमारा सहयोग करें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

डॉक्टर साहब कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी की भावनाओं का मैं कद्र करता हूं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मजदूरों का उत्थान वह दिल से चाहते हैं। उनकी नीयत पर कोई संदेह नहीं है मगर 15 प्वाइंट प्रोग्राम 10 साल तक कॉग्रेस सरकार ने मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए चलाया।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप जब बात करते हो तो यही बात करते हो, मुसलमानों की बात कहां से आ गयी।

डा0 मो0 अय्यूब–

अध्यक्ष जी, में सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह सारा जब श्रम विभाग है तो जातियों में बांटने की क्यों बात कर रहे हैं।

डा0 मो0 अय्यूब–

अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। 15 प्वाइंट प्रोग्राम 10 साल तक चलाया केन्द्र सरकार ने और 20 परसेन्ट मात्रांकित इस प्रदेश सरकार ने किया है मुसलमानों के लिये विकास में।

श्री अध्यक्ष–

आप लेबर पर बोल रहे थे यह कहां आ गये।

डा0 मो0 अय्यूब–

मैं उसी पर आ रहा हूं अपने सब्जेक्ट पर। मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं इस माध्यम से कि 20 परसेन्ट मात्रांकित करने के बाद 2017 में यह प्रोग्राम चलाने के बाद। 2007 में सच्चर कमीशन ने यह कहा कि मुसलमान दलित से भी बदतर हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

लेबर पर बोलिये ना। चलिये रहने दीजिये। अब कुछ नहीं। मैं प्रश्न कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,11,73,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 83,28,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

शिक्षा में कई प्रकार की शिक्षा है और यह आप माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों रखेंगे ?

श्री बलराम यादव–

पहले व्यावसायिक ले लें। मैं पढ़ देता हूं मिश्रा जी उस पर बल दे देंगे।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69–व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,12,60,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कटौती रख दें।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–69–व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)–

माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट मैं अपनी बात रख दूं। आज व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मिशन के माध्यम से समाजवादी सरकार ने यह प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश का जो नौजवान जो बच्चे बच्चियां हमारे टेंथ के बाद, ट्वेल्थ के बाद वोकेशनल एजूकेशन के रास्ते पर जा रहे वो और जो ड्राप आउट्स थे 14 से 35 साल की उम्र के बीच में स्किल्ड डेवलेपमेंट मिशन के माध्यम से उन सारे नौजवानों को एक सशक्त माध्यम से एक ट्रेनिंग के प्रोग्राम से जोड़ करके उनको ट्रेंड किया जाय जिससे उनको सीधे इम्प्लाइमेंट से जोड़ा जा सके। आज की तारीख में मुझे कहते हुए खुशी है कि हिन्दुस्तान का सबसे मजबूत, सबसे अच्छा और सबसे बड़ा स्किल्ड डेवलेपमेंट और आई0टी0आई0 का एज्यूकेशन में प्रोग्राम उत्तर प्रदेश चला रहा है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अनुदान संख्या–69–व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69–व्यावसायिक षिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 7,12,60,76,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–72–षिक्षा विभाग (माध्यमिक षिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 89,56,83,06,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–12 (10) भी पढ़ दीजिए।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–73–षिक्षा विभाग (उच्च षिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवष्यक धनराषि की पूर्ति के लिए 25,85,01,22,000 रुपये से अनधिक धनराषि स्वीकृत की जाय।

श्री नदीम जावेद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, जो परम्परा रही है उसमें माननीय मंत्री जी कुछ अपनी बात रखेंगे उसके बाद मैं उस चर्चा में शामिल होऊंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात रख दीजिए।

'श्री नदीम जावेद–

अध्यक्ष जी, मैंने 2012 से 2015 तक के जो बजट आए हैं चूंकि अभी यह आएगा उसको पढ़ा साथ ही जो कटौती की चर्चा में शामिल हुए हैं उनके अंश भी मैंने पढ़े और मुझे यह अन्दाजा है कि समय बहुत हो चुका है बहुत संक्षेप में प्रयास करूंगा कि अपनी बात रखूं। जब पहला बजट आया था तो उसमें तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री जी ने बजट रखा था और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी शिक्षा है वह बुनियाद है जो माध्यमिक शिक्षा है वह रास्ता है और जो उच्च शिक्षा है वह मंजिल है और मैं जब पूरे बजट को पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने जो नारा दिया था जो बात 2012 में की थी इस बजट में वह विजन कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं इस बात की चर्चा इसलिए अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कर रहा हूं कि किसी भी सरकार के लिए शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि शिक्षा के माध्यम से हमारी अर्थनीति हमारी राजनीति और हमारा समाज सब कुछ उसी

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के माध्यम से तय होता है और जब मैं इसको कह रहा होता हूं तो मैं बुनियादी स्ट्रैक्चर पर आता हूं वह चाहे उच्च शिक्षा का हो चाहे प्राइमरी शिक्षा हो। अध्यक्ष जी यह टीचर्स के आंकड़े हैं किसी भी इन्सटीट्यूशन की स्थापना में चार–पांच चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी संस्थान में किसी भी इंस्टीट्यूशन में उसके टीचर्स कैसे हैं उसके पास संशाधन क्या हैं उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसा है। उसका सेलेबस कैसा है क्या उस व्यवस्था में समावेशी विकास है समावेशी शिक्षा है समाज के हर वर्ग को अधिकार मिला है उसमें पढ़ने का महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ उस संस्थान का व्यवहार क्या है। अध्यक्ष जी जो आंकड़े मुझे राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं उन आंकड़ों के आधार पर यह है कि 50 प्रतिशत पद टीचरों के खाली हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त रहा है। हाई कोर्ट ने कई बार गम्भीर टिप्पणी की है। ऐडेड कालेज जिसमें मैंनेजमेंट के माध्यम से भर्ती होती हैं उसमें भारी भाई भतीजावाद होता है और शोषण भी होता है। जो सेल्फ फाइनेंस के कालेजेज हैं उनकी हालत क्या है यह पूरा देश और उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। जो टीचर्स को प्रमोट करने की व्यवस्था है उस बजट भाषण के अंश मैंने देखे हैं जो व्यवस्था है चाहे उनके ट्रेनिंग की बात हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो चाहे उनकी इफीसिएंशी बढ़ाने की बात हो इसमें कहीं किसी प्रकार की योजना दिखाई नहीं देती। विद्यालयों के पास संशाधन क्या हैं और जब संसाधन की चर्चा होती है पेज 3 पर स्वयं सरकार ने यह माना है कि विद्यालयों में बहुत सारे विद्यालय जो चल रहे हैं उनमें भवन का अभाव है। पेज 23 पर बहुत स्पष्ट शब्दों में सरकार ने लिखा है और जिस प्रकार के संशाधन को उपलब्ध कराने की राज्य सरकार को आवश्यकता थी उसका अभाव दिखाई देता है। उच्च शिक्षा में सरकार ने यह कहा है 26 विश्वविद्यालय हैं प्राइवेट 23 विश्वविद्यालय हैं जो राज्य चलाता है। उच्च शिक्षा में जो राजकीय महाविद्यालय हैं वह 331 हैं जो एडेड हैं लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस के महाविद्यालय हैं वह 4,689 हैं। यानी पूरी तरह से सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि उच्च शिक्षा में जिस प्रकार का सहयोग जिस प्रकार का समर्थन सरकार को देना चाहिए वह नहीं देगी और खासतौर से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इसको खड़ा करने का प्रयास करेगी। सेलेबस की भी चर्चा होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन या सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सेलेबस को समझने का प्रयास करे। पिछली बार डाक्टर साहब ने कटौती प्रस्ताव रखा था आपने एक हवाला दिया था कि 10,000 करोड़ रुपए का नकल का एक रैकेट चलता है। वह इसलिए चलता था या चलता है अभी भी कि जिस प्रकार का सेलेबस बनाने की हमें बदलते चेलेंजेज के साथ आवश्यकता थी उस प्रकार का सेलेबस बनाने में हम नाकामयाब रहे। यूरोप में अब तो जो हमारे राज्य हैं केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में वहां पर यह प्रयास हो रहा है कि बच्चों को एक्जाम से दूर रखा जाय उनकी ओवरआल डेवलपमेंट के लिए या उनके टैलेंट को पहचानने के लिए ऐसी व्यवस्था हो कि किताबों का कम से कम प्रयोग करते हुए उनकी जानकारी किस प्रकार से बढ़ाई जाए। इतना बड़ा सेलेबस होता था और इस तरह से ट्रेडीशनल शिक्षा दी जाती थी कि उसके माध्यम

से एक नकल का रैकेट चलता था उसमें बहुत सारे बच्चों की जिन्दगी तबाह होती थी। सरकार ने ऐसा लगता है जैसे एक परम्परा का निर्वाह किया है। जो एक विजन होना चाहिए कि इस बदलते चैलेंजेज के साथ हम शिक्षा में क्या बदलाव करेंगे मुझे लगता है कि इसमें दूर–दूर तक दिखाई नहीं देता। क्या हम ग्रेड सिस्टम बना सकते थे सीधे बच्चों को एक्जाम में मार्क के आधार पर नहीं बल्कि ग्रेड के आधार पर पास करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कम्प्यूटर के सम्बन्ध में भी बड़ी चर्चा हुई है सरकार की योजना भी है कि प्रत्येक विद्यालय के अन्दर 10 कम्प्यूटर लगाए जाएंगे लेकिन जो विद्यालय में कम्प्यूटर लगाने की व्यवस्था है उसमें बमुश्किल सरकार 10 से 15 प्रतिशत विद्यालयों में पहुंचने में कामयाब हो पाई है। लगता है कि यह बड़ा लांग टर्म प्रोसेस है।

समावेशी विकास की बात होती है समावेशी शिक्षा की भी बात होती है थोड़ा बहुत लोहिया को मैंने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत मधूलिमए को पढ़ा है। जो लोहिया का विचार था या मधूलिमए का विचार था यह समाजवादी मूवमेंट था उसमें समावेशी विकास और समावेशी शिक्षा की बात थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे इंस्टीट्यूशन जब बने थे तो उसमें यही था कि कालाहांडी का उड़ीसा के किसी बहुत पिछड़े जनपद का छात्र और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टीफेंस का आया हुआ छात्र भी एक कैम्पस के अन्दर एक ही कमरे में रह सकेगा और उसको समान अवसर मिलेंगे, परन्तु दुर्भाग्य यह है कि सरकार के द्वारा जो उपलब्ध संसाधन प्रीमियर इस्टीट्यूशन या स्कूल को दिये गये हैं, उन इस्टीट्यूशन और उन इदारों में केवल समाज के इलीट को मौका मिलता है। समाज के शोषित और वंचित वर्ग को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिये, दुर्भाग्यवश नहीं मिल पाती है।

मैं यह भी देख रहा था कि क्या सरकार इस प्रकार की कोई योजना लायी है या बजट में कोई ऐसा प्राविधान किया है कि आलरेडी जो इस्टीट्यूशन्स चल रहे हैं, इंदारे चल रहे हैं उसमें इस तरह के लोगों को हिस्सा मिले। डाक्टर साहब, आपने पिछली बार कोट किया था, मैं दोबारा आपकी बात को कोट करता हूं कि अगर दो साल मैं सरकार मैंट्रो का प्रोजेक्ट लाकर उसको कम्पलीट कर सकती है तो क्या हम जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान, एक ही सही, पांच साल के कार्यकाल में नहीं बना सकते ? अगर नहीं बना सकते तो हम समझते हैं कि हम कहीं न कहीं उच्च शिक्षा में फेल हो रहे हैं। बच्चियों की शिक्षा की बात की गई, मैं कहता हूं कि सामाजिक न्याय और सामाजिक आंदोलनों की बार–बार बात होती है। समाज का एक हिस्सा पिछड़ा रहे और वह अशिक्षित रहे इससे बात नहीं बनती है। साहिल ने कहा था कि मदद चाहती है यह हव्वा की बेटी जुलेखा की हमजिन्स राधा की बेटी पयम्बर की उम्मत यशोधा की बेटी। 50 प्रतिशत हमारा हिस्सा उस विकास में शामिल न हो सके। सरकार एक योजना लाई, लड़कियों के लिये वह योजना है। जिनकी आमदनी 35 हजार रूपये से कम होगी उनको सरकार 30 हजार रुपये देती है। गांधी जी ने कहा था कि कोई लड़का पढ़ता है तो इंसान पढ़ता है, लड़की पढ़ती है तो खानदान पढ़ता है। मैं सरकार से केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं कि लड़कियों को

समाज मैं बराबर भागीदारी देने के लिये उनके परिवार की जो भी आर्थिक स्थिति हो उसको दरकिनार करते हुये उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिये कन्या धन योजना को बढ़ाने का प्रयास किया जाये और यह प्रयास हो कि सभी लोगों को उस योजना का लाभ मिले। उर्दू के संबंध में भी बात हुयी और उर्दू के संबंध में यह कहा गया है कि उर्दू और दूसरी भाषाओं को बढ़ाने के लिये जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें चर्चा होगी। उर्दू की बात मैं इसलिये करता हूं, क्योंकि गालिब और मीर से लेकर बाल्मीकि और तुलसी तक और शहंशाह अकबर से लेकर पूरे फ्रीडम मूवमेंट तक उर्दू एक ऐसी जुबान रही जिसने हिन्दुस्तान की जम्हूरियत को ताकत दी और हिन्दुस्तान के लोगों को जोड़े रखने का काम किया। अगर किसी क्लास में पांच लड़के उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो सरकार की योजना है कि एक टीचर उनको उर्दू पढ़ायेगा। यह एक अच्छी योजना है, लेकिन उस टीचर को जो अलग से धन मिलेगा उसकी तनख्वाह के अतिरिक्त उसकी हौसला अफजाई के लिये वह मात्र 70 रुपये है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह की जुबान जिसने इस मुल्क की गंगा–जमुनी तहजीब को जोड़े रखने का काम किया है, उसको बढ़ाने के लिये अगर कोई टीचर इस प्रकार से बढ़कर सेवा करता है तो उसको थोड़ा और ताकत दी जाये ताकि बात ठीक से हो पाये। मा0 अध्यक्ष जी, तीन–चार बातें और भी थीं, लेकिन मुझे यह अंदाजा है और जिस तरह से आपका इशारा हो रहा है तो मुझे यह लगता है कि मैं फैज की इस नज्म के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करूं कि 'यह दागदाग उजाला यह शबकाजिदा शहर वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जायेगी कहीं न कहीं, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आयी' मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री रविन्द्र जायसवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, अभी विश्व स्तर के सभी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की गयी, उसऐक्टं उत्तर प्रदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी 100 की रैंक में नहीं है, 200 की रैंक ऐक्ट नहीं है, 300 की रैंक में नहीं है। वर्ल्ड लेवल की 500 यूनिवर्सिटीज में उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज का नाम आता है जो चिन्ता का विषय है। दूसरा, जो नाम टेक्निकल एजूकेशन में 100 के अन्दर आते हैं वह कर्नाटक के आते हैं, आंध्र प्रदेश के आते हैं। यह कहीं न कहीं चिन्ता का विषय है। मैं फिर कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के ही लोग हायर एजूकेशन में जितने यहां ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें से 99 परसेंट लोगों के बच्चे यू0पी0 से बाहर पढ़ते हैं। जितने यहां पालीटिशियन होंगे शायद उनमें से 99 परसेंट लोगों के बच्चे यू0पी0 से बाहर पढ़ रहे होंगे। जो व्यापारी हैं वह अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहा है। कहीं न कहीं यह चिन्ता का विषय है कि उत्तर प्रदेश का हायर एजूकेशन इतना कमजोर क्यों है, इतना दयनीय क्यों है और हम इसके लिये क्या करने वाले हैं ? जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, फैजाबाद विश्वविद्यालय में 12 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। काशी विद्यापीठ में नौ लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, नौ–नौ लाख, वहां पर एक तरह से प्रिटिंग मशीन का काम करते हैं, प्रिंटिंग मशीन से डिग्री बांटते हैं और हम देश में बेरोजगार पैदा कर

रहे हैं, बेरोजगार नौजवान पैदा कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको रोजगारपरक सेलेबस बनाना पड़ेगा। भारत सरकार ने भी किया था, वोकेशनल कोर्सेज, पूरे जोर से प्रयास किया कि हर यूनीवर्सिटी में अनिवार्य कर दिया जाए लेकिन अभी यू0पी0 में उसे लागू नहीं किया गया है। इसलिए मेरा सुझाव है, मैंरी मॉग है कि वोकेशनल कोर्सेज पर जोर दिया जाए और हर जिले में उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा न हो जहां पर सेल्फ यूनीवर्सिटियां न हों, जैसे आपके यहां बना दिया गया है। उसी प्रकार से 75 जिले हैं, 75 यूनीवर्सिटियां खुलनी चाहिए। उनमें किसी भी स्थिति में एक लाख से अधिक बच्चे नहीं होंगे, तभी हम सुधार पायेंगे। अध्यक्ष जी, महिलाओं के बारे में कहा गया, हायर एजूकेशन में महिलाओं को पढ़ाने के लिए, महिलाओं के कालेज खोलने के लिए भूमि में 50 परसेण्ट की छूट दी गयी लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला विश्वविद्यालय नहीं है, न गवर्नमेण्ट के और न प्राइवेट सेक्टर के, जबकि राजस्थान के अन्दर तीन–तीन हैं, लेकिन यू0पी0 में कहीं नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 22 विश्वविद्यालय खोले गए प्राइवेट सेक्टर के लेकिन यह सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। मेरा सुझाव है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और बनारस कभी हब होता था, यहां पर जमीन में छूट दी जाए कि 100 एकड़ भूमि वहां पर सम्भव नहीं है। इसलिए महिलाओं की शिक्षा के लिए वहां भूमि में छूट करनी चाहिए। डिग्री कालेज खोलने के लिए छूट है, महिलाओं के डिग्री कालेज खोलने के लिए जमीन में 50 परसेंट की छूट है, लेकिन यह छूट विश्वविद्यालय के लिए नहीं है। मैंरी मांग है कि महिलाओं के विश्वविद्यालय वहां खुलें और जमीन में छूट करनी चाहिए और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 एकड़ भूमि सम्भव नहीं है, विदेश के लोग भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, वहां 100 एकड़ भूमि नहीं मिल सकती है, इसलिए उसमें छूट दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री गुलाम मौहम्मद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा जो हमारी सरकार चला रही है, सच्चे मायनों में देखा जाए तो गरीबों की शिक्षा का यही एक साधन है। आजकल जिस तरह से इंग्लिश मीडियम के नाम पर, कान्वेंट्स के नाम पर स्कूल, कालेजों की बाढ़ आयी हुई है, ऐसे हालात में हमारा माध्यमिक शिक्षा डिपार्टमेण्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। भारत सरकार के साथ मिल कर भी वहां से जो एन0सी0ई0आर0टी0 की नयी–नयी कोशिश होती है, रिसर्चेज होती हैं, उनको लागू करता है और हमारे ग्रामीण और शहर से ले करके तमाम कालेजों को कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से गरीब इंसान तक हमारी बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल हो जाए। यह शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा है, कम से कम ही आधार बनता है, जो आजकल शिक्षा का रुझान है, चाहे टेक्निकल एजूकेशन की तरफ जायें, चाहे मैंडिकल एजूकेशन की तरफ जायें, जिस तरफ भी जायेंगे,

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इण्टरमीडिएट पढ़ने के बाद में हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं और यह रिकार्ड हमैंशा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा का जो सिलेबस पढ़ करके बच्चा आगे गया है, वह हमेशा कामयाब हुआ है और इसी प्रोग्राम के तहत, इसी योजना के तहत हमारे इस डिपार्टमेण्ट ने लड़कियों के लिए खासतौर से कालेज खोलने का काम किया है। जो असेवित हमारे ब्लाक्स हैं, उन ब्लाक्स में हमारे इण्टरमीडिएट और हाई स्कूल कालेज वहां बच्चियों के लिए खोले जा रहे हैं और यही नहीं बल्कि जो हमारे प्रबन्ध–तंत्र हैं, उनको सहायता देकर अलग से भी विद्यालय खोले जा रहे हैं ताकि हमारी उन बच्चियों की शिक्षा हो सके, जिसको हमारे नदीम भाई ने खानदान की शिक्षा कहा है। मैं समझता हूं कि यह सरकार चाहे मधुलिमये हों, चाहे डा0 लोहिया जी हों, हमारे आदरणीय नेता जी हों और हमारे युवा मुख्य मंत्री जी हों, उसी तरफ हम लोग चल रहे हैं कि गरीब तक शिक्षा पहुॅचे और गरीब तक शिक्षा पहुंच रही है। कोई ब्लाक ऐसा नहीं रहा, जहां हम अपने कालेज, अपने स्कूल नहीं खोल रहे हैं, बल्कि अब तो और आगे बढ़ करके बच्चियों के लिए मॉडल स्कूल खोल रहे हैं। जिसमें हमारी बच्चियों को न सिर्फ पहली क्लास से लेकर 12वीं तक की तालीम मिलेगी बल्कि वहां पर हमारे जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं वह भी खोले जा रहे हैं। उसी कैम्पस में आपको कोचिंग भी मिलेगा। उसी कैम्पस में आपको हुनर भी सीखने को मिलेगा। ताकि कल वह रोजगार भी हासिल कर सकें। इस तरह का काम हमारी यह सरकार कर रही है। और मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे जो कालेजों की बिल्डिंग्स जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। उनको भी आगे बढ़ाने का उनकी भी मरम्मत करने का उनकी भी देख–रेख करने का यह विभाग काम कर रहा है। यही नहीं बल्कि हमारे जो विकलांग बच्चे हैं उनके भी कालेज और स्कूल खोले जा रहे हैं। इसी तरह से जो व्यवसायिक शिक्षा है। एन0सी0ई0आर0टी0 ने हमारे यहां जो छोटी–छोटी ट्रेड्स हैं जिसे पढ़कर 12वीं पास करके बच्चा रोजगार हासिल कर सकता है। अपनी रोजी–रोटी कमा सकता है। ऐसी 40 ट्रेड्स इंट्रोड्यूज की थी।

श्री अध्यक्ष–

वह व्यवसायिक शिक्षा का है वह पास हो गया। अब उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तक सीमित करिये।

श्री गुलाम मोहम्मद–

सर, यह इसी का हिस्सा है। इसी में हमारी इण्टरमीडिएट एजूकेशन में ही एक एन0सी0ई0आर0टी0 के जरिये से व्यवसायिक शिक्षा भी लागू की गयी है। मैं उसी पर बात कर रहा हूं। मैं आई0टी0आई0 वाली शिक्षा पर बात नहीं कर रहा हूं। तो मान्यवर, इसमें और भी आई0टी0, सिक्योरिटी, आटोमोबाइल और रिटेल। इन ट्रेड्स को भी हम इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मंत्रालय इस पर बराबर कोशिश कर रहा है और यह कोशिश हो रही है कि किसी तरह से भी हमारे बच्चे रोजगार हासिल कर सकें। इससे आगे हमारा कम्प्यूटर एजूकेशन है। हर विद्यालय में 10–10 कम्प्यूटर वहां भेजे गये हैं और काम चल रहा है। हमारी सरकार शिक्षा के मामले में सजग है। क्योंकि इसी से

तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा अभियान हमारी सरकार चला रही है और उसी के तहत काफी कालेज बन रहे हैं। बालिका छात्रावास हम लोग बना रहे हैं। जिससे बालिकायें वहीं रहकर छात्रावास की कमी पूरी करके बेहतर से बेहतर पढ़ायी कर सकें। जो हमारी मेधावी छात्रायें हैं उनको लैपटाप भी दिये जा रहे हैं और उनको कन्या विद्याधन भी दिया जा रहा है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए काम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब संक्षेप करें।

श्री गुलाम मोहम्मद–

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग रेगुलर तौर से नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए पत्राचार शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी है। बहुत से लोग हैं जो किसी मेडिकल स्टोर में काम करते हैं, किसी कारखाने में काम करते हैं, ड्रापआउट्स हैं। वह अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं उनके लिए पत्राचार व्यवस्था हमारी सरकार ने, इस माध्यमिक शिक्षा विभाग ने की है। अब उसमें हमारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कराकर दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह से मुक्त विद्यालय से भी हम फायदा उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, अब समाप्त करिये।

श्री गुलाम मोहम्मद–

मेरी आप लोगों से दर्खास्त है कि उसके बावजूद हम चाहते हैं कि जो नये स्कूल कालेज बने हैं, हमारे क्षेत्र में भी बने हैं, हम चाहते हैं कि उनमें शिक्षा के लिए जो अध्यापक हैं, जो स्टाफ है उसकी पर्याप्त व्यवस्था रहे। धन्यवाद।

श्री कपिल देव अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे विधान सभा सदस्य हैं नदीम भाई, उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देते हुए अपना विषय रखना चाहता हूं। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा का विषय है। माध्यमिक शिक्षा में एक दीवार जो सी0बी0एस0ई0 के विद्यालय हैं और जो अपने माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं उनके बीच में लगभग खड़ी हो गयी है। एक बच्चे वह हैं जो लगातार कहीं न कहीं सेंट्रली ।ि स्कूलों में पढ़ते हैं। बढ़िया बसों से बढ़िया गाड़ियों से आते हैं। बढ़िया शिक्षा व्यवस्था है। बढ़िया सी0बी0एस0ई0 का पैटर्न है। एक शिक्षा हमारे पास अपनी माध्यमिक शिक्षा की है जिसमें सामान्यतः मध्यम श्रेणी या उससे भी नीचे की श्रेणी के जो बच्चे हैं दलित हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं और जिनके परिवार के लोग या उनके मुखिया उनके पिता बहुत छोटा व्यवसाय करते हैं उनके बच्चे हैं। उनके पास सेल्फ फाईनेन्स स्कूलों की फीस देने के लिए नहीं है, उनके बच्चों के अन्दर एक इन्फीरियटी कान्प्लेक्स है कि मुझको पब्लिक स्कूल में नहीं इण्टरमीडिएट और माध्यमिक स्कूल के अन्दर पढ़ना

पड़ता है। मान्यवर, एक ओर अध्यापकों का वेतन बहुत अच्छा है, दूसरी ओर बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास जब विद्यालय में आते हैं, में देखता हूं कई बार उनके पास जर्सी, जूते और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं। मान्यवर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनके चेहरे पर जो कान्फिडेंस बच्चों के अन्दर होना चाहिए वह कान्फिडेंस इस शिक्षा के अन्दर नहीं रहता और एक इन्फीरियटी लगातार रहती है कि मैं गरीब, साधारण परिवार का बालक हूं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उन बच्चों के अन्दर खासतौर से जब कक्षा–छः से उनकी अंग्रेजी की शिक्षा शुरू होती है और जो पब्लिक स्कूल हैं, उन ऐक्ट एल0के0जी0 से उनकी शिक्षा शुरू होती है, तो जो कान्फिडेंस उनमें आना चाहिए, आगे जाकर के जब वह प्रोफेसनल कोर्स में जाते हैं, बी0सी0ए0 में एम0बी0ए0 में या एम0सी0ए0 में तो उसे वह कम्पीट नहीं कर पाते और लगातार कहीं न कहीं हीन भावना रहती है, 80 प्रतिशत तक मार्क्स लाने के बाद भी जो आगे की एजूकेशन है चाहे वह सी0पी0एम0टी0 का हो, चाहे आई0आई0टी0 का हो, चाहे सी0पी0यू0टी0 का हो, उनके अन्दर वह क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण से लगातार एक वर्ग के अन्दर जो 50 प्रतिशत से भी ज्यादा संख्या उनकी है, चाहे बेटियां हों, चाहे बच्चे हों, उनके अन्दर हीन भावना रहती है। मान्यवर मेरा निवेदन यह है कि उन बच्चों को कहीं न कहीं प्राईमरी एजूकेशन से इंग्लिश की शिक्षा बहुत जरूरी है, अगर अंग्रेजी की शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाती है तो कान्फिडेंस लगातार उनका गिरता जाता है। दूसरा विषय मान्यवर मेरा यह है कि अभी व्यवसायिक शिक्षा का विषय आया, व्यवसायिक शिक्षा में वित्तीय वर्ष 9–10 में 73215 बच्चे अपने प्रस्ताव में दिये हैं और लगातार उच्च शिक्षा गिरती जा रही है बजाय बढ़ने के वित्तीय वर्ष 14–15 के अन्दर वह संख्या 47326 है, यानी 9–10 में 73215 और 14–15 में 47326 जो बढ़नी चाहिए थी, वह लगातार घट रही है, इस प्रकार छात्रों की संख्या उन्होंने दी है 890 विद्यालयों के अन्दर 74647 विद्यार्थी व्यवसायिक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, जबकि छात्रों की संख्या 01 करोड़ 37 लाख 20 हजार 873 है। मान्यवर मेरा निवेदन यह है कि व्यवसायिक शिक्षा भी बढ़नी चाहिए, जो बच्चे इण्टर मीडिएट करने के बाद बाबू जैसी मानसिकता उनकी निकलती है, यह बच्चे बहुत अधिक प्रोफेसनल हों। दूसरा मेरा निवेदन अध्यापकों के लिए है, अध्यापकों में सी0टी0 ग्रेड खत्म हो गया है, इसके बावजूद भी एल0टी0 ग्रेड में उनका चयन नहीं हुआ है जिसके कारण से शिक्षकों के अन्दर रोष है और एल0टी0 ग्रेड में उनका चयन होना चाहिए। मान्यवर, एक टी0जी0टी0 है ट्रेण्ड ग्रेजुएट टीचर, उसकी जो क्वालीफिकेशन है वह बी0ए0, बी0एड0 है, लेकिन उनके प्रमोशन के समय उनसे ड। पास मांगा जा रहा है, उनको भी शिकायत इस बात की है कि हमारा प्रमोशन बी0ए0, बी0एड0 के आधार पर ही होना चाहिए न कि अन्य के आधार पर, उस पर भी मान्यवर आप विचार कर लें, एक छोटी सी बात और है कि 2005 के बाद जो नियुक्तियां हुई हैं, उनकी पेन्शन की प्रक्रिया नहीं चल रही है, उनकी पेन्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो, उस पर ध्यान रखें, धन्यवाद् मान्यवर आपने मुझे अपना विषय रखने का मौका दिया, आपका बहुत आभार।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ही जब दसवीं और बारहवीं पास कर के बच्चे निकलते हैं, उनका जो भविष्य है, उसके ऊपर ही निर्धारित होता है कि वह कौन सी लाईन चूज करेंगे, वह इसी के ऊपर आधारित होता है। मा0 अध्यक्ष जी, लेकिन मुझे लगता है कि जितना अनदेखी, लापरवाही या आंख बन्द कर के इस विभाग में लापरवाही बरती जा रही है, वह अन्य किसी विभाग में नहीं बरती जा रही है। आज बच्चों के एक्जाम हैं, लेकिन नकल माफियाओं का और प्रशासन का जिस तरीके से गठजोड़ है वह आप कहीं भी निकल जाइये वहां पर पूरी तरीके से नकल चल रही है, नकल माफिया प्रशासन पर पूरी तरीके से हावी हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आदरणीय कल्याण सिंह जी की गवर्नमेण्ट में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे। वह नकल विरोधी विधेयक ले कर आए थे और उसको दीर्घकाल तक जनता ने सराहा था। मैं समझती हूं कि इस पर और उसके बाद कोई भी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहती हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। बच्चों के भविष्य का सवाल है और यह देश तो युवाओं का देश है। यदि युवाओं को सही दिशा मिल जाये, सही शिक्षा मिल जाये तो मैं समझती हूं कि भारत देश को विश्व गुरू बनने से कोई रोक नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ी समस्या है, कि माध्यमिक स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। आयोग की तरफ से टीचर्स नहीं भेजे जा रहे हैं। बार–बार डिमाण्ड की जा रही है लेकिन वहां पर टीचर्स उपलब्ध नहीं हैं। मेरे ही गांव खानपुर के स्कूल में स्थित किसान इंटर कालेज, विद्या नगर जनपद बुलन्दशहर में मात्र एक सरकारी अध्यापक है। उस पर प्रधानाचार्य का चार्ज है। इसके कारण वहां के छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वहां पर शीघ्रतिशीघ्र टीचर्स भेजने की व्यवस्था कराएं। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री बलराम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा, चाहे वह बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस संबंध में इस बजट पर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर हमारे साथी श्री नदीम जावेद साहब, जो बड़ी जगहों पर रह कर पढ़े भी हैं और अपनी बातों को रखने का उनमें एक अच्छा गुण है। आदरणीय जैसवाल साहब, जहां जो उच्च शिक्षा का हब कहा जाता था, वाराणसी के हमारे विधायक जैसवाल साहब और हमारे साथी श्री गुलाम मौहम्मद जी, जो बहुत ही शानदार इंटर कालेज मेरठ के प्रिंसिपल भी रहे और माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती सोलंकी जी ने इस संबंध में बहुत सुझाव दिए। किसी न किसी रूप में शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर सभी लोगों ने चिन्ता जताई है। मैं पूर्ण रूप से सहमत तो नहीं हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जो भी जिस तरह से विनीत, आजाद भारत को शिक्षा के महत्व को देते हुए बनाना चाहिए था जिसके कारण जो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, उसके 5 प्रतिशत ही हमारे

राज्य के अनुदानित विद्यालयों में पढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि 1986 के बाद, वित्त विहीन विद्यालय का प्रचलन चला। बड़ी संख्या मैं लगभग 95 प्रतिशत गरीब और गांव के बच्चे ऐसे विद्यालय में पढ़ते हैं, जो वित्त विहीन हैं। इसलिए जो भी स्थिति है, उस स्थिति को सुधारने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार को जब–जब अवसर मिला है, वह काम किया है। बालिका, महिलाओं की शिक्षा के संबंध में नदीम साहब ने चिन्ता व्यक्त की है, और सही है। जब हम सन् 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय नेता जी के नेतृत्व में बनी तो उन्होंने सर्वे कराया था और कैबिनेट के अंदर पूछा था, अधिकारियों से पूछा था कि लड़कियों के पढ़ने के कितने इंतजाम हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश में शायद 926 ब्लाक थे, 200 से कम ब्लॉकों में। बालिकाओं के पढ़ने के लिए जी0आई0सी, जी0जी0आई0सी0 या इस तरह के, लेकिन आज शिक्षा, शिक्षक और छात्रों के लिए जो कुछ भी उपलब्ध है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा में, यह गर्व के साथ मैं कह सकता हूं। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह जी की देन है और दूसरी बात उन्हीं परम्पराओं को कायम करते हुए माध्यमिक शिक्षा ऐक्ट सुधार लाने के लिए एक नहीं अनेक कार्यक्रम बालिकाओं की शिक्षा को उस समय उस सर्वे के आधार पर उन्होंने शुरु किये थे असेवित ब्लाकों में कैसे एक ही वर्ष में इतने विद्यालय खोले जाएं। मान्यवर, अधिकारियों ने कोई राय नहीं दी थी। मैं उस समय कैबिनेट में था। अधिकारियों ने राय नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर सभी जगहों पर स्कूल खोल दिए जाएंगे चूंकि उत्तर प्रदेश के बजट में उस समय क्षमता ही नहीं थी, तब मा0 नेता जी ने एक सोच निकाली थी कि जो असेवित ब्लाक हैं उनमें प्रबन्ध तन्त्र केवल अपनी रजिस्ट्री करा करके, प्रबन्ध तंत्र रजिस्ट्रेशन कापी लाये और फिर उनको 20 लाख रुपये और आवश्यकता हो तो 01 एकड़ जमीन देकर के उसी वित्तीय वर्ष में 400 से अधिक प्रबन्ध तंत्र के विद्यालय, बालिकाओं के विद्यालय खोलने का सिलसिला शुरू हुआ था। आज वही सिलसिला के कारण बालिकाओं की पढ़ाई ऐक्ट काफी सुधार हुआ है। क्या यह सही नहीं है कि कन्या विद्या धन योजना चलाने के बाद जिन बच्चियों ने पढ़ाई बन्द कर दी थी, हमारे पिछड़े समाज में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश ऐक्ट कम उम्र ऐक्ट शादी होती थी उन्होंने शादी के बाद भी इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होकर के कन्या विद्या धन के लिए उस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं और महिलाओं में जो पढ़ाई की, शिक्षा का औसत बढ़ा, वह किसी योजना के अन्तर्गत नहीं है। मान्यवर, आज बहुत सुझाव दिये गये, सुझाव बहुत अच्छे हैं। सबके सुझाव जो विभाग के लोग हैं में जरूर उनसे आग्रह करूंगा, आदेश भी देना चाहूंगा कि जो सुझाव आये हैं उन सुझावों को सुधार के रूप ऐक्ट ले जो गलतियां हो रही हैं, उनको लें। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया को प्रतिभायें दिया करता था। यही हमारे प्राइमरी स्कूल थे, यही हमारे माध्यमिक विद्यालय थे, यही हमारा पाठ्यक्रम था और यही हमारी तीन–चार यूनिवर्सिटी थीं चाहे काशी विश्वविद्यालय हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे लखनऊ हो, मान्यवर, ये प्रतिभायें देती थीं। आज सदन के सामने सोचने का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश क्या दे रहा है। मान्यवर, यह है और इसमें सुधार की जरूरत है। यह समय लम्बा

है और शायद असामयिक भी लगे लेकिन आज सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए झांसी, मैंनपुरी में निरंतर मुख्य मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार से आप जितने भी सैनिक स्कूल हमको देंगे, अनुमन्यता दीजिए, मान्यता दीजिए और हम सैनिक विद्यालय खोल करके पठन–पाठन का स्तर बढ़ायेंगे और अगर केन्द्र पैसा नहीं देगी तो मुफ्त जमीन देकर के करेंगे। मान्यवर, इसलिए इस बजट में झांसी, मैनपुरी, अमैंठी में सैनिक स्कूल खोलने के लिए 150 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। मान्यवर, जो भारत सरकार ने मॉडल स्कूलों के माध्यम से शिक्षा ऐक्ट बदलाव लाने की कोशिश की थी लेकिन वर्तमान सरकार ने मॉडल स्कूलों की अपनी नीति को वापस ले लिया। अब उन 151 निर्मित स्कूलों को जो मॉडल स्कूल थे, मण्डल स्तर का एक–एक विद्यालय राज्य सरकार अपने साधनों से सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के माध्यम से और हर एक में हॉस्टल बना करके लड़कियों के पढ़ने के लिए 18 विद्यालय राज्य सरकार चलाएगी और शेष को पी0पी0पी0 मॉडल पर सी0बी0एस0ई0 बोर्ड की मान्यता देकर के उनको चलवाने की कोशिश करेगी। मान्यवर, यह हमारा प्रयास है, मा0 मुख्य मंत्री जी का प्रयास है और समाजवादी नीतियों का प्रभाव है। इसमें से 18 मण्डलों में एक–एक है। इसी तरह से मान्यवर, जो हमारे राजकीय बालिका विद्यालय हैं इसमें पुराने बहुत से विद्यालयों में शौचालय वगैरह नहीं थे। उनमें शौचालयों का निर्माण करने के लिए हम इस योजना के अन्तर्गत 306 बालिका इंटर कालेजों में शौचालयों के निर्माण के लिए हमने वर्ष 2015–16 में 60 करोड़ बजट रखा था और अब के वर्ष में 40 करोड़ की धनराशि रखकर हम उन विद्यालयों को भी सुविधायुक्त बनाकर उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दसवीं, बारहवीं पास छात्र–छात्राओं को निशुल्क लैपटॉप देने के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था इस साल के इस बजट में की गई है। मान्यवर, जो हमारे बहुत दिनों से वित्त विहीन विद्यालयों की मांग चली आ रही थी, जो कि बड़ी संख्या में हैं, उनको मानदेय दिये जाने की उनकी बहुत मांग थी और समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा–पत्र में भी लिखा गया था कि इन वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देंगे। शिक्षकों को उस वादे को भी पूरा करने के लिए मान्यवर, 200 करोड़ के परिव्यय रखा गया है। जहां तक उच्च शिक्षा की बात है मान्यवर, उच्च शिक्षा में भी बहुत प्रयास किये जा रहे हैं कि इसमें सुधार आए। मैं समझता हूं कि बहुत से विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था तो मान्यवर, बहुत कम विश्वविद्यालय थे। आज सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में बहुत से विश्वविद्यालय आ रहे हैं और मैं तो बधाई देना चाहता हूं आपको मान्यवर, कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से और सरकार की कृपा से आपने एक ऐसा विश्वविद्यालय कायम करवाया है कि एक वर्ष में वह पूरा भी हो रहा है और शायद शिक्षण–सत्र भी चालू करवाने जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

एक वर्ष के अंदर क्लास चलने लगी हैं, वह भी अपनी बिल्डिंग में।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, इलाहाबाद में भी हम राज्य विश्वविद्यालय अलग से बनाने जा रहे हैं। जनपद इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी काफी धनराशि दी जा रही है। एक नहीं अनेक, क्योंकि शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य ये हमारी सरकार की प्राथमिकतायें हैं और उन्हीं प्राथमिकताओं के अनुसार बहुत से सुधारों की जो अपेक्षा है, उस बजट के अनुसार उसमें प्रयास किये जा रहे हैं। मान्यवर, मैं नदीम साहब से यह जरूर आग्रह करूंगा कि यह शिक्षा में बहुत सुधार चाहते हैं और उसके लिए बहुत प्रयास भी हो रहे हैं। समय के अभाव के कारण हमें सीमित रहना पड़ रहा है अन्यथा बहुत सी बातें आप भी कहते और हम भी कहते और आप से सुझाव तो लेते ही रहते हैं और सुझाव मिलेगा तो उसको जोड़ेंगे लेकिन शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर काटकर एक रुपया दे दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

इनका परिवार भी शिक्षा संस्थाएं बहुत चलाता है, ये न समझिये।

श्री बलराम यादव–

नदीम साहब आप कह रहे हैं कि इसका सब बजट काट कर एक रुपया कर दिया जाए, तो आप बतायें क्या सुधार हो जायेगा। आप इतनी बड़ी–बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं। आप अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और एक मिसाल कायम करें। बहुत–बहुत, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नदीम साहब आप वापस लेंगे।

श्री नदीम जावेद–

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष की यह जिम्मेदारी है कि जो भी सत्तापक्ष लाता है और उसमें जो कमियां होंगी, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार है और यह हमारी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष–

हां, ठीक कह रहे हैं, यही परम्परा है।

श्री नदीम जावेद–

चचा के सम्मान में मैंने समय भी कम लिया और मैंने ज्यादा प्रयास भी नहीं किया। उनका जवाब जो आया है, उस पर मैं समझता हूं कि आगे की कार्यवाही आप करेंगे।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज–

माननीय अध्यक्ष जी, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आपने वित्त विहीन विद्यालयों के लिए मानदेय की व्यवस्था की उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं लेकिन मानदेय कितना देंगे इसकी जानकारी सदन को देना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, वह अभी नहीं बाद में। अभी तो बजट का प्राविधान है, पहली अप्रैल के बाद लगेगा, तब देखना।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मॉग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 89,56,83,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपयाकर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 27,85,01,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष मैं अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,80,66,05,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,99,93,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(इस समय 5 बजकर 45 मिनट पर श्री अधिष्ठाता श्री राजबली जैसल पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बेसिक शिक्षा पर बजट पेश करने का मौका दिया। जहां तक सर्वविदित है, सर्व मान्य भी है कि समाज के आलराउण्ड डेवलेपमेंन्ट्स के लिए बेसिक शिक्षा का अपना एक विशेष महत्व है और समाजवादी पार्टी का सारा इतिहास, समाजवादी पार्टी की नीतियां, श्री मुलायम सिंह साहब का सारा संघर्ष गरीब, गांव के लिए ही है और उनका नारा ही था कि 'दवा पढ़ाई मुफ्त होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी' तो पढ़ाई का नारा ही देकर समाजवादी पार्टी यहां तक सरकार में भी आई और मुझे खुशी है कि जो घोषण–पत्र में वादा किया था कि वो बेसिक शिक्षा पहली से आठ दर्जे तक सारी शिक्षा निःशुल्क कर देंगे मुझे खुशी है कि 6 साल से 14 साल तक के समस्त बच्चों को उत्तर प्रदेश मैं जितने भी स्कूल हैं सबकी शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी, लागू कर दी गयी और आज जारी है। यह सरकार ने अपने घोषणा–पत्र में जो वादा किया था उसको पूरा किया। दूसरे उन्होंने घोषणा–पत्र में कहा था कि दो यूनिफार्म उनको दिया जायेगा, वह लागू भी किया, बजट भी दिया, हम माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद भी देंगे, बधाई भी देंगे कि जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश मैं तमाम विभागों को संशाधन दिया है उतना तो मैं समझता हूं कि शायद देश के किसी मुख्य मंत्री ने अपने संशाधनों से उन विभागों की मदद नहीं की। एक महत्वपूर्ण घोषणा यही थी हमारे बेसिक शिक्षा में जब मां बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करने के बाद सबसे पहले प्राइमरी स्कूल मैं भेजते हैं, प्राइमरी स्कूल में सुपुर्द करते हैं बड़ी उम्मीदों से आशाओ ंसे कि उनके बच्चों की पढ़ाई होगी, विकास होगा और वह क्लीन से होते हैं उन बच्चों को कोई किसी तरह से न तो प्रिज्यूडिस होता है न कोई शिक्षा होती है वही होता है जो वह मां–बाप की गोद में पाते हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ भेजे जाते हैं और यह जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा है यह जैसी शिक्षा होगी, वैसा वह बनेगा वैसे ही प्रदेश और देश दोनो बनेगा। कैसा देश होगा, कैसा प्रदेश होगा इन्हीं प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटियों से बनता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे तौर पर इसको महसूस किया। सबसे बड़ी बात यह है कि निःशुल्क शिक्षा का जब वायदा पूरा कर दिया तो दूसरा उसका लक्ष्य था कि गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाय, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाय ।इस समय सबसे बड़ी कठिनाई जो थी वह यही थी कि उत्तर प्रदेश में एक लाख चौदह हजार 256 प्राइमरी स्कूल हैं, 54 हजार 155 अपर प्राइमरी स्कूल हैं सारे स्कूलों में बहुत बड़ी तादाद है लेकिन आपने देखा होगा इन्हीं में, इन स्कूलों में जो सबसे बड़ी कम्मि थी वह टीचरों की थी सभी स्कूलों में टीचरों की कमीं थी और गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बल्कि मैं समझता हूं गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए पहली बार किसी एक

सरकार ने अपने संशाधन से अपने कार्यकाल में 4 साल में 2 लाख 41 हजार 992 अध्यापकों की भर्ती पूर्ण करके दिखा दिया। रिकार्ड है देश के अन्दर, पहला रिकार्ड है। उत्तर प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई दूँगा कि इतने भर्ती किये गये उनकी तनख्वाहें दी गयी, उनकी पोस्टिंग की गयी पारदर्शिता से कोई बेइमानी नहीं की गयी, कहीं कोई उंगली नहीं उठी, इसके लिए बधाई माननीय मुख्य मंत्री जी को।

दूसरी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई जो शिक्षा के क्षेत्र में हुई है, टी0ई0टी0 की पहली परीक्षा 2011 में हुई, टी0ई0टी0 के बगैर कोई टीचर पास नहीं हो सकता और 2000 में पहली बहुजन समाज पार्टी की सरकार में टी0ई0टी0 की परीक्षा हुई थी। अगर बहुजन समाज पार्टी में घपला न हो तो मामला ही कहॉ बनता है वह परीक्षा सस्पेण्ड हुई और उसमें डायरेक्टर जेल गये, बहुत से अधिकारी जेल में गये और गड़बड़ हुआ परीक्षा सफल नहीं हुई लेकिन समाजवादी सरकार को मैं बधाई दूंगा कि समाजवादी सरकार ने टी0ई0टी0 की परीक्षा में जो पारदर्शिता और इमानदारी की मिशाल कायम की है। वह देश के अन्दर कहीं नहीं है। जून, 2013 में पहली प्राइमरी टी0ई0टी0 की परीक्षा हुई, फरवरी, 2014 में दूसरी, फरवरी, 2016 में तीसरी तीनों टी0ई0टी0 परीक्षा में एक भी कहीं किसी जगह उंगली नहीं उठी। ऐसी पारदर्शी इमानदार सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी के मार्गनिर्देशन में जो नियम बनाये गये, जो कानून बनाये गये उसने एक रिकार्ड कायम किया और यही कारण था कि आज बेसिक शिक्षा में काफी अच्छा रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। जहां तक सवाल है कि जो काम हो रहे हैं हम जानते हैं कि निर्धारित हो रहे हैं कुछ नये काम जो पुराने हो रहे थे लेकिन आपने देखा कि मध्याह्न भोजन योजना में मिड–डे–मील योजना है, वह इसीलिए थी कि गरीब बच्चों को अगर भोजन दिया जायेगा तो वहां जायेगा। मैंने पहले ही बताया कि 1 लाख 14 हजार 256 प्राइमरी स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। 54 हजार 155 अपर प्राइमरी स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है और इस राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजनों में जो सबसे बड़ा काम देश के और जगहों पर जो है उससे ज्यादा उसमें किया है वह काबिले तारीफ है। पहली बात तो माननीय मुख्य मंत्री ने यह किया है कि जो निर्धारित मैंन्यू है उसके लिए अब अतिरिक्त एक सप्ताह में एक दिन गरीब बच्चों को बेसहारा बच्चों को जिनको ठीक से खाना भी नहीं मिलता था उनको फल देने की व्यवस्था की है हरेक बच्चे के लिए अपने संशाधन से। हरेक बच्चे के लिए अपने संसाधन से करने का काम किया है, इसलिये वह बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी जब वह खाना खाते थे तो अपने घर से बर्तन ले जाते थे, बड़े घर के बच्चे, छोटे घर के बच्चे, तरह–तरह के बच्चे, अब सरकार उन्हें अपने संसाधनों से स्टेनलेस स्टील के बर्तन, खाने की थाली, सब देगी और उन सभी बच्चों के लिए एक तरह की व्यवस्था करने का काम करेगी। सरकार समाजवाद उन बच्चों के बीच में लायेगी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अब इसको पास करा दें।

श्री अहमद हसन–

पास करा दें तब तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि बेइंतहा अच्छा काम इन चार सालों में हुआ है। दो बातें और मैं कहना चाहता हूं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में परीक्षा बंद कर दी गई थी, पहली से आठ तक के बच्चों की परीक्षा बिल्कुल बंद कर दी गई थी। क्या पढ़ाते थे टीचर, क्या नहीं पढ़ाते थे, पता नहीं चलता था, अब पहली बार परीक्षा लागू कर दी गई है जिससे असेसमेण्ट होगा, उसके लिए पैसे भेज दिये गये हैं, अठारह करोड़ रूपये देकर कापी, किताब, परीक्षा सब इसी मार्च के आखिर में करा देंगे। दूसरा काम यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने वर्ष 2011 में बच्चों का खेल बंद कर दिया था। यह भी बहुत गड़बड़ काम इन्होंने किया था, बच्चों के विकास के लिए अच्छे खेल का होना भी बहुत जरूरी हैं, तो इसको हमने चालू किया है। स्कूलों में खेल प्रतियोगिताओं को चालू कर दिया गया है और इस साल में उसके लिए बजट भी दिया गया है और खेल सब जगह कराये जा रहे हैं। खेल और पढ़ाई अच्छी तरह से करने के सारे इंतजाम किये जा रहे हैं। स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए काम किया जा रहा है। हर जनपद में जो एक स्कूल सबसे अच्छा पाया जायेगा, उसको एक लाख बीस हजार रूपये का ईनाम दिया जायेगा, सरकार ने सारा फण्ड भेज दिया है, इसलिये में आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि चुनौतियॉ हैं, लेकिन चुनौतियों का मुकाबला करना जरूरी है। में समझता हूं कि हम लोगों में बहुत से लोग इन्हीं प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर आये हैं। इन्हीं स्कूलों के अंदर से मिडिल स्कूलों से पढ़कर आये हैं। छप्पर में हाई स्कूल पढ़ा, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहुंच गये, इन्हीं स्कूलों से पढ़कर हम लोगों ने हमैंशा फर्स्ट डिवीजन हासिल किया, टाप किया। इन्हीं स्कूलों से लोग आई0ए0एस0 में आये, पी0सी0एस0 में आये। हम भी आई0पी0एस0 में आये, पी0पी0एस0 में आये। तो मैं सोचता हूं कि जब हम लोग इसमें पढ़कर आगे आ सकते हैं, तो उनको भी इसी स्तर पर ले जायेंगे, क्योंकि सरकार 2017 में बनेगी और हम लोग इसी स्तर पर इन बच्चों को ले जायेंगे। जो भी अच्छे से अच्छे स्कूल होंगे उनके बराबर समाजवादी पार्टी की सरकार इन स्कूलों को ले जायेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बधाई, धन्यवाद। इसलिये हम लोग उस काफिले के मुसाफिर हैं, उनके साथी हैं कि जो विकास और वेलफेयर, ईमानदार प्रशासन और पारदर्शिता की तरफ प्रदेश को ले जा रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, आप हम लोगों का सहयोग करें, जो कमियां आप कहीं देखें उसको हमें बतायेंगे, तो उसको पूरा किया जायेगा, खत्म कर दिया जायेगा। धन्यवाद।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बेसिक शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। माननीय मंत्री जी, इस पर कुछ बात आना बहुत जरूरी है क्योंकि बेसिक शिक्षा पूरे प्रदेश या किसी देश के सर्वांगींण विकास के लिये अच्छा होना बहुत जरूरी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बेसिक शिक्षा एक रीढ़ की हड्डी के समान है। शिक्षा राष्ट्र या राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के साथ–साथ मानवता संबंधों ऐक्ट प्रगाढ़ता लाने के लिये भी बहुत सहायक व उपयोगी होती है। मान्यवर, प्राचीन समय में शिक्षा गुरूकुल पद्वति पर देने का काम किया जाता था, बाद में मंदिरों, मस्जिदों और मठों के द्वारा इसका प्रचलन चला । देश की आजादी के पूर्व 1858 में केन्द्र सरकार के अधीन इलाहाबाद के अन्तर्गत शिक्षा की व्यवस्था ब्रिटिश शासकों द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक देने का काम किया गया था । माननीय अधिष्ठाता महोदय, बाद में देश आजाद हुआ और तमाम संशोधन करने के बाद प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय स्नातक स्तर की शिक्षा को अलग–अलग विभागों में करने का काम किया गया। उसी के चलते 1985 में बेसिक शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गयी थी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बेसिक शिक्षा में भारत सरकार की नीतियों को और बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को कार्यरत रहते हुये या कार्य से अलग होने से पहले उनको प्रशिक्षण देने का काम करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना 1981 में की गयी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये बेसिक शिक्षा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज प्राथमिक विद्यालयों का बहुत बुरा हाल है। आज प्रत्येक वर्ग के अंदर इन विद्यालयों के प्रति उदासीनता दिखाई देने लगी है। प्रत्येक वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, चाहे गरीब, मजदूर, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, वह भी अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय मैं इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ाने की कोशिश करता है। मान्यवर, सरकार ने इन विद्यालयों को काफी हद तक सुधारने का काम किया लेकिन उनको अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है वास्तव में यह चिन्ता का विषय है। निश्चित रूप से आज निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों की प्रदेश के अंदर बाढ़ सी आ गयी है लेकिन इन संस्थाओं का उद्देश्य कमाई का रहा है उसकी वजह से शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से हमें बेसिक शिक्षा के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों पर एक अध्यापक हो और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 बच्चों पर एक अध्यापक हो। लेकिन जिस हिसाब से माननीय मंत्री जी ने प्राथमिक विद्यालयों का आंकड़ा एक लाख चौदह हजार

पांच सौ छप्पन और उच्च प्राथमिक विद्यालय का चौवन हजार पांच सौ पन्द्रह देने का काम किया, उनके अनुरूप अभी शिक्षकों की भारी कमी है ...

श्री अधिष्ठाता–

समय का ख्याल रखें, अभी कई मद बाकी हैं।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन भारत सरकार के जनगणना निदेशालय के द्वारा जो वर्ष 2011 की जनगणना हुई उसमें यह बात आयी कि 06 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों में 03 करोड़ 45 लाख बच्चे अभी भी विद्यालय नहीं जा रहे हैं। यह निःसंदेह चिंता का विषय है। इसका कारण है अभिभावकों का प्रवासी मजदूर होना। जो गरीब लोग होते हैं वह एक जगह मजदूरी न करके विभिन्न जगहों पर उनको जाना होता है इसलिए अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेज पाते हैं जिसके कारण आज प्रदेश देश के अंदर साक्षरता में 29वें स्थान पर आ गया है। मान्यवर, लगभग 35 प्रतिशत बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। शिक्षकों की कमी तो है ही लेकिन एक सर्वेक्षण के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि आज 21 प्रतिशत शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूल मैं पढ़ाने नहीं जाते हैं और 6.8 प्रतिशत शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षक अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को हजार, दो हजार रुपया दे करके पढ़ाने की व्यवस्था कर रखी है। यह बहुत चिंता का विषय है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की बात करेंगे यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी बात होगी। आज भी अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के अंदर 21,029 प्राथमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है। बाउण्ड्रीवॉल न होने के कारण मैंने खुद देखा है मेरे क्षेत्र में कई विद्यालयों में बरसात के समय घरों का पानी विद्यालयों में घुसने का काम होता है, गंदगी फैलती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज 11,556 उच्च प्राथमिक विद्यालय की बाउण्ड्रीवॉल नहीं है। सरकार ने विकलांग बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में रैम्प की व्यवस्था की थी लेकिन बहुत दुःख की बात है आज भी 4769 विद्यालयों में रैम्प की व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मिड–डे–मील योजना लागू की गयी, उसके लिए किचेन की व्यवस्था की गयी। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि आज भी प्रदेश के अंदर 373 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें किचेन की व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है और खुले में भोजन बनाने का काम होता है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य अपनी बात जल्दी समाप्त करिये।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी तो ठीक से शुरूआत भी नहीं हुई। मान्यवर, जो शिक्षा विभाग में ए0बी0एस0ए0, बी0एस0ए0 हैं, खण्ड शिक्षा अधिकारी हैं इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्होंने एक योजना लागू कर दी है, इस योजना का नाम है

एम0एस0टी0 योजना। एम0एस0टी0 योजना का मतलब मन्थली सैलरी टैक्स। आज हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो मन्थली टैक्स देने का काम ए0बी0एस0ए0 को करते हैं।

श्री वसीम अहमद–

यह गलत बात है, इस तरह का इल्जाम सरासर गलत है। आप झूठ बोलने का काम करते हो, इस तरह का इल्जाम लगा रहे हो।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

में आपको सही बता रहा हूं माननीय मंत्री जी आज भी कई ऐसे अध्यापक हैं जो ए0बी0एस0ए0 को 5 हजार, 3 हजार और 2 हजार रुपये महीना देने का काम करते हैं।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर शोर/व्यवधान)

श्री वसीम अहमद–

हमारे मंत्रियों पर इस तरह का इल्जाम लगाओगे तो इस्तीफा दे देंगे। आपकी तरह से हम पैसे देकर टिकट लेने का काम नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी में टिकट पर भी पैसा लेने का काम किया जाता है। यह काम हम लोग नहीं करते हैं। आप अपने गिरेबान में झांकने का काम करो और गलत इल्जाम मत लगाओ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहिये। मा0 सदस्य आप अपने कटौती पर बोलिये।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहीं तक नहीं है फर्जी नियुक्तियां कर दी गई हैं। कोई अध्यापक नहीं रहा लेकिन उसको मृत दिखा करके उसके लड़के को फोर्थ क्लास में नियुक्ति देने का काम किया है। यह शासन ने भी संज्ञान लिया है लेकिन विभाग ने उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री जी हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं, और हमारे सम्मानित भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। आपने अभी यूनीफार्म की बात कही थी। सही बात है माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो दो सेट यूनीफार्म का देने का काम किया है लेकिन माननीय मंत्री जी 200 रूपये प्रति सेट के हिसाब से देने का काम किया है जिसमें कपड़ा और सिलाई दोनों है। माननीय अधिष्ठाता महोदय आज 200 रूपया सिलाई होती है तो 200 रूपये में कपड़ा सहित सिलाई करने में गुणवत्ता कहां से आ जायेगी। यही नहीं मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो यूनीफार्म का रंग है वो खाकी ड्रेस है, इस बात से बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा होनी लगी है। वह हीन भावना इसलिये पैदा होने लगी है हम लोग देखते हैं सुबह बच्चे एक साथ निकल कर जाते हैं प्राथमिक विद्यालय के, तो लगता है कि यह प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जा रहे हैं। कान्वेन्ट के बच्चे जाते हैं तो लगता है कि कान्वेन्ट के बच्चे जा रहे हैं। एक तरफ हम बात करते हैं प्राथमिक स्कूल और कान्वेन्ट की समानता करने की और उसी के अनुसार हमने पिछली बार 1 अप्रैल से शिक्षण–सत्र को लागू करने का काम किया। इसको लागू करने से हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हमको बहुत कुछ देखना पड़ेगा उनके बराबर करने के लिये। माननीय

अधिष्ठाता महोदय, पिछली बार इस समाजवादी पार्टी की सरकार ने यूनीफार्म के रंग को बदलने का काम कर दिया। बहिन मायावती जी की सरकार थी तो उनकी ड्रेस सफेद शर्ट और नीला पैंट था, उनके ड्रेस का कलर कान्वेन्ट स्कूल के जैसा था लगता था कि बच्चे कान्वेन्ट स्कूल जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त कीजिये। 12 मिनट से ऊपर समय हो गया है।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, पूरा कर दूं। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं नीले रंग से क्यों नफरत हो गई है। इन्होंने नीला रंग बदल करके खाकी करने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पता नहीं सरकार को नीले रंग से क्यों नफरत हो गई है, इन्होंने ड्रेस का रंग बदल दिया अगर इनका बस चलता तो यह आसमान का भी रंग बदलने का काम करते मान्यवर। अधिष्ठाता महोदय, पहले बहिन मायावती जी की सरकार में दलित समाज के लोगों के बच्चों को, गरीबों लोगों के बच्चों को, प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को वजीफा देने का काम होता था आज समाजवादी पार्टी की सरकार ने वजीफा देने का काम बंद कर दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बात अभी माननीय मंत्री जी ने मिड–डे–मील की की थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सितम्बर, 2004 से मिड–डे–मील योजना लागू हुई। पहले प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को मिड डे मील दिया गया। 2007 से उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को मिड–डे–मील दिया गया। उसी क्रम में 2011 से बाल श्रमिक विद्यालयों, मदरसों और सहायता प्राप्त विद्यालयों सभी को मिड डे मील देने का काम होता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी तरह से मध्यान्ह भोजन के आयोग का गठन किया गया है जिससे बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले। इसका उद्देश्य माननीय अधिष्ठाता महोदय यह था कि बच्चों का विद्यालय में ठहराव हो, छात्र संख्या बढ़े, कक्षा में रूकने की प्रवत्ति बढ़े और जो बच्चे बीच में घर बैठ जाया करते थे उसका परसेन्टेज कम हो। यह बच्चों के अंदर एक भाई चारा पैदा हो यह योजना थी लेकिन इसमें जो खाद्यान्न चावल गेहूं भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया जाता है लेकिन सब्जी तेल मसाले के लिये कर्म्बजन कास्ट जो है 3 रुपये 86 पैसे प्राथमिक विद्यालयों के लिये है और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये 5 रुपये 78 पैसे है। माननीय अधिष्ठाता...

श्री अधिष्ठाता–

कुशवाहा जी, समय का ध्यान रखें। 15 मिनट हो गया है।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता जी, बड़ी मुश्किल से समय मिला है। मान्यवर, जो रसोइयां रखे जाते हैं उनको 1 हजार रुपये मानदेय दिया जाता है जो कि बहुत ही कम है। अभी माननीय मंत्री जी ने बर्तन की बात कही, बर्तन रखे जायेंगें, यह अच्छी बात है लेकिन इन बर्तनों की सफाई की व्यवस्था क्या होगी, इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसका

कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अधिष्ठाता महोदय अभी 15 जुलाई 2015 को सरकार ने फैसला किया कि बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में दो सौ एम0एल0 दूध देने का काम सरकार करेगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अच्छी बात है कि दूध मिले बच्चों को, लेकिन बुधवार का दिन निश्चित किया गया कि बुद्धवार के दिन दो सौ एम0एल0 दूध भोजन के दो घंटे बाद दिया जाए लेकिन मान्यवर, दूध के बजट की व्यवस्था कुछ नहीं की है। उसी पौष्टिक आहार में से बच्चों को दूध देना था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज अध्यापक अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने पास से दूध बांट रहे हैं। मान्यवर बुधवार को दूध बंटेगा आगरा मैं तीन लाख बच्चों में 60 हजार लीटर दूध की आवश्यकता होती है। बुधवार के दिन तो दूध की व्यवस्था हो जाएगी किसी तरह बुधवार के दिन दूध की व्यवस्था हो गई लेकिन और दिन जो होंगे उसमें दूध की सप्लाई कहां होगी, अब यह तो है नहीं कि भैंस बुधवार के दिन दूध देगी और दिन नहीं देगी यह तो हो नहीं सकता है तो बाकी दूध कहां जाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

मान्यवर जो दो सौ एम0एल0 दूध है इसकी कास्ट 12 रुपया प्रति बच्चा आती है लिहाजा अपनी नौकरी बचाने के लिए अध्यापकों ने खराब दूध लेने का काम कर दिया इसकी वजह से सिन्थेटिक दूध सप्लाई होने का काम हो गया।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

मान्यवर इसमें कास्टिक सोडा और यूरिया की मिलावट होती है। इसी तरह से लखनऊ के 139 बच्चे यही दूध पीकर के बीमार हो गए ।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भैय्या'–

मंत्री जी ने इतना कम समय लिया और कटौती 15 मिनट की हो रही है 27 विभाग हैं।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

उस सिन्थेटिक दूध को पीकर इतने बच्चे बीमार हो गए। वह तो यह गनीमत रही कि जो सिन्थेटिक दूध दिया गया था उसमें आधा पानी मिलाकर दिया गया था।

श्री अधिष्ठाता–

बस हो गया समाप्त करिए।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

अभी तो शुरू किया है।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं नहीं अब समाप्त करिए।

'श्री जाहिद वेग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने बेसिक शिक्षा पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद्। आज मैं बोलने के मूड में नहीं था मैं किसी भी बजट पर नहीं बोला लेकिन जब सच्चाई गलत तरीके से पेश की जाएगी तो सदन को सच्चाई से अवगत कराना हमारा कर्तव्य बनता है। अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे कटौती के प्रस्ताव पर, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, अभी मंत्री जी बतायेंगे। एक बात और कहा गया इससे पहले जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे, यह सदन गवाह है, प्रेस गवाह है, आपके कार्यकाल में ही बेसिक शिक्षा मंत्री जेल के अन्दर गए हैं यह इस बात का प्रमाण है..

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री जाहिद बेग–

जो आपने कहा ठीक कहा लेकिन आपने अपनी सरकार की बात कही हमारी सरकार की बात नहीं कही है। आपके शिक्षा मंत्री आपके कार्यकाल में जांच के दौरान जेल के अन्दर गए थे नाम कहेंगे तो नाम बता दूंगा। माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री रंगनाथ मिश्रा जी....

श्री अधिष्ठाता–

आप बेसिक शिक्षा के समर्थन में अपनी बात रखिए।

श्री जाहिद बेग–

इनकी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री सारे के सारे जेल गए थे। आप क्या बोलेंगे जो शिक्षा के नाम पर जेल गया हो जिसके कार्यकाल में मंत्री जेल में गए हों आप आइना दिखाएंगे तो मैं भी आइना दिखाऊंगा इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

'श्री दीपक पटेल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं मेरी विधान सभा क्षेत्र इलाहाबाद की करछना विधान सभा क्षेत्र है वहां तकरीबन एक दर्जन स्कूलों के हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। विभाग से बात की जाती है शिक्षा विभाग में बी0एस0ए0 से भी बात करी विभाग के पास कोई बजटोरियल प्रोवीजन नहीं होता आपकी बहुत सारी योजनाएं चाहें एम0डी0एम0 हों बच्चों को तो दिक्कत हो ही रही है हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जो भी बजटीय प्राविधान कर रहे हैं तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए पानी के लिए अलग से व्यवस्था कर दें कमोवेश यही स्थितियां पूरे प्रदेश की हैं सभी लोग वाकिफ हैं। यही निवेदन है।

श्री अहमद हसन–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय बात तो दूर तक चली गई अभी मिड डे मील के बारे में बताया था लेकिन मिड डे मील में आजकल जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार प्रतिदिन अध्यापकों को कम्प्यूटर जनित मोबाइल काल भेजकर अध्यापकों से उनके विद्यालय में उस दिन भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की सूचना प्राप्त की जाती है तो यह अनुश्रवण प्रणाली जो लागू हुई है इसको देश में नम्बर 1 का इनाम भी मिला है। और इण्टरनेशनल इनाम भी मिला है। हम बहुत ही मार्डनाइज कर रहे हैं कोशिश पूरी कर रहे हैं हम समझते हैं कि चुनौतियां भी हैं कमियां भी हैं उनको ठीक करने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। वर्तन साफ कैसे होगा वह तो लड़के खुद ही कर लेंगे हम वर्तन दे देंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा जिससे मुझे चिन्ता भी हुई दुःख भी हुआ कि उन्होंने मंत्री के बारे में कुछ कहा।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

हमने मंथली शुल्क कहा था।

श्री अधिष्ठाता–

सदस्य ने मंथली कहा था। अब उस बात को खत्म करिए।

श्री अहमद हसन–

आपने मंत्री शुल्क कहा।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

हमने मंथली शुल्क कहा।

श्री अहमद हसन–

बुरा न मानना क्योंकि भ्रष्टाचार से मेरी बड़ी भारी दुश्मनी है जिन्दगी भर और रहेगी हम यह बात आज कह रहे हैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ सदन में हमने ज्यादा नहीं बोला है कि हम लोग स्वयं अपनी जिन्दगी में हम तो 37 साल पुलिस में रहे हैं आई0पी0एस0 रहे हैं एस0एस0पी0 रहे हैं डी0आई0जी0रहे हैं लेकिन मेरी जिन्दगी में कोई दाग नहीं लगा बहुत जिलों में रहा राजनीति में भी हमने कोशिश यही की है कि बेदाग रहें। चूंकि आपके यहां हिसाब किताब ठीक हो जाता है बहन जी अगर खुश हैं तो मामला ठीक हो जाता है हम लोगों के यहां स्थिति दूसरी है हमारे यहां एक तो पैसा लेकर टिकट नहीं दिया जाता ईमानदारी से दिया जाता है आपकी पांच साल की सरकार में मंत्री बहुत जेल में गए चार साल रहे अभी निकले हैं।

(इस समय 6 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

चार साल जेल में रहे हैं और मेरे ख्याल में इतनी जांच–पड़ताल और लोकायुक्त की जो रिपोर्टें हैं, अभी बहुत से मंत्रियों की बारी है। तो देखिये, भ्रष्टाचार के बारे में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज सरकार के चार साल का कार्यकाल हो गया, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि समाजवादी सरकार का कोई भी मंत्री ऐसा काम नहीं करेगा जिस कारण वह जेल जाये या उससे भ्रष्टाचार की बू आये। बहुत बुरा हाल हुआ है, सी0एम0ओ0 मारे गये हैं। भ्रष्टाचार के बारे में हम और आप मिलकर काम करें। बेसिक

शिक्षा विभाग के बारे में मैं कह सकता हूं कि अधिकारियों की बात तो दूसरी है, कितने ही अधिकारी शिक्षा में सस्पेंट किये गये हैं, मैंने सस्पेंट किये हैं। दूसरे विभागों ऐक्ट भी सस्पेंट किये गये हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने बेईमानों के खिलाफ जितनी कार्यवाही की है उतनी कार्यवाही आज तक किसी सरकार में नहीं हुयी है, या तो मुलायम सिंह साहब की सरकार में हुयी है या इस सरकार में हुयी है। इसलिये हम लोगों को मिलकर आपस में बैठकर जो कुछ भी कमियॉ हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिये। हम जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, सिस्टम क्या है, दिक्कते हैं, कठिनाईयां हैं, आपको भी हैं, हमको भी हैं। इसलिये मैं आपसे विनम्र अपील करूंगा कि आज जो कठिनाईयां हैं जो चुनौतियां हैं, उसके प्रति सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है और इन्हीं पर ज्यादा हमले भी हो रहे हैं, इसलिये आप जो भी आरोप लगायें, बहुत जिम्मैंदारी के साथ लगायें। मैं यह कह सकता हूं कि पिछले चार सालों में बेसिक शिक्षा में बहुत अच्छा काम हुआ है, सिस्टम के तहत हुआ है और पारदर्शिता के साथ हुआ है। आगे भी हम लोग ऐसी ही कोशिश करेंगे, आगे भी हमें बहुत कुछ करना है। अभी बहुत कुछ ठीक–ठाक नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। मिड–डे–मील भी ठीक करेंगे तो आपकी मदद से करेंगे। आप और हम गांव में रहते हैं इसलिये हमें पूरी उम्मीद है कि हम और आप मिलकर ऐसा काम करेंगे कि शिक्षा विभाग ही नहीं हर विभाग, जिन्दगी का हर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश देश के अन्दर सबसे ऊंचाइयों पर जायेगा, यही हम लोगों की कामना है और इसी तरफ हम लोग कोशिश करें। धन्यवाद।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दे दें तो मा0 मंत्री जी ने जो बातें रखीं हैं उसी पर मेरा एक बहुत छोटा सा सुझाव है। मैं मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इससे पहले जब हम प्रतिनिहित विधायन समिति में थे तो वहां पर बेसिक शिक्षा के अधिकारी आये थे तो उसमें एक मसला उठा था कि बेसिक शिक्षा को कैसे ठीक किया जाये। यह आप भी चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी भी कल चिंतित थे। वहां पर यह मसला उठा था कि अध्यापक जब जाये तो उसकी हाजिरी लगे और जब वापस आये तो फिर उसकी हाजिरी लगें। बायोमीट्रिक के लिये उन्होंने कहा था इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर जरूर गौर करें, क्योंकि अध्यापक अगर स्कूल में रहेगा तो कुछ न कुछ पढ़ायेगा। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

(मा0 सदस्य श्री भगवान सिंह कुशवाहा और श्री काली चरन सुमन के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

कुशवाहा जी, आप तो बोल चुके हैं। अब बजट पास होने दीजिये। ठीक है, आप संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

मा0 अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में तमाम महिला अध्यापिकायें अपने पति से 300–400 कोस दूर रह रही हैं। मेरा अनुरोध यह है कि यदि उनका स्थानान्तरण उसी जनपद में कर दिया जायेगा तो वह और अच्छा पढ़ायेंगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 03 खरब, 80 अरब, 66 करोड़, 05 लाख, 52 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,99,93,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–74 गृह विभाग (होमगार्ड्स)

'(होम गार्ड्स प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री) श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–74–गृह विभाग (होमगार्डस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,18,86,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य रहा कि इस विभाग का बजट वर्ष 1993–94 में रखने का मेरे ऊपर उत्तरदायित्व था, माननीय नेता जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। श्रीमन्, होमगार्डस स्वयं सेवकों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और है। इसकी स्थापना

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, वर्ष 1963 में हुई और वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो इनको भी बंग्लादेश के बार्डर पर लगाया गया था और इन्होंने बहुत ही कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। श्रीमन्, इस समय प्रदेश में 1,18,348 होमगार्डस स्वयं सेवक हैं। जिसमें से 50,335 होमगार्डस स्वयं सेवकों को डिप्ल्वायमेंट में रखा गया है। श्रीमन्, आज मुझे इस आदरणीय सदन में कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री, मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की जैसे ही सरकार बनीं, उन्होंने होमगार्डस स्वयं सेवकों के लिए यह पहली सरकार है कि उन्होंने भत्ता बढ़ाने का काम किया है और आज पहली अप्रैल से इन होमगार्डस जवानों को 300 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलने का काम होगा और यह पहले 225 था। श्रीमन्, कितनी विडम्बना है कि इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी कि जो गरीब, कमजोर और दलित की बात करती थी, यद्यपि 2012 के पहले 05 साल का कार्यकाल प्रदेश में रहा है। इन होमगार्डस जवानों के स्वयं सेवकों को जो भत्ता मिलता था, 120 रुपये से ले करके और लास्ट तक पांच साल के अन्दर 160 तक हुआ और जब माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि अभी सरकार को हमारी 04 साल हुआ है और इस 04 साल में 140 रूपये की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि बहन मायावती के राज्य में 05 साल में केवल 40 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है, जब कि होमगार्डस स्वयं सेवकों में ज्यादातर गांव के गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग और गांव के गरीब लोगों के बच्चे होते हैं। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और इतनी अच्छी विचारधारा के रहते और चलते, जिन्होंने श्रीमन्, संकल्प लिया था, शपथ लेते ही कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे तो उत्तम प्रदेश बनाने के काम में यह एक कड़ी है, एक शुरूआत है, एक एचीवमेंट है। मुझे कहते हुए, श्रीमन्, इस आदरणीय सदन में खुशी हो रही है कि हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश केवल एक जहां पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की एन0आई0सी0 साफ्टवेयर के माध्यम से उनकी ड्यूटी लगायी जाती है। जहां पर इस प्रदेश के किसी व्यक्ति को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। और श्रीमन्, यह होमगार्ड जो गांव में रहते हैं, पुरवों में रहते हैं। अब तो गांव से तमाम सड़कें बन गयीं। लेकिन उनकी कहां ड्यूटी है, उनके मोबाइल न0 के जरिये एस0एम0एस0 के माध्यम से उनको जानकारी दे दी जाती है कि आपकी ड्यूटी फलां जगह पर है। आप फलां जगह पर ड्यूटी पर पहुंचे। यही नहीं श्रीमन्, मुझे होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि अभी वर्ष 2012–13 में इलाहाबाद में महाकुम्भ मैंला हुआ था। और उस महाकुम्भ में मा0 मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण वहां पर दुनिया के तमाम लोग आये, दुनियां के लोगों ने उस महाकुम्भ के इंतजाम को देखकर प्रशंसा किया है और वहां पर होमगार्ड के जवानों ने बहुत अच्छे तरीके से पुलिस बल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। 07 हजार स्वयंसेवक की ड्यूटी वहां लगी थी। पहले होमगार्ड के जवान जब ड्यूटी पर जाते थे तो उनको धान के पैरा पर होमगार्ड को लेटने के लिए दिया जाता था। लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी की सोच है और कितनी अच्छी सोच है कि सबको सम्मान देना चाहते हैं सबको साथ लेना चाहते हैं। सबको उठाना चाहते हैं। जो भी

होमगार्ड जवान के स्वयंसेवक इलाहाबाद कुम्भ के मैंले में गये थे। मान्यवर, आपको पता ही है कि यह कुम्भ मेला दिसम्बर से मार्च, 2012–13 तक चला था तो उसमें चारपाई की व्यवस्था की गयी और उनको खाने के लिए अतिरिक्त 60 रुपये प्रतिदिन भोजन के लिए दिया गया है। यह पहली सरकार है, यह पहले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इन होमगार्ड जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए निष्ठापूर्वक काम करने के लिए यह व्यवस्था किया है। मान्यवर, होमगार्ड विभाग में मानदेय बढ़ाया गया है। चाहे हमारे कमाण्डेंट हों, चाहे सहायक कमाण्डेंट हों, चाहे प्लाटून कमाण्डर हो। दुगुना मानदेय बढ़ाने का काम हुआ है। श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए अफसोस भी हो रहा है कि होमगार्ड जवानों को 2008 से वर्दी नहीं मिली थी। मा0 मुख्य मंत्री जी के कृपापूर्ण निर्णय के आधार पर होमगार्ड जवानों को वर्दी खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था कर दी गयी है। और वर्दी खरीदने के लिए होमगार्ड डी0जी0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है और बहुत जल्दी हमारे इन तमाम जवानों को जो होमगार्ड के जवान 2008 से वर्दी नहीं पाये थे, वर्दी देने की व्यवस्था हो जाएगी। आज मुझे यह कहते हुए भी गर्व हो रहा है कि मेरे पास 1993–94 में होमगार्ड विभाग था। उस समय होमगार्ड विभाग का कोई दफ्तर नहीं था। यह बैरकों में हमारे डी0जी0, एडिशनल डी0जी0 बैठते थे। आई0जी0 बैठते थे। लेकिन जब हमारे माननीय नेताजी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने बहुत शानदार मुख्यालय होमगार्ड जवानों के लिए लखनऊ में बनाया है और जहां पर हमारे डी0जी0 और तमाम हमारे अधिकारी बैठते हैं। तो इसको देखकर हमारे तमाम होमगार्ड के जवान ड्यूटियों पर लगाये जाते हैं। चाहे उनकी मेला में ड्यूटी हो, चाहे कहीं दंगा में हो, चाहे कहीं बाढ़ में हो, चाहे यातायात में हो। श्रीमन्, आप भी देखते होंगे कि जब आपकी गाड़ी निकलती है तो होमगार्ड के जवान बहुत अच्छी वर्दी पहनकर अच्छे ढंग से सीटी भी बजाते हैं और लगता है कि सारी कमान होमगार्ड के जवानो ने संभाल ली है, यह हमारे लिए गर्व की बात है, विभाग के लिए गर्व की बात है, श्रीमन् यही नहीं मा0 मुख्य मंत्री जी ने होमगार्ड के जवानों के लिए होमगार्ड के जो अधिकारी हैं, पहले पिस्टल और थ्री–नाड–थ्री मिलती थी, थ्री–नाड–थ्री तो अब पुलिस विभाग में भी नहीं है, अब दूसरी रायफल एस0एल0आर0 रायफल खरीदी गई है और तमाम अत्याधुनिक असलहे होमगार्ड विभाग में जिस तरह से मा0 मुख्य मंत्री जी ने पुलिस विभाग को चुस्त–दुरुस्त करने के लिए तमाम आधुनिक योजनायें चलाई हैं जिससे कि जो क्राइम करने वाले हैं, वह पकड़ के बाहर न रहें, बल्कि उनको पांच सेकेण्ड के अन्दर पकड़ लिया जाय, उसी तरह से होमगार्ड विभाग में भी तमाम आधुनिक व्यवस्थायें की गई हैं। मान्यवर, यही नहीं मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में होमगार्ड जिला मुख्यालय बन गया है, 08 में विचाराधीन है, मण्डलीय होमगार्ड कार्यालय बन रहे हैं, हमारा लक्ष्य है पूरा करने का, जैसे मुरादाबाद है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, आगरा है यहां पर मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्ड का कार्यालय बनाने के लिए हमारी योजना है, हमारा लक्ष्य है। तो श्रीमन् मुझे पूरा विश्वास है यह हमारे होमगार्ड के जवान और यह होमगार्ड संगठन यह अपनी निष्ठा के बल पर अपनी कर्तव्य परायणता के बल पर लोगों के मनों में इनका बड़ा ऊंचा स्थान है, यह चर्चा चली है कि होमगार्ड विभाग पुलिस के साथ कन्धे से कन्धा

मिलाकर के कानून–व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होने में और मा0 अखिलेश यादव जी ने जब उत्तर प्रदेश को, उत्तम प्रदेश बनाने का जो बीड़ा उठाया है, संकल्प लिया है, उसमें यह विभाग जरूर सहायक होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–74–गृह विभाग (होमगार्डस) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मा0 अध्यक्ष जी, होमगार्ड में जो लोग सेवायें दे रहे हैं, वाकई मैं उनकी हालत बहुत खराब है और आज की तारीख में सबसे कम अगर किसी को सुविधायें हैं तो वह होमगार्ड्स की हैं और उनसे ड्यूटी ली जा रही हैं, उनको चौराहों पर लगा दिया जाता है, हर जगह और अभी मा0 मंत्री जी ने बताया कि वह पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो सेना के साथ वह बार्डर पर भी भेजे गये। अभी इलाहाबाद में जब कुम्भ हुआ तो वहां लगाये गये। तो जब उनकी सेवायें आप हर जगह ले रहे हैं, तो फिर उनको सुविधायें देने में क्यो पीछे है सरकार, यह एक गम्भीर विषय है और मान्यवर जैसे हर वर्ष पुलिस दिवस मनाया जाता है, उसी तरह से होमगार्ड्स दिवस भी पहले मनाये जाते थे, लेकिन जब से यह सरकार आई है, इन्होंने होमगार्ड दिवस को मनाना बंद कर दिया है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि मा0 मंत्री जी इस पर ध्यान दें और अगर उनका होमगार्ड विभाग का जो भी संगठन है, उसका जब दिवस मनाया जायेगा तो जो होमगार्ड्स के जवान हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। मान्यवर, होमगार्ड जवानों का शोषण भ्रष्टाचार रोकने के लिए तो मा0 मंत्री जी ने अभी बताया कि दिनांक 01 जनवरी, 2013 से कम्प्यूटर द्वारा होमगार्डों की ड्यूटी लगाने की पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन जो मेरी खास जानकारी है कि होमगार्ड के मुख्यालय द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और इसकी वजह से कई अधिकारी आज भी इसका उल्लंघन कर रहे हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई न कर के उनको उच्च अधिकारी खुला संरक्षण दे रहे हैं। वैसे अभी मुझे लग रहा है मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और विभाग बदल कर दिया है मंत्री जी को लेकिन विभाग बदलने के बाद भी जो भ्रष्टाचार का पूरा काकश हैं, होमगार्डों के ऊपर, वह अभी सक्रिय है उसको भी ठीक करने की जरूरत है। मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि होमगार्डस को 225 रुपये पहले दिए जा रहे थे, आपने कहा कि 1 तारीख से हम उसको 300 रूपये करने जा रहे हैं लेकिन में अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमसे लगा हुआ उत्तराखंड जो पहले हमारे प्रदेश का हिस्सा था, आज वहां 400 रूपये उनको रोज दिया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, आज 300 रूपये तो लेबर ले रहा है। लेबर तो 30 दिन काम कर सकता है, इनको आप 30 दिन काम भी नहीं देते हो, तो कम से उत्तराखंड के समान 400 रूपये का प्रतिदिन भत्ता यानि कि जो आप आज दे रहे हैं, कम से कम उसको दोगुना करने का

काम करिए। यह 300 रूपये बहुत कम हैं। मान्यवर, वर्दी के लिए बात आई, लगभग 5 वर्षों से होमगार्डस को वर्दी नहीं मिली है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, शायद इनको वर्दी मिल जाये। हमारे यहां पर उत्तराखंड की तरह इनको बीमे की व्यवस्था भी करने की आवश्यकता है। जैसे हमारा जवान, जो होमगार्ड का है, उसको प्रतिदिन काम नहीं मिलता है। अगर उसके साथ कोई घटना–दुर्घटना होती है और वह ड्यूटी पर नहीं है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। जबकि हमसे अलग हुए उत्तराखंड में होमगार्ड जवानों को, रिटायर होने के बाद एकमुश्त 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। वह व्यवस्था भी हमारे यहां नहीं है। अगर होमगार्ड रिटायर होगा तो वह खाली हाथ अपने घर जा रहा है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अगर उत्तराखंड दे सकता है, तो फिर उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दे सकता ? यह भी चिन्ता का विषय है। मान्यवर, होमगार्ड में जो लोग ड्यूटी पर लगे रहते हैं, अभी हमारे क्षेत्र की एक घटना है, उन लोगों की ड्यूटी गोण्डा में लगाई गई। चुनाव की ड्यूटी पर वह जा रहे थे, रास्ते में कहीं बिजली के तार से घटना घट गयी। उसमें एक–दो लोग मर गए और कुछ लोगों को ऐसे शॉक लगे हैं, कि उनका इलाज हुआ और इलाज होने के बाद एक तरह से वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनके परिवार की महिलाएं हमसे मिली थीं। मान्यवर, उनको कोई भी आर्थिक सहायता आज तक नहीं दी गयी है। मैंने उस संदर्भ में उनके सभी प्रत्यावेदनों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से पत्र तो आ गया कि फलां जगह भेज दिया गया है लेकिन उसमें अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान दें और जो भी होमगार्ड हैं, उनका दुर्घटना बीमा जरूर करवा दिया जाये। दुर्घटना बीमा होने से ही अगर कहीं कोई घटना घटती है, तो इनके परिवार को पैसा मिल सकता है। मान्यवर, महिला सुरक्षा में महिला होमगार्ड की भूमिका, जो आपने वूमैंन पॉवर लाइन बनायी है वहां पर भी आपने लगाया है। महिला सम्मान प्रकोष्ठ यातायात व्यवस्था तथा प्रदेश के सभी थानों में ड्यूटी लगाकर प्रभावी बनाने के लिए होमगार्डों के 33 प्रतिशत तक, महिलाओं से आरक्षित करने के लिए भी पिछड़े वर्ग की महिलाओं में सुरक्षा एवं सशक्तीकरण की भावना में वृद्धि होगी। जिससे उत्तर प्रदेश में अग्रणी प्रदेश बनेगा। मान्यवर, लगभग सभी विभागों में लोगों का कैडर रिव्यू होता है लेकिन यह एक ऐसा विभाग है, जहां पर कैडर रिव्यू कई वर्षों से नहीं हुआ। कम से कम इस पर भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें कि जो भी इनका कैडर है, इसका रिव्यू साल में एक बार किया जाये और जिस तरह से हमारे पुलिस के जवान प्रदेश की सुरक्षा में, प्रदेश की व्यवस्था में अपना हाथ बंटाते हैं, होमगार्ड के लोग उससे पीछे कहीं नहीं हैं। होमगार्ड के लोगों को भी यही ध्यान देते हुए कि उनको भी हम उन्हीं की तरह सेवाएं ले रहे हैं, तो उनको सुविधाएं देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो आज आपने उनका भत्ता बढ़ाया है, उसको दोगुना करने का काम करें। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, बसपा सॉरी।

(सदन में हंसी)

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय मंत्री जी, मैं बहुजन समाज पार्टी का साधारण सदस्य हूं। मैं नेता नहीं हूं। जो मुंह से निकल गया, उसको संशोधन कर लीजिए।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह बहुत विद्वान साथी हैं और आपने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिया है, इसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। आपने दो–तीन महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अच्छे सुझाव दिए हैं। लगता है आपको पता हो गया है कि हम उस पर काम कर रहे हैं। आपने उत्तराखण्ड की बात की है तो आप तो पढ़ते–लिखते भी हैं और कहां उत्तराखण्ड बाहर है। ये उत्तराखण्ड तो उत्तर प्रदेश में था। जब से उत्तर प्रदेश का बॅटवारा हो गया, उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखण्ड हो गया है वहां के लोगों को जाकर देखिए उनकी हालत क्या है। वे याद करते हैं कि अच्छा रहता कि अगर हमारा बंटवारा न होता और हम उत्तर प्रदेश ऐक्ट ही रहते। खैर, अभी यह विषय नहीं है। आपने यह कहा है कि उत्तराखण्ड ऐक्ट होमगार्ड विभाग के स्वयं सेवकों को 400 रुपये मिलने का है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से कि अभी तो हाउस चल भी रहा है। आप पता लगा लीजिए, नहीं मिल रहा है, केवल घोषणा ही हुई है लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा है, न उसके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड ऐक्ट किसी प्रकार के बजट की कोई व्यवस्था हुई है। ये मैंरी निश्चित जानकारी है और आप तुलना उत्तराखण्ड से कर रहे हैं। उ0प्र0, जहां पर 01 लाख 18 हजार स्वयं सेवक हों होमगार्ड के और उत्तराखण्ड में ज्यादा से ज्यादा 10 हजार होंगे, बहुत ज्यादा होंगे तो 10 हजार होंगे। मान्यवर, लेकिन सरकार की नीयत देखी जाती है। दो चीजें होती हैं किसी भी सरकार की नीति और नीयत। हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की चाहे नीति हो, चाहे नीयत हो और चाहे उनके लायक बेटे, हम लोगों के नेता, सदन के आदरणीय नेता, मा0 मुख्य मंत्री जी, अखिलेश यादव जी उनकी नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है कि नीति कुछ हो और नीयत कुछ हो। जो जुबां पर है, वही दिल में है। जो दिल में है वही जुबॉ पर है। जहां तक आपने कहा है कि इनके लिए बीमा होना चाहिए, बीमा योजना होनी चाहिए। मान्यवर, बीमा योजना के लिए आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 01 करोड़ 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और एक कल्याण निधि की स्थापना की गई है जहां से हम उनकी मदद करेंगे। आपने अपने जनपद शाहजहांपुर के होमगार्ड के लोगों के लिए कहा जो गोण्डा ड्यूटी करने गये थे तो आपने इस दुखद घटना के बारे मे मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। मैं आपको साथ लेकर वहां चलूंगा, हमारे डी0जी0, होमगार्ड्स एवं प्रमुख सचिव को साथ लेकर चलूंगा और उन मृतकों के परिवार को 5–5 लाख रुपये देने का काम करूंगा। साथ ही जो और सुविधाएॅ भी अनुमन्य होंगी, वह चलकर उनको देने का काम करूंगा।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मा0 मंत्री जी, आपको इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अवधेश प्रसाद–

अब आप बताएं कि बचा क्या है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, अब कुछ नहीं बचा है, आपने सबका उत्तर दे दिया है।

श्री अवधेश प्रसाद–

आपसे निवेदन है कि हम आप मिलकर इस बजट को पास कराएं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मैंने तो आपके बीच ऐक्ट सुझाव रखे और आपने सुझावों पर विचार करने की बात कही है। आपने घोषणा की है मैं आपका आभारी हूं, आपका धन्यवाद करता हूं लेकिन में अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–74–गृह विभाग (होम गार्ड्स) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–74–गृह विभाग (होम गार्ड्स) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,18,86,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,05,15,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसमें विवाद नहीं है सिर्फ पास करा देना है।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग(स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,05,15,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, मैं आप की अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 21,85,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कटमोशन दीपक पटेल जी आप रखेंगे। जल्दी कर दें, इसको हम पास करा दें।

श्री दीपक पटेल–

मान्यवर, दो लाइन बोल लें। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपयाकर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, इसमें कहने को कुछ ज्यादा है भी नहीं। चार पन्नों की यह पुस्तिका है, नाम तो बड़ा महत्वपूर्ण है इसका नागरिक सुरक्षा संगठन और पहले पेज में इसके स्थापना के जो उद्देश्य हैं, वह भी बड़े महान हैं, बड़े हैं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा ये आखिरी पेज में इसका बजटीय प्राविधान है। मात्र 18 करोड़, 95 लाख 81 हजार रुपये का है।

श्री अध्यक्ष–

21 करोड़, 85 लाख, 39 हजार है।

श्री दीपक पटेल–

मान्यवर, जो किताब मिली है, उसमें 18 करोड़ ही है।

श्री अध्यक्ष–

जो किताब मिली है, वह अलग है, वह परफारमेंन्स वाली होगी। उसमें कई मद का होगा।

श्री दीपक पटेल–

मान्यवर, कुछ कहने के लिए इसमें है नहीं। 17 जिलों में यह है, हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि इसको पूरे प्रदेश में करिये और 21 करोड़ भी आप दे रहे हैं तो एक के पीछे एक करोड़ रुपया भी नहीं आ रहा है तो इसको बढ़ा दें मान्यवर, तो इसकी उपयोगिता हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 21,85,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

परिवहन राज्य मंत्री, स्वत्रंत प्रभार (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,03,80,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

दीपक पटेल जी आप ही कटमोशन रखेंगे। आप अपना कटौती का प्रस्ताव रख दीजिए।

श्री दीपक पटेल–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, समय की व्यस्तता को हम समझते हैं लेकिन यह विभाग हल्के में नहीं है। प्रदेश के लाखों नौजवानों की उम्मीदों का विभाग है और आपकी कृपा रही है तो पिछले दो साल से इस विभाग पर मुझे बोलने का अवसर मिलता रहा है और पिछले दोनो तीनो वर्षो मैं अपना सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें जिन माननीय मंत्री जी ने उस विभाग का बजट पेश किया, उनके हाथ से यह विभाग चला गया। भगवान आपका भला करे, हमारे साथी हैं विभाग के मंत्री तो नहीं हैं आप। मान्यवर, इसी नाते बड़े गम्भीर सुझाव हम नौ जवानों के पक्ष में देते हैं, लेकिन कभी इसका हल निकलता नहीं है पता नहीं कौन सी ऐसी दुर्घटना घट जाती है। मान्यवर बड़ी वजनी पुस्तिका है 200 पन्नों की है और आधा किलो से ऊपर इसका वजन होगा बहुत सारी बाते इसमें लिखी हुई हैं पिछली बार भी हमने ध्यान आकृष्ट कराया था यह प्राविधिक शिक्षा जिसके अन्दर इन्जीनियरिंग कालेजेस और पालिटेक्निक कालेजेस, फार्मेसी कालेजेस आते हैं पूरे प्रदेश में आज दुर्दशा का शिकार हैं, दिन–प्रतिदिन यह बेदम होते जा रहे हैं, बेजार होती जा रही है। बजट पास होने के दर्मियान इस पर बड़ी गम्भीर चर्चायें होती हैं लेकिन कभी उसमें अमल नहीं होता। ज्यादा भूमिका में नहीं जाऊंगा आज प्राविधिक शिक्षा है उसकी दुर्गति का आलम यह है कि हमारे पास लाख से ऊपर सीटे हैं और जो प्रवेश परीक्षा हैं जितनी सीटे हैं उतने छात्र भी प्रवेश के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। पिछले वर्ष तो इसकी और भी खराब स्थिति थी कि सवा लाख के अगेंस्ट कुल छियालिस हजार दो सौ छियानबे छात्रों ने

प्रवेश लिया। आज स्थिति यह है, अभी शिक्षा पर बहुत देर से बहस चल रही है, नये स्कूल खोलने की बात हो रही है। आज शिक्षा को ए0आई0सी0टी0 द्वारा जहां खोलने की बात हो रही है वहां इसको बन्द करने का सरलीकरण किया जा रहा है कि आपका कालेज हम बन्द कर देंगे। मान्यवर, बहुत खराब स्थिति है सरकारी स्तर पर। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराऊंगा सरकारी स्तर पर भी हर साल एक–दो नये कालेजेस की शुरुआत कर दी जाती है और यू0पी0टी0यू0 एशिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, टैक्निकल एजूकेशन की लेकिन मान्यवर बहुत ही अव्यवस्था का शिकार है, एक भी परमानेन्ट इम्प्लाई नहीं है, इक्जामिनेशन कन्ट्रोलर नहीं है जिनके ऊपर परीक्षा का कार्यभार है और जो भी काम होने चाहिए यूनिवर्सिटी के अन्दर खास कर परीक्षाओं के उसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है। मनमाने तरीके से निजी संस्थाओं को काम देकर यह काम संचालित किया जाता है और जो सरकारी क्षेत्र के इन्जीनियर कालेज खुले हैं न कोई स्थायी टीचर है, न कोई योग्य टीचर है न कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर है लेकिन हर साल एलान हो जाता है कि हम चार खोल रहे हैं, पांच खोल रहे हैं। जो पुराने चल रहे हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। मान्यवर यह तो प्राकथन में था अब हम इस पुस्तिका पर नजर डालते हैं इसका पेज–2 है जिसमें गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का द्वितीय चरण टेकिफ सेकेण्ड ये 2011–12 से शुरू है मैंने पिछले दो वर्षो में भी ध्यान आकृष्ट कराया था कि आप निजी क्षेत्र के इन्जीनियरिंग कालेज को अगर मदद करनी है, इसमें चार करोड़ रुपये की सहायता विभाग के लोग दे रहे हैं, अगर मदद करना ही चाहते हैं तो उन संस्थाओ की मदद करिये जो बन्द हो रहे हैं, जो खराब हो रहे हैं। मान्यवर हमने देखा पिछली बार इसने तीन निजी क्षेत्र के दो इन्जीनियरिंग कालेज थे इस बार घटाकर एक कर दिया, जो आई0एफ0डी0एम0 यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में है उसको चार करोड़ रुपया दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि यह पहले से एक इन्जीनियरिंग कालेज था और आज की तारीख मैं यह स्थापित यूनिवर्सिटी है इनके पास पैसों की कमी नहीं है, पूरा एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं उनको सरकार इस तरह की मदद की आवश्यकता कहां से आ पड़ी। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके चयन का तरीका क्या है ?

किस लिहाज से क्या पिक एण्ड चूज कर लिया गया या जिसको इच्छा हुई दे दिया गया। करोड़ो रुपया हम दे रहे हैं और एक का चयन कर लिया, निश्चित तौर पर मान्यवर इसके पीछे क्या है, यह समझने की बात है। पेज 5 पर यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सुविधाओं की बात कही गयी। सुविधाओं के नाम पर इन्होंने 21–2 और 27 प्रतिशत आरक्षण की बात कही है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यह तो संवैधानिक व्यवस्था है यह कोई विश्वविद्यालय स्तर से सुविधा नहीं दे रहे हैं। अगर सुविधा देनी है मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि यूपीटीयू हमारे देश का इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जहां कमजोर वर्ग चाहे वह सामान्य हो, चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे छात्रायें हो एक रूपये की छूट का प्राविधान नहीं है।

प्राविधान तो दूर की बात है पिछले वर्ष इस परीक्षा शुल्क को दुगना करने का काम यूपीटीयू के लोगों ने किया। कई बार प्रश्न आया, चिट्ठी लिखी क्वैश्चन भी लगाया लेकिन कही कोई हल नहीं निकला। अब आगे आते हैं यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है यह सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेजेज यह पेज 7 पर है स्वीकृत प्रवेश क्षमता, 4544 छात्रों की प्रवेश क्षमता है और 4046 छात्रों ने प्रवेश लिया है सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेजों में। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मान्यवर, कि आज उत्तर प्रदेश का छात्र उत्तर प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कालेज में नहीं पढ़ना चाहता। यह टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लोग जो बैठे हैं इनके लिए सोचने की बात होगी कि क्यों आखिर। निश्चित है हमारे पास सुविधा नहीं है हमारा आकर्षण खत्म हो रहा है यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। मान्यवर, इसी पेज में टापिक 172 पर जायेंगे तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है जो वर्ष 13 में 70 था वर्ष 14 में 81 हुआ और पता नहीं इस बार कौन सी आफत आई है यकायक 16 प्रतिशत घटकर यह 66 प्रतिशत पर आ गया यह बहुत ही चिन्ता की बात है। पेज संख्या 61 पर देखिये विश्वविद्यालय के स्तर पर इन्होंने लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एससी, एसटी, अल्पसंख्यक के लोगों को सुविधाओं के नाम पर 25 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह के लिए यह पुस्तकालीय सहायता दे रहे हैं। पिछली बार भी हमने कहा था एक टेक्निकल स्टूडेन्ट के लिए जिसकी फीस किसी भी संस्थान में 50 हजार रूपये वार्षिक से कम नहीं है ओर यह 25 रुपया महीना दे रहे हैं। पिछली बार भी हमने ध्यान आकर्षित कराया था और मंत्री जी शर्मशार हुये थे उन्होंने स्वीकार किया था कि गलती है। मान्यवर, यह बजट पुस्तिका फिर उसी रूप में हमारे सामने आ गयी इसमें कहीं से भी कोई सुधार नाम की चीज नहीं है। यह कहीं न कहीं अफसोस भी होता है। मान्यवर, मैंने सुझाव दिया है माननीय मंत्री जी नौजवान हैं हमारे मुख्य मंत्री भी टेक्नोक्रेट हैं उन्होंने टेक्निकल एजूकेशन ली है इस विभाग पर कुछ विशेष निगाह रखेंगे ऐसा हमें भरोसा है बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री यासर शाह–

मान्यवर, दीपक जी ने बहुत अच्छी–अच्छी बाते कहीं। पिछली बार भी उन्होंने इसी प्राविधिक शिक्षा का कटमोशन पेश किया था और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने वही फिर वही प्रेक्टिस दोबारा दोहराई है। मैं सिर्फ यह कहूंगा बहुत ज्यादा लम्बी बात नहीं कहूंगा अगर लम्बी बात करेंगे तो सरकार की या प्राविधिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियां अपने आप में इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा समय लग जायेगा। मुझे भी पता है कि बहुत समय हो गया है मैं सिर्फ यह कहूंगा कि अगर कोयले की खान से हीरे को निकालने का काम माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा करती है तो हीरे को तराश करके आभूषण में लगाने का काम प्राविधिक शिक्षा विभाग करता है। प्राविधिक शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो किसी भी बच्चे को किसी के भी टैलेन्ट को उभार सकता है और उसको इस लायक बना सकता है कि वह इस दुनिया में आकर के अपनी दो वक्त की रोटी कमा सके और अपने देश का, अपने परिवार का अपने घर का नाम रोशन कर सके। बहुत सारी योजनायें प्राविधिक शिक्षा विभाग ने शुरू करी हैं, बहुत सारी योजनायें

हमारी हैं बहुत सारी योजनायें हम लेकर के आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात जो माननीय सदस्य ने कही कि सरकारी कालेजों में प्रवेश के लिए बच्चे नहीं मिलते इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में आने वाले कल के लिए एक ऐसी तैयारी कर दी है कि आने वाले समय में जो पिछले चार साल से जो मैंहनत, जिस तरह से बड़ी बड़ी कम्पनी का उत्तर प्रदेश में आने का रास्ता साफ हुआ है नौकरी आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमैंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में उस हिसाब से यह तैयारी करना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में बच्चों को पढ़ने के लिए एडमीशन के लिए कोई दिक्कत कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े और आज भी हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट जो कानपुर में है वह उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा ग्रहण करने का टाप टेक्निकल कालेज हैं और वह भी सरकारी कालेज ही है और उसका स्टैण्डर्ड सारे प्राइवेट कालेजों से कहीं बेहतर है। मैं माननीय सदस्य से सिर्फ यही कहूंगा कि आने वाले कल के लिए बच्चों के भविष्य के लिए उनको अच्छी प्राविधिक शिक्षा देने के लिए इस बजट को पास करा दिया और कटमोशन वापस ले लिया जाय, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं। इन्होंने कहा कि कर सब सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं यह बड़ा अफसोसजनक है। कुछ कर दीजिये, हम कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ बातें हमारी मान लीजिये। मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,03,80,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–21 खाद्य एवं रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21–खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 79,84,91,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं आपका, माननीय नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी का जिन्होंने मुझे खाद्य एवं रसद जैसे महत्वपूर्ण विभाग का बजट रखने का मौका दिया। मान्यवर, खाद्य एवं रसद विभाग वह महत्वपूर्ण विभाग है जो गरीब, कमजोर और हर उस आदमी को जिसको जरूरत है, उसे खाद्यान्न और जरूरत का सामान मुहैया कराता है। यह विभाग हमारे उस अन्नदाता जो इस देश की सुरक्षा में लगे जवानों के लिए, उस किसान के लिए जो तपती धूप और सर्द रातों में मैंहनत करके अपनी फसल उगाता है और सोचता है कि कहीं उसकी फसल कोई बिचौलिये न ले जाये या बिचौलिये उसका शोषण न कर लें। जब वह फसल पैदा करता है तो सोचता है कि उसकी कीमत और लाभकारी मूल्य उसे मिल जाये। उसकी फसल को शोषण से बचाकर खरीद करने का काम हमारा विभाग करता है। अध्यक्ष जी, अभी जब कृषि विभाग का बजट प्रस्तुत हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय साथी और कांग्रेस पार्टी के कई साथियों ने कहा कि कहीं पर भी धान की खरीद हम लोगों को देखने को नहीं मिली, कहीं पर सेण्टर नहीं देखने को मिले। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2015–2016 के अंदर समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अपनी एजेन्सियों से बहुत खरीद की, जबकि हमारा निर्धारित लक्ष्य तीस लाख मीट्रिक टन था, उसके सापेक्ष 42.51 मीट्रिक टन हम लोगों ने खरीद की, जो सापेक्ष लक्ष्य से बहुत अधिक है। किसानों से हम लोगों ने 42.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। यह खरीद पिछले पन्द्रह सालों में सबसे अधिक है। इतनी खरीद कभी नहीं हुई और हिन्दुस्तान के अंदर पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नम्बर का सूबा है जिसने माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी खरीद करने का काम किया है। जहां तक सवाल है गेहूं की फसल का, हम लोगों ने इस बार तीस लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार हम लोग बिचौलियों के शोषण से बचाकर किसान के हित मैं रिकार्ड खरीद करेंगे और इसकी तैयारी के लिए हम लोग 5164 क्रय केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं। किसान हित के अंदर कई काम हमारी सरकार कर रही है। किसानों से खरीद, केन्द्रों पर उतराई, सफाई का कोई पैसा विभाग द्वारा नहीं लिया जाता है। यह व्यवस्था मण्डी परिषद् से की जाती है और जहां तक सवाल है कि खरीद के अंदर, किसानों के अंदर जागृति लाने के लिये हम लोग अखबार के माध्यम से, एफ0एम0 रेडियो के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का काम करते हैं । अध्यक्ष जी, हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग अपने–अपने क्षेत्रों के अंदर जब जाते थे तो क्षेत्रों के अंदर जाने पर अक्सर किसी गांव के अंदर, या किसी शहर के अंदर जब किसी गरीब बस्ती के अंदर जाते थे तो हम लोगों को लोग घेर लिया करते थे और कहते थे कि हम लोगों का लाल राशन कार्ड बनवा दो, सफेद राशन कार्ड बनवा दो, बी0पी0एल0, अंत्योदय का कार्ड बनवा दो वह लोग कहते थे कि हम लोग जरूरतमंद है और हमें राशन कार्ड की जरूरत है। हम लोगों को राशन कार्ड

मिले, हम लोगों के सामने सीमित संख्या होने के कारण उन लोगों का राशन कार्ड नहीं बनवा पाते थे । इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे जरूरतमंद लोग थे जो राशन मिल पाने से रह जाते थे। मैं नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके नेतृत्व में हम लोगों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण में 28 जिलों के अंदर और पहली मार्च को 47 जिलों के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया है। आज आप देखिये पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड यह ऐसे छोटे–छोटे राज्य हैं जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के बाद अपनी बात बड़ी करने के लिये कहते हैं। लेकिन मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में इतनी बड़ी स्कीम मैं जो खामियां और कमियॉ थीं, उनको दूर करके हम लोगों ने इस स्कीम को लागू करने का काम किया है। इस स्कीम के तहत हम पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 80 फीसदी और शहरी क्षेत्रों के अंदर करीब 65 फीसदी लोगों को कवर करने जा रहे हैं, इन लोगों को हम लोग दो रूपये किलो गेहूं, तीन रुपये किलो चावल और एक रुपये किलो मोटा अनाज मुहैया कराने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस बार डबल फोर्टीफाइड नमक की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर की है जहां पर 10 जनपदों के अंदर गर्भवती महिलायें, मातायें और बच्चे एनीमिया की वजह से प्रभावित हो जाते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस बीमारी को और कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिये 10 जनपदों में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत डबल फोर्टीफाइड नमक बांटने का निर्णय किया है। इसको हम लोग 10 जनपदों में बी0पी0एल0, अंत्योदय और ए0पी0एल0 के साथ न्यूट्रीशन वाले कार्डो पर लोगों को मुहैया करायेंगे। जहां तक सवाल है बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों को वितरण के समय चीनी नहीं मिल पाती थी, इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग पूरे प्रदेश में चाहे ए0पी0एल0 वाला हो, बी0पी0एल0 वाला हो, अंत्योदय या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत आता हो, हम सारे लोगों को चीनी वितरण करने का काम करेंगे। जहां तक सवाल है अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी हमेशा बुन्देलखंड के लिये चिन्तित रहे हैं हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है और माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से लिखा है मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहूंगा कि खाद्य सुरक्षा के तहत जो हम लोग योजना लाये हैं उसके अंदर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत 80 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में जो 64–65 फीसदी लोगों को कवर कर रहे हैं इसमें हम लोगों ने केन्द्र सरकार को चिठ्ठी लिखी है कि इसमे हम लोगों को छूट दे दी जाय जिससे हम लोग बुन्देलखंड के अंदर 100 परसेंट लोगों को कवर कर लें और यह हम बुन्देलखंड में फ्री देंगे। यदि यह छूट मिल जायेगी तो हम लोग इसे करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषणा की है कि जो दो रुपये तीन रुपये किलो मिलेंगे, उसको भी यह सरकार वहन करेगी । विभाग के अंदर हम लोगों का पूरा प्रयास है कि निष्पक्षता के साथ, जो गरीब का हक है, जो सरकार की प्राथमिकता है जो गरीब किसान, जो अन्नदाता, जो हमारे लिये इस देश के लिये रोटी

रोजी मुहैया कराता है उसकी सही उचित मूल्य की खरीद हो और वह लोग जो इसके वास्तविक हकदार हैं उनका हक हम उन तक पहुंचा दें यह हम लोगों का पूरा प्रयास है।

श्री दीपक पटेल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, हमारा उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यह विभाग भी बहुत पुराना है, आजादी के पहले का यह विभाग है और बहुत बड़ी आबादी की अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ यह विभाग है। माननीय मंत्री जी ने विभाग के बारे में, योजनाओं के बारे में बड़े विस्तार से बताया लेकिन जो सच्चाई है, विभाग की जो सामाजिक छवि है, माननीय मंत्री जी की भाषा की इस बजट पुस्तिका से कोई साम्यता नहीं है, कोई मैंच नहीं है। आज विभाग की जो सामान्य छवि है वह नौकरशाही और जो प्रशासनिकतंत्र इसमें शामिल है, उस मकड़जाल में उलझी हुई और भ्रष्टाचार के आकण्ठ में डूबी हुई, पूरा का पूरा विभाग आज इन स्थितियों में है। जिन असहाय, कमजोर लोगों की मद्द के लिए विभाग की स्थापना की गयी थी आजादी से पहले, उनको छोड़कर जो भी इस तंत्र में शामिल हैं, इस विभाग में शामिल हैं सभी खुशहाल हैं सिर्फ दुःखी वही है जिसके लिए इस विभाग की स्थापना की गयी थी। मैं निजीतौर पर वह विभाग जो जनता की सहूलियत से जुड़ा हो, मैं उसकी मुखालिफत में बहुत यकीन नहीं करता। लेकिन मान्यवर, अपनी ऑखों के सामने जो भ्रष्टाचार हो रहा है खासतौर से इस विभाग में, यह देखकर चुपचाप भी नहीं रहा जा सकता। यहां बैठे सारे लोग, बहुत बड़ा काम है विधान सभा में आना, बड़े व्यवहारिक हैं जमीनी स्तर से लड़कर, जूझकरके आते हैं। सबको हकीकत पता होगी कि कोटेदार, भ्रष्टाचार और मालदार। मान्यवर, कहीं न कहीं हम सबको दोष नहीं देते, सिस्टम में भी दोष है ऊपर से नीचे तक। अभी तीन दिन पहले प्रश्नकाल में बहस हो रही थी, मैं तो नहीं था लेकिन समाचार पत्रों में आया था कि 58 फीसदी जो पी0डी0एस0 सिस्टम का अनाज है वह गरीबों तक नहीं पहुॅच पा रहा है। मेरे हिसाब से यह ऑकड़े और ज्यादा हैं, माननीय मंत्री जी इस पर गौर करने की जरूरत है। सही मायनों में अगर आप उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं जो अभी आपने कहा है, अभी–अभी आपने मंत्रालय संभाला है, बहुत दिन नहीं हुए हैं बहुत कुछ आपको करने की जरूरत है। मान्यवर, अब हम किताब की ओर जाते हैं यह जो किताब है पिछली बार, सही मामलों में कटौती का प्रस्ताव तो हम लोग दो दिन से कर रहे हैं, असली कटौती, घटौती है तो इसी विभाग में है। आज पी0डी0एस0 सिस्टम जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको कहते हैं कि आज की तारीख में यह वास्तव में धोखा सिस्टम है, जिस तरीके से सरकारी स्तर पर जो हम कमीशन कोटेदार को देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो पारदर्शिता बरतेगा, ईमानदारी बरतने का काम करेगा,

यह सम्भव नहीं है फिर भी हम सब जानकरके आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, बहुत गंभीर बात है। हम तो कहेंगे कि पारदर्शिता लाईये। जो निचले स्तर की इकाई है, जो भी कोटेदार हैं या जो भी हैं जो काम कर रहे हैं वह जनसेवा के लिए नहीं कर रहे हैं उनका उद्देश्य भी लाभार्जन है। मनमाफिक फायदा तो नहीं कहेंगे लेकिन एक जेन्यूइन प्रॉफिट जो किसी भी व्यापार में होता है, अगर वह नहीं मिलेगा तो वह कैसे काम करेगा ? वह निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार करेगा। मैंने देखा है बचपन से, काफी दिनों से जब से सामाजिक जीवन में आये, अब तो नहीं जानते, जाना नहीं होता, नहीं तो तहसीलों में जो जनरेटर चला करते थे एस0डी0एम0 साहब के तो कोटेदार लोग चन्दा करके चलाया करते थे तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं करेप्शन होगा।

अपने पास से तो करेंगे नहीं मान्यवर, कहीं न कहीं घटतौली और कटौती जो हमने कहा है उसी के आधार पर करेंगे। मान्यवर, योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन यह वास्तविकता के धरातल पर उतरनी चाहिए। अभी इन्होंने फूड सिक्योरिटी जिसका जिक्र हमारे माननीय मंत्री जी कर रहे थे, यह जो ऐक्ट इन्होंने बनाया, लागू किया पूरे प्रदेश के अंदर अच्छा है मान्यवर। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर पहुंचते–पहुंचते मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि सिस्टम वही है, काम करने वाले वही है, यह भी उसी का शिकार हो जायेगा जैसे इस विभाग की सारी योजनाएं चली गईं। मैं गौर कराना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि अभी जो राशन कार्डों का डिजिटाइजेशन का काम हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ प्रदेश के अन्दर। बड़ी संख्या मैं लोगों का यह अधूरा है और राशन कार्डों की जो जांच की जा रही है वह भी पूरी नहीं हुई है। तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं मान्यवर, इन स्थितियों में हम कि इन योजनाओं का लाभ समाज के उस अन्तिम व्यक्ति को मिलेगा जिसके उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है। मान्यवर, एक बात और गौर करने वाली है कि बहुत बड़े पैमाने पर कर्मचारियों का भी अभाव है विभाग के पास और इधर पिछले कई वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पर इस विभाग में करेप्शन बढ़ा है। सी0बी0आई0 जांच तक हो रही है कोर्ट के माध्यम से। और मान्यवर, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं डोर स्टैप डिलीवरी के बारे में। अगर भ्रष्टाचार को कम करना है मान्यवर, तो आप बजट बढ़ा लें, बजटीय प्राविधान बढ़ा लें और इसको लागू करना माननीय मंत्री जी हम माननीय अध्यक्ष के माध्यम से आपके कहना चाहेंगे कि यह जो डोर स्टैप डिलीवरी है आप इस पर फोकस करें। कन्सन्ट्रेट करें और काफी हद तक करेप्शन खत्म हो जायेगा अगर यह सिस्टम प्रदेश के अंदर लागू होगा। मान्यवर, यही हाल रसोई गैस के डिस्ट्रीब्यूशन का भी है।यह भी इसी विभाग का एक हिस्सा है। और जो योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने का उद्देश्य इसका है जिसमें केन्द्र सरकार के साथी भी है।। यह जो बी0पी0एल0 अन्त्योदय या जो भी कार्ड की दिक्कतें हैं यह पात्र व्यक्तियों के पास नहीं हैं इसलिये नहीं पहुंच पा रहा है। मान्यवर, इसलिये जरूरत इस बात की है कि यह फिर से रिवाइज हों। 2001 के बाद कोई रिवाइज नहीं हुआ। यह रिवाइज हो और सही पात्र व्यक्ति इसमे आयं तब ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। आखिरी बात के साथ मान्यवर, मैं इशारा समझ रहा हूं। विधान सभा की कैन्टीन की

अधिकारिता भी मंत्री जी की है। आज मंत्री हुए हैं तो जाना कम होता होगा लेकिन इसके पहले कई बार वहीं पर मुलाकात होती थी। वहां की स्थिति बहुत खराब है। वह इस तरीके से खाना परोसा जाता है। हम चाहेंगे कि जो यहां से सब्सीडी जाती है उसको बढ़ा दें और हम लोग पैसा देने को तैयार हैं जो भी हो। उसमें पैसा ले लें एकदम टू पे रखें हम नहीं कहते कि हम लोगों को खाना सब्सीडाइज करें लेकिन क्वालिटी सुधारें। क्वालिटी सुधारें, जगह तो खैर ठीक है। कुछ आइटम बढ़ा दें जो माननीय सदस्यों को पसन्द हों। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं ध्यान आकर्षित करूंगा और लिखकर भी दूंगा कि यह जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें कई कोटेदार हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र में हैं बीस–बीस सालों से आधा–आधा दर्जन तक कोटा इनके पास है।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे खाद्य के बजट पर बोलने की अनुमति प्रदान की।

श्री अध्यक्ष–

बोलने की नहीं दी। कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे पटेल जी ने कोई चीज छोड़ी नहीं है। आपको हर चीज जरूरी लगती है।

'श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज–

माननीय मंत्री जी ने बुन्देलखंड के बारे में बहुत चिन्ता व्यक्त की है। मैं बुन्देलखण्ड के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि वहां अकाल की स्थिति पड़ी हुई है। आपने कहा कि वहां राहत सामग्री बांटने की बात की जा रही है। वहां भुखमरी की स्थिति पड़ी हुई है। पूरा बुन्देलखण्ड अकाल की स्थिति से जूझ रहा है। वहां तत्काल राहत दिये जाने की आवश्यकता है। आप कब देंगे समझ में नहीं आ रहा है। जब तक लोग पलायन करने की स्थिति में हैं, भाग रहे हैं। आपने कहा कि अन्त्योदय लोगों को ही हम राहत सामग्री बांटेंगे। हम चाहते हैं कि वहां पर शत प्रतिशत लोगों को राहत की आवश्यकता है। 90 परसेन्ट वहां किसान की बुआई नहीं हुई, सूखा पड़ा हुआ है। दाने दाने को वह मोहताज हो रहे हैं। आज बुन्देलखंड के बारे मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिन्ता व्यक्त की है, सारे सदन ने चिन्ता व्यक्त की है। आपने भी अपनी बातों मैं कहा है। मैं चाहूंगा कि बुन्देलखंड को थोड़ा गम्भीरता से लें और वहां तत्काल राहत पहुंचाई जाय। शत प्रतिशत परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाई जाय। श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरु भैया मान्यवर, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद् आपने बोलने का अवसर दिया मान्यवर खाद्य के जो लाइसेंस बनते थे कोटेदार की जो दुकानें बनती थीं उसमे अध्यक्ष जी व्यवस्था यह है कि शहरों में डी0एस0ओ0 के अधिकार में रहता था दुकानें चयन करना, निरस्त करना, निलम्बित करना,उनके नियंत्रण में होता था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह एस0डी0एम0 के पास है और एस0डी0एम0 अगर कोई गलत काम करता है उसको सस्पेंड करने का, उसको बहाल करने का या उसमे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो यह खाद्य

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग के अधीन आता नहीं है। हमने यहां तक कहा, कई बार हमने यह मामले उठाए कई बार खाद्य मंत्री जी ने खाद्य विभाग में उसकी जांच कराई, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से मॉग करता हूं कि अब जो लागू करने जा रहे हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसमें खाद्य पहुंचेगा तो इसमें ऐसी व्यवस्था हो कि गलत अगर कोई कर रहा है तो विभाग जैसे जेल मंत्री जी ने जेल विभाग के लिए बहुत सी घोषणायें की, तो खाद्य विभाग के इन दुकानदारों पर एस0डी0एम0 महोदय, परगनाधिकारी द्वारा गलत किया जाता है तो इसमे खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए उसको अपने नियंत्रण में रखा जाए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर,एक जानकारी हम चाहते हैं हम अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं हम यह जानना चाह रहे हैं कि यह जो खाद्य सुरक्षा बिल आप लाए हैं और गांव में जो आप पात्रों का चयन करेंगे जो पहले गड़बड़ियां होती थीं कि पात्रों के चयन ऐक्ट भेदभाव हो जाता था और सचमुच के जो पात्र हैं वह छूट जाते थे और जैसे हमारी प्रधानी है तो हमारे पक्ष के लोग हो जाते थे ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप यह भी आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा जो सचमुच पात्र व्यक्ति है उस तक आपका मैंटीरियल कैसे पहुंचेगा यह जरूर बता देंगे।

श्री कमाल अख्तर–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक सवाल है हमारे साथी दीपक जी ने कट मोशन रखा है उन्होंने कहा कि कोटेदारों के जो डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम हैं, कोटेदारों के वितरण सिस्टम में गड़बड़ी के बारे में उन्होंने बताया। तो माननीय अध्यक्ष जी हम लोगों की प्राथमिकता है और हम लोग चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के अन्दर जो खामियां हैं उसको हम लोग दूर करें यह हम लोगों की प्राथमिकता है और हम लोगों ने इसमें प्रयास भी किया है क्योंकि कोटेदार को बहुत कम धनराशि लाभांश की मिलती थी इससे पहले हम लोगों ने बढ़ाया था जो राशि 17 रुपये प्रति कुंतल मिलती थी उसको हमने बढ़कर 30 रुपये कुंतल किया था और अब एन0एफ0एस0ए0 लागू होने के बाद लाभांश बढ़कर 70 रुपये कुंतल हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि लाभांश जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पर उनकी नीयत और सोच में कहीं न कहीं बदलाव आएगा। जहां तक सवाल है इसके अन्दर जहां–जहां हम लोगों को पता चला है वितरण प्रणाली के अन्दर गलत हो रहा है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हम लोगों ने उसके ऊपर त्वरित कार्यवाही की है और आगे भी अगर इस तरह की चीजें पता चलती हैं तो हम लोग उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। हमने अप्रैल 2015 से लेकर नवम्बर 2015 तक, 22 हजार 355 छापे मारे, 332 एफ0आई0आर0 दर्ज की गईं और 114 लोग गिरफ्तार हुए, 1806 दुकानें निलम्बित हुईं, 937 दुकानें निरस्त हुईं और एक करोड़ 56 लाख रुपये की जमानत राशि जब्त की गई और 5 लाख 56 हजार की आवश्यक वस्तुयें जब्त की गईं। यह हम लोगों ने इस पर कार्यवाही की है और आगे भी कहीं कोई इस तरह की चीज होती है तो हम लोग उस पर कार्यवाही सख्त से सख्त करेंगे। जहां तक

कार्ड का मामला है खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद इसमें पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग बहुत जल्दी शहरों के अन्दर डिवाइस सिस्टम लागू करने जा रहे हैं निश्चित तौर पर पारदर्शिता इसमें आएगी। जहां तक राशन कार्ड का मामला है तो यह सारे जिलाधिकारियों को निर्देश कर दिए गए हैं जो इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन एवं राशनकार्डों के वितरण में परिवारों के वर्तमान राशनकार्डों का सत्यापन अभियान चलाकर निरस्त करने के निर्देश समस्त जिलापूर्ति अधिकारियों को दिए गए हैं। किसी भी दशा ऐक्ट पात्र व्यक्ति योजनानुसार राशन प्राप्त करने से वंचित न रह जाए और कोई अपात्र व्यक्ति राशन प्राप्त न कर पाए पूरी जिम्मैंदारी डी0एस0ओ0 की है हम लोग बहुत जल्द इसके डेटा फीड करने जा रहे हैं। जहां तक घरेलू गैस का सवाल है उसके अन्दर भी हम लोग कार्यवाही करने जा रहे हैं जहां तक हमारे साथी ने चिन्ता व्यक्त की मैं इस बात को स्वीकार करता हूं इस सदन का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो कैंटीन के भोजन पर अपनी चिन्ता व्यक्त न करता हो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी से दिशा निर्देश लेकर जब अगली बार हम लोग इस सदन में मिलेंगे तो निश्चित तौर पर इसका अलग नजारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपकी इच्छानुसार हम लोग वहां पर अच्छा भोजन उपलब्ध कराएंगे। बस अध्यक्ष जी की कृपा हो जाएगी तो हम लोग कर देंगे। जहां तक बुन्देलखण्ड का सवाल है भदौरिया जी ने कहा माननीय मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकताओं में बुन्देलखण्ड है माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे पूरे विभाग की प्राथमिकता में बुन्देलखण्ड है मैं समझ रहा हूं कि हम लोगों ने जो तत्कालिक काम किए हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो भी चीजें थीं उसके बारे में बहुत सख्त निर्देश गए हैं और अधिकारियों की पूरी अलग से टीम बनाकर बुन्देलखण्ड के हर जिले के अन्दर हमने तैनात किया है। इस योजना के अन्तर्गत लोगों को खाद्यान्न मिल जाए जिससे उनकी जो परेशानी है उसका हल हो सके। जहां तक डोर स्टेप डिलेवरी का आप लोगों ने सवाल किया हम लोग इस तरफ तेजी से काम कर रहे हैं में पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस वित्त वर्ष के अन्दर हम लोग बहुत जल्दी इसको पूरा कर लेंगे जहां तक श्री राजेश त्रिपाठी जी ने बताया है कि इसमे चयन की प्रक्रिया है तो हम लोग न्याय पंचायत स्तर पर ब्लाक स्तर पर और जिला स्तर पर प्रचार के माध्यम से और इस योजना के अन्तर्गत क्योंकि यह ऐसी स्कीम है जिसमे माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अगर सारे जनप्रतिनिधि पूरा सहयोग कर देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह स्कीम पूरी तरह से इम्प्लीमेन्ट हो जाएगी। हर जन प्रतिनिधि जानता है कि अगर वह अपने क्षेत्र में इस योजना को अच्छी तरह से लागू करके ले गया तो मैं नहीं समझता कि 2017 में किसी को परेशानी होगी। जहां तक पात्रता का सवाल है हम लोगों की पूरी जागृति अखबारों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने अधिकारियों को न्याय पंचायत स्तर पर भेजकर खुली बैठक करके पात्र व्यक्तियों का चयन करें अगर कहीं पर कोई कमी रहेगी तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमें लिखित में दे दें तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि पात्रों को हम लोग

उसमे शामिल करा लेंगे जहां तक कटौती प्रस्ताव का सवाल है यह गरीबों से जुड़ा हुआ किसानों से जुड़ा हुआ मामला है मैं समझता हूं कि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो गरीबों के लिए न सोचती हो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आपकी पार्टी गरीबों के लिए कम सोचती हो लेकिन मैं कहता हूं कि गरीबों के हक के लिए किसानों के हक के लिए इस कटौती प्रस्ताव को वापस लेकर इस बजट को पास कराने का कष्ट करें।

श्री दीपक पटेल–

हमारे मंत्री जी बहुत काबिल हैं योग्य हैं और नाम के अनुरूप कमाल भी करते हैं इनको बहुत तगड़ा प्रमोशन मिला है हमें उम्मीद है कि विभाग में भी कमाल करेंगे मंत्री जी बहुत आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। मान्यवर एक छोटी सी बात रह गई थी यह कई लोगों से जुड़ी हुई है हमारे बगल की विधान सभा क्षेत्र में एक भारतगंज कस्बा है यहां पचासों लोग पात्र थे पिछले चार महीने से स्थानीय कोटेदार द्वारा इनको वंचित कर दिया गया है यह बी0पी0एल0 के लोग हैं तहसील मेजा है हम इसे लिखकर भिजवा देंगे। मंत्री जी इस पर गौर कर लेंगे। एक पालिसी बना दें कि एक कोटेदार के पास जो एक दर्जन अटैच होते हैं एक नीति बना दें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि अभी पूरी ग्राम पंचायतों के पूरे प्रदेश में परिसीमन हुये हैं तो जो नयी पंचायतें गठित हुयी हैं वहां पर कोटेदारों की नियुक्तियां आप कब तक करेंगे ? दूसरा, मा0 मंत्री जी को मेरा एक सुझाव है कि जो भी राशन वितरण हो रहा है, यह तय है कि हमको इसको दो किलो देना है, पांच किलो देना है। इसलिये इसके पैकेट बंधवा लिये जायें जिससे इसमे जो लीकेज है वह कम हो जाये। धन्यवाद।

श्री कमाल अख्तर–

मा0 अध्यक्ष जी, जो नयी ग्राम पंचायतें बनी हैं उनका आदेश जारी कर दिया गया है और मैं समझता हूं कि एक महीने के अन्दर सभी दुकानों का चयन हो जायेगा और जो हमारे पटेल साहब ने कहा, उस पर हम लोग क्योंकि कई अटैचमेट लगने के बाद अक्सर यह शिकायतें थीं कि बहुत सारे ग्रामीण एरिये के अंदर और शहरी एरिये के अंदर बहुत सारी दुकानें निरस्त थीं या किसी कारण से नयी दुकानें नहीं हो पायी थीं, अटैचमेट लगने की वजह से अक्सर ऐसा होता था कि जो जरूरतमंद लोग थे उन्हें राशन नहीं मिल पाता था, उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती थी। हमने आदेश कर दिया और एक माह के अंदर–अंदर हम लोग उन सारी दुकानों का प्रस्ताव कराकर जो पात्र लोग होंगे उनको दे दी जायेंगी और निश्चित तौर पर जो अटैचमेंट का सिस्टम है, हमारा प्रयास है कि वह ज्यादा लंबा न खिंचे और एक महीने के अंदर जो भी डीसी स्तर पर पेंडेंसी हैं उसको भी खत्म करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 79,84,91,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 05 मार्च, 2016 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 06 मार्च, 2016 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायें।

2–दिनांक 08 मार्च, 2016 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मदें ली जायें:–

1–उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण)(संशोधन) विधेयक, 2016

3–उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016

4–उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

3–शेष कार्यक्रम यथावत रखा जाए।

नियोजन एवं ऊर्जा, राज्य मंत्री (श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई'')–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मा0 चिकित्सा मंत्री जी प्रस्ताव रखें।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और महामहिम श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 62,59,40,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,14,71,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 53,77,58,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं, अच्छी तरह से भिज्ञ हैं, 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के समय पटरी से बे–पटरी हुए इस स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी जब हम लोगों के कंधों पर आयी थी, उस समय पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के ऊपर ऐसा बदनुमा दाग लगा था, जिसका असर केवल देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जगजाहिर हो रहा था और जिसके बारे में आप जानते हैं कि हम लोगों ने नहीं, सी0बी0आई0 कोर्ट ने इस विभाग के जो जिम्मेदार लोग थे, उस समय के उन जिम्मेदार लोगों में मंत्री सहित सैकड़ों लोग आज भी जेल में हैं। ऐसे बदनामशुदा विभाग की जिम्मेदारी जब मा0 मुख्य मंत्री जी ने बहुत सोच–समझ करके हम लोगों के कंधे पर रखा था तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंज था कि पूरे प्रदेश में इस स्वास्थ्य विभाग के लिए जो गरीब के लिए है, सरकारी अस्पताल गरीबों का अस्पताल होता है,

जहां पर केवल गरीब अपनी दवा कराने जाता है और वह गरीब जहां पर दवा लेने जाता है, वहां की हालत पूरे प्रदेश में कमोवेश यह हो गयी थी कि केवल दवाओं का पर्चा लिखा जाता था। उसका कारण था, माननीय अध्यक्ष जी कि पूरे प्रदेश में दवाओं की खरीद एक जगह से होती थी, सेन्ट्रलाइज ढंग से खरीद की जाती थी और उस खरीद के नाम पर करोड़ों–करोड़ों रूपये का वारा–न्यारा होता था तो सबसे जरूरी चैलेंज यह था कि गरीब को दवा किस तरह से उपलब्ध हो। तो सबसे पहला काम जो पूरे प्रदेश में गरीब को दवा उपलब्ध कराने का था, उन्हें तीन दिन की दवा मिलती थी, उस तीन दिन की दवा को 5 दिन के लिए उपलब्ध कराने का आदेश किया गया सरकार बनने के 3 दिन के अन्दर और गंभीर परिस्थितियों में, क्रिटिकल बीमारियों में मरीजों को एक साथ 15 दिन की भी दवा दिए जाने की व्यवस्था की गयी थी। उस समय 2012 में जो आवश्यक दवाओं की सूची थी, जो सरकारी तौर पर खरीदने का था, उसमें केवल 547 दवाएं थी, उसको बढ़ा करके सूची में 1079 आवश्यक दवाओं का विस्तार किया गया। दवा सही ढंग से पहुंचे, क्योंकि विशाल प्रदेश है तो प्रदेश की विशालता के हिसाब से विभिन्न एरिया में विभिन्न किस्म की बीमारियों का प्रकोप होता है, कहां पर किस दवा की जरूरत है तो इसको उपलब्ध कराने के लिए दवाओं की खरीद का विकेंद्रीकरण कराया गया। सी0एम0ओ0 को यह अधिकार दिया गया कि कौन सी दवा कितनी जरूरत है वह अपनी आवश्यकता के अनुसार दवा का आर्डर देगा और वहां से दवा जो आर0सी0 होगी, उसको आर0सी0 की दवा लेगा। इसी तरह से पूरे प्रदेश में हम लोगों ने कोशिश की कि सम्पूर्ण दवा और मुफ्त दवा अस्पतालों में उपलब्ध हों। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में अंतः रोगियों का जो फीस था गरीब को 35 रूपये एडमिट होने के लिए जो फीस था उस फीस को समाप्त कर एक रुपया कर दिया गया। फ्री दवा, फ्री एम्बुलेंस सेवा दिया। 100 पैथालाजी जांच को फ्री किया गया। डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराया गया।

इससे लोगों का सरकारी अस्पताल के प्रति विश्वास बढ़ा। और उसी का परिणाम है कि सरकार बनने के बाद हर साल लगभग 01 करोड़ ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ी है और वह एक करोड़ हर साल संख्या जो बढ़ी उसका परिणाम यह हुआ कि आज 9.7 करोड़ मरीजों की संख्या सालाना हो गयी है। महीने का लगभग 80 लाख पेशेंट को हम हर महीना देख रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, हमने चिकित्सा कैसे सस्ता सुलभ हो सके इसके लिए भी हमने काम किया। एक्स–रे हमने फ्री किया, अल्ट्रासाउंड की जांच हमने फ्री किया। 2011 में जो संख्या 115 लाख थी वह 2015 में पैथोलाजी की जांच 212 लाख, दुगुनी हो गयी है। अल्ट्रासाउंड जांच भी 20 प्रतिशत बढ़ा है। एक्स–रे की संख्या 2011 में 15 लाख थी। आज 2015 में एक्स–रे की संख्या बढ़कर 21 लाख हो गयी है। हमने तीन जगह पर एम0आर0आई0 की व्यवस्था की है। केवल लखनऊ में एम0आर0आई0 था। कानपुर में भी था, इलाहाबाद में भी हमने एम0आर0आई0 की सुविधा से जोड़ने का काम किया। पूरे प्रदेश में 38 डिजिटल एक्स–रे, 155 कलर डापलर थ्री डी अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था किया है। और पूरे प्रदेश में हमने अब तक 38 जगह पर आर्थोपेडिक सर्जरी, डाक्टर साहब को पता है कि आथ्रोपेडिक सर्जरी में जब हम

आपरेशन करते हैं, सीआर्म मशीन से आपरेशन होने पर केवल दस प्रतिशत ब्लीडिंग होता है। तो पूरे प्रदेश में हमने 38 जगह पर सीआर्म मशीन को भी इंस्टाल किया है। 40 जिलों में हाई एण्ड टेस्ट प्राइवेट सेक्टर को प्रतिष्ठित लेबोरेट्रियों के द्वारा हम सहयोग से निशुल्क कर रहे हैं। उनकी जांच निशुल्क करने की व्यवस्था की है। मा0 अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में आप भिज्ञ हैं अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग ग्रामीण अंचल से आते हैं। जब कभी कोई आकस्मिक दुर्घटना होती थी। अचानक कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाती थी तो उस समय गरीब को वाहन की व्यवस्था करने में पैसे की व्यवस्था करने के चक्कर में लाखों लोग हर साल काल के गाल में समा जाते थे। मा0 मुख्य मंत्री जी का सबसे बड़ा निर्देश यह था कि पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था मुहैया कराओ। जिससे गरीब को किन्हीं भी गम्भीर परिस्थितियों की बीमारी की दशा में उनको 20 मिनट से 25 मिनट के अन्दर अस्पताल ऐक्ट पहुंचाया जा सके, क्योंकि दुर्घटना मरीज का जो पहला घण्टा होता है, वह उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 14 सितम्बर, 2012 से समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा की शुरुआत की गई, आज पूरे उत्तर प्रदेश में 108 समाजवादी एम्बुलेन्स 1488 एम्बुलेन्स के द्वारा अब तक हम 51 लाख रोगियों को आवश्यकता पड़ने पर हम मरीजों को समय से पहुंचाने का लाभ दे चुके हैं। मान्यवर, यह व्यवस्था केवल जिले से जिले में थी, जिले के बाहर जाने के लिए रोगियों को परेशानी थी, तो अब वह भी व्यवस्था एम्बुलेन्स के लिए किया गया है कि अन्तर–जनपदीय ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी गोरखपुर से, जरूरत पड़ी बनारस से, जरूरत पड़ी जौनपुर से उसको केजीएमसी या पीजीआई में रिफर किया वहां के डाक्टर ने तो वहां से लखनऊ तक पहुंचाने की व्यवस्था एम्बुलेन्स के द्वारा की जा रही है और इन सब सेवाओं के साथ–साथ गर्भवती महिलाओं, हमारी माताएं, बहनें, बेटियों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए निःशुल्क 102 एम्बुलेन्स की जो व्यवस्था हमने किया है, 1964 एम्बुलेन्स 102 की अब तक चल रही हैं, आने वाले 15 मार्च को जिस दिन हमारे उत्तर प्रदेश की अपनी समाजवादी सरकार का 04 वर्ष पूरा होने पर 15 मार्च को समाजवादी विकास वर्ष मनाने जा रहे हैं, उस दिन हम 300 और नई 102 एम्बुलेन्स जोड़ने जा रहे हैं और जून–जुलाई तक हम 200 और एम्बुलेन्स देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, यह सारी बातें जो आपकी परफामेन्स वाली किताब होगी, उसमें सब लिखा होगा, अलग से कुछ बताने वाला हो तो बता दें।

श्री शंखलाल मांझी–

मान्यवर, अब एम्बुलेन्स 102 के द्वारा अब तक 80 लाख जरूरतमंदों को गन्तव्य तक पहुंचाने का काम किया है। मानव संसाधन की जहां तक बात है मा0 अध्यक्ष जी, सरकार बनने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी चुनौती थी सूबे के लिए 16 हजार से ज्यादा पदों के सापेक्ष मात्र साढ़े नौ हजार के करीब डाक्टर मौजूद थे, सरकार बनने के बाद लोक सेवा आयोग को हम लोगों ने अधियाचन भेजा था और लगातार प्रयास करने बाद चार सालों में अब तक हमने 4500 नए डाक्टरों की नियुक्तियां और

कराने में सफल हो पाये, आज भी हमारे यहां डाक्टरों की संख्या लगभग साढ़े बारह हजार के आस–पास ही है, जबकि आवश्यकता हमें 16 हजार से ज्यादा की है और उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने एन0आर0एच0एम0 के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संविदा पर डाक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की भी हमने बड़ी संख्या में भर्तियां की हैं, तीन वर्षों में हमने 2283 फार्मासिस्ट और 3281 ए0एन0एम0 की भर्ती स्थाई रूप से किया है। एस0सी0पी0 योजना के सेवा निवृत्त डाक्टर जो हमारे पास विषय विशेषज्ञों की जो शार्टेज थी, उस शार्टेज को दूर करने के लिए एस0एस0सी0पी0 योजना में सेवा निवृत्त विषय विशेषज्ञ डाक्टरों को पुनर्नियुक्ति हेतु 500 डाक्टरों तक की पुनर्नियुक्ति करने का आदेश जारी किया गया है और उसमें काफी बड़ी संख्या में विषय विशेषज्ञों की हमने भर्ती भी की है, 1500 नर्सों की पुनर्नियुक्ति के लिए भी आदेश दिया गया है। मा0 अध्यक्ष जी, हमने शिकायतों के निस्तारण के लिए टोल–फ्री नम्बर भी 24 ऑवर 7 डेज का 18001805145 यह व्यवस्था की है, और इसकी बकायदा जिस तरह से 1090, 100 नम्बर की मॉनिटरिंग होती है, उसी तरह की मॉनिटरिंग का यह टोल–फ्री नम्बर दिया है, जिसकी बकायदा मॉनिटरिंग करके हम व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री शंख लाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, बस शार्ट में खत्म कर दूंगा। हमने मुख्य रूप से अभी बजटीय में व्यवस्था बढ़ा दी है, वह है चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए योजनागत पक्ष के अंतर्गत कुल रूपये 8221.74 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में रुपये 7329.75 करोड़ के सापेक्ष लगभग 892 करोड़ लगभग 12.16 प्रतिशत अधिक के बजट का प्राविधान इस वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है। मान्यवर, आप जानते हैं, सपा सरकार ने जितनी योजनाओं को घोषित किया था, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए, निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं और अक्टूबर 2016 तक निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए कटिबद्ध हैं। जिसके लिए हमने रूपये 523.6 करोड़ की बजट व्यवस्था की है जो 2015–16 के सापेक्ष 139.48 करोड़ यानि 36.36ः ज्यादा बजट की व्यवस्था की है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप संक्षेप करें, वह बजट की किताब में है।

श्री शंख लाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह चूंकि पूरे प्रदेश के गरीबों से जुड़ा मुद्दा है इसलिए मैं थोड़ा सी कुछ अपनी बात रखना चाह रहा था लेकिन मैं आपका इशारा समझ रहा हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अभी सब लोग बोलेंगे तो उसमें आपको बोलने का मौका दिया जायेगा, उसमें कह लीजिएगा। बैठिए।

डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने अभी माननीय मंत्री जी का भाषण सुना और आपने भी सुना। माननीय मंत्री जी की सारी प्राथमिकता इस बात पर थी कि हमें जिला अस्पतालों में कितनी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। सारा जोर संसाधन पर था और कितना पैसा दे दिया है। इनकी सारी व्यवस्था से प्रदेश के नागरिकों की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बेहतर हो गयी, माननीय मंत्री जी इस पर एक शब्द नहीं बता पाए।

श्री अध्यक्ष–

वह अभी बाद में बोलेंगे। वह तो बोलना चाह रहे थे।

डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, पहले बोलना और बाद में बोलना यह तो कोई बात नहीं। हम लोगों ने तो उन्हें रोका नहीं। उनके पास कोई जानकारी होती तो वह रुकने वाले नहीं थे और यदि जानकारी होगी तो बाद में दे देंगे, हम लोग वह देख लेंगे। मान्यवर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह हम लोगों की गलतफहमी है कि अगर स्वास्थ्य की सुविधाओं की हम उपलब्धता करा देंगे तो नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर हो जायेगा। एक बहुत अच्छा अध्ययन काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री विभाग से संदर्भ में आया था। जिसमें एक पैमाने पर स्वास्थ्य की सुविधायें प्रति लाभ की जनसंख्या पर अस्पताल, पी0एस0सी, डॉक्टर्स, नर्सेंस इनकी संख्या और इन सुविधाओं के रहते हुए इन जनपदों में जन्म दर, मृत्यु दर, फर्टेलिटी रेट, संस्थागत प्रसव, एक वर्षीय बच्चों की मृत्युदर और पांच वर्षीय बच्चों की मृत्यु दर। इन दोनों आंकड़ों को कोरिलेट किया गया है। कोलिरेट करने पर जो निष्कर्ष आया चूंकि यह एकेडमिक अध्ययन है, ये कोई राजनैतिक अध्ययन नहीं है, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का अध्ययन है। हम जानते हैं कि वह एक मानदण्ड अन्तरराष्ट्रीय संस्था है। अध्ययन करने पर जो तथ्य निकलकर आया कि जिन शहरों

ऐक्ट स्वास्थ्य की सुविधाएं हमने बहुत बेहतर मुहैया करा दीं वहां के नागरिकों का स्वास्थ्य सचमुच बेहतर हो गया, ऐसा नहीं है क्योंकि सुविधाओं से सब कुछ बेहतर होता भी नहीं है। अध्यक्ष जी, उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि गोरखपुर 6वें स्थान पर आया उस पैरामीटर में, उसके पहले वाराणसी, कानपुर, जे0पी0 नगर, लखनऊ और मेरठ थे लेकिन जब स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया गया तो गोरखपुर 20वें स्थान पर चला गया। सुविधाओं की दृष्टि से फर्रुखाबाद 8वें स्थान पर आया और जब नागरिकों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया गया तो वह 50वें स्थान पर चला गया। अलीगढ़ 9वें स्थान पर आया और जब उनके स्वास्थ्य की सेवाओं का मूल्यांकन किया गया तो वह 27वें स्थान पर चला गया। इलाहाबाद 10वें स्थान पर आया और जब नागरिकों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया गया तो वह 55वें स्थान पर चला गया। जिन शहरों ऐक्ट स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थीं वहां भी नागरिकों का स्वास्थ्य बहुत बेहतर पाया गया, जैसे सुलतानपुर, बागपत, उन्नाव, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, हाथरस इत्यादि। जहां बहुत अच्छी थी वहां सुविधाओं में बहुत पीछापन पाया गया। आप कह रहे थे कि जो नहीं लिखा है वह बताओ, बाकी तो सब बजट ऐक्ट पढ़ ही लेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो नहीं लिखा है वह बताना इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट काम है। डिफिकल्ट काम ये है क्योंकि सत्य उजागर होकर के सामने आ जाएगा और चिल्ला–चिल्ला करके बोलने लगेगा। भारत सरकार के स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर भी एक हेल्थ मन्थली इन्फॉरमैंशन सिस्टम होता है, एच0एम0आई0एस0। इसमें प्रत्येक माह सभी राज्य सरकारें केवल उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है, भारत सरकार के स्तर पर उनके क्षेत्र में क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इनकी पूरी सूचना उपलब्ध कराती है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2015 में वह जो सूचना इस सरकार ने उस एच0एम0आई0एस0 सिस्टम को उपलब्ध कराई है उसके हिसाब से आदर्श 5000 के नागरिकों पर एक सब सेण्टर होना चाहिए। इस प्रदेश में 8527 नागरिकों पर एक सब सेण्टर है। 30,000 नागरिकों पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए, इस प्रदेश में 42,107 नागरिकों पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। 01 लाख 20 हजार नागरिकों पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए, इस प्रदेश में 01 लाख 90 हजार 707 नागरिकों पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। जो हमने कम्युनिटी हेल्थ सेण्टर बनाए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसे हम यह मानकर चलते हैं कि ये 247 दिन भर सेवा देंगे और सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जो इन्होंने अपनी सूचनाएं दिसम्बर तक दी हैं तो 920 सी0एच0सीज़ में सिर्फ 132 सी0एस0सीज़ में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। सिर्फ 164 में बच्चों के डॉक्टर हैं, सिर्फ 102 में बेहोशी के डॉक्टर हैं, सिर्फ 498 में फन्क्शनल ऑपरेशन थियेटर हैं, सिर्फ 170 डेजिग्नेटेड फर्स्ट रेफरल यूनिट की तरह काम कर रही हैं और सिर्फ 22 सी0एच0सीज़ ऐक्ट ब्लड स्टोरेज यूनिट्स काम कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। अगर इनके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को देख लिया जाए तो सिर्फ 73 परसेण्ट पी0एच0सीज़ में मेडिकल ऑफिसर है, लेडी ऑफिसर अधिकांश अस्पतालों में नहीं हैं, सिर्फ 6 परसेण्ट ऐक्ट है। आयुष मेडिकल अफसरों की संख्या जिसके बारे में

(एक मा0 सदस्य द्वारा कोरम का सवाल उठाने पर)

श्री अध्यक्ष–

जब नया विषय लिया जाता है तब कोरम का सवाल उठता है, बैठिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

आयुष मेडिकल ऑफिसर इनके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सिर्फ 25 परसेण्ट स्थानों पर हैं। जबकि हजारों की संख्या में चिकित्सक नौकरियों के लिए घूम रहे हैं। फंक्शनल पी0एच0सी0 के 24 घंटे चलने का जो प्रतिशत है वह 27 प्रतिशत है, सिर्फ आधे पी0एच0सी0 में चार बेड के अस्पताल हैं और सिर्फ 10 प्रतिशत पी0एच0सी0 में बिजली की रेगुलर सप्लाई है यह सरकार के अपने आंकड़े हैं। सब सेन्टर की हालत तो अध्यक्ष जी पूछिये मत सिर्फ 5 प्रतिशत सब–सेन्टर में बिजली की सप्लाई होती है। 38 जनपदों में किसी भी सब–सेन्टर पर बिजली का कनेक्शन है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, हर सब–सेन्टर में एक एडीशनल ए0एन0एम0 होती है। प्रदेश में सिर्फ 9.2 प्रतिशत सब–सेन्टर में एडीशनल नर्सेज हैं और अध्यक्ष महोदय एक दूसरा सर्वे होता है डिस्ट्रिक लेविल हेल्थ सर्वे। डिस्ट्रिक लेविल हेल्थ सर्वे–3 और डिस्ट्रिक लेविल हेल्थ सर्वे–4, हेल्थ सर्वे–4 की रिपोर्ट अभी दो–तीन महीने पहले प्रकाशित हुई है और उनके आंकड़ों का देखा जाए तो दो हेल्थ सर्वे के बीच में जो अपनी सरकार की उपलब्धियां माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, सब–सेन्टर्स में ए0एन0एम0 की संख्या 99 प्रतिशत से घटकर 95 प्रतिशत हो गई। मेल हेल्थ वर्कर्स की संख्या 6.2 से घटकर 1.8 हो गई ऐसे ए0एन0एम0 जिन्हें रहने के लिए मकान दिया गया कि जो गांव में रह सकें उनकी संख्या 57 परसेन्ट से घटकर 30 परसेन्ट हो गई। 24 घंटे चलने वाली पी0एच0सीज की संख्या 45 परसेन्ट से घटकर 27 परसेन्ट हो गई। चार बेड के अस्पताल 56 परसेन्ट से घटकर 54 परसेन्ट हो गए। अब अध्यक्ष महोदय, हमें बोल लेने दीजिए यह महत्वपूर्ण बजट है। रेफलर सर्विस ऑफ द डिलीवरी 23 परसेन्ट घटकर हो गई। सी0एच0सी0 में चलने वाली ओ0टी0 की संख्या डी0एल0एच0एस0–3 में 88 परसेन्ट होती थी, डी0एल0एच0एस0–4 में वह घटकर 54 परसेन्ट हो गयी है। यानि इन दो सर्वे के बीच में अध्यक्ष महोदय इस सरकार की क्या उपलब्धि रही, यह सरकार के द्वारा स्वयं इकट्ठे किये गये आंकड़ों से स्पष्ट रूप से साफ हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मिनिष्टरी ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की रेटिंग कराई कि ये किस प्रकार की सेवायें दे रहे हैं। यह रेटिंग खाली उत्तर प्रदेश की नहीं है पूरे देश की हुई है में उसमें से वह हिस्सा निकालकर आपके सामने रख रहा हूं, जिसका सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से है और इस रेटिंग में।

(सत्तापक्ष से आवाज आई की गुजरात के बारे में बता दें।)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय मैं आग्रह करूंगा कि मैं बताने लगूंगा तो फंस जायेंगे ये लोग, आप जानते हैं मैं रखता हूं। बीच में नहीं बोलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो क्राइटेरियाज तय किये गये थे ह्यूमन रिर्सोस एब्लिबिल्टी में डॉक्टर, नर्सेज और बेड।

इन्फ्रास्ट्रेक्चर में सेपरेट पब्लिक यूटीलिटी फॉर मेल एण्ड फीमेल ओ0टी0 एब्लिबिल्टी एण्ड स्टैण्ड फैसिल्टी, ड्रग्स की सप्लाई जिसकी चर्चा बार–बार माननीय मंत्री जी कर रहे थे, दो महीने की सिनसियल डेथ की उपलब्धता, दो महीने के टीके की उपलब्धता और दो महीने के परिवार–तलिवार के उपकरणों की उपलब्धता, सर्विस एब्लिबिल्टी, क्लाइंट ओरिएशन और सर्विस यूटीलाइजेशन। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को क्या टिप्पणी करनी चाहिए हमें नहीं मालूम इस स्टार रेटिंग में 920 में से सिर्फ 9 ऐसी सी0एच0सीज थीं एक अलीगढ़, एक इलाहाबाद, एक फिरोजाबाद, एक गाजियाबाद, एक झांसी, एक कानपुर नगर और तीन लखनऊ। ये सिर्फ 9 ऐसी थीं जिनको स्टार रेटिंग में वास्तव में फाइव स्टार प्राप्त हुआ। 426 ऐसी सी0एच0सीज थीं, जिन्हें यह मान लिया गया कि इनका मूल्यांकन ही नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह जो मेनडेटरी क्राइटेरिया हैं ह्यूमन रिर्सोस का और इन्फ्रास्ट्रेक्चर का उसको ही पूरा नहीं करते है। माननीय अध्यक्ष जी, यह इनकी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता है और जब मैंने स्वयं पहले भी कहा था कि स्वास्थ्य सेवाएं इस बात की गारंटी नहीं होती हैं कि आप बेहतर स्वास्थ्य कर पाएंगे लेकिन जब स्वास्थ्य सेवाएं ही ऐसी हो तो हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि यह सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर कितनी चिन्तित है। जैसे अध्यक्ष महोदय हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, क्राइटेरियाज क्या हैं, जिसके आधार पर तय किया जाए उसमें एक ही इनफैन्ट मॉरटिलिटी, न जाने कितनी बार में इसकी चर्चा करता हूं। अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश, पूरे देश में मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा के बाद नीचे है पचास नौजात शिशुओं की मृत्यु प्रति हजार पर अभी भी है जबकि मिलेनियम डेवलेपमेन्ट गोल में इसे घटाकर 27 करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत के अधिकांश प्रान्तों ने केरल ने इसे 12 कर लिया, महाराष्ट्र ने इसे 24 कर लिया, तमिलनाडू ने इसे 21 कर लिया हमारी उपलब्धता 50 है। अण्डर फाइव माटेलिटी, पांच वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु का दर यह सारे लक्ष्य ही हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहस्त्राबदी वैकातिक लक्ष्यों के रूप में प्रकाशित हुए थे, जिन्हें हमें प्राप्त करना था। अध्यक्ष महोदय, देश में सिर्फ एक ऐसा प्रान्त है आसाम, जहां यह 73 हैं अन्यथा, हम उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सर्वाधिक 64 हैं। मातृत्व मृत्यु दर, मरने वाली माताओं की संख्या इसलिए क्योंकि वह जन्म देती हैं अध्यक्ष महोदय आपको जानकर आश्चर्य होगा आसाम को छोड़कर देश में हम सबसे ऊपर हैं, 285 माताएं प्रति लाख जन पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं और इस बात की सम्भावना कि जन्म देने के नाते उनकी मरने की सम्भावना कितनी होती है, 100 में से एक महिला जन्म देने के नाते मर जाती है जबकि भारत सरकार ने इस स्तर को 167 प्राप्त किया है और अध्यक्ष महोदय बहुत से प्रान्तों ने क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है, केरल–61, तमिलनाडू–89, महाराष्ट्र–68, आन्ध्र–92 और हम 285 और अध्यक्ष महोदय इस 285 को हम मण्डल वाइज बांटे तो बड़ी अजीब स्थिति क्रिएट हो जायेगी।

डा0 शिव प्रताप यादव–

आप ईयर वाईज बता दीजिये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

जी मंत्री जी ईयर वाइज आप बताईये आपका काम है सूचना देना यह मेरा काम नहीं है। आपने बजट रखा है और आपको लगता था कि कुछ ईयर वाइज इम्प्रूवमेन्ट हो गया है तो आपको यहां बता देना चाहिए था। बजाये इसके कि दो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपतो मंत्री भी हैं, मुझे आपसे पूछना चाहिए। सत्य बड़ा कड़वा होता है, अध्यक्ष महोदय सत्य को पचाना इतना आसान नहीं होता। सच्चाई यह है कि प्रदेश के पास एक स्वास्थ्य मंत्री था, साढ़े तीन साल की यात्रा के बाद स्वास्थ्य मंत्री को भी गायब कर दिया गया और आज हम उत्तर प्रदेश के लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज मुख्य मंत्री के पास कितना समय है, आज अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को चला रहे हैं, यह माननीय राज्य मंत्री कभी मीटिंग की बहस भी कर पाते होंगे, मुझको तो नहीं लगता क्योंकि परम्परा नहीं है। अध्यक्ष महोदय मैं बहुत छोटी–छोटी दो बाते करूंगा, अगर ये डिस्टर्ब करेंगे तो मैं तो बहुत डिस्टर्ब कर दूंगा, अध्यक्ष महोदय आप तो जानते हैं मैं बहुत डिस्टर्ब कर दूंगा मुझे तो कोई समस्या नहीं है। मैंने इनकी बाते ध्यान से सुनी आप रोक रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा और बोलिये, लेकिन अब ये कहां से बोले। अध्यक्ष महोदय सच्चाई क्या है, आपको जानकर आश्चर्य होगा सिर्फ एक बार पूर्व प्रसव स्वास्थ्य परीक्षा, सरकार के आकड़े हैं सिर्फ 46 प्रतिशत महिलाओं की होती है, तीन बार स्वास्थ्य परीक्षा जो आईडियल है वह घटकर 32 प्रतिशत हो जाती है, आइरन और फोलिक एसिड की टैबलेट, लगातार चर्चा होती है गर्भवती महिलाओं में खून की कमी के बारे में, माननीय मुख्य मंत्री अपने भाषण में उल्लेख कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गर्भवती महिलाओं को 100 दिन आईरन और फोलिक एसिड पाने वाली महिलायें सिर्फ 8 प्रतिशत है और इस नाते फल क्या हुआ है क्म्प्लीट ए0एन0सी0एन0टी0 नटल चैकअप जिसे हम लोग कहते हैं कि तीन बार हीमोग्लोबिन की जांच, ब्लडप्रेशर की जांच और आइरन और फोलिक एसिड, ऐसे सम्पूर्ण प्रसव की जांच कराने वाले लोगों की संख्या 100 में सिर्फ 05 प्रतिशत है।

श्री अध्यक्ष–

यह श्रोत क्या है ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे पास अपने कोई श्रोत नहीं है एनुवल हैल्थ सर्वे, मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूं सब लिखित है मुझे कोई प्राब्लम नहीं है आप जानते हैं मैं तो तथ्यों के आधार पर बोलता हूं।

एनुअल हेल्थ सर्वे, भारत सरकार का सर्वे, हेल्थमंथली इनफामेशन सिस्टम सरकार का अपना डाटा है। सरकार जाने, सरकार उसे बोल नहीं रही है मैंने उसे रखने का काम किया है।

(डा0 शिव प्रताप यादव द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आप बैठिये। आप कुछ सुझाव दीजिए, नीतिगत बात बताइये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

आपने कहा, बड़ा अच्छा लगता है मंत्री होकर डिस्टर्ब करते हैं। इतना मजा आता है यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि कहां मंत्रियों को विपक्ष डिस्टर्ब करता है कहां विपक्ष की कटौती को माननीय मंत्री जी, यह भी स्वास्थ्य मंत्री है राज्य के किसी को पता ही नहीं होगा प्रदेश में । शायद हैं न, हैं हैं। शायद यह है अध्यक्ष जी।

डा0 शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, यह फर्जी आंकड़ा है आप यह बताइये कि हमने एस0एल0आर0 पूरे हिन्दोस्तान में किसी प्रान्त में जो रैनबैक्सी की जो लैब है उनका टेस्टिंग कोई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, बैठ जाओ अभी आप बोलकर पूरी बात कह देना काहे बीच में छेड़ते हो।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, खर्चे की बात कर रहे थे माननीय मंत्री जी, प्रति व्यक्ति भारत सरकार के स्तर पर जो औसत स्वास्थ्य का व्यय है वह 1280 रुपये है और माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार का बजट स्वयं बताया 16 हजार 834 रुपये, प्रति व्यक्ति का आंकड़ा हुआ 765 रुपये। औसत भारत सरकार का नागरिक पर व्यय 1280 और उत्तर प्रदेश का व्यय 765 भारत वर्ष के 16.5 प्रतिशत नागरिक उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और स्वास्थ्य का व्यय सिर्फ 12.6 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा कर रहे थे प्लान नान प्लान का में उस पर जाना नहीं चाहता था लेकिन अब यह चले ही गये हैं तो इनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य पर जो खर्चा होता है उसमें टेपिकल पूंजीगत परिव्यय सिर्फ 13.74 प्रतिशत है जब कि गुजरात का कैपिटल व्यय 28 प्रतिशत है।

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब, गुजरात का जी0डी0पी0 का कै प्रतिशत स्वास्थ्य पर है ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, यह जब बजट आयेगा तब देखेंगे। 28 प्रतिशत है जो आंकड़े मेरे पास हैं उसके हिसाब से 28 परसेन्ट हैं। मैं एक बात कह करके अपनी बात का समाप्त करूंगा वह बात है शहरी स्वास्थ्य को लेकर के क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र का विधायक हूं। शहर क्षेत्र के स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी गम्भीर लापरवाही बरती जा रही है जिला अस्पताल के अलावा शहर क्षेत्र में जितने भी हेल्थ पोस्ट हैं सब ताले में बन्द रहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब जरा सिटी स्कैन वगैरा पर बतायें, ग्रामीण अंचलों में बहुत जरूरत रहती है इस पर तो बोल नहीं रहे हो आकड़े सुना रहे हो।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, यह इनका काम है बताना, हम क्यों बतायें। ।

श्री अध्यक्ष–

आप मांग तो कर सकते हैं सुझाव तो दे सकते हैं अब आंकड़ा पढ़ रहे हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिटीस्कैन की कितनी जरूरत है कहां किसकी जरूरत है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, हम वह बतायेंगे जो नहीं है यह ये बताये जो हैं। अगर माननीय मंत्री जी को नहीं मालुम है तो कहां से बतायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जो मैं कह रहा था शहरी स्वास्थ्य के बारे में। कुल मिलाकर 6.30 प्रतिशत गरीब शहरी क्षेत्र में रहते हैं शहर में कहीं भी कोई हेल्थ पोस्ट काम नहीं कर रहा है यूनिवर्सल हेल्थ मिशन के नाम पर हम लोगों ने एक लक्ष्य लिया था कुल मिलाकर अगर जो आंकड़े हैं साढ़े तीन लाख प्रिगनेन्सी शहर में होती हैं और तकरीबन जो संस्थागत प्रसव तक उनकी पहुंच कम है उनका टीकाकरण कम होता है, उनकी इनफैन्ट मोर्टिलिटी गांव से ज्यादा है, उनमे कुपोषण की संख्या गांव से ज्यादा है, उनमे संक्रामक रोग गांव से ज्यादा है, बाकी चीजे जो हैं तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान देना उचित है जरूरी है कोई असहमति नहीं है। लेकिन अब नगर में बहुत बड़े गांव बसने लगे हैं, जिसमें सुविधायें गांव से भी ज्यादा खराब हैं जिन्हें हम स्लम्स एरिया के नाम से कहते हैं। तीस परसेण्ट जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य सेवाओं को नगरीय स्लम नागरिकों तक कैसे पहुंचाया जाये, अब सरकार को इसकी योजना बनानी चाहिये। चूंकि आपने कहा तो सुझाव के नाम पर मैं यह सुझाव दे रहा हूं।

श्री नागेन्द्र सिंह 'मुन्ना यादव'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, फिर से वही बात आती है कि पार्टियां चलती हैं नीतियों और कार्यक्रमों से। हम समाजवादी लोगों के लिए गरीब और कमजोर ईश्वर के बराबर होता है। इसीलिये जब–जब माननीय नेता जी के नेतृत्व में सरकार बनी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तभी से हमारी सरकार ने गरीब और बीमार के लिए व्यवस्था करने का काम किया है। यह हमारी नीति है कि जो बीमार हैं, लाचार हैं उनके लिए नीतियां बनाकर उनको कार्यरूप देने का काम करते हैं। इसीलिये अगर कहीं एक्सीडेन्ट हो जाये तो 108 नम्बर की बटन दबाने पर समाजवादी एम्बुलेन्स तुरन्त पहुंचती है। 102 नम्बर की बटन दबाने पर जो गरीब हैं, महिलायें हैं, लाचार हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं उनको 102 नम्बर की एम्बुलेन्स उनको अस्पताल ले जाती हैं। अगर वहां पर सुविधा नहीं है, तो जहां पर उनको रेफर किया जाता है, वहां तक उनको ले जाने का काम 102 नम्बर की एम्बुलेन्स कर रही है। इसीलिये गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए तमाम योजनायें हमारी जो चल रही हैं। सारे

टेस्ट और जांचें जिला अस्पतालों में मुफ्त कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि बड़ी लम्बी बात यह लोग करते हैं इनकी भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश के अंदर तब इन्होंने क्या नीतियां बनाई थीं, क्या कार्यक्रम बनाये थे गरीबों के लिए, बीमारों के लिए। मैं कहना नहीं चाहता हूं ऐसे–ऐसे बुद्धिजीवी डाक्टर और गलत मानसिकता के लोग हैं जो गरीबों का कायदे से इलाज नहीं करना चाहते हैं। वहां पर पहुंचने पर उनको अपमानित करने का काम ऐसी मानसिकता के डाक्टरों ने करने का काम किया था। मान्यवर, चिकित्सा के इस बजट पर इतना लम्बा खर्च हमारी सरकार करने जा रही है या कर रही हैं, उसका सारा लाभ जो इस प्रदेश के गरीब हैं, कमजोर हैं वह उसका लाभ उठा रहे हैं। अभी डाक्टर साहब अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे। वर्ष 2014–2015 की जो डब्ल्यू0एच0ओ0 की रिपोर्ट आई थी गुजरात जिसका नाम लेकर इन्होंने लोक सभा का चुनाव लड़ा था, उसमें हर तीसरा बच्चा कुपोषित पाया गया था। यह डब्ल्यू0एच0ओ0 की रिपोर्ट वर्ष 2014–2015 में आई थी। माननीय अध्यक्ष जी, बजट भी पास कराना है इसलिये ज्यादा लम्बा नहीं खींचना चाहता हूं। जो डाक्टर साहब बोल रहे थे इनके दल के लोग बोल रहे थे, एक भी कार्यक्रम बीमारों के लिए इनकी पार्टी का नहीं था। इनकी सरकार में सारे बीमार अस्पतालों से कराह–कराह के वापस जा रहे थे। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने ऐसी योजना चलाकर पूरे प्रदेश को लाभान्वित करने का काम किया है। आपने बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसलिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन)–

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी डाक्टर भी हैं और जानकार भी हैं। मान्यवर, ऐसा मैं मानता हूं कि इन्होंने जो आंकड़ें यहां पर पेश किये हैं तो इनकी बात का जवाब तो माननीय मांझी दे देंगे प्वाइंट–बाई–प्वाइंट लेकिन जिन एजेन्सीज का इन्होंने जिक्र किया है वह एजेन्सीज यूनिवर्सिटी थी, वह एजेन्सी आप समझ रहे हैं कि कौन सी एजेन्सी थी और कहां से इन्होंने आंकड़े पेश किये हैं। यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन दुनिया की दो सबसे बड़ी एजेन्सीज हैं और पूरे देश, प्रदेश और दुनिया भर की सारी समीक्षा और इक्जामिनेशन वह करते हैं और उनकी रिपोर्ट हर साल आती है, इस साल भी आई है आप चाहें, तो इंटरनेट पर देख लें। यूनिसेफ ने कहा कि पिछले चार सालों में उत्तर प्रदेश ने एक्सीलेंट वर्क किया है ऐसा किसी प्रदेश ने नहीं किया है ये यूनिसेफ ने कहा है। इसलिये मैंने कहा कि मोटरलिटी रेट में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है पिछले चार सालों में। बेइंतहा मां की डेथ घटी है, बच्चों की डेथ घटी है इसकी भी तारीफ होनी चाहिये। मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि देश का कौन सा ऐसा प्रदेश है कि जहां पर 108 एम्बुलेंस 20 मिनट में निःशुल्क पहुंच जाती है। सारी जगहों पर यह एजेन्सी फेल हो गयी है सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी एम्बुलेंस 108 काम कर रही है बाकी सारी जगहों पर आप पता कर लीजिये। गुजरात में इसका सबसे ज्यादा बुरा हाल है जो लोग चला रहे थे वह लोग भाग गये। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एड बंद कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी

को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने बजट से उत्तर प्रदेश में सारी एम्बुलेंस के खर्चे वहन किये। इसलिये उत्तर प्रदेश में पिछले चार सालों में जो काम हुआ है, उसकी प्रंशसा चारों ओर है। लेकिन अब माननीय राधा मोहन जी ने जो आंकड़े पेश किये हैं वह भी बनारस यूनिवर्सिटी के। आप जानते हैं और केन्द्र सरकार कैसी है वह भी आप जानते हैं। माननीय अध्यक्ष जी आपको तो पता ही है कि यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के बयान का कैसा किया है कैसी ट्यूटर्ड डाक्टर्ड है। मेरे ख्याल में मुझे तो बहुत अफसोस है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के खर्चे पर जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी और उसमें कन्हैया ..

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप स्वास्थ्य पर बोलिये।

श्री अहमद हसन–

कन्हैया की गिरफ्तारी के सिलसिले में एक ही बात कहूंगा कि यह कितना डाक्टर्ड और ट्यूटर्ड काम कर सकते हैं, यह किस हद तक जा सकते हैं। मैं आपको वही कह रहा हूं और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी वहां का लड़का है तो यह समझना चाहिये कि यूनिवर्सिटीज और एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो चिंगारी उठती है वह फिर शोला बनकर जला देती है, भाजपा अभी समझ नहीं रही है कि यह क्या है। इसलिये इस तरह के आंकडे पेश मत करो। हम उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्य मंत्री जी को कहेंगे कि इतना फंड इतना संसाधन जिस तरह से किया है वह तारीफ योग्य है। माननीय राधा मोहन जी ने जो कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लखनऊ में अरबन हेल्थ पोस्ट देख लीजिये, अभी चलिये और देखिये कि कितने मरीज हैं, कितनी दवा है और बगैर पर्चे के लोग दवायें पा रहे हैं इतनी सुविधा और वही स्टेन्डर्ड दवा यह भी इनको दिखाई नहीं पड़ता, पता नहीं ऐसा क्यों है। विपक्ष ने आंख क्यों बंद कर ली है यह हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे ख्याल में चारों तरफ देश प्रदेश में इसकी प्रंशसा हो रही है बाकी मांझी जी आपको आंकड़े से बता देंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि कमियां जो हैं लेकिन कमियां कहां थीं आजादी के 66 सालों में कहां थी और हम लोगों ने उसे पिछले चार सालों में कहां पहुंचा दिया। आखिर एक रूपये का पर्चा तो माननीय नेताजी ने किया उसी जमाने में मुफ्त दवा की गयी और उसी को आगे बढ़ाया गया। गरीबों के इलाज के लिये सब मुफ्त किया गया इस चीज को इन्हें समझना चाहिये। आप केरल की बात कर रहे हैं उस समय केरल में भाजपा की सरकार नहीं थी इसलिये वहां तरक्की हो गयी। केरल में कम्युनिस्टों के जमाने से होती रही होगी, छोटी आबादी है, उन्होंने किया हम सबका सौभाग्य है। मैं इस बात का फख्र महसूस करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री काफी फारवर्ड लुकिंग हैं उन्होंने जो कुछ किया है स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा और मा0 राधामोहन जी से कहूंगा कि यह जो इनका आंकड़ा है बड़े जाल–बट्टे वाला आंकड़ा है, इस आंकड़े को भूल जाईये, सच्चे आंकड़े, सच्चे सरकार के काम, सच्ची उपलब्धियां,

शानदार परफार्मेन्स जो सरकार की रही है उसको महसूस करें। माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे संसाधन उपलब्ध कराये कि में हैरान रहा। शिक्षा विभाग में भी वैसे ही काम कर रहे हैं मा0 राधामोहन जी, मेरे ख्याल मैं कुछ बड़ा ही डिपार्टमेण्ट आपने दे दिया है आप क्यों परेशान हैं इसलिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं।

(भा0ज0पा0 के कई सदस्यों द्वारा बोलने के लिए हाथ उठाने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपकी पार्टी की ओर से कटमोशन रखा गया अब ब0स0पा0 का नम्बर है इसलिए उस दल के सदस्य को बोल लेने दीजिए।

(श्री शमशेर बहादुर सिंह शेरू भईया के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप ही दिन भर बोलेंगे ?

श्री शमशेर बहादुर सिंह शेरू भइया–

आदरणीय अध्यक्ष जी, बस दो मिनट में कुछ सुझाव दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आपको भी लोग भाषण माफिया कहेंगे।

श्री शमशेर बहादुर सिंह शेरू भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे दो–तीन छोटे–छोटे सुझाव हैं–एक तो, ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर लोग जाते हैं पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 पर इनके रहने की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिले पर तो सभी रहना चाहते हैं, पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 जो गांवों में हैं मैंने विजिट किया, मैं पी0एच0सी0 पर गया और सी0एच0सी0 पर गया, डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहां बहुत ही छोटे भवन बने हुए हैं उनमें रहना पड़ रहा है, आप जब यहां से जांए विधान सभा चलेगी तो वहां कहियेगा कि सरकार सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 जो ग्रामीण अंचलों की है उन पर रहने की व्यवस्था करा दे। दूसरी चीज, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मरीजों को लेकर क्वीनमेरी, मेडिकल कॉलेज और पी0जी0आई0 गया, क्वीनमेरी में इलाज हो रहा है। महिलाओं का इलाज अच्छे तरीके से हो रहा है, गरीब लोग जो ऑपरेशन नहीं करा सकते 20–30 हजार रुपये देकर, क्वीनमेरी में ऑपरेशन सुचारु रूप से वहां के डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन वहां पर बेड कम है उनके रूकने की व्यवस्था कम है, उसको अध्यक्ष जी, बढ़ाया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जो बी0पी0एल0 कार्ड धारक हैं ऐसा प्राविधान सरकार के द्वारा किया गया है कि गंभीर रोगों पर जैसे उनके किडनी, लिवर, कैंसर, हार्ट का है, वाल्व चेंज करने का है, ये गंभीर इलाज निःशुल्क कराये जाते थे और हो रहे थे लेकिन इस बीच जब मेडिकल कॉलेज जाने का अवसर मिला तो वहां पर उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कतें आयी हैं जिनके कारण गरीबों का जो यह इलाज हो रहा था अब नहीं

हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पूर्व की भांति, फण्ड पड़ा रहता था, में हार्ट के लोगों को पी0जी0आई0 में ले करके गया उनका इलाज हुआ, किडनी का, लिवर का, कैंसर का इलाज हुआ तो उसी तरीके से बी0पी0एल0 कार्ड धारकों का पूर्व की भांति इलाज हो रहा था उसमें कोई बाधा न आये। यह गरीब की ध्यान रखने वाली सरकार है।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिये।

श्री शमशेर बहादुर सिंह शेरू भइया–

मान्यवर, मैंने जो सुझाव दिये हैं उस पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मा0 अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अनीसुर्रहमान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक प्रस्ताव रखना चाहूंगा अपने क्षेत्र के मुत्तालिक। हमारे मुरादाबाद में एक नगर पंचायत है उमरीकला। यह 98 प्रतिशत अल्पसंख्यक बहुल नगर पंचायत है और यहां पर बीड़ी बनाने का काम होता है और ये लोग खेती–बाड़ी का काम करते हैं और सीसे का काम करते हैं। लेकिन पूरे नगर पंचायत उभरी कलां में जिसकी जनसंख्या 50 हजार है एक भी एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर नहीं है और किसी भी स्वास्थ्य समस्या या इमरजेंसी के टाइम पर 40 किलोमीटर दूर मुरादाबाद मुख्यालय पर जाना पड़ता है। मान्यवर, मेरा यह प्रस्ताव है, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध कर रहा हूं कि मंत्री जी इसको कहीं नोट कर लें कि नगर पंचायत उमरीकला में पी0एच0सी0 स्थापित करा दें ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के जो 98 प्रतिशत लोग वहां रहते हैं उनका भला हो सके। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

सत्तापक्ष की तरफ से कोई मा0 सदस्य बोलेगा?

जन्तु उद्यान एवं चिकत्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा0 शिवप्रताप यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। समाजवादियों का यह नारा रहा है कि रोटी कपड़ा सस्ता होगी दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी और इसी थीम पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जैसा अभी डाक्टर साहब आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे थे अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है कि पूरे हिन्दुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश हो जहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी इतना संवेदनशील हों स्वास्थ्य के प्रति। उन्होंने एलान किया है कि गम्भीर से गम्भीर बीमारियों चाहे किडनी का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे कैंसर का हो बड़े से बड़े अस्पताल अगर एम्स में या पी0जी0आई0 कहीं भी इलाज करावे केवल इस्टीमेट बनाया जाय और कहीं भी जिलाधिकारी या किसी भी मिनिस्टर या किसी के भी द्वारा जनता दरबार में दे दें इलाज का सारा पैसा अस्पताल में जाता है और इलाज होता है। कोई

प्रदेश बता दें, मैं डाक्टर साहब को चुनौती देना चाहता हूं कि क्या गुजरात में क्या यह व्यवस्था है ? जहां तक सवाल है अभी तक सारी सुविधाएं जो हमारे सरकार ने किया वह तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है। आज हमारी सरकार ने यह भी फैसला लिया कि कोई भी जांच हो उस जांच को हम फ्री में, यहां तक कि थायराइड जैसी जांच, डाक्टर साहब जानते हैं 5–5 हजार रुपये की जो जांच है उसको भी फ्री। हमारी सरकार कोशिश कर रही है और अभी मण्डलीय अस्पताल में व्यवस्था किया है एस0एल0आर0 लैब की, रेनबैक्सी की जो कम्पनी है उसके हम कलेक्शन सेन्टर भी बनवा रहे हैं, लैब की व्यवस्था करवा रहे हैं। सारी जांच और यहां तक कि चूंकि विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी है इसलिये ऑन लाइन भी उनसे परामर्श के लिये भी व्यवस्था की जा रही है। यह तमाम बातें हैं माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इतना सम्वेदनशील हैं और यहां तक कि कुपोषण के बारे में स्कूलों में, विद्यालयों में जो टीम जाती है बच्चों की जांच करती है, 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं। जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिये सी0एच0सी0 में और अस्पतालों में एक वार्ड भी बनाया गया है, वहां पर उनके लिये दवाइयां हैं और उनके पोषण के लिये पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। महिलाओं के लिये विशेष सुविधा है, कुपोषण के लिये काम हो रहा है। यह तमाम काम हो रहा है इसलिये मत्यु दर भी घटा है। ईयरवाइस आप बता दीजिये। चार साल से पहले, हमारी सरकार बनने से पहले, आप आंकड़ा देते। और यह जो सारे माननीय अहमद हसन साहब ने कहा है यूनीसेफ की रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में चार सालों में स्वास्थ्य विभाग में बहुत काम हुआ है और इसीलिये यह आंकड़ा जो डाक्टर साहब प्रस्तुत कर रहे थे। यह कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। एक बात और कहकर कि आज स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ जनता का विश्वास बढ़ा है, वह सुविधाएं मिली हैं इसीलिये आज मेला लगा रहता है अस्पतालों में, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं। डाक्टर साहब आप भी जानते हैं आप सुझाव दें आप भी जानते हैं कि गोरखपुर में क्या हालत है। 36 हजार केवल टीकाकरण किया है और प्रयास हो रहा है। मैं चाहूंगा कि मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह बनो हमने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ।

श्री अध्यक्ष–

अबकी बार बड़ा कविता और शायरी हो रही है। सब शायराने मूड में हैं क्योंकि होली निकट आ गई है।

'श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सामान्य अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं वह रखना चाहता हूं। बहुत विद्वता के साथ आदरणीय डाक्टर राधा मोहन जी ने तमाम आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, वास्तविकता तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज स्वास्थ्य की बड़ी भारी दिक्कत है। जितना भी मैं अपने विधान सभा की बात करूं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जब हम लोग जाते हैं वहां डाक्टर नहीं हैं जब डाक्टरों के बारे मैं कहा जाता है तो यह कहा जाता है कि डाक्टरों की कमी है आठ दिन में एक डाक्टर भेज दिया जाएगा मेरे विधान सभा क्षेत्र में गढ़ीमुक्ता नाम का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है में वहां गया जब सी0एम0ओ0 से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि डाक्टरों की कमी है आठ दिन में एक बार सोमवार को हम डाक्टर वहां भेज दिया करेंगे। मान्यवर, 70 हजार की आबादी उस नगर पंचायत की है 70 हजार की आबादी में भी अगर आठ दिन में एक डाक्टर जाएगा तो क्या हाल स्वास्थ्य सेवाओं का होगा। अध्यक्ष जी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं शामली जनपद का सृजन 2011 मैं हुआ 2011 से लेकर आज 2016 है अब तक अध्यक्ष जी शामली जनपद में जिला चिकित्सालय के मानक की कोई सुविधा नहीं है। न भवन है न किसी प्रकार की सुविधायें हैं न बाल रोग विशेषज्ञ है और अभी आपने याद दिलाया सी0टी0 स्कैन मशीन की बहुत आवश्यकता है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों से डेंगू का कहर है बार–बार हमने भी यहां प्रश्न के माध्यम से सवाल उठाए हैं ब्लड कम्पोनेंट मशीन, मान्यवर, डेंगू एक ऐसी बीमारी है यदि वह मच्छर काट ले तो किसी भी सूरत में एक लाख से कम में वह मरीज ठीक हो ही नहीं सकता है या तो वह पानीपत जाएगा या दिल्ली जाएगा। आसपास कहीं भी उसका इलाज नहीं होगा इतना मंहगा उसका इलाज है तो प्लेटलेड्स बदलने के लिए ब्लड कम्पोनेंट मशीन जो है वह हमने मांग की थी कि हर जिला चिकित्सालय को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम उसकी स्थापना हो जाए। उसकी भी कहीं चर्चा नहीं है। न सी0टी0 स्कैन मशीने हैं। अध्यक्ष जी, आर्थोपैडिक सर्जन की बहुत अधिक आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में है। एक्सीडेंट होता है कोई भी आवश्यकता होती है तो जो शहरों में आर्थोपैडिक सर्जन हैं वह बड़ी राशि, बहुत बड़ा धन लोगों से वसूलते हैं। गरीब आदमी इस बात को लेकर बहुत परेशान है और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं नगर पंचायतों के उन पर प्लास्तर तक करने की सुविधायें नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश चाहे मेरठ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे शामली हो, सहारनपुर हो बागपत हो सारा का सारा जो भी ग्रान्ट जा रहा है उत्तराखण्ड में, वहां के मेडिकल कालेज में सारा जा रहा है, हजारों की संख्या में सब वहां जाते हैं, मेरा सरकार से निवेदन है कि इन जिलों में कोई बड़ा संस्थान, आपका मेडिकल कालेज सहारनपुर में है, मेरठ में है लेकिन उनका इस तरह से नहीं है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप बड़ा मेडिकल संस्थान बनाएं जिससे कम से कम वहां के लोगों की स्वास्थ्य सेवायें हो सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत–बहुत आभार।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

अध्यक्ष जी, आज आप बहुत खुश हैं हम पर और इसलिए खुश हैं चूंकि ..

श्री अध्यक्ष–

अब नौ बज रहे हैं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

अध्यक्ष जी, नौ बजे की कोई दिक्कत नहीं है आजकल बारातें चल रही हैं राजनीति के लोग हैं तीन–चार बज जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूं समाजवादी पार्टी कहती है एक चौपाई है–आपन मुंह तु आपन वरनी, यह अपने मुंह से अपनी बढ़ाई कर रहे हैं।

श्री राजेश त्रिपाठी–

चौपाई पूरी कर दीजिए।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

आपन मुंह तु आपन वरनी, देख अनेक भांत बहु वरनी, अब तो हो गई पूरी। ब0स0पा0 में आप एक ऐसे आदमी हो जो ऐसे कपड़ों में आते हो, वरना बहुत दूर लोग भगा दिए जाते हैं खुशी की बात है कि लंका में रावण के साथ एक विभीषण था एक आप बैठे हैं मुझे खुशी है। माननीय अध्यक्ष जी में कहना यह चाहता हूं कि में सवेरे से परेशान हूं।

श्री राजेश त्रिपाठी–

यह मानसिक हैं ।

'श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

ठीक है जो भी है मानसिक भी होंगे तो राम भक्त होंगे, कृष्ण भक्त होंगे, देवी भक्त होंगे लेकिन हम पत्थर भक्त नहीं होंगे हम एक भक्त नहीं होंगे हम हजारों वाले हैं हजारों भक्त होंगे, हमारे मोदी जी भी होंगे, राजनाथ सिंह जी भी होंगे, सुषमा स्वराज भी होंगी, बहुत नेता होंगे।

श्री अध्यक्ष–

समय बर्बाद न करिए बजट पर बोलें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट दो मिनट इतना बोले सब लोग, सबको प्यार, हमसे क्या है बेकरार। सबको प्यार हमसे क्यों बेकरार।

श्री अध्यक्ष–

बजट पर बोलिए।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

अध्यक्ष जी मैं सुबह से घूम रहा था कोई पूछ नहीं रहा था आपने पूछा हमारे नेताओं ने तो पीछे कर दिया था लेकिन आपको धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी यह जो

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी ने बहुत कुछ किया है लेकिन यह हमें बताएं कि क्या किया है। मंत्री जी अगर मैं कानपुर के बारे में बता दूं आप एक रुपया की बात करते हैं एक रुपया तो देखने के लिए है दिखौटा है। वह जो डाक्टर हैं जो कर्मचारी हैं वह जेबें भरते हैं यह मुखौटा है। अब देखो कि क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

सीधे खड़े होकर बोलिए इतना बदन क्यों हिला रहे हैं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

अध्यक्ष जी बोल लेने दीजिए सरकार के सामने अगर सही बात नहीं आएगी तो कौन देखेगा मैं बता रहा हूं सरकारी अस्पतालों मैं कोई गरीब भी डायलिसिस नहीं कराना चाहता है। बिकना चाहता है खेत बेचना चाहता है जेवर बेचना चाहता है मकान बेचकर डायलिसिस कराता है जैसे कानपुर में रीजेंसी अस्पताल है या बड़े–बड़े अस्पताल हैं वहां जाते हैं आपके अस्पतालों में क्यों नहीं कराते क्योंकि आपके अस्पतालों में सफाई नाम की चीज नहीं है। पैसा पूरा पीछे से लेते हैं, नीचे से पूरा पैसा लेते हैं आपको मालूम है सरकार में कई लोग पकड़े भी गए थे मान्यवर, आपके सामने ही पकड़े गए थे।

श्री अहमद हसन–

हमने ही जाकर पकड़ा था।

श्री अध्यक्ष–

भदौरिया जी भाषण करिए। नाटक कर रहे हो।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर मुझे आधा मिनट दे दीजिए। मुझे बोलने का शौक नहीं है बहुत बोल लेता हूं। लेकिन क्या गरीबों के लिए यही है कि एक रुपए की बात करोगे और हजारों रुपए की जेब ढीली करोगे। मैं कह रहा हूं जांच करो मैं जांच करवाता हूं विकलांग सर्टीफिकेट बनवाने में तो पैसा गरीब जाए आपरेशन के लिए तो पैसा बी0पी0एल0कार्ड पर कोई दवाई होती नहीं कार्डियोलाजी में जाएं तो बता देते हैं कि यह वाला नहीं लगभग 92 हजार वाला लोगे या एक लाख बीस हजार वाला लोगे तो ठीक रहेगा उससे कहेंगे कि जाओ विधायक जी के पास चले जाओ सरकार के पास चले जाओ। मैं यथार्थ की बात बोल रहा हूं जनता और समाज सबके लिए बात करता हूं। मंत्री जी अवगत हो जाएं यही अवसर होते हैं। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं क्या कारण है कि गरीब आदमी आज बड़े अस्पतालों मैं जाना चाहता है जबकि अस्पतालों की हैसियत यह है कि जब आदमी मरने लगता है तो वहीं भेज देते हैं। रखते नहीं हैं धक्का मारकर भेज देते हैं। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं यह जो रोज की घटना आप देख रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में एक मरा पत्थर तोड़े गए उसके शीशे तोड़े गए। यह दवाई क्या करते हैं इनको कहीं न कैमरे लगाना चाहिए मरीज बाहर से देखे मुर्दा मरीज रखे रहते हैं क्योंकि उनका पूरा पैसा मिल जाए कहीं कह देंगे कि मर गया तो रुपया नहीं मिलेगा इसलिए पूरा पैसा लेने के बाद।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, केवल आधा मिनट और अवसर दे दें। मैं केवल सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्राइवेट अस्पतालों में जरूर कैमरे लगवाए जाएं जब कोई आई0सी0यू0 में हो उसकी पूरी की पूरी बाहर स्क्रीन लगी हो लोग देखें मरीज कैसा है।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, आप मेरे अध्यक्ष हैं मैं सुबह से तड़प रहा हूं केवल आधा मिनट और दे दें। मैं जनता के लिए बोल रहा हूं गरीब के लिए बोल रहा हूं उत्तर प्रदेश के गरीब और दलितों के लिए बोल रहा हूं अस्पताल में दवाई फ्री होना चाहिए अगर कोई अस्पताल छोड़कर जाता है तो यह देखना चाहिए कि यह अस्पताल छोड़कर क्यों जाता है। मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं अभी 108 की बात आई यह 108 किसने दिया था यह केन्द्र सरकार से आई थी कि आपके पास से आई थी। एन0आर0एच0एम0 के द्वारा यह बनी थी। घुमा–फिरा कर पैसा केन्द्र का आयेगा, लेकिन सरकार आपकी है तो आप ही खर्च करेंगे। जैसे आप पैसा देते हैं वहां में क्रेडिट लेता हूं कि मैंने ही यह सड़क बनवा दी। केंद्र पैसा देता है, लेकिन क्रेडिट आप उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त कीजिये। अब आपका लिखा नहीं जायेगा।

श्री राजबली जैसल–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र जनपद–इलाहाबाद के कोरांव विधान सभा क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां सी0एच0सी0 कोरांव है सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरांव है जो शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक भी महिला डाक्टर नहीं है। वहां पर एक महिला डाक्टर की नियुक्ति कर दी जाये। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ोखर है जो शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर एक भी डाक्टर नहीं है। मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ोखर में एक डाक्टर की नियुक्ति कर दी जाये। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री ललितेशपति त्रिपाठी–

मा0 अध्यक्ष जी, डाक्टर साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये आपने मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की दो–तीन समस्याओं से मा0 मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सड़क वाराणसी से शक्तिनगर राजमार्ग का निर्माण हुआ है। उस रास्ते पर बनारस से

राबर्ट्सगंज की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, उसके बीच में मेरे क्षेत्र का एक नगर पालिका अहरौरा पड़ता है। अहरौरा नगर पालिका में जो सी0एच0सी0 है वह एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। मा0 अध्यक्ष जी, आपने एक बार उस क्षेत्र का दौरा भी किया है। सरकार की ऐसी मंशा है कि हर तहसील में एक ट्रामा सेंटर का निर्माण होगा तो अगर अहरौरा सी0एच0सी0 पर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो जाता है तो उस हाई–वे पर सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग घायल होते हैं, उनके उपचार के लिये तत्काल में एक व्यवस्था हो जायेगी। मा0 अध्यक्ष जी, पटैहरा विकास खण्ड मुख्यालय पर जो सी0एच0सी0 बना है वह आज से लगभग 25 साल पहले बना था और सी0एच0सी0 पटैहरा की स्थिति आज बहुत खराब हो गयी है। मैं जानता हूं कि सरकार ने आज 108 एम्बुलेंस की सुविधा दी है। धीरे–धीरे इंस्टीट्यूश्नैलाइज्ड डिलीवरी की जो एक नीति बनी है, सी0एच0सी0 पटैहरा में डिलीवरी के इतने केस आते हैं कि अन्य मरीजों के लिये न कोई कमरा है और न ही कोई बिस्तर है। अगर सरकार के पास कोई व्यवस्था होती कि वहां पर अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हो जाता तो उस क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलता। मुझे अभी मेरे एक साथी जो बनारस से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ने अवगत कराया है कि आशापुर चौराहे पर एक छोटा सा अस्पताल आज से लगभग 30–35 वर्ष पहले बना था, जबसे उस अस्पताल का निर्माण हुआ है उस पर ताला लटका हुआ है, वहां न कोई डाक्टर जाता है, शायद वहां कोई डाक्टर तैनात नहीं है। बनारस जैसी महत्वपूर्ण जगह का यह हाल है तो मुझे लगता है कि जो मेरा पिछड़ा और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां के डाक्टरों का क्या हाल होगा, वह उसी से स्पष्ट होता है। कई बार इस पर चर्चा हुयी थी, मुझे लग रहा है कि पिछली बार भी जब स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हुयी थी तब एक नीति शायद बनी थी कि हर अस्पताल पर, हर पी0एच0सी0 पर, हर सी0एच0सी0 पर बायोमीट्रिक स्कैनर लगाया जायेगा। आज की डेट में वह बायोमीट्रिक स्कैनर 6 हजार या 5 हजार रुपये में आता है, उससे जो डाक्टर हैं, जो नर्स हैं और जो अन्य कर्मचारी उस स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत हैं, वह सबेरे अपनी हाजिरी उस बायोमेट्रिक स्कैनर के माध्यम से अगर कर देते तो मुझे लगता है, इस समस्या का निदान होता। क्योंकि मेरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, 40–45 कि0मी0 का जंगल बीच में पड़ जाता है और 40–45 कि0मी0 के जंगल में जो बिजली की सप्लाई मिर्जापुर शहर से आती है, बरसात के मौसम में, कभी आंधी–पानी में वह तार टूट जाते हैं। कभी–कभी 6–7 दिन लग जाता है, उस तार को जोड़ने में। उसको देखते हुए अगर इस तरह के क्षेत्रों में अगर सोलर इन्वर्टर इन अस्पतालों को उपलब्ध करा देते तो कम से कम वहां पर डाक्टरों को रहने के लिए और कम से कम जो मरीज हैं, उनको शाम को रोशनी मिल जाती। मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है, मैं जानता हूं कि यह सीधे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा नहीं है, सरकार का जो शासनादेश होगा, माननीय असीजा जी ने भी इस बात को उठाया था। मान्यवर, पोस्टमार्टम की जो व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में, उसमें एक सुधार की जरूरत है। पोस्टमार्टम के लिए जिस परिवार को जाना होता है, वह लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं, चाहे वह उनका पिता हो, चाहे उनका बेटा हो और धीरे–धीरे जितनी

योजनाएं हैं, चाहे वह बीमा की योजना हो, चाहे वह किसी अन्य योजना का लाभ लेने के लिए उनको पोस्टमार्टम कराने की जरूरत हो, चाहे मुकदमें के लिए पोस्टमार्टम कराना आवश्यक हो। पोस्टमार्टम के लिए जो समय 2.00 बजे से लेकर सूर्यास्त तक निर्धारित हुआ है। अब मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि पोस्टमार्टम किसी भी समय। मान्यवर, हम लोगों को सौभाग्य है कि मिर्जापुर के जिलाधिकारी कहते हैं कि इन लोगों को जब जरूरत हो, लगभग रात 11. 00–12.00 बजे तक भी हम उनको सूचना कर देते हैं कि पोस्टमार्टम होना है, वह तुरन्त आदेश दे देते हैं और पोस्टमार्टम करा देते हैं। मान्यवर, अगर यह आदेश सरकार से हो जाता कि पोस्टमार्टम की जब भी जरूरत हो, मैं एक समय–सीमा को बढ़ाने की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, एक जानकारी दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 20 वर्ष पहले मा0 अध्यक्ष जी, आपके द्वारा हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक सी0एच0सी0 अस्पताल बनवाया गया था, 20 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक वहां पर सारे विभागों के डाक्टर तैनात नहीं हैं, वहां पर महिला डाक्टर नहीं हैं, जिससे दिक्कत होती है और वहां पर आर्थोपैडिक डाक्टर नहीं हैं, सर्जन वहां नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बड़हलगंज जो गोला तहसील का सी0एच0सी0 है और गोला सी0एच0सी0 है, वहां पर आप डाक्टर्स की व्यवस्था करा दें। दूसरा यह कहना था कि एक नया अस्पताल आपने सी0एच0सी0 दिया है, हमारे यहां गोला तहसील में, अरांव जगदीश में, वह बिल्डिंग बन कर तैयार है एक साल से, कृपया आप वहां स्टाफ भेज दें, डाक्टर्स भेज दें ताकि वहां पर इलाज की व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं कि गोरखपुर और मऊ, आजमगढ़ के बीच में एक बड़हलगंज सेण्टर पड़ता है, नेशनल हाई–वे है वह, अगर वहां पर आप ट्रामा सेण्टर की व्यवस्था करा दें तो बहुत सारे लोगों की जान लम्बी दूरी तय करने में जिस तरह से दिक्कत होती है, उनकी जान बच सकती है। मैं चाहूंगा कि सरकार वहां पर ट्रामा सेण्टर की व्यवस्था करा दे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब आप बैठिए।

वीरपाल राठी जी, बोलिए।

'श्री वीरपाल राठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने स्वास्थ्य विभाग पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, साथ ही एक बात की तारीफ भी करूंगा कि 04 साल से स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। जो 108 एम्बुलेंस को माननीय मुख्य मंत्री जी ने चलाया है, क्योंकि एक गरीब आदमी को कोई साधन नहीं

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलता था, वह सड़कों पर पड़ा रहता था, उसके लिए कोई साधन नहीं जुटता था, वह वहीं पर दम तोड़ देता था। अब टेलीफोन करते हैं। हमारे पास जो टेलीफोन है, जब हम 108 नं0 पर टेलीफोन करते है कि यहां पर एक्सीडेंट हुआ है तो तुरन्त व्यवस्था होती है। इससे गरीब आदमी की बहुत मदद होती है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि आज ग्रामीण अंचल के अन्दर परिवर्तन करना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को, शहरों में जो सुविधाएं हैं, वह गांवों में सुविधाएं नहीं हैं। अभी राणा जी बोल रहे थे, उन्हीं की बात मैं बल दूंगा कि गांव के अंचल में, मैंने मंत्री जी से भी मौखिक रूप से बताया कि डाक्टर्स की भारी कमी है और डाक्टर ग्रामीण अंचल में जाना ही नहीं चाहता। वहां पर लोग परेशान हैं, डिलेवरी के मामले को लेकर, आम आदमी प्राइवेट अस्पतालों में जाने की कोशिश करता है। मेरा निवेदन है कि ग्रामीण अंचल की तरफ भी ध्यान दिया जाये और जो सी0टी0 स्केन और एक्सरे मशीन यह सब ग्रामीण अंचल में लगाये जायें। यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब अब अपना आप सब वाइंडअप करेंगे। कि आप बोल चुके अब कुछ नहीं कहना है। रहने दीजिए पास कराते हैं। मा0 मंत्री जी जवाब दें।

श्री शंखलाल मांझी–

मान्यवर, अभी डा0 राधामोहन जी बहुत लुभावने ढंग से बहुत बढ़िया झूठा आंकड़ा जिसको झूठा तो नहीं असत्य कहेंगे। आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे थे और जहां का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे थे उसके बारे में मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बता दिया। मा0 अध्यक्ष जी, यह डा0 राधा मोहन दास जी बहुत अच्छे आदमी हैं। यह बात अलग है कि इनपर प्रभाव भगवा है। और यह लोग बात को बड़े ही नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने के माहिर हैं। मा0 अध्यक्ष जी, 2014 में इसी नाटकीयता के लाभ की बदौलत यह इस देश की सरकार को चला रहे हैं और आप जो आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे थे उसके रिसोर्स के बारे में मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन आंकड़ा अगर आप यूनिसेफ का देते, डब्ल्यू0एच0ओ0 का देते। जिसको प्रदेश यह माना जा रहा था कि पोलियो उन्मूलन के मामले में जो बहुत कठिन बात मान रहे थे जिस स्तर पर, हमने पहले ही उस पर पोलियो से निजात पाया और हमें पुरस्कृत भी किया गया। बहरहाल डाक्टर साहब के आंकड़े उनको मुबारक हो। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि इस तरह के आंकड़ों से पूरे सदन को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। एच0आई0एम0एस0 मे अभी पूर्ण सूचनायें संबंधित चिकित्सालय द्वारा भरी जा रही हैं। इसलिए इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। आपने विद्युत फीडर, विद्युत सप्लाई के बारे में कहा। उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमने अब तक कुल जिला अस्पताल के कम्बाइंड अस्पताल, पुरुष जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल 157 अस्पतालों मैं से 109 अस्पतालों को चौबीस घण्टे विद्युत सप्लाई निर्बाध रूप से बनी रहे हेतु 109 अस्पतालों को हमने स्वतंत्र विद्युत फीडर से जोड़ दिया। उसको चालू कर दिया। 24 निर्माणाधीन हैं और बहुत ही जल्दी उनको भी

हम क्रियाशील कर देंगे। जहां तक आप मातृ शिशु मृत्यु दर के बारे जो आंकड़ा बता रहे थे। अध्यक्ष जी, हम ज्यादा तो नहीं कहना चाहेंगे। सिर्फ हम इतना ही बताना चाहेंगे कि यहां पर हमने जो दो साल के अंदर हमारी जो जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा योजना है नियमित टीकाकरण है, नवजात शिशुओं की देखभाल है और उपचार के लिए जो विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन किया है। उससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर मैं दोनों में कमी आयी है। दो वर्षों में शिशु मृत्यु दर जो 57 प्रति हजार था अब घटकर 50 प्रति हजार पर आ गया है और मातृ मृत्यु दर जो था 359 प्रति लाख था आप 285 पता नहीं कहां से आंकड़ा लेकर बैठे हैं। हम आपके आंकड़े थोड़ी मानेंगे। जो सरकारी आंकड़ा है हमारा जो रिकार्डेड आंकड़ा है हम उसको बता रहे हैं। जो 359 प्रति लाख था वह घटकर 258 हो गया है। अब आप 258 को 285 कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अरे आंकड़े छोड़ो। अब नीतिगत कुछ बात बताना हो तो बताओ। आंकड़े तो बहुत आ गये।

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी आपकी बात का सम्मान करते हुए हमने उस बार भी अपनी पूरी बात को नहीं रखा था और यह डा0 साहब कटमोशन रखते समय बार–बार इस बात को इंगित कर रहे थे और ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, की यही सही है कि आप डाक्टर हो बहुत भिज्ञ हो, लेकिन अपने को सबसे ज्यादा समझदार समझना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, कुछ मजबूरियां थीं और समय की नजाकत थी इसलिए हम उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। हम पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 के बारे में जो 50 बेड के हैं, यह भी आंकड़ा दे सकते हैं, लेकिन लेट हो रहा है। अण्डर फाईव शिशु मार्टिलिटी रेट जो है 2012 में 68 था अध्यक्ष जी उसको घटा कर के 64 प्रति हजार किया है। मान्यवर, हम और भी आंकड़े देना चाहते हैं, लेकिन समय की नजाकत को हम समझ रहे हैं, अभी और बजट हमें पास कराना है। मान्यवर, बहुत से सुझाव आये हैं, अभी जैसल साहब ने बरौखर के बारे में कहा कि वहां एक भी डाक्टर नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि वहां पर कम से कम एक डाक्टर की व्यवस्था जरूर हो जानी चाहिए। त्रिपाठी जी आपने भी बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं, आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है हम जानते हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता में है, मिर्जापुर, सोनभद्र को हम लोग प्राथमिकता से ले रहे हैं, जैसा आप बायोमैंट्रिक एटेण्डेंस की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कोशिश कर रहे हैं। सोलर इन्वर्टर के बारे में भी आपका सुझाव अच्छा है, पोस्टमार्टम के समय के बारे में आपने जो कहा है, उसकी कुछ विधिक अड़चने हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत है, मैं ज्यादा और बात न कहते हुए, राठी साहब आपने जो सुझाव दिये, बहुमूल्य सुझाव हैं, उसमें हमारे अधिकारी अभी बैठे भी हैं सामने, वह नोट भी कर रहे हैं और अनीसुर्रहमान साहब ने अपनी जो मांग रखी है, आपने हमे लिखकर के दे दिया हम उस पर कार्रवाई करवा देंगे, अभी जैसा मा0 सदस्य भाजपा ने ट्रामा सेण्टर का जिक्र किया, तो ट्रामा सेण्टर अगर बन कर तैयार है तो हम

उसको दिखवा लेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका वह ट्रामा सेण्टर चालू किया जा सके। मा0 अध्यक्ष जी यह स्वास्थ्य विभाग जनता से सीधे गरीबों से सीधे जुड़े हुए मामलों वाला विभाग है और यह सरकार कटिबद्ध है और हमारी सरकार के संकल्प का और कटिबद्धता का असर हो रहा है, डाक्टर साहब का नजरिया चूंकि चश्मा इनका भगवा है, इसलिए इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है और यह सरकार का चार साल का स्वास्थ्य विभाग के प्रति और खासतौर से मा0 मुख्य मंत्री जी का जो विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने और स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को बेहतर बनाने का हमेशा उनका संकल्प रहता है और निर्देश रहता है, यह उसका असर है कि पूरे प्रदेश मैं स्वास्थ्य विभाग के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। हमें डाक्टर साहब आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इस सरकार को जनता का जो रूझान बढ़ा है, एक करोड़ से ज्यादा लोगों की हर साल जो आमद बढ़ी है, हम 80 लाख लोगों की हर महीने जो दवा दे रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन है जनहित में चाहूंगा कि आप इस कटमोशन को वापस लें और बजट का समर्थन करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 62 अरब, 59 करोड़, 40 लाख, 95 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 07 अरब, 14 करोड़, 71 लाख, 69 हजार रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 53 अरब, 77 करोड़, 58 लाख, 30 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष मैं अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,45,72,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री राजेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन की मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है।

श्री रवीन्द्र भड़ाना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह दूध विकास और दुग्धशाला का विषय है और किसान से जुड़ा है। हम लोग पश्चिम से आते हैं। ऐसा हो सकता है, कुछ समस्याएं पूरब के अंदर न हों। मान्यवर, दुग्ध के विकास की जहां सरकार बात करती है, बहुत अच्छी बात है। गांव का किसान भी अपने घर में भैंस पालता है। उसका दूध बेचता है और अपना जीवन–यापन चलाता है। कृषि से जुड़ा हुआ यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है लेकिन एक बड़ा हास्यास्पद विषय है। दूध का विकास तो हो रहा है लेकिन साथ–साथ में एक और विकास पश्चिम के अंदर चल रहा है। खास तौर से वह मेरी विधान सभा के अंदर वह सारा मामला है। सारा बवाल हापुड़ रोड पर स्थित है, वह कमेले जो इन पशुओं को काट–काट कर दूध का विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। हजारों पशु रोज वहां कटते हैं। मान्यवर, मैं जो कहना चाहता हूं, वह एक मांग के अनुसार मीट का कटान हो, ठीक है, समझ में आती है। मीट पैकेजिंग प्लांट है। वे गाय का कटान करके

मीट पैकेजिंग का कार्य कर रहे है। अभी एक कांग्रेसी नेता के परिवार की मीट की फैक्ट्री में गाय का मीट पकड़ा गया था।

श्री अध्यक्ष–

यह इससे संबंधित नहीं है वह पशुपालन मंत्री जी बोल रहे थे तो उस पर बोलना चाहिए। यहां दूध की बात करिए।

श्री अध्यक्ष–

भड़ाना जी, ये इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है, यह पशु पालन विभाग से सम्बन्धित है।

श्री रवीन्द्र भड़ाना–

मान्यवर, हम अपनी बात आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। आज मेरठ के अन्दर गो–कटान की मण्डी बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,45,72,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष ऐक्ट अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 42,18,91,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मा0 अध्यक्ष जी, कुल तीन–चार बातें मैं मा0 मंत्री जी के संज्ञान मैं देना आवश्यक समझता हूँ इसलिए दे रहा हूं कि रिकॉर्ड मैं आ जाए। पहली चीज तो यह है कि गोरखपुर मेडिकल कालेज ऐक्ट पुनर्वास केन्द्र प्रारम्भ हुआ है। यह पुनर्वास केन्द्र वर्ष 2012 से करीब–करीब बन्द है। बन्द इसलिए है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुआ था जिसके आधार पर 31 मार्च, 2012 के बाद उस पी0एम0आर0 केन्द्र में जितने भी पोस्ट क्रिएट हुए उन सारी पोस्टों को राज्स सरकार को क्रिएट करना था और उनके वेतन का वहन करना था, शेष सारा खर्चा भारत सरकार देती। 31 मार्च, 2012 से लेकर आज तक ये पोस्ट क्रिएट नहीं हुए। लगातार पत्र आ रहे हैं मेडिकल कालेज से कि इन पोस्ट को क्रिएट किया जाए अन्यथा ये विभाग बन्द हो जाएंगे। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि एम0बी0बी0एस0 की सीटें बढ़ी हैं, इसमें कोई डिनायल किसी को नहीं हो सकता, ये तथ्य है।

(सत्ता पक्ष के एक मा0 सदस्य द्वारा कोई आंकड़ा बोलने पर)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, अब ये आंकड़े गिना रहे हैं, मैं गिनाने लगूंगा तो देर हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

अरे, अब आंकड़े–वांकड़े मत गिनाओ।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, इनसे कहिए कि जितना जानते हैं उसी में रहें। अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मैंने लगातार इस बात का प्रपोजल दिया है कि मेडिकल कालेज ऐक्ट जो बच्चे एम0बी0बी0एस0 पढ़ने आते हैं, उनसे इस बात का बॉण्ड भरवाया जाए कि एम0बी0बी0एस0 करने के बाद कम से कम 5 साल, 10 साल ग्रामीण अंचलों में सरकारी सेवा दें और उसके बाद प्रैक्टिस में जाएं। हम बार–बार इस बात को सदन में कह रहे हैं और पिछले 5 सालों से कह रहे हैं कि सरकार को क्या आपत्ति है, मुझे नहीं मालूम। आर्म्ड फोर्सेज़ में तो इस प्रकार के बॉण्ड भराए जाते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है तो मा0 मंत्री जी दें कहां से तो इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस बॉण्ड भराने की प्रक्रिया पर सरकार को एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। तीसरी चीज, अध्यक्ष महोदय ने इसी सदन में विषय उठाया था और अभी भी समय है क्योंकि 13 मार्च से उसकी एप्लीकेशन्स एक्सेप्ट हो जाएंगी। मैंने एम0डी0, एम0एस0 ऐक्ट प्रवेश परीक्षा में वह बच्चे जो इसी प्रदेश के डोमेसाइल हैं, नागरिक हैं प्रदेश के बाहर जाकर के एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई करके एम0डी0, एम0एस0 की परीक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, यह सरकार उन्हें अनुमति नहीं दे रही है और इसी प्रदेश के निजी मेडिकल कालेजों में ऐसे बच्चे जिनका यू0पी0 में डोमेसाइल नहीं है उनको एम0डी0, एम0एस0 की प्रवेश परीक्षा में अनुमति दे रही है। यह एक बहुत बड़ा अन्याय है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि इस बैठक में अधिकारी भी बैठे होंगे। सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि अभी समय है सरकार इस

आदेश को बदल सकती है, वापस ले सकती है, किसी जिद की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, एक असाध्य रोग नियमावली है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार एक प्रशंसनीय योजना चलाती है जिसमें गम्भीर मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है लेकिन उसकी एक समस्या है, उसमें जो गरीबी रेखा निर्धारित है। वह अभी भी 30 हजार रुपये निर्धारित है, जबकि सारी अन्य योजनाओं के लिए गरीबी रेखा शहर में 56 हजार और गांव में 46 हजार है तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि मेडिकल कालेजों में जो असाध्य रोग नियमावली अभी 30 हजार पर सेवा देने का प्राविधान करती है इसको बढ़ाकर गरीबी रेखा के अनुरूप किया जाए।

'श्री राममूर्ति वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राधा मोहन अग्रवाल जी ने जो सुझाव दिये हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व ढंग से सुधार किया है और खासतौर से चिकित्सा शिक्षा विभाग में इस वर्ष के बजट में तो 32 परसेन्ट की लगभग वृद्धि है और 2012 के पूर्व कुल आठ मेडिकल कालेज संचालित थे। चार वर्षों में हमने चार मेडिकल कालेज बढ़ाये आने वाले समय में दो मेडिकल कालेज बांदा और बदायूं इसमें और बढ़ जाएंगे। कुल एम0बी0बी0एस0 की जो सीटें थीं 1340 पहले उपलब्ध थीं अब हमारी सीटें सब मिलाकर 1740 हो रही हैं और गरीबों के इलाज का जहां तक मसला है उसमें बी0पी0एल0 श्रेणी का व्यक्ति, 35 हजार से कम आमदनी का व्यक्ति, सवा तीन एकड़ तक की जोत का व्यक्ति, सवा तीन एकड़ खेती रखने वाला व्यक्ति ये माननीय मुख्य मंत्री जी के पीड़ा से इनका निःशुल्क असाध्य रोगों का इलाज करने की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर रखी है और जितने हमारे प्रदेश में ट्रामा सेन्टर हैं, उनमें 24 घंटे तक जितना भी पेसेन्ट का इलाज होगा वह पूरे प्रदेश में निःशुल्क है। पूरे प्रदेश में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था पहले 24 घंटे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर रखी है। इसके साथ–ही–साथ आप सभी जानते हैं कि 25 लाख रुपये गरीबों के इलाज के लिए सभी माननीय विधायकों को माननीय मुख्य मंत्री जी ने दे रखा है और प्रत्येक वर्ष में जहां तक समझता हूं कि अरबों रुपये से अधिक धनराशि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने विवेकाधीन कोष से गरीबों के इलाज के लिए देने का काम करते हैं तो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने मैं यह समझता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में जितना सुधार हुआ है, इतना पूरे देश में किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया होगा इसलिए हमारा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लें और जनहित में इस बजट को पास करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

'वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 42,18,91,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,94,11,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,94,11,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ)

मद संख्या– 12 (25) हो चुकी है अब अगली लेते हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग

परिवहन राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,65,45,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

'श्री ब्रिजेश कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर किसी भी प्रदेश के विकास के लिए दो महत्वपूर्ण अंग हैं, एक कम्यूनिकेशन सिस्टम और दूसरा है ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम। मान्यवर, परिवहन मैं केवल रोड ट्रान्सपोर्टेशन हमारे यहां सक्रिय है और जल यातायात पर अभी तक सरकार ने कोई संतोषजनक कदम नहीं उठायें है, यदि जल यातायात को प्रोत्साहन दिया जाये तो प्रदेश में पर्यटन का भी विकास होगा, साथ में जो सड़को पर जाम लगा रहता है, उससे भी निजात मिलेगी। मान्यवर, मैं हरदोई जनपद से चुनकर आता हूं वहां पर बिलग्राम विधान सभा से मैं विधायक हूं वहां की अनेकों समस्यायें हैं। कई दफा मैंने कई नियमों के माध्यम से कई समस्याओं को उठाया परन्तु एक भी समस्या का निदान अभी तक नहीं हुआ। 2013 मैं एक बस चलती थी जो बिलग्राम माधौगंज होते हुए कुरसठ होते हुए सुबह 10 बजे यात्रियों को लखनऊ पहुंचाने का काम करती थी परन्तु मान्यवर, कई बार प्रश्न लगाने के उपरान्त भी, कई दफा आश्वासन भी मिला कि उस बस को पुनः चालू कर दिया जायेगा परन्तु किसी भी प्रकार से उस बस को चालू नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इनकी बस चलवा देंगे।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

जी मान्यवर, चलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,65,45,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

'वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,15,12,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कटमोशन रखिये आप अपना।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, वह कुछ बोल दें तब हम रख दें।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, विभाग इतना महत्वपूर्ण है इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि रोजगार देने में कृषि के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई रोजगार दे रहा है तो वह सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्योग विभाग दे रहा है। एक करोड़ 80 लाख बेरोजगारों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग रोजगार उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा जो नई योजनायें माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे विभाग को इस बजट में दी हैं उसके बारे मैं बताना चाहूंगा। हर सदन में युवाओं के रोजगार की बात होती है। कल माननीय डाक्टर साहब ने भी अपने तारांकित प्रश्न में रोजगार के मसले को उठाया था और मैंने उसका जवाब दिया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने लगातार यह प्रयास किया उत्तर प्रदेश में कि कैसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायें उत्तर प्रदेश में और रोजगार बढ़ाया जाय। इस बजट में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आभार व्यक्त करूंगा कि इस बार पहली बार बजट में हमारे विभाग में समाजवादी व स्वरोजगार योजना की शुरुआत करी है जिसमें 40 करोड़ रुपये इस स्कीम में दिये हैं। जो नौजवान उत्तर प्रदेश ऐक्ट लघु उद्योग को लगााना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और मदद करने के लिए योजना शुरू करी जा रही है।

अध्यक्ष जी, दूसरी सबसे इम्पार्टेन्ट योजना जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने हम लोगों को दी है इस प्रदेश में लगभग 15 लाख हस्तशिल्पी हैं और यह बहुत बड़ी धरोहर हमारे प्रदेश की हैं क्योंकि हस्तशिल्पी जो अपने हाथ से सामान बनाते हों और चाहे पूर्वान्चल हो, चाहे मध्य यू0पी0 हो चाहे पश्चिमांचल हो अलग अलग जगह पर अलग–अलग हस्तशिल्पी मिलते हैं। मुरादाबाद में अगर कापर का काम किया जाता है तो सहारनपुर में लकड़ी का काम किया जाता है। मेरठ में स्पोर्ट्स का काम किया जाता है। मैं खुद कई हस्तशिल्पियों से मिला था मैंने पूछा कि आपके बच्चे इस ट्रेड में क्यों नहीं आना चाहते हैं जो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी है वह इसे ट्रेड में क्यों नहीं आना

चाहती तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनको कोई फ्यूचर इसमें दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि कमाई बहुत कम होती है इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी इस ट्रेड में नहीं आती है। बहुत से हस्तशिल्पी कार्य ऐसे उत्तर प्रदेश में हैं क्योकि वह हाथ से काम करते है जो जरदोजी का काम करते हैं यह देखा गया है कि उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, जो कापर में बहुत महीन काम करते हैं उनके लंग्स खराब हो जाते हैं वह 50 साल से ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। इसको देखते हुए मुख्य मंत्री जी ने हस्तशिल्प पेंशन योजना की शुरुआत इस बजट में करी है जिसमें 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। वह हस्तशिल्पी जिनके काम करने से गुर्दे खराब हो जाते हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं आंखें खराब हो जाती है वह आगे काम करने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं उनको कुछ पेंशन देकर उनका परिवार कैसे आगे चले उसकी योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी है।

तीसरी योजना जो उन्होंने दी है उद्यमिता विकास संस्थान को 10 करोड़ रुपये का उन्होंने प्राविधान किया है कि कैसे जो नये इंटरप्रिन्योर हैं वह कैसे आगे बढ़ें उनको प्रशिक्षित कैसे किया जाय इसके लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपये दिये हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत ब्याज उत्पादन की नई स्कीम हम लोगों ने शुरू करी है। यह देखा गया है कि प्राइम लेन्डिग रेट से जो नार्मली लोन होते हैं किसी भी उद्योग के लिए वह जो बैंक होते हैं वह प्राइम लेन्डिंग रेट से 3 से 4 प्रतिशत ज्यादा ब्याज दर लेती है तो 11 परसेन्ट से 14 परसेन्ट तक ब्याज देना पड़ता है अगर कोई उद्योग लगाता है और बैंक से लोन लेता है। हम लोगों ने विभाग ने सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रतिशत की सब्सिडी देने का प्राविधान रखा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फाइव परसेण्ट की सब्सिडी देने का प्रावधान रखा है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। इसमें करीब दो करोड़ साठ लाख रुपये का इस साल प्राविधान किया है, जो आगे बढ़ायेंगे भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत काम किया है। यह बात आपको सुनने में खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश देश में पिछले चार सालों में एक्सपोर्ट छत्तीस हजार करोड़ से बढ़कर सत्तासी हजार करोड़ रुपये हो गया है। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो रोजगार बढ़ेगा, नये उद्योग और लगेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउसिंल का गठन किया गया, निर्यात बन्धु का गठन किया गया। आज अगर प्रदेश में उद्योग बन्धु है तो एक्सपोटर्स के लिए भी एक प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश में दिया गया है और उनका एक निर्यात बन्धु बना दिया गया है कि अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस निर्यात बन्धु में आकर अपनी समस्या को रख सकते हैं। एम0एस0एन0ई0 पोर्टल जिसकी बहुत जल्दी माननीय मुख्य मंत्री जी शुरुआत करने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि विभाग की है, क्योंकि यह पोर्टल उन लोगों को एक प्लेटफार्म देने जा रहा है जो लोग छोटे कारोबार में हैं, जो लोग अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा एडवरटाइज नहीं कर सकते हैं। उस पोर्टल के माध्यम से वह देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट का एडवरटाइज कर सकते हैं जिससे आज जो उनका सीमित दायरा है, वह दायरा बढ़कर देश और विदेश तक चला जायेगा। बहुत सारी और चीजें हैं, समय

कम है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा और बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि इस साल हमारे प्लान्ड बजट में उन्होंने तकरीबन 61 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। यह पहली बार हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि यह विभाग उनके नेतृत्व में सूक्ष्म लघु उद्यमियों को आज जो प्लेटफार्म देने का काम कर रहा है उससे बहुत जल्द ही एक बहुत बड़ा चेंज उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है और जो माहौल उत्तर प्रदेश में उद्यमियों के लिए बना है उसके लिए हम सबको उन्हें एक स्वर से धन्यवाद देना चाहिये।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं लम्बा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे दो–दो मंत्री हमारे ऊपर बहुत दबाव बनाये हुये हैं कि बोलोगे नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा डिटेल में न जाकर दो–चार बिन्दु ही बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे आंकड़े रखे हैं। मैंने सुने और पढ़े भी हैं, क्योंकि जो पुस्तक दी गई थी लघु उद्योग एवं प्रोत्साहन विभाग की उसमें सब कुछ लिखा हुआ है और वह इन्होंने पढ़कर बताया है। जहां पर इन्होंने खत्म किया था, मैं वहीं से शुरू करता हूं क्योंकि इन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग के लिए बनाया हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह तो यही है कि क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिए। मान्यवर, माहौल यह है कि अगर इण्डस्ट्रलिस्ट की सुविधा की बात की जाये तो कहा जाये कि बराबर के स्टेटस में जिस प्रकार से इलेक्ट्रिीसिटी टैरिफ है जो विद्युत का रेट है, उसके अनुरूप कुछ विचार करें ताकि यहां पर उद्योगों को बढ़ावा मिले और उनको प्रोत्साहन मिले। जिस समय यह प्रश्न आता है तो उस समय उसका जवाब सरकार की तरफ से आता है कि जितने उद्यमी हैं वह सारे के सारे चोर हैं। अब जब यह पूछा जाये कि सबके लिए कह रहे हैं तो कहते हैं कि हां सबके लिए कह रहे हैं। मान्यवर, अगर कोई उद्योग लगाने के लिए यहां पर आता है और उसको सहयोग देने की बजाय उनको चोर की संज्ञा दी जाये। मान्यवर, उन्हें टेड़ीमार कहेंगे, डन्डीमार कहेंगे।

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, टेड़ीमार और डन्डीमार यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और यह यह लोग साजिश के तहत प्रदेश में व्यापारियों से अनर्गल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं।

श्री सतीश महाना–

छोड़ो न आपको थोड़े ही कह रहे हैं। अब आपको तो कहा नहीं, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं।

श्री जाहिद बेग–

मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग उद्योग को बन्द कराने की साजिश रच रहे हैं। इन्हें बोलने का कोई हक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, आप जल्दी समाप्त करें। काफी समय हो गया है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, बस दो–तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं बस दो सुझाव दूंगा। कहते हैं कि इतने हजार उद्योग लग गये, कहां लग गये पता नहीं। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय ने प्लास्टिक उद्योग पर बैन लगाया मैं उसका स्वागत करता हूं। क्योंकि यह बात सही है कि प्लास्टिक ने बहुत नुकसान किया है लेकिन उसके विकल्प के रूप में हमने कुछ भी नहीं सोचा कि जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, छोटा–छोटा काम करने वाले हैं, उसके विकल्प के रूप में हम उनको क्या सहयोग कर सकते थे, क्या उनको जूट के लिये कोई विकल्प ला सकते थे कि जूट के कुछ बैग्स बनाये, उसके लिये मान्यवर, किसी भी प्रकार की बात न बजट में है और न सरकार के संज्ञान ऐक्ट है। दूसरी और अंतिम बात मैं कहूंगा कि हम लोग मान्यवर, फेडरल सेक्टर में काम करते हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आफ इंडिया दोनों की अपनी–अपनी जिम्मेवारियां होती हैं । लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर हम यहां पर खड़े होकर कहते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से आप यह बात करो तो पता नहीं, सरकार को गवर्नमेंट आफ इंडिया के नाम से चिढ़ क्यों होने लगती है और चुन्ने क्यों काटने लगते हैं। तो वहां पर जो अच्छा होता है तो आप उसी अनुसार यहां अच्छा कर लीजिये और नहीं होता है तो उसको आप ड्राप कर दीजिये, लेकिन प्रयास तो करिये। अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा कि हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भी मेक इन इंडिया का पार्ट है। मंत्री जी कह देंगे कि मेक इन उत्तर प्रदेश। आबीवियसली जब मेक इन इंडिया होगा तो मेक इन उत्तर प्रदेश होगा, मेक इन महाराष्ट्र होगा, मेक इन गुजरात होगा, मेक इन राजस्थान होगा, मेक इन गोरखपुर होगा तो सारे का सारा मेक इन इंडिया ही होगा तो आप उससे चिढ़े नहीं। यदि आप उससे चिढ़ोगे तो आपको कठिनाई होगी और तब आप उसका लाभ नहीं ले सकते। मान्यवर, जब स्टार्ट अप इंडिया की बात आई, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इसकी जानकारी की कि स्टार्ट अप इंडिया है क्या। नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कौन–कौन सी योजनायें लाये हैं, क्या–क्या फैसिलटीज दे रहे हैं इसकी आप जानकारी तो करिये। इंडिया में ही यू0पी0 है आप इंडिया के बाहर अपने आपको समझ कर क्यों चलते हो। पहली बात तो मान्यवर, सरकार को यह मत स्पष्ट होना चाहिये कि यह भी इंडिया में हैं और बिना उत्तर प्रदेश के विकास हुये इंडिया का विकास नहीं हो सकता। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को लेकर इन्हें बड़ी परेशानी होती है। दूसरी बात जो आप स्माल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की बात करते हो, गवर्नमेंट आफ इंडिया के द्वारा उसमें भी बहुत सारी योजनायें लायी गयी हैं। मैं स्किल डेवलपमेंट की बात करूं जो मिनिस्ट्री आफ स्किल डेवलपमेंट बनी वही बात तो जो आप कह रहे हैं,

वही बात तो वह कह रहे हैं। आप क्यों नहीं उस बात को स्वीकार करके उस बात को आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहन देने का उसमें सहयोग देने का काम कर रहे हैं अल्टीमेंटली उससे जो लाभ होगा वह यहां रहने वाला का ही होगा। उत्तर प्रदेश का रहने वाला भारतवर्ष में ही रहता है, उसके बाहर नहीं रहता। मैं अपने आपको यहीं तक सीमित रखते हुये केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की सारी स्कीम्स आई हैं आप विस्तार से उसकी जानकारी करिये, उसमें जो भी सहयोग उनसे ले सकते हैं, वह लीजिये। उपभोक्ता को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंटरप्रेन्योर को उसमें जितना लाभ हो सकता है, सहयोग हो सकता है, वह करें और एक माहौल बनायें, एक वातावरण बनायें। इस समय जो इंडस्ट्री है वह सिर्फ एन0सी0आर0 को छोड़कर नोएडा और गाजियाबाद के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आती। थोड़ी बहुत कानपुर में बस नजर आती है तो उत्तर प्रदेश का विकास जब होगा, जब पूरे प्रदेश का विकास होगा, जब इंडस्ट्री ईस्ट यू0पी0 में भी लगेगी, मिडिल यू0पी0 में भी लगेगी, वेस्टर्न में तो है ही क्योंकि वेस्ट में वह आ जाता है। चारों तरफ मान्यवर, क्षेत्रीय संतुलन भी होना चाहिये और इसमें जिस प्रकार से इंडस्ट्री रोजगार सब एक दूसरे के साथ चलते हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, बनारस का इन डेढ़ सालों में सारा कायाकल्प करना चाहते है।

श्री अध्यक्ष–

अरे अब आप बैठो।

श्री सतीश महाना–

अपने विभाग पर तो बोलते नहीं हैं और जब मैं बोलने खड़ा होता हूं तो टोकते हैं। आपके आदेश का अनुपालन करते हुये मैं अपने आपको यहीं तक सीमित रखता हूं। इस आशा के साथ कि गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा जो नई पालिसीज इंडस्ट्रीज के संबंध में लायी गयी हैं आप उसका प्रचार–प्रसार और सदुपयोग कर पायें, इतनी बात कहकर में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,15,12,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख01ण16, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 5–3–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 72 सूचनायें प्राप्त हुईं।

1–श्री ममतेश शाक्य की जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम औना परगना गोडवा में स्व0 राम लाल के वारिसों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में,

2–श्री त्रिलोकी राम की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के अन्तर्गत मुरसान मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

3–श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद गौतमबुद्धनगर के तहसील जेवर में अवैध रूप से चलाये जा रहे मैंरिज हाल/बैंक्विट हाल पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में,

4–श्री मनोज कुमार सिंह की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन अशोक नगर सचिवालय कालोनी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

5–श्री गुलाब चन्द सरोज की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत गोमती नदी पर नैपुरा खरचलपुर पाल्टून/पीपा पुल के स्थान पर सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6–श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के विकास खण्ड फखरपुर अन्तर्गत भूपानी जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–श्रीमती सीमा की जनपद जौनपुर की तहसील मछलीशहर के ग्राम पोहा की चकबन्दी 1972 में होने के उपरान्त आज तक धारा 52 का प्रकाशन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

8–श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के आंवला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चकरपुर व महमूदपुर के बीच अरिल नदी पर सेतु का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

9–श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा में ब्लाक फरह में पेयजल आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

10–श्री जगराम पासवान की जनपद बलरामपुर में संचालित आदर्श जनजातीय बेसिक प्राइमरी पाठशाला बालापुर, जरवा के शिक्षकों के नियमित वेतन एवं अवशेष वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में,

11–श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में सार्वजनिक परिवहन/सिटी बस सर्विस का प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

12–श्री सुदेश शर्मा की जनपद बुलन्दशहर के कस्बा बुगरासी जलालपुर मार्ग के पास अवैध रूप से चलायी जा रही चर्बी निकालने वाली फैक्ट्री को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में,

13–श्री इरफान सोलंकी की डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर बरेली द्वारा करोड़ों रुपये की भूमि की फर्जी नीलामी दिखा कर बन्दरबांट करने के सम्बन्ध में,

14 श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में विद्युत सप्लाई 22 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में,

15–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद कानपुर महानगर के छावनी के कतिपय मोहल्लों में सीवर लाइन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

16–श्री सुरेश राणा की जनपद शामली में समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन तथा समाजवादी पेंशन में घोर लापरवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

17–श्री नूर सलीम राणा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

क्रम सं0	नाम
1	श्री सिनोद कुमार शाक्य
2	श्री वाचस्पति
3	श्री बृजेश कुमार
4	श्री संजय प्रताप जयसवाल
5	श्री हजरत मुर्सरत अली बिट्टन
6	श्री विनय तिवारी
7	श्री राधेश्याम जायसवाल
8	श्री जगन प्रसाद गर्ग
9	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
10	श्री रवि शर्मा
11	श्री सुरेश कुमार खन्ना
12	मो0 रेहान
13	श्री अगयश राम सरन वर्मा
14	ठा0 दलवीर सिंह
15	श्री जय प्रकाश निषाद
16	श्री रविदास मेहरोत्रा
17	श्री भगवान सिंह कुशवाहा

18	श्री गेंदा लाल चौधरी
19	श्री अनीसुर्रहमान
20	श्री राजबली जैसल
21	श्री अविनाश कुशवाहा
22	श्री आशीष कुमार यादव
23	श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर
24	श्री योगेन्द्र उपाध्याय
25	श्री अरविन्द सिंह यादव
26	श्री मुकेश श्रीवास्तव
27	श्री पंकज गुप्ता
28	श्री रविन्द्र जायसवाल
29	श्री उपेन्द्र तिवारी
30	डा0 अरुण कुमार
31	श्री कुलदीप सिंह सेंगर
32	श्री ओम कुमार
33	श्री राकेश प्रताप सिंह
34	कुंवर कौशल सिंह
35	श्री संजय कपूर
36	श्री सतीश महाना
37	श्री अनूप कुमार गुप्ता
38	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
39	श्री चन्द्र भान सिंह पटेल
40	श्री अबरार अहमद
41	श्री राजनारायण बुधौलिया
42	श्री जय प्रकाश अंचल
43	श्री भीम प्रसाद सोनकर
44	श्री फेरनलाल अहिरवार
45	श्री जाकिर अली
46	श्री काली चरन सुमन
47	श्री गुटियारी लाल दुबेश
48	श्री सन्त राम कुशवाहा
49	श्री सुरेश बंसल
50	श्री राजीव गुम्बर

51	श्री जय प्रकाश निषाद
52	श्री उमेश पाण्डेय
53	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया
54	श्री राम चन्द्र यादव तथा
55	श्री दलजीत सिंह

जनपद सहारनपुर नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री राजीव गुम्बर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

श्री राजीव गुम्बर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 25–02–2016....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

ख्को दी गयी सूचना निम्नवत् है :–

''सहारनपुर नगर निगम का गठन पिछले लगभग 8 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमे अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं और नगर निगम जनप्रतिनिधियों से वंचित हैं, जिस कारण यहां के अधिकारी व कर्मचारी निरंकुश व भ्रष्टाचारी हो गये हैं। सहारनपुर नगर निगम द्वारा वर्तमान में हाउस टैक्स का सर्वे करवाया जा रहा है, जिसमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार, धांधली व जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। छोटे–छोटे मकानों व दुकानों पर 5–20 गुना तक कर आरोपित किया जा रहा है और नगर निगम के अधिकारी इस सर्वे में भ्रष्टाचार कर लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जिन लोगों के द्वारा पैसे नहीं दिये जाते उन पर अत्याधिक कर लगाया जा रहा है। नगर निगम कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कृत्यों के कारण आम जनमानस में अत्यन्त रोष व्याप्त है। आमजन परेशान हैं। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2–इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर ने अवगत कराया गया है कि तत्कालीन नगर पालिका परिषद्, सहारनपुर को उच्चीकृत कर 32 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 01–10–2009 को नगर निगम का गठन किया गया था।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासनादेश संख्या–3005/ नौ–9–2013–85ज0/2005 टी0सी0, दिनांक 27–12–2013 में उ0 प्र0 नगर निगम सम्पत्ति कर (द्वितीय संशोधन नियमावली, 2013) में दिये गये निर्देश के क्रम में वार्डवाइज न्यूनतम किराये की पुनरीक्षित दरें प्रकाशित कर नागरिकों से आपत्ति मांगी गयी थी। कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने पर उक्त दरों को दिनांक 24–05–2014 को सरकारी गजट उ0 प्र0 में प्रकाशित कराकर लागू कर दिया गया। इन दरों में विगत वर्ष 2009 के सापेक्ष अधिकतम 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। नगर निगम के कर्मचारियों से कराये जा रहे सामान्य सर्वे में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण कर बिल निर्गत किये जा रहे हैं। करारोपण नियमानुसार किया जा रहा है तथा यदि कोई आवेदक आपत्ति करता है तो नियमानुसार सुनवाई कर नगर निगम द्वारा उसका निस्तारण भी किया जा रहा है।,

जनपद गोरखपुर के मलौनी बांध से ग्राम सभा सनहा के पास चौरी होते हुए रायगंज सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 5.70 कि0मी0 है।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

ख्जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग का निर्माण कार्य 04 चरणों में हुआ है जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1–चैनेज 0.000 से 1.100 कि0मी0 तक–मार्ग के इस भाग का नवनिर्माण वर्ष 2010–11 में किया गया है, जिसकी दशा संतोषजनक है।

2–चैनेज 1.100 से 4.400 कि0मी0 तक–मार्ग के इस भाग की लम्बाई 3.30 कि0मी0 है जिसका निर्माण वित्तीय वर्ष 2006–07 में किया गया है। मार्ग का चैनेज 1. 100 से 4.400 कि0मी0 तक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

3–चैनेज 4.400 से 4.4600 कि0मी0 तक–मार्ग के इस भाग का विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2014–15 में किया गया है। मार्ग की दशा अच्छी है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4–चैनेज 4.600 से 5.700 कि0मी0 तक–मार्ग के इस भाग का निर्माण वित्तीय वर्ष 2014–15 में श्री राम शरण दास ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तेली टोला सम्पर्क मार्ग के नाम से किया गया है। मार्ग की दशा अच्छी है।,

उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग के आदेशों की अनदेखी करते हुए मुख्य अभियन्ता अलीगढ़ द्वारा काष्ट डाटा बुक से निर्धारित दर से अधिक पैसा जमा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं) के पत्रांक 15420 दिनांक 21–12–2013....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

ख्के अन्तर्गत निर्गत निर्देशों को समस्त विभागीय विनियमों का परिशीलन करने पर नियम विरुद्ध पाये जाने के कारण भूतलक्षीय प्रभाव से कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2339/मु0अ0अ0क्षे0/तक दिनांक 20–02–2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा कास्ट डाटा बुक के प्राविधानों के विपरीत चार्ज की गई अतिरिक्त धनराशि को सम्बन्धित उपभोक्ताओं के बिलों में समायोजित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

2–विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित कास्ट डाटा बुक में निर्धारित दरों के अनुसार निजी नलकूप के नये विद्युत उपभोक्ताओं के संयोजन हेतु धनराशि जमा कराने के निर्देश पत्रांक–715 दिनांक 24–02–2016 द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

3–जमा योजना के अन्तर्गत डबल पोल एवं परिवर्तक की धनराशि रु0 1.00 लाख जमा कराये गये उपभोक्ताओं की धनराशि में से अतिरिक्त धनराशि को नियमानुसार बिलों में समायोजित किये जाने हेतु पत्रांक–2818 दिनांक 29–02–2016 के द्वारा आदेशित किया गया है।

4–टी0पी0एम0ओ0 न लगाये जाने वाले परिवर्तकों के उपभोक्ताओं को समानुपातिक धनराशि उनके बिलों में समायोजित करने के आदेश पारित कर दिये गये हैं तथा टी0पी0एम0ओ0 उपलब्ध न होने पर प्राक्कलन में टी0पी0एम0ओ0 की धनराशि को चार्ज न किये जाने हेतु पत्रांक–2818, दिनांक 29–02–2016 के द्वारा आदेश पारित किये गये हैं।,

---

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जो बात कहनी थी इसके माध्यम से मैंने कही है और वह सरकार ने स्वीकार कर ली है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। किसानों के साथ बड़ी भयंकर बेईमानी हुई। दक्षिणांचल के एम0डी0 आगरा और अलीगढ़ मण्डल दोनों का काम देख रहे थे उन्होंने जो नियामक आयोग ने रेट तय किये थे उससे दोगुने–तिगुने रेट से पैसे वसूल किये। आज इसमें स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गयी, हमने यह वसूल कर लिये, यह हम किसानों को वापस करेंगे और जिसने गलती की है, वह रिटायर हो गया। तो मैं आपके माध्यम से इसमें जरूर कार्रवाई कराना चाहता हूं। आप पीठ से निर्देश दें कि इसमें जितने भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो करोड़ो–करोड़ रुपया किसानों का इन्होंने जमा कर लिया है मय ब्याज के इनके वेतनों से वापिस किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको देखेंगे।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम रीगा के मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गेंदा लाल चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बांदा में तहसील नरैनी के ग्राम....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

ख्रीगा का मुख्य मार्ग जो ग्राम बन्डे तक जाता है की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग अत्यन्त ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, जिस कारण स्थानीय निवासियों को आवागमन में अत्यन्त ही विषयम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रायः बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्तियों को इस कारण समय से इलाज भी नहीं मिल पाता है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव स्थानीय निवासियों की परेशानियों का दृष्टिगत रखते हुए शासन का अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग की मरम्मत/पुनःनिर्माण की मांग करता हूं।

वक्तव्य

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि जनपद बांदा में तहसील नरैनी के ग्राम रीगा को जोड़ने वाला बन्डे से रीगा सम्पर्क मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जिसकी लम्बाई 2.70 कि0मी0 है। यह मार्ग लेपन स्तर तक 08 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था। वर्तमान में बन्डे से रीगा मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सीतापुर के अन्तर्गत आने वाले गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

विधान सभा क्षेत्र सीतापुर, जनपद सीतापुर के अंतर्गत डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

ख्एवं त्वरित आर्थिक विकास योजना सहित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (वर्तमान में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाहित) के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था मे0 ज्योति कन्सट्रक्शन कम्पनी को डिस्काम से आवंटित किया गया था। प्रश्नगत कम्पनी द्वारा कार्य में रुचि नहीं ली गई। इस सम्बन्ध में स्थानीय व डिस्काम स्तर से कार्यदायी संस्था मैं0 ज्योति कन्सट्रक्शन कम्पनी को कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु फिर भी अपेक्षित परिणाम न आने के कारण कार्यदायी संस्था के विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिसके अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर के पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 2015 एवं प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के पत्र दिनांक 24–02–2016 एवं पत्र दिनांक 24–02–2016 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसके माध्यम से कार्यदायी संस्था मैं0 ज्योति कन्सट्रक्शन कम्पनी को अनुबन्ध समाप्त करने तथा जमा सी0पी0जी0 (कान्ट्रेक्ट परफारमेन्स गारण्टी)

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जब्त करने की नोटिस दी गयी है तथा फर्म को यह भी अवगत करा दिया गया है कि भविष्य में निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।,

जनपद मथुरा के कतिपय ग्राम सभाओं स्थित नेशनल हाई–वे–2 व गोवर्धन रोड के दोनों तरफ बसी आबादी से उत्सर्जित जल की समुचित निकासी हेतु गहरे नालों का निर्माण कराये जाने के

सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी कि विधान सभा क्षेत्र–मथुरा में नेशनल हाई–वे–2....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

ख्व गोवर्धन रोड की दोनों तरफ स्थित ग्राम सभा–बाकलपुर, मथुरा बांगर, नवादा, तंतूरा, विर्जापुर, महोली, गणेशरा तथा सतोहा आदि की भूमि पर तमाम कालोनियों का निर्माण हो चुका है। इस क्षेत्र में लाखों की आबादी रहती है। मथुरा शहर से लगी हुई इस आबादी क्षेत्र में जल निकासी के लिये नाला न होने के कारण हाई–वे के दोनों किनारे कालोनियों का गन्दा पानी भरा रहता है। इस गन्दे पानी से भयंकर जलजनित संक्रामक बीमारी होने का खतरा हर समय बना रहता है। नेशनल हाई–वे–2 की तरफ से इन कालोनियों से सटाते हुए मथुरा गोर्धन रोड पर नाले का निर्माण, गोवर्धन चौराहे से मण्डी समिति तक, मण्डी समिति से हाई–वे थाने तक, हाई–वे थाने से रिफाइनरी टाउनशिप तक नेशनल हाई–वे–02 पर मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण/प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा यहां गहरा नाला निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। नेशनल हाई–वे–2 का चौड़ीकरण कर 6 लेन बनाये जाने का कार्य वर्तमान में यहां चल रहा है। इसमें नेशनल हाईवेज अथारिटी आफ इण्डिया से जिलाधिकारी, मथुरा व उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण बातचीत करके जगह–जगह नेशनल हाई–वे को क्रास करती हुई अन्डर ग्राउन्ड ह्यूम पाइप बड़ी वाली डलवाई जानी चाहिए जिससे भविष्य में सड़क के दोनों तरफ बढ़ रही आबादी से उत्सर्जित गन्दे पानी से होने वाले जलभराव से बचा जा सके तथा इन ह्यूम पाइपों के माध्यम से दूसरी तरफ पानी जा सके। यहां पर बड़ी ब्यास की ह्यूम न डाले जाने से बरसात के दिनों में कोई गम्भीर

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

घटना घट सकती है। इसी प्रकार मथुरा–गोवर्धन रोड पर स्थित सतोहा तक जहां औद्योगिक क्षेत्र में कालोनी बसी है, पर लोक निर्माण विभाग एवं मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा दोनों ओर गहरा नाला निर्माण कराये जाने से यहां पर लाखों की आबादी वाली बसी कालोनियों की जल निकासी सम्भव हो सकेगी। इसलिये वहां तथा नेशनल हाई–वे–2 के दोनों तरफ गहरे नाले का निर्माण जनहित में आवश्यक है। प्रकरण अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मथुरा में नेशनल हाई–वे–2 व गोवर्धन रोड के दोनों तरफ बसी आबादी से उत्सर्जित जल के समुचित निकासी हेतु गहरे नाले का निर्माण शीघ्र कराये जाने तथा बरसात के समय जलभराव से बचने के लिये नेशनल हाई–वे–2 पर जगह–जगह नेशनल हाई–वे–2 को क्रास करती हुई बड़ी ब्यास की अन्डर ग्राउन्ड ह्यूम पाइप डाले जाने हेतु एन0एच0ए0आई0, भारत सरकार के अधिकारियों व जिलाधिकारी, मथुरा व उपाध्यक्ष/सचिव, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण से बातचीत/पत्राचार कर समाधान निकालने व शीघ्र कार्यवाही करने की मांग करते हुए इस पर शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।

प्रकरण अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का है। अतएव समाधान निकालने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने की मांग करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

2–उक्त सूचना के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी, मथुरा से प्राप्त आख्या के आधार पर अवगत कराना है कि मथुरा–वृन्दावन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नेशनल हाई–वे–2 व गोवर्धन रोड के दोनों तरफ स्थित ग्राम सभा बाकलपुर, मथुरा, बांगर, नवादा, तंतूरा, विर्जापुर, महोली, गणेशरा तथा सतोहा आदि कालोनियों बसी हुई हैं। इन कालोनियों की आबादी से उत्सर्जित जल के समुचित निकासी हेतु कोई गहरे नाले आदि की व्यवस्था नहीं है। नेशनल हाई–वे–2 के साथ दोनों तरफ पूर्व में खुला नाला था, जिसमें उक्त कालोनियों का पानी जा रहा था परन्तु वर्तमान में नेशनल हाई–वे चौड़ीकरण के कारण खुले नाले को तोड़कर बन्द सीवर लाइन डाली जा रही है। जिसमें केवल नेशनल हाई–वे–2 का ही पानी जायेगा। कालोनियों के पानी की निकासी हेतु नाले आदि की आवश्यकता है, जोकि एक वृहद कार्य है, जिसे ग्राम पंचायतों के संसाधन से कराया जाना सम्भव नहीं है।,

नगर पालिका परिषद् मोदीनगर गाजियाबाद की अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुदेश शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनॉक 25–02–2016 को यह सूचना दी गयी कि ''नगर पालिका परिषद मोदीनगर,....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

ख्गाजियाबाद की अध्यक्षा की अनेकों घोर अनियमितताओं के चलते शासन द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाई गई है। जिसके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय ने जो स्थगन आदेश दिया है उस स्थगन आदेश में स्पष्ट है कि अध्यक्षा नगर पालिका मोदीनगर को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इनके द्वारा अनियमित तरीके से किये गये अवैधानिक कृत्यों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा पत्रों के माध्यम से शासन को अवगत कराया जा चुका है। उक्त प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अध्यक्षा नगर पालिका परिषद् मोदीनगर, गाजियाबाद को सुनवाई का अवसर प्रदान करने सम्बन्धी पत्रावली शीघ्र शुरू कराकर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इनके द्वारा किये गये अनियमित व अवैधानिक कृत्यों पर कार्यवाही की जाये।

उल्लेखनीय है कि अध्यक्षा नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर के द्वारा की गयी अनियमितताओं की फेहरिस्त बहुत लम्बी है। इनके द्वारा अनेकों बार पद का दुरुपयोग किया गया है तथा राजकीय धन की हानि भी की गयी है। जिससे विकास सम्बन्धी समस्त कार्य भी ठप्प पड़े हैं। उक्त प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमती सरोज शर्मा, अध्यक्षा, नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर, गाजियाबाद द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में शासन के आदेश दिनांक 1–9–2015 द्वारा उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रविरत (वंचित/प्रतिबन्धित) करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध श्रीमती शर्मा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या–58307/2015 में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21–12–2015 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24–2–2016 को शासन स्तर पर श्रीमती शर्मा की व्यक्तिगत सुनवाई निर्धारित की गयी थी किन्तु श्रीमती शर्मा के दिनांक 26–2–2016 तक मुख्यालय से बाहर होने के कारण दिनांक 9–3–2016 को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई निर्धारित की गयी है।,

जनपद महोबा में जिला कारागार के नवीन भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कारागार मंत्री का केवल वक्तव्य

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

मा0 सदस्य ने अपनी सूचना के माध्यम से जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र महोबा.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

ख्मैं जिला कारागार का निर्माण अभी तक न हो पाने की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला कारागार महोबा की बन्दी क्षमता 175 है, जिसके सापेक्ष दिनांक 24–02–2016 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में 357 बन्दी निरुद्ध रहे हैं। इस प्रकार जिला कारागार महोबा में ओवरक्राउडिंग की समस्या है। जनपद महोबा में कारागार के निर्माण के लिये भूमि की तलाश प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी महोबा को दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में जिलाधिकारी, महोबा ने अपने पत्र दिनांक 26–06–2015 द्वारा अवगत कराया है जिला कारागार महोबा के निर्माण हेतु ग्राम सभा बिलवई में कुल 15.917 हेक्टेयर भूमि उपयुक्त पायी गयी है, जिसमें से 14.603 हेक्टेयर भूमि ग्राम सभा की है तथा यह भूमि बंजर है। शेष 1.314 हेक्टेयर भूमि दो काश्तकारों की है जिसे आपसी समझौते के आधार पर क्रय किया जाना प्रस्तावित है। जिला कारागार के निर्माण हेतु चयनित भूमि में जल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया गया कि वाटर लेविल की जांच सम्बन्धित एजेन्सी से अवश्य करा ली जाय ताकि भविष्य में पानी की समस्या उत्पन्न न हो।

शासन के पत्र दिनांक 05–08–2015 द्वारा जिलाधिकारी, महोबा को निर्देशित किया गया कि जिला कारागार के निर्माण हेतु 15.917 हेक्टेयर भूमि के अतिरिक्त 15.00 हेक्टेयर भूमि की तलाश और कर ली जाय ताकि बन्दियों की क्षमता के अनुसार उपयुक्त कारागार का निर्माण कराया जा सके। जनपद महोबा में जिला कारागार के निर्माण हेतु पर्याप्त एवं उचित भूमि की तलाश प्राथमिकता के आधार पर करायी जा रही है। भूमि की व्यवस्था होने के उपरान्त जिला कारागार का निर्माण कराया जायेगा।,

जनपद कासगंज के अन्तर्गत सिढ़पुडा में ग्राम पिलखुनी से अखतउमंगपुर स्थित गंजडुडवारा मार्ग पर कला बम्बा की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद कासगंज अंतर्गत सिढ़पुडा में ग्राम पिलखुनी.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

ख्से अखतउमंगदपुर स्थित गंजडुडवारा मार्ग पर कला बम्बा की क्षतिग्रस्त पुलिया की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त पुलिया विगत लगभग 02–03 वर्षों से टूटी पड़ी हुई है। जिस कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन हेतु कई किलोमीटर का चक्कर लगा कर ही यात्रा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं।

अतः स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए उल्लिखित पुलिया की मरम्मत/नवनिर्माण कराये जाने हेतु शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।

केवल वक्तव्य

प्रश्नगत पुलिया फर्रुखाबाद शाखा प्रणाली के मोहनपुर राजवाहा के कि0मी0 7.820 पर निर्मित है। इस पुलिया की स्लैब क्षतिग्रस्त हो गई है। इसकी मरम्मत हेतु रु0 2.45 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत हो गया है। सूखे की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में फर्रुखाबाद शाखा रबी सिंचाई हेतु चल रही है। फर्रुखाबाद शाखा की आगामी नहर बन्दी की अवधि में उक्त क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।,

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के अन्तर्गत दोहरीघाट खटिक टोला स्थित देशी शराब की दुकान की बहाली कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

श्री उमेश पाण्डेय, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25–02–2016 को नियम–51 के अंतर्गत....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

ख्यह सूचना दी गयी कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड–दोहरीघाट के थाना दोहरीघाट के अन्तर्गत दोहरीघाट खटिक टोला कस्बा के निवासी–त्रिलोकी प्रसाद सोनकर पुत्र स्व0 वंशराज सोनकर को देशी शराब की दुकान आवंटित थी। जिसे वर्ष 2013 में पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा अवैध तरीके से सीज कर दी गयी थी। दिनांक 08–04–2013 को जिलाधिकारी, मऊ द्वारा उक्त देशी की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। दिनांक 25–9–2014 को माव उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में दिनांक 3–11–2014 को जिलाधिकारी, मऊ द्वारा दुकान को पुनः संचालित किये जाने हेतु आदेश दिया गया है, परन्तु दुकान लगभग 10 माह तक संचालित हुई। इस बीच दिनांक 08–07–2015 को चरित्र सत्यापन के आधार पर उक्त देशी शराब की दुकान के लाइसेन्स को पुनः निलम्बित कर दिया गया, जबकि त्रिलोकी प्रसाद सोनकर के चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में जो पुलिस/उपजिलाधिकारी द्वारा रिपोर्ट भेजी गयी, उसके कोई भी विपरीत तथ्य अंकित नहीं किया गया। जिलाधिकारी, मऊ द्वारा शासकीय अधिवक्ता, मऊ से विधिक राय भी ली जा चुकी है, जिसमें उन्होंने सोनकर की देशी शराब दुकान को बहाल करने में किसी भी प्रकार की विधिक बाधा नहीं होने की राय दी है। उक्त दुकान ही त्रिलाकी प्रसाद सोनकर के परिवार की जीविकोपार्जन का साधन है, परन्तु उत्पीड़न करने के उद्देश्य से त्रिलोकी प्रसाद सोनकर का चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है और न ही उनकी देशी शराब दुकान की बहाली की जा रही है, जिससे पीड़ित परिवार में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

2–उक्त सूचना के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त से प्राप्त आख्या के आधार पर अवगत कराना है कि दिनांक 26–03–2013 को देशी शराब दुकान दोहरीघाट खटिक टोला पर पुलिस एवं आबकारी विभाग के संयुक्त कार्यवाही में अनुज्ञापित परिसर से कुल 125 पेटी अवैध शराब व 282 पेटी वैध शराब बरामद हुई। कुल 05 बोरों में भराई हेतु 2500 प्लास्टिक की नई शीशियां, 8500 नकली रैपर, लगभग 1000 ढक्कन, नकली होलोग्राम 805, एक बोतल कैरोमल द्रव्य, एक बोतल इसेन्स, 20 लीटर के 02 जरीकेनों में कुल 25 लीटर यूरिया नौसादर आदि से अपमिश्रित रेक्टीफाइड स्प्रिट, 500 लीटर की नीचे टोटी लगी विजन ब्राण्ड की टंकी, अवैध शराब की बिक्री का 44960 रु0 बरामद हुआ। गिरफ्तार विक्रेता रामउजागिर दुबे पुत्र स्व0 श्रीराम दुबे नि0 त्रिलोकपुर, थाना बेलघाट, गोरखपुर व अनुज्ञापी त्रिलोकी प्रसाद सोनकर पुत्र स्व0 बंशराज के विरुद्ध

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थानीय थाना दोहरीघाट में आबकारी अधिनियम की धारा–60/72 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 472, 272, 273 के अन्तर्गत अभियोग संख्या 98/2013 दर्ज कराया गया। दुकान में उपलब्ध 282 पेटी वैध शराब को भी धारा–72 सी के अन्तर्गत जब्त किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी, मऊ के आदेश संख्या 25–27/दिनांक 08–04–2013 द्वारा दुकान का अनुज्ञापन निरस्त करते हुए अनुज्ञापी द्वारा जमा बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली गयी तथा दुकान का नये सिरे से स्थाई व्यवस्थापन कराया गया था।

3–लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी, मऊ के उक्त आदेश दिनांक 08–04–2013 के विरुद्ध अनुज्ञापी श्री त्रिलोकी सोनकर द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के समक्ष अपील संख्या–13/2013 दाखिल की गयी, जो दिनांक 12–08–2013 द्वारा खारिज कर दी गयी। श्री सोनकर द्वारा इस अपील में आपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–2013 के विरुद्व शासन में रिवीजन संख्या–21/2013 दाखिल की गयी, जां प्राधिकृत अधिकारी के आदेश दिनांक 26–11–2013 द्वारा खारिज कर दी गई। अपील एवं रिवीजन खारिज होने के उपरान्त श्री त्रिलोकी सोनकर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ में रिट याचिका संख्या–8446(एम0एस0)/2013 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा इस रिट में पारित निर्णय दिनांक 25–09–2014 द्वारा श्री सोनकर द्वारा योजित याचिका को स्वीकार करते हुए लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी, मऊ के आदेश दिनांक 08–04–2013, अपील सं0–13/2013 में अपीलीश प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–2013 एवं रिवीजन सं0–21/2013 में पारित आदेश दिनांक 26–11–2013 को निरस्त कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के इस आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, मऊ के आदेश दिनांक 01–11–2014 द्वारा श्री त्रिलोकी सोनकर के पक्ष में देशी शराब दुकान दोहरीघाट खटिक टोला बहाल कर दी गयी थी।

4–देशी शराब दुकान–दोहरीघाट खटिक टोला का अनुज्ञापन श्री त्रिलोकी सोनकर पुत्र स्व0 बंशराज सोनकर नि0 दोहरीघाट खटिक टोला, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ के नाम से वर्ष 2015–16 हेतु नवीनीकृत है। उ0प्र0 आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के नियम 8 (घ) (चार) में उल्लिखित है ''यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला जहां का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लाइसेंस जारी होने के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक इतिहास नहीं है।'' किन्तु श्री सोनकर द्वारा वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में न प्रस्तुत करने पर लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी, मऊ द्वारा 03–01–2015 को श्री त्रिलोकी सोनकर के विरुद्ध नोटिस जारी की गयी कि

नोटिस प्राप्ति के 20 दिन के अन्दर चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। श्री सोनकर द्वारा इस नोटिस का उत्तर दिनांक 19–01–2015 को प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर दिया गया है। प्रमाण पत्र मिलते ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

5–श्री त्रिलोकी सोनकर द्वारा चरित्र प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराने के कारण जिला आबकारी अधिकारी, मऊ के पत्र सं0–393/जि0आ0अ0, मऊ/15–16, दिनांक 28–07–2015 द्वारा अनुज्ञापन निलम्बित करते हुए पुनः कारण बताओ नोटिस दी गयी कि सात दिन के अन्दर श्री सोनकर अपना उत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा श्री सोनकर का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा। श्री सोनकर द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक 05–08–2015 को प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि ''वह एक राजनैतिक व्यक्ति हैं। विरोधियों द्वारा उसकी छवि धूमिल करने हेतु शिकायती–पत्र दिये गये। किसी न्यायालय से किसी आबकारी अपराध के लिये दोष सिद्ध नहीं किया गया है। अतः नोटिस निरस्त करते हुए अनुज्ञापन बहाल किया जाय।''

6–श्री सोनकर के उक्त उत्तर दिनांक 05–08–2015 के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी के पत्र संख्या–3853/वै0सहा0/एडीएम–15, दिनांक 06 अगस्त, 2015 द्वारा पुलिस अधीक्षक से पुनः आख्या मांगी गयी। पुलिस अधीक्षक, मऊ की आख्या दिनांक 02–09–2015 प्रेषित की गई, जिसमें थानाध्यक्ष दोहरीघाट की रिपोर्ट दिनांक 16–08–2015 ऐक्ट अवगत कराया गया है कि श्री त्रिलोकी सोनकर के विरुद्ध मु0सं0–772/06 धारा–406, आई0पी0सी0, मु0अ0सं0–1325/11 धारा–356, 342, 323, 504 आई0पी0सी0, मु0अ0सं0–110/13 धारा–3 गुण्डा ऐक्ट, मु0अ0सं0–183/13 धारा–147/323 आई0पी0सी0 विचाराधीन है तथा अन्य मुकदमों में दोष मुक्त है। पुलिस अधीक्षक, मऊ की उक्त आख्या पर जिला आबकारी अधिकारी के पत्र संख्या–591/जि0आ0अ0/मऊ, दिनांक 08–09–2015 द्वारा प्रकरण में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) से विधिक राय ली गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा दिनांक 21–09–2015 को राय दी गयी, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि जब तक आरोपी सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया जाता है वह अपराधी की श्रेणी में नहीं आता। अतः निलम्बन आदेश/कारण बताओ नोटिस दिनांक 28–07–2015 निरस्त किया जाना विधि सम्मत् होगा।

7–जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) की उक्त राय के आलोक में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मऊ के पत्र संख्या–903/जि0आ0अ0, मऊ दिनांक 19–10–2015 द्वारा पुलिस अधीक्षक, मऊ से आख्या मांगी गयी। श्री सोनकर के चरित्र प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, मऊ के पत्र सं0–वीआरनं0–920/2015 दिनांक 01–01–2016 द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रभारी निरीक्षक, थाना दोहरीघाट द्वारा वर्तमान में अनुज्ञापी का आचरण उत्तम होने के आधार पर चरित्र सत्यापन की संस्तुति की गई है, किन्तु अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि ''आवेदक का 16 अभियोगों का लम्बा अपराधिक इतिहास होने, शातिर अपराधी होने तथा चरित्र उत्तम नहीं होने के कारण दिनांक 25–05–2015 को चरित्र

सत्यापन हेतु संस्तुति नहीं अंकित है तथा धारा–4 (3) आब0अधि0 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुज्ञापी का कोई आपराधिक इतिहास न होने की शर्तों का प्राविधान है। ऐसी स्थिति में आवेदक के आपराधिक इतिहास के कारण संस्तुति नहीं की जाती है।''

अतः पुलिस अधीक्षक, मऊ की उक्त आख्या के आलोक में देशी शराब दुकान दोहरीघाट खटिक टोला के अनुज्ञापी श्री त्रिलोकी सोनकर का चरित्र उत्तर न होने के कारण उ0 प्र0 आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 के नियम–21 (घ) के तहत दिनांक 11–02–2016 को देशी शराब दुकान दोहरीघाट खटिक टोला (नेशनल हाई–वे के पश्चिम) को निरस्त करते हुए उक्त दुकान की जमा बेसिक लाइसेन्स फीस तथा प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में समपहृत करते हुए श्री त्रिलोकी सोनकर को काली सूची में डाल दिया गया है।,

जनपद हाथरस के अन्तर्गत ग्राम पिछोती से धुवई होते हुए सिकन्दराराऊ हसायन तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

कृपया आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला हाथरस के अन्तर्गत ग्राम.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

खपिछोती से धुवई होते हुए सिकन्दराराऊ–हसायन मार्ग तक की सड़क (ल0 लगभग 5 कि0मी0) जर्जर/क्षतिग्रस्त अवस्था में है। उक्त सड़क कई गांवों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। क्षतिग्रस्त सड़क पर लगभग पांच ग्राम पंचायत एवं दो लिंक सड़कें पड़ती हैं। उक्त क्षतिग्रस्त सड़क से हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त होने क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों के साथ मार्ग दुर्घटनायें हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक उक्त क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर में सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

केवल वक्तव्य

जनपद हाथरस में पिछोती से धुवई ग्राम तक मार्ग की लम्बाई 3.25 किमी0 है। यह लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जो क्षतिग्रस्त है। ग्राम धुवई से लोधीपुर होते हुए सिकन्द्राराऊ–हसायन मार्ग (पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्मित) तक मार्ग की लम्बाई 2.60 कि0मी0 है जो संतोषजनक स्थिति में है। पिछोती से धुवई तक 3.25 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र कस्ता में पानी की टंकी से निकलने वाली समस्त पाइप लाइनों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार लाला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25–02–2016 को दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

ख्अवगत कराना है कि जनपद–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र कस्ता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र कस्ता के अन्तर्गत मेंगलगंज एवं औरंगाबाद में पानी की टंकी है जिससे पेयजल हेतु ग्रामवासियों को पानी मिलता है। परन्तु उक्त पानी की टंकी से निकलने वाली पाइपें कहीं चोक हो गयी हैं, कहीं टूट गयी हैं और कई ध्वस्त हो चुकी हैं। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में जिले के उच्चाधिकारियों को कई बार अवगत करा चुका हूं। परन्तु अभी तक उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है जिससे पेयजल की समस्या लगातार बनी हुयी है एवं जनता त्राहि–त्राहि कर रही है। उक्त पाइप लाइनें जहां ध्वस्त हो गयी हैं अथवा जहां चोक हो गयी हैं और जहां टूट गयी हैं वहां से पानी निकल रहा रहा और विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी किसानों से पैसा लेकर उक्त पानी से सिंचाई करा रहे हैं। मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है एवं धन उगाही का कारण भी बन रहा है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र कस्ता के अन्तर्गत विकास खण्ड पसगवां की मेंगलगंज ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जून,

---

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2010 में प्रारम्भ हुआ जिसे मार्च, 2012 में पूण्र कराया गया। मैंगलगंज ग्रामीण पाइप पेयजल योजना को पूर्ण कराने के उपरान्त दिनांक 26–11–2013 को योजना सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तगत करा दी गयी। उक्त तिथि के पश्चात् योजना का रख–रखाव सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है।

3–विधान सभा क्षेत्र कस्ता के अन्तर्गत विकास खण्ड पसगवां की औरंगाबाद ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सामान्यतः पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य में एक से डेढ़ वर्ष का समय लगता है जबकि प्रश्नगत योजना का निर्माण कार्य माह नवम्बर, 2014 में प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय, वितरण प्रणाली एवं स्टैण्ड पोस्ट का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है। केवल विद्युत संयोजन का कार्य अवशेष है। विद्युत संयोजन प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।,

जनपद मथुरा अन्तर्गत अन्तर्गत मथुरा एवं वृन्दावन में केन्द्र की तत्कालीन सरकार की जेनर्म एवं यू0डी0आई0 एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत बिछाई गई सीवर लाइन को एस0टी0पी0 से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

श्री प्रदीप माथुर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25–02–2016 को निम्नलिखित सूचना दी गयी है.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

ख्विधान सभा क्षेत्र, मथुरा एवं वृन्दावन में केन्द्र की तत्कालीन यू0पी0ए0 सरकार की जेनर्म एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत जो सीवर लाइन बिछायी गयी थी अभी तक उनमें सीवेज कनेक्टीविटी नहीं किया गया है। सीवेज नाली व जुड़ने से इस क्षेत्र की जनता नारकीय जीवन–यापन करने को मजबूर है। सीवर की पानी खुले में फैलने के कारण यहां के हालात बद् से बद्तर होते जा रहे हैं। इसलिये यहां पर तत्काल सीवर लाइन को एस0टी0पी0 से कनेक्ट करते हुए यहां के निवासियों को सीवर कनेक्शन दिया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0/यू0आई0डी0 एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत बिछायी गयी सीवर लाइन को पम्पिंग स्टेशन से जोड़कर एस0टी0पी0 से कनेक्ट कर दिया गया है। मथुरा ट्रान्स यमुना जोन हेतु 21200 नग सीवर हाउस कनेक्शन हेतु रु0 6211.21 लाख का प्राक्कलन 'अमृत' योजना के अन्तर्गत तैयार किया गया है जिसे यथाप्रक्रिया स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जायेगी। योजना के स्वीकृत होने तथा धनराशि की व्यवस्था हो जाने के पश्चात् सीवर लाइनको घरों से जोड़ने की कार्यवाही की जा सकेगी।,

जनपद मेरठ के अन्तर्गत मवाना शुगर मिल द्वारा हजारों किसानों के गन्ने का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभु दयाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अंतर्गत दिनांक 25–02–2016 को दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वसीम अहमद–

ख्कि जनपद मेरठ में मवाना शुगर मिल द्वारा हजारों किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान न हो पाने की वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवार भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से किसानों के बकाये का भुगतान शीघ्र कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मेरठ में स्थित निजी क्षेत्र की चीनी मिल, मवाना शुगर वर्क्स लि0, मवाना पर पेराई सत्र, 2014–15 के अन्तर्गत दिनांक 29–02–2016 तक रु0 94.15 करोड़ गन्ना मूल्य अवशेष है। अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु चीनी मिल, मवाना के विरुद्ध दिनांक 20–08–2015 को वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। तद्नुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है।

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेराई सत्र, 2015–16 के अन्तर्गत दिनांक 29–02–2016 की स्थिति के अनुसार चीनी मिल, मवाना पर रु0 230/–प्रति कुन्तल की दर से 14 दिन पूर्व अवधि तक कुल रु0 172.83 करोड़ का गन्ना मूल्य देय हुआ है। चीनी मिल द्वारा अभी तक कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु चीनी मिल को उ0 प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 11–02–2016 तथा दिनांक 01–03–2016 को निर्गत की गयी है।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 09 बजकर 53 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 05 मार्च, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 146 विधान सभा (170) 17–08–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।